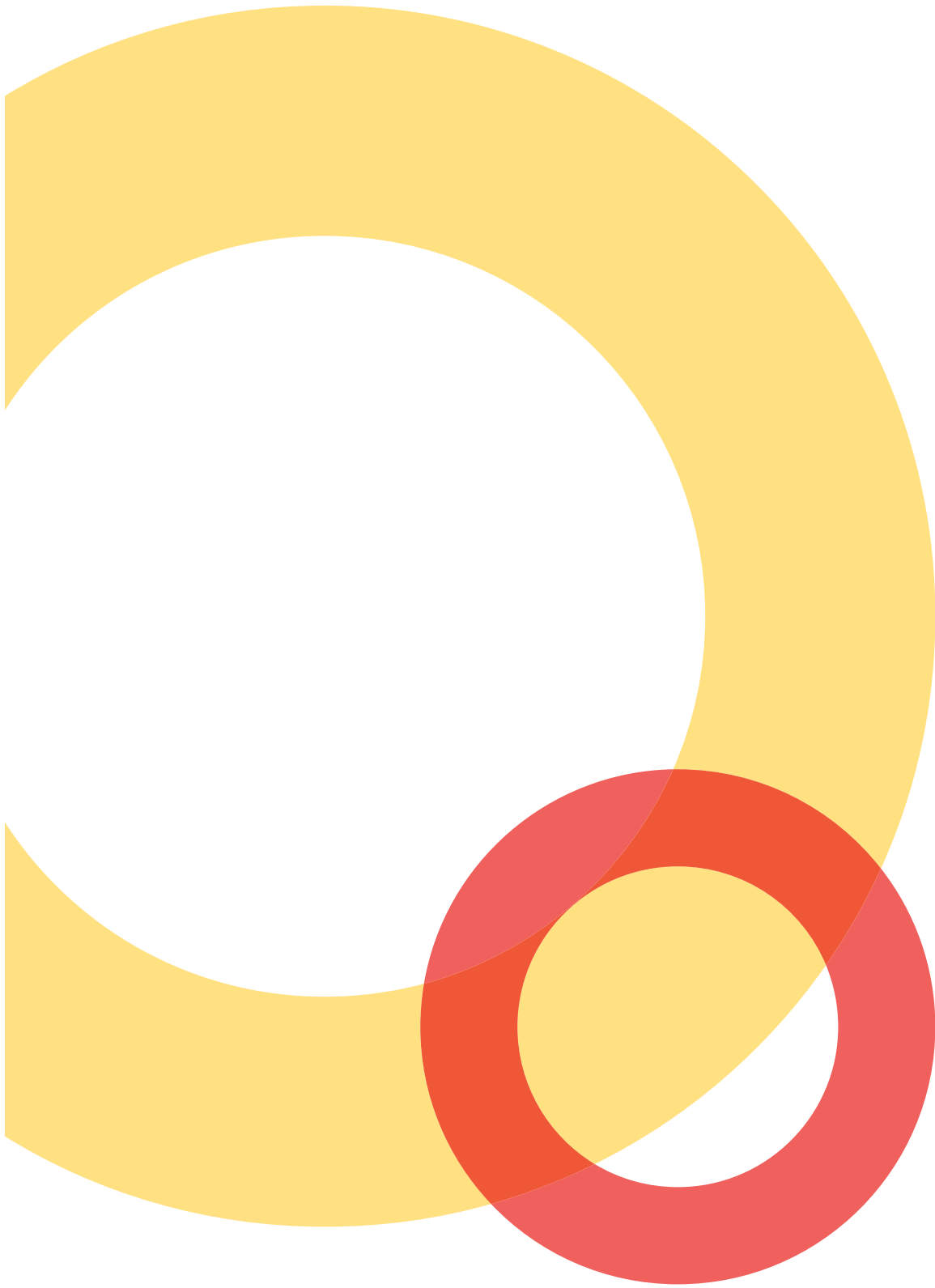




भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में तारीख 01 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप के अनुरूप है।



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
www.ibbi.gov.in

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

2 Floor, Jeevan Vihar Building, Parliament Street, New Delhi, 110001

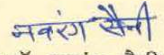
Tel: +91 11 2346 2999, +91 11 2346 2900, +91 11 2346 2800 Web: www.ibbi.gov.in

बोर्ड-18011/1/2021-आई.बी.आई.

31 दिसंबर, 2021

सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110001

महोदय,
मैं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 229 के उपबंधों के अनुसार, भारत के राजपत्र में तारीख 1 मई, 2018 को अधिसूचित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. नवरंग सैनी)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

BOARD-18011/1/2021-IBBI

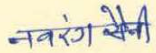
31st December, 2021

The Secretary to Government of India
Ministry of Corporate Affairs
'A' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi- 110 001

Dear Sir,

In accordance with the provisions of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, I forward herewith a copy of the Annual Report of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the period 1st April, 2020 to 31st March, 2021, in the form prescribed in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018 notified on 1st May, 2018 in the Gazette of India.

Yours faithfully,


(Dr. Navrang Saini)

Encl.: As above.

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष



डॉ. एम. एस. साहू

पूर्णकालिक सदस्य



डॉ. नवरंग सैनी



डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय



श्री सुधाकर शुक्ला

पदेन सदस्य



डॉ. श्यांकांक सक्सेना
सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय



श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय



डॉ. राजीव मणि
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
विधिक कार्य विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय



श्री उनिकृष्णन ए.
विधि सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

अंशकालिक सदस्य



श्री बी. श्रीराम
पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



डॉ. कृष्णामूर्ति सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलहाकार
भारत सरकार

आईबीबीआई के अधिकारी

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)



श्री रितेश कावड़िया
ईडी



डॉ अनुराधा गुरु
ईडी



श्री संतोष कुमार गुक्ला
ईडी



श्री देबज्योति रे चौधरी
सीजीएम



श्री राजेश कुमार गुप्ता
सीजीएम



श्री अप्पला सुबह्णयम
सीजीएम



श्री दिलीप अर्जुन खंडाले
डीजीएम



डॉ. कोकिला जयराम
डीजीएम



श्री सुनील कुमार
डीजीएम



श्री सुशांत कुमार दास
डीजीएम



श्री रामचंद्र राव
डीजीएम



श्री बी. संकरनारायण
डीजीएम



श्री केशव कुमार गिरिधारी
डीजीएम



श्री नीतीश सैनी
एजीएम



श्री मयंक मेहता
एजीएम



श्री पंकज कुमार
एजीएम



श्री राहुल खन्ना
एजीएम



श्री अनिकेत शर्मा
प्रबंधक



श्री प्रतीक जैन
प्रबंधक



श्री पंकज धापोदकर
प्रबंधक



श्री राघा रमन कुमार
प्रबंधक



श्री अशिकेक मित्तपल्ली
सहायक प्रबंधक



श्री अंशुल अग्रवाल
सहायक प्रबंधक



सुश्री अर्चना शर्मा
सहायक प्रबंधक



श्री अक्षित बेहरा
सहायक प्रबंधक



श्री दीपणु सिंह
सहायक प्रबंधक



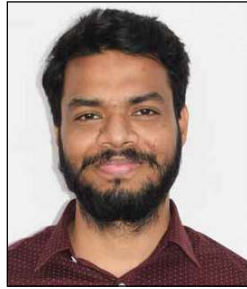
सुश्री मनप्रीत कौर
सहायक प्रबंधक



सुश्री मेधा शेखर
सहायक प्रबंधक



सुश्री नमिषा सिंह
सहायक प्रबंधक



श्री ओम प्रकाश
सहायक प्रबंधक



श्री ओमबीर सिंह
सहायक प्रबंधक



सुश्री पूजा सिंगला
सहायक प्रबंधक



श्री राघव माहेष्वरी
सहायक प्रबंधक



श्री राममिलन सिंह यादव
सहायक प्रबंधक



श्री एस के बेहरा
सहायक प्रबंधक



श्री सरम संतोष
सहायक प्रबंधक



श्री सौरव मनोहर सरदार
सहायक प्रबंधक



सुश्री तुहिना माडी
सहायक प्रबंधक



श्री विनय पाण्डेय
सहायक प्रबंधक



श्री यादविवंदर सिंह
सहायक प्रबंधक

कार्यकारी निदेशक

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

नाम	प्रभाग
श्री रितेश कावडिया	कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट परिसमापन, स्थापना, मूल्यांकन परीक्षा, दिवाला परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी
डॉ. अनुराधा गुरु	अंतर्राष्ट्रीय मामले, बोर्ड सचिवालय, कार्यनीति, व्यक्तिगत दिवाला, व्यक्तिगत शोधन अक्षमता, राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन, डेटा प्रबंधन और प्रसार, मानव संसाधन, संसद कक्ष, स्नातक दिवाला कार्यक्रम, संचार और आरटीआई, सतत व्यावसायिक शिक्षा, ज्ञान प्रबंधन और भागीदारी, समर्थन।
श्री संतोष कुमार शुक्ला	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, संगठन (आईयू, आईपीए, आईपीई, आरवीओ), दिवाला व्यावसायिक और दिवाला व्यावसायिक अभिकरण, निगरानी, जांच, परिवाद, वित्त और लेखा, विधिक मामले, न्यायनिर्णयन, न्यायालय की कार्यवाही।

विषयवस्तु

बॉक्स मदों की सूची.....	ix
सारणियों की सूची.....	ix
चित्रों की सूची.....	xi
संक्षेपाक्षर	xii
खंड क : अध्यक्ष का कथन	1
खंड ख : समीक्षाधीन वर्ष	
वृहत आर्थिक सन्दर्भ	9
प्रमुख नीतिगत घटनाएं	11
खंड ग : नीतियां, कार्यक्रम और क्रियाकलाप	
ग. 1 : सेवा प्रदाता	
दिवाला व्यावसायिक	21
दिवाला व्यावसायिक एंटीटीज	23
दिवाला व्यावसायिक अभिकरण	23
सूचना उपयोगिताएं	24
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	25
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन.....	26
परिपत्र	27
ग.2 : प्रक्रियाएं	
कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया	28
फॉस्ट ट्रेक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया.....	29
कारपोरेट परिसमापन	29
स्वैच्छिक परिसमापन	30
वित्तीय सेवा प्रदाता	30
व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता.....	30
ग.3 : पक्ष-समर्थन और जागरूकता	
कार्यक्रम	34
शैक्षणिक नियोजन.....	35
न्यूजलेटर.....	36
ग.4 : अनुसंधान	
खंड घ : बोर्ड के कार्य	
अर्ध विधायी कार्य	39
कार्यकारी कार्य	41
अर्ध न्यायिक कार्य	55
खंड ड. : परिणामों का विप्लेषण	
कारपोरेट दिवाला समाधान	57
कारपोरेट परिसमापन	62

बारह बड़े खाते	63
स्वैच्छिक परिसमापन	64
वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान	66
व्यक्तिगत प्रक्रिया	66
उभरता न्यायशास्त्र	67
खंड च : संहिता का प्रभाव	81
खंड छ : बोर्ड का कार्य-निष्पादन	88
खंड ज : ग्रासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन	101
खंड झ : बोर्ड का वित्तीय कार्य-निष्पादन	110
खंड ञ : सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन	112
खंड ट : संगठनात्मक मामले	
उत्तरदायित्व केन्द्र	118
मानव संसाधन	119
परिदाय अभिकल्प	120
वार्षिक दिवस समारोह	124
सूचना का अधिकार और पारदर्शिता	125

बॉक्स ढदों की सूची

1	कोविड-19 के प्रति दिवाला विधि प्रतिक्रिया	12
2	जीवन और आजीविका बचाने के लिए व्यवसायों को बचाना: जी30 से नीतिगत नुस्खे	14
3	संहिता, नियम और विनियमन – एक सफल यात्रा.....	68
4	दिवाला कानून और क्रेडिट चैनल	84
5	आईबीबीआई: एक स्व-मूल्यांकन.....	95
6	नियामक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीके और साधन	100
7	प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान	105
8	समाधानशीलता : कंपनियों प्रक्रिया की सजीव इच्छा.....	106
9	दिवाला कानून के सामाजिक प्रभाव	108
10	संहिता के अधीन समाधान के लिए एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता.....	109

सारणियों की सूची

1	नीति और नियामक घटनाओं का कालक्रम, 2020-21	18
2	एनईएसएल के पास जानकारी का विवरण	25
3	बोर्ड द्वारा 2020-21 में जारी परिपत्र.....	27
4	2020-21 के दौरान सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन	28
5	2020-21 के दौरान परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों में संशोधन	29
6	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते.....	30
7	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते	30
8	बोर्ड के समर्थन और जागरूकता कार्यकलाप	31
9	आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी	31
10	2020-21 के दौरान कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण	31
11	2020-21 में अधिसूचित विनियमन.....	40
12	विषयवार गोलमेज आयोजन.....	40
13	सेवा प्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति की संरचना	41
14	कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी सलाहकार समिति की संरचना.....	41
15	आईपी का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरणों का निरस्तन	42
16	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का वितरण	42
17	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण.....	42
18	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का आयु प्रोफाइल	44
19	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त आईपीई	44
20	31 मार्च, 2021 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापन	44
21	2020-21 के दौरान तैयार किया गया आईपी का पैनेल	45
22	2020-21 में आईपी के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम.....	45
23	2020-21 में अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम.....	46
24	2020-21 में आयोजित सीओसी कार्यशालाएं.....	46
25	2020-21 में आईपीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम	46
26	2020-21 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण	47
27	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा निष्पादित सीपीई घंटे	48
28	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी.....	48
29	31 मार्च, 2021 तक आरवी का पंजीकरण	49
30	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकक संस्थाएं	49

31	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार आरवी	49
32	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी का आयु प्रोफाइल.....	51
33	31 मार्च 2021 तक क्षेत्रवार सीमित दिवाला परीक्षा.....	51
34	संपत्ति वर्ग भूमि एवं भवन में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा	52
35	संपत्ति परिसम्पत्तियों वर्ग संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा.....	52
36	वर्ग प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसम्पत्तियों में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा.....	52
37	आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों निरस्तन	53
38	31 मार्च, 2021 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान	53
39	बोर्ड और आईपीए द्वारा आयोजित आईपी का निरीक्षण.....	54
40	आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई.....	54
41	आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निपटान	55
42	2020-21 में अनुशासनात्मक कार्यवाही का समापन.....	55
43	31 मार्च, 2021 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया.....	57
44	31 मार्च, 2021 तक पीठ वार सीआईआरपी का प्रवेश और समापन	58
45	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत.....	58
46	31 मार्च, 2021 तक सीआईआरपी के अधीन सीडी का क्षेत्रीय वितरण.....	59
47	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सीआईआरपी की स्थिति.....	59
48	31 मार्च, 2021 तक वापसी द्वारा सीआईआरपी का समापन.....	59
49	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार योजना में परिणित सीआईआरपी	60
50	31 मार्च की स्थिति के अनुसार हितधारक-वार शुरु की गई सीआईआरपी का परिणाम.....	60
51	कारपोरेट दिवाला में परिहार लेनदेन.....	61
52	परिसमापन के आदेश के साथ समाप्त सीआईआरपी.....	62
53	31 मार्च, 2021 को परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति	62
54	31 मार्च, 2021 तक परिसमापन का विवरण.....	62
55	240 परिसमापन प्रक्रियाओं में दावे जिनमें अंतिम रिपोर्ट जमा की गई.....	63
56	12 बड़े खातों की स्थिति	63
57	31 मार्च, 2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन की शुरुआत.....	64
58	900 परिसमापनों का विवरण (7 वापसियों को छोड़कर).....	64
59	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों की देनदारियों और आस्तियों का वितरण	64
60	स्वैच्छिक परिसमापन का क्षेत्रवार वितरण	64
61	स्वैच्छिक परिसमापन के कारण	65
62	स्वैच्छिक परिसमापन का चरणीकरण	65
63	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते.....	65
64	व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान.....	66
65	लेनदारों द्वारा वसूली	85
66	क्रेडिट संस्कृति पर प्रभाव.....	86
67	तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों का बचाव	86
68	संहिता के अधीन प्रक्रिया को पूरा करने का औसत समय.....	87
69	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विनियमन.....	89
70	आईपी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	91
71	2020-21 के दौरान आईबीबीआई द्वारा जारी विभिन्न आदेश.....	91
72	2020-21 में प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियाँ	93

73	शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति.....	101
74	2020-21 के दौरान शासी बोर्ड का निष्पादन.....	102
75	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आय और व्यय विवरण.....	110
76	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि.....	110
77	सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण.....	112
78	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का गवर्निंग बोर्ड.....	118
79	अनुशासन समिति की संरचना.....	119
80	आईबीबीआई के कर्मचारी.....	119
81	2020-21 में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान.....	121
82	2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले आईबीबीआई के अधिकारी.....	121
83	आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम.....	122
84	आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील की प्राप्ति और निपटान.....	126

चित्रों की सूची

1	जीडीपी, क्रेडिट और जीएनपीए की वृद्धि.....	10
2	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईपी का भौगोलिक वितरण.....	43
3	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी का भौगोलिक वितरण.....	50
4	सीआईआरपी में सीडी का माह-वार प्रवेश.....	58
5	व्यावसायिकों का वर्ष-वार रजिस्ट्रीकरण.....	82
6	2016-17 से 2020-21 तक का वर्ष वार समाधान.....	82
7	2016-17 से 2020-21 तक स्वीकृत सीआईआरपी का रुख.....	83
8	सीआईआरपी का वर्ष वार समापन.....	83
9	सीडी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन.....	83

संक्षेपाक्षर

ए.ए.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
ए.सी.	सलाहकार समिति
सलाहकार समिति विनियमन	आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017
एसीएसटी	राज्य कर सहायक आयुक्त
एडीआर	वैकल्पिक विवाद समाधान
एफए	कार्य के लिए प्राधिकृत करना
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एएलडब्ल्यू	प्रशासनिक विधि खंड
एएम	सहायक प्रबंधक
एआर	प्राधिकृत प्रतिनिधि
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एसोचैम	एसोसिएटेड चोम्बर्स आफ कामर्स और इंडस्ट्री आफ इंडिया
बीसीआईसी	बैंगलोर चोम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलआरसी	शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति
बोर्ड/आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड विनियमन	आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2017
बीएसई	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीटी	शोधन अक्षमता न्यासी
उप-नियम विनियमन	आईबीबीआई (आदर्श उप-नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016
सी-एजी	भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक
केयर्स निधि	आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीडी	कारपोरेट ऋणी
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत् आयोग
सीईवी	अभियंता और मूल्यांकक परिषद्
सीएफए	चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक
सीएफआई	भारतीय समेकित कोष
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएन	कारपोरेट पहचान संख्या
सीआईआरपी (एस)	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/प्रक्रियाएं
सीआईआरपी विनियमन	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सीएमएस	केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली
सीएनआई ब्राजील	कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ब्राजील
सीओसी	लेनदारों की समिति
संहिता/आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सीओई	विशेषज्ञ समिति
सीओपी	प्रेक्टिस प्रमाणपत्र
सीपीई	सतत व्यावसायिक शिक्षा
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानिट्रिंग प्रणाली
सीवीएसआरटीए	सेंटर फॉर वेल्थेशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन

डीसी	अनुशासनात्मक समिति
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफआई	विकास वित्त संस्थान
डीजीएम	उप-महाप्रबंधक
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महा निदेशालय
डीएचएफएल	दीवान हाउसिंग फाइनंस कारपोरेशन लिमिटेड
डीआईडी	अंतरों में अंतर
डीआरटी	ऋण उगाही अधिकरण
डीटीआरटीआई	प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
डीवीआई	डेक्कन मूल्य निवेश
ईएसी पीएम	प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद
ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यहास और ऋण-मुक्ति
ईडी	कार्यकारी निदेशक
ईआईआरसी ऑफ आईसीएआई	आईसीएआई की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
परीक्षा	सीमित दिवाला परीक्षा
ईएक्सआईएम	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
फॉस्ट ट्रेक विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फॉस्ट ट्रेक दिवाला प्रक्रिया) विनियमन, 2017
एफसी/एफसीज	वित्तीय लेनदार/ लेनदारों
एफसीडीओ	विदेश, कामनवेल्थ और विकास कार्यालय
फिक्की	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री
एफओआईआर	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स
एफपीसी	फोर्बर्ड मार्केट कमिशन
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफआईएसपी	वित्तीय सेवा प्रदाता
एफआईएसपी नियम	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन प्रक्रिया) नियम, 2019
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीबी	शासी बोर्ड
जीडीपी	सकल देशीय उत्पाद
जीईएम	गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस
जीएफसीई	सकल स्थिर उपभोग व्यय
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईपी	स्नातक दिवाला कार्यक्रम
जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां
जीओआई	केन्द्रीय सरकार
जीएसटी	वस्तुएं और सेवाएं कर
जीवीए	सकल वर्धित मूल्य
एचसी	उच्च न्यायालय
आईए	निरीक्षण प्राधिकारी
आईएआईआर	अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक एसोसिएशन
आईबीए	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीडी	दिवाला प्रारम्भ तारीख

आईसीएफएआई	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान
आईसीएआई (लागत)	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीएलएस	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआई- आईआईपी	आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईडीएफ	भारतीय विकास प्रतिष्ठान
आईईजी	आर्थिक विकास संस्थान
आईईपीएफ	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि
आईईएस	भारतीय आर्थिक सेवा
आईएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र प्राधिकरण
आईआईबीएफ	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान
आईआईआई	अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान
आईआईआईपी	भारतीय आईसीएआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएलसी	दिवाला विधि समिति
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
निरीक्षण विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निरीक्षण और अन्वेषण) विनियमन, 2017
आईएनएसओएल	अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना, दिवाला और शोधन अक्षमता व्यावसायिक एसोसिएशन
आईओवी	मूल्यांकक संस्थान
आईओवीआरवीएफ	आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान
आईपी / आईपीज	दिवाला व्यावसायिक / दिवाला व्यावसायिकों
आईपी विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
आईपीए / आईपीएज	दिवाला व्यावसायिक अभिकरण / अभिकरणों
आईपीए विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016
आईपीए आईसीएआई	आईसीएआई का दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
आईपीई / आईपीईज	दिवाला व्यावसायिक एंटीटी / दिवाला व्यावसायिक एंटीटीज
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरपी	अंतरिम समाधान व्यावसायिक
आईआरपीसी	दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत
आईएसटीएम	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान
आईयू / आईयूज	सूचना उपयोगिता / सूचना उपयोगिताएं
आईयू विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
परिसमापन विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
एलएनसीटी	लक्ष्मी नारायण प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीसीआई	मर्चेट्स चौम्बर ऑफ कामर्स - इंडस्ट्री
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएलजे	विधि और न्याय मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

एमओआर	संचालन-समीक्षा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भावन निर्माण निगम
एनसीईईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनईएसएल	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनआई अधिनियम	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईपीएफपी	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति
एनएलआईयू, भोपाल	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
एनएलएसआईयू	भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय, बंगलूरु
एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एनएलयूडी	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
एनपीए	अनर्जक परिसम्पतियाँ
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
ओसी/ओसीज	प्रक्रियागत लेनदार/लेनदारों
ओपीडी	बहिरंग रोगी विभाग
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीजी/पीजीज	व्यक्तिक प्रत्याभूतिदाता/ व्यक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं
पीएचडीसीसीआई	पी.एच.डी. चौम्बर आफ कामर्स और इंडस्ट्री
पीएनबी	पंजाब नेशनल बैंक
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएसबी/पीएसबीज	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक्स
पीएमएलए	प्रिवेशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002
पीपीआईआरपी	प्रि-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया
पीवीआई	दि प्रैक्टिसिंग वैल्युअर्स एसोसिएशन
पीडब्ल्यूसी	प्राइस वाटर हाउस कूपर्स
क्युएफसी	अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध
आर1	प्रथम प्रतिवादी
आर2	द्वितीय प्रतिवादी
आरए	समाधान आवेदक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
रेसा	स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
आरबीएसए	आरबीएसए सलाहकार
आरएफआरपी	समाधान योजना के लिए अनुरोध
आरपी	समाधान व्यावसायिक
आरएमडब्ल्यू	रजिस्ट्रीकरण और निगरानी विंग
आरआरडब्ल्यू	अनुसंधान और विनियमन विंग
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवी/आरवीज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों
आरवीई	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एंटीटी
आरवीओ/आरवीओज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन/ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों
एसएपी	कार्यनीतिक कार्य योजना

एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	भारतीय उच्चतम न्यायालय
एससीसी	हितधारक परामर्श समिति
एससीबीज	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएन	कारण बताओ सूचना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
एसएलपी	विशेष अनुमति याचिका
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसओए	समझौता अथवा व्यवस्था स्कीम
युएनसीआईटीआरएएल	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
मूल्यांकन नियम	कंपनी (मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017
स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन	आईबीबीआई(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017
डब्ल्यूजी	कार्यकारी समूह
आईसीएआई का डब्ल्यूआईआरसी	आईसीएआई का पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य



अध्यक्ष का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी/संहिता) एक महान कानून है क्योंकि यह व्यक्ति के तनाव को दूर करने का प्रयास करता है, चाहे वह कोई कंपनी हो, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या साझेदारी फर्म हो, या कोई व्यक्ति हो। हालांकि, मैं इस कथन को कंपनियों और एलएलपी तक सीमित कर रहा हूँ, क्योंकि कारपोरेट देनदारों (सीडी) के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं से संबंधित आईबीसी के उपबंध प्रवर्तित हो चुके हैं, लेकिन व्यक्तियों से संबंधित आईबीसी के उपबंध अभी तक प्रवर्तित नहीं हुए हैं।

कभी-कभी कोई कंपनी अपने नियंत्रणाधीन और कभी-कभी उसके नियंत्रण से परे कारणों की वजह से, तनाव अनुभव कर सकती है, अर्थात्, वह समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसके पास उस पर किये गए दावों की तुलना में कम परिसंपत्तियां हैं। प्राथमिक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जब किसी कंपनी के पास अपर्याप्त परिसंपत्तियां होती हैं, तो किसी व्यक्तिगत लेनदार का दावा कंपनी की परिसंपत्तियों के अनुरूप हो सकता है, लेकिन सभी लेनदारों के संयुक्त दावों के अनुरूप नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, लेनदार दूसरों से पहले अपने दावों की वसूली के लिए बेचैन हो जाते हैं, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों को हासिल करने की दौड़ शुरू हो जाती है। वे 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर वसूली करते हैं जब तक कि कंपनी की परिसंपत्तियां समाप्त नहीं हो जाती और परिणामस्वरूप कंपनी के समाप्त होने की स्थिति आ जाती है। यह एक नकारात्मक-योग का खेल है।

दूसरी ओर, यदि कंपनी का व्यवसाय व्यवहार्य है तो आईबीसी में बाजार प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को बचाने के लिए पुनर्गठन की व्यवस्था है और यदि व्यवहार्य नहीं है तो इसे बंद करने का भी प्रावधान है। बचाव करने के मामले में, कंपनी को एक चालू कंसर्न के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। लेनदारों के दावों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसका भुगतान उन्हें तुरंत कर दिया जाता है या समय के साथ-साथ किया जा सकता है। बंद होने की स्थिति में, कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच दिया जाता है, और आय को प्राथमिकता के नियम के अनुसार लेनदारों को तुरंत वितरित कर दिया जाता है। आईबीसी तनावग्रस्त कंपनी के पुनर्गठन की जिम्मेदारी वित्तीय लेनदारों (एफसी) को सौंपता है, क्योंकि उनके पास अपने दावों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छाशक्ति है। वे एक ऐसी कंपनी को बचाने की संभावना रखते हैं जिसके पास प्रचलित अधिशेष है और जो कंपनी और एफसी के हितों के अनुरूप है, जिससे यह एक सकारात्मक-योग खेल बन जाता है। इस पृष्ठभूमि में, यह जानना वांछनीय है कि आईबीसी किस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है।

परिणामों के लिए मेट्रिक्स

दिवाला सुधार सहित, हर आर्थिक सुधार समग्र आर्थिक कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से बाजार सहभागियों के लिए खेल के नियमों की कुछ हद तक पुनर्संरचना कर देता है। इस प्रकार यह हितधारकों के हितों को प्रभावित

करता है: पुराने आदेश की तुलना में कुछ को लाभ हो सकता है जबकि कुछ अन्य को हानि हो सकती है। इसकी संभावना नहीं है कि घाटा खाने वाले या लाभ कमाने वाले, जो आम तौर पर अपने स्वार्थ में अंधे होते हैं, एक ऐसे मीट्रिक का उपयोग करेंगे जो समग्र रूप से और निष्पक्ष रूप से सुधार के परिणाम का आकलन करता है। वे अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए अलग-अलग उदाहरणों का हवाला देंगे। पुराने आदेश का लाभार्थी, दिवाला सुधारों का रोना रोने के लिए घोटारिंगा मिनरल लिमिटेड और ऑर्किड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का हवाला दे सकता है। वह दावा कर सकता है कि संहिता के अधीन इन दोनों कंपनियों के परिसमापन से लेनदारों के लिए कुछ हजार करोड़ रुपये के उनके दावों की तुलना में बहुत कम की वसूली हुई। हालांकि, वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि दिवाला कार्यवाही में प्रवेश करने के समय पर इन कंपनियों के पास पर कोई परिसंपत्ति थी ही नहीं। मूल्यांकन के लिए मीट्रिक का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हितधारक मेज के किस ओर बैठता है।

ऐसा निष्पक्ष विश्लेषक, जो वृहत् परिप्रेक्ष्य में सुधार को देखता है, उसके द्वारा ऐसा मीट्रिक उपयोग किये जाने की संभावना है जो कि सबसे उपयुक्त होने की बजाय आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से समझ में आता हो और विश्लेषण के लिए उपयुक्त हो। दिवाला कार्यवाही के माध्यम से वसूली के बारे में विश्वसनीय आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों अर्थों में वसूली को आसानी से समझा जा सकता है। इसका उपयोग एक कंपनी के समाधान की दूसरी कंपनी के साथ तुलना करने के लिए या समाधान और वसूली के विभिन्न विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। कुछ विश्लेषक इस सुविधा के कारण दिवाला सुधारों के परिणाम का आकलन करने के लिए मीट्रिक के रूप में वसूली का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं, भले ही यह दिवाला सुधारों का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, और यह कुछ दिवाला कार्यवाही के उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। दिवाला कार्यवाही को बंद करने में लगने वाला समय एक अन्य सुविधाजनक मीट्रिक है। एक आशावादी, पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था की तुलना में संहिता के अधीन लिए गए समय का निरीक्षण कर सकता है, जबकि एक निराशावादी वास्तव में लिए गए समय और संहिता के अधीन परिकल्पित समय के बीच के अंतर पर विचार कर सकता है।

कुछ सुविधाजनक मेट्रिक्स भ्रामक हो सकते हैं। वसूली, हालांकि एक सटीक मीट्रिक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। संहिता के अंतर्गत समाधान योजनाएँ स्वीकृत दावों का औसतन X% वसूल करती हैं। वसूली का ऐसा स्तर किसी के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि यह उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम की वसूली करता है। यह दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेनदार स्वीकृत दावों के Y% (100 - X) की कटौती करते हैं। इसके अलावा, स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली का अधिक अर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि ये अक्सर देनदार या लेनदार की बहियों में परिलक्षित नहीं होते हैं। जो प्राप्त किया जा सकता था वह देनदार की बहियों में उपलब्ध संपत्ति के मूल्य से परिलक्षित होता है और जो प्राप्त किया जाना चाहिए वह लेनदार

की बहियों में ऋण के द्वासात मूल्य से परिलक्षित होता है। क्या वसूली की जानी चाहिए या क्या वसूली की जा सकती है, की तुलना में की गई वसूली X% से बिलकुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है।

विधि और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी दिवाला सुधार को बहुत गहरे परिप्रेक्ष्य में देखता है। उसका मानना है कि प्रत्येक आर्थिक कार्यकर्ता ने तर्कसंगतता को सीमित कर दिया है और वह सभी संभावित आकस्मिकताओं/परिणामों का आकलन या अनुमान नहीं लगा सकता। यही कारण है कि यह अनुबंध संपन्न करता है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अपनी शर्तों पर पुनःबातचीत करके उन्हें संशोधित करता है, और फिर भी हर अनुबंध कुछ कमियों और लुप्त अनुबंधों के साथ अधूरा रह जाता है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता, श्री ओलिवर डी. हार्ट का तर्क है कि एक फर्म अधूरे अनुबंधों की श्रृंखला संपन्न करती है जो प्रत्येक लेनदार को क्रेडिट के बदले फर्म की परिसंपत्तियों पर बंदी-पूर्व अधिकार प्रदान कर देता है। प्रत्येक लेनदार 'अकेले चलो' आधार पर सहज महसूस करता है और फर्म सामान्य रूप से प्रत्येक लेनदार के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करती है और जीवन चलता रहता है। हालाँकि, जब फर्म पर जोर दिया जाता है, तो वह एक या कुछ लेनदारों के दावों का पूरी तरह से सम्मान कर सकती है, लेकिन सभी लेनदारों के दावों का एक साथ नहीं। यदि प्रत्येक लेनदार अपने दिवाला-पूर्व अधिकारों पर अडिग रहता है, तो न तो तनाव का समाधान संभव है और न ही कोई लेनदार अपने बकाया का भुगतान कर सकता है। दिवाला फ्रेमवर्क परिस्थितियों में वास्तविक रूप से संभव सीमा तक लेनदारों के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए तनाव को हल करने का प्रयास करता है। इस प्रकार दिवाला सुधार एक व्यापक अनुबंध है, जो सभी अपूर्ण द्विपक्षीय अनुबंधों को पूरा करता है, सभी लेनदारों के दावों को सुसंगत बनाता है और फर्म की परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को रोकता है। एक व्यापक अनुबंध की अनुपस्थिति में, पार्टियाँ अपूर्ण अनुबंधों की श्रृंखला को लागू करेंगी, जिससे देनदार का सफाया हो जाएगा और कुछ लेनदारों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। व्यापक अनुबंध देनदार और लेनदारों को बचाने की कोशिश करते हुए, सभी अपूर्ण अनुबंधों को लागू करता है। मान लें कि किसी देश में अनुबंध प्रवर्तन में चार वर्ष लगते हैं जबकि दिवाला कार्यवाही में एक वर्ष लगता है। विधि का विद्यार्थी अनुबंध प्रवर्तन में बचाए गए समय को, जबकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी देनदार और लेनदारों को होने वाली हानि से बचाने को मीट्रिक के रूप में उपयोग कर सकता है।

एक व्यवसायी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है। स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊँचा होता है, अर्थव्यवस्था में व्यापार करना उतना ही आसान होता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था : "स्वतंत्रता योग्य नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।" एक व्यवसायी को अवसर मिलने पर व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वतंत्रता और असफल होने पर व्यवसाय से बाहर निकलने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। वह आमतौर पर तब व्यवसाय शुरू करता है जब उसके पास उससे बाहर निकलने का आश्वासन होता है। वह विफल हो जाता है जब वह शुम्पेटेरियन के 'रचनात्मक विनाश की आंधी' का शिकार हो जाता है, जहाँ उसका व्यवसाय या तो कालातीत हो जाता है या सामान्य लाभ नहीं कमाता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की तीव्रता जितनी अधिक होती है, विफलता की दर उतनी ही अधिक होती है, घाटे वाले व्यवसायों के स्थान पर लाभ वाले व्यवसायों के आगमन के अवसर उतने अधिक हो जाते हैं, और बाहर निकलने की स्वतंत्रता की आवश्यकता भी अधिक होती है। ईमानदार व्यवसायी दिवाला सुधार के परिणाम का आकलन करने के लिए व्यवसाय से बाहर निकलने की स्वतंत्रता की डिग्री और गुणवत्ता का उपयोग मीट्रिक के रूप में करता है।

हम अंधे व्यक्ति और हाथी के दृष्टांत से परिचित हैं, जहाँ सात अंधे लोगों में से प्रत्येक अपने सीमित अनुभव के आधार पर एक ही हाथी का वर्णन

अलग-अलग ढंग से करता है। इसी तरह, कोई एकल मीट्रिक से दिवाला सुधार के परिणाम को पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। विश्व बैंक की "डूइंग बिजनेस रिपोर्ट" मेट्रिक्स के समूह का उपयोग करती है, जो किसी अर्थव्यवस्था के दिवाला समाधान के लिए किसी स्कोर पर पहुंचने के लिए दिवाला कार्यवाही के समय, लागत और वसूली और दिवाला ढाँचे की ताकत का भी अध्ययन करती है। इसकी अपनी सीमाएँ हैं, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली लगभग 200 देशों, जिनमें से प्रत्येक को दिवाला परिणामों का अनूठा अनुभव रहा है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

एक एकल मीट्रिक या मेट्रिक्स का संयोजन अक्सर अपेक्षाकृत नरम पहलुओं जैसे कि दिवाला से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण, या हितधारकों के व्यवहार परिवर्तन को नहीं देखता है। वे आम तौर पर संहिता के बाहर प्रेरित समाधानों, गहरे संकटों से उद्यमियों का बचाव, गहरे संकट में कंपनियों का बचाव, उत्पादक उपयोगों के लिए बेकार पड़े संसाधनों को निर्गत करना, और ऋण की बेहतर उपलब्धता जैसे प्रणालीगत लाभों को कैप्चर नहीं करते हैं। एक मीट्रिक उसे कैप्चर करता है जो मापा जा सकता है और जो मायने रखता है और उसे अनदेखा करता है जिसे मापा नहीं जा सकता है। जैसा कि इलियट आइज़नर कहते हैं : "हर चीज जो मायने रखती है उसे मापा नहीं जा सकता, और वह सब कुछ जिसे मापा जा सकता है, वह मायने नहीं रखता।"

एक सुव्यवस्थित मीट्रिक, परिणाम को मापने के बजाय इसको प्रभावित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जब हम परिणाम के माप के रूप में कोई विशिष्ट पैरामीटर सेट करते हैं, तो एक ही खेल में, अन्व्यों को समान रूप से, या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं और परिणाम के आयामों को नजरअंदाज करते हुए, उस पैरामीटर पर उच्च स्कोर हासिल करने की प्रवृत्ति होती है। गुडहार्ट का नियम चेतावनी देता है कि : "जब कोई उपाय लक्ष्य बन जाए, तो वह अच्छा उपाय नहीं रह जाता।"

मीट्रिक एकल बारगी मामला नहीं है। इसके लिए वर्षों तक सावधानीपूर्वक पोषण और सुधार की आवश्यकता होती है और मेट्रिक्स के निर्माण के लिए प्रामाणिक डेटा और सूचना के प्रावधान की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संकेतकों को बनाए रखने और उनकी सेवा के लिए विशिष्ट संगठन सामने आए हैं। जब दिवाला सुधार गहरी जड़ें जमा रहा हो, तो परिणामों को मापने के लिए ठोस मीट्रिक के बीज बोने का समय आ गया है। मीट्रिक (मीट्रिकों) को समग्र रूप से और निष्पक्ष रूप से परिणाम को मापना चाहिए, जिसमें बाजार की संरचना, प्रक्रियाओं और डिजाइनों का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रत्येक खंड अर्थात्, कारपोरेट दिवाला और परिसमापन, और व्यक्ति दिवाला और शोधन अक्षमता में अपनी निष्पक्षता, अखंडता और विश्वसनीयता में योगदान देता है। यदि उपयुक्त मीट्रिक क्या है, इस बारे में कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, और ऐसी मीट्रिक की सेवा के लिए डेटा/सूचना का कोई प्रावधान नहीं है, तो बाजार सुविधा के किसी भी मीट्रिक का उपयोग कर सकता है, जो सुधार के उद्देश्य का लाभ से अधिक नुकसान कर सकता है।

एक बार उपयुक्त मीट्रिक उपलब्ध हो जाता है और इसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है, इसे विधि के भावी पाठ्यक्रम के लिए डेटा-संचालित नीति बनाने की दिशा में उपयोग किया जा सकता है। यह अधिकारियों को उनकी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने और शक्तिशाली परिणाम देने में सहायक होगा। इसमें अच्छी नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए नीतियों पर तर्कसंगत सार्वजनिक बहस का सृजन करने और इस तरह से विचारों की क्राउडसोर्सिंग में मदद करने का अतिरिक्त लाभ है। मजबूत डेटा के बिना नीतियों को डिजाइन करना मुश्किल काम है और ऐसी नीतियों के परिणामों को मापना भी उतना ही मुश्किल है। एक ऐसा ढाँचा होना अनिवार्य है जो

प्रासंगिक डेटा निर्माण और प्रसार को संचालित करे और साथ ही नीति डिजाइन और कार्यान्वयन के मामलों में उपयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करे।

किसी भी तरह मेट्रिक्स के विकास पर बहस को सीमित किए बिना, इसके छह मूलभूत उद्देश्यों के आधार पर संहिता के परिणामों को मापने के लिए मेट्रिक्स का पता लगाया जा सकता है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं : (क) समयबद्ध तरीके से तनाव का समाधान; (ख) संपत्ति के मूल्य का अधिकतमीकरण; (ग) उद्यमिता को बढ़ावा देना; (घ) ऋण की उपलब्धता में वृद्धि; (ङ.) सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना, और (च) दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना। इन उद्देश्यों को दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के परिणामों की छह संभावित परतों में अनुदित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

(क) दिवाला व्यावसायिक (आईपी), दिवाला व्यावसायिक अभिकरण (आईपीए), दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं (आईपीई), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ), सूचना उपयोगिताओं (आईयू), न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एए), अपीलीय अधिकरण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), सरकार, न्यायालय, आदि को समाहित करके दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, शक्ति की वृद्धि और दक्षता;

(ख) प्रक्रियाओं अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान (सीआईआरपी), कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, पूर्व-पैक दिवाला समाधान, नई शुरुआत, सीडी के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं (पीजी) का समाधान, स्वामित्व का समाधान और साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता की शक्ति, दक्षता और प्रभावकारिता;

(ग) बाजारों जैसे कि अंतरिम वित्त के लिए बाजार, समाधान योजना, परिसमापन संपत्ति, दिवाला सेवाएं, लागत दक्षता, सूचना दक्षता, आदि की वृद्धि और दक्षता;

(घ) पूंजी की लागत, पूंजी संरचना, ऋण की उपलब्धता, उद्यमिता, क्षमता उपयोग, रचनात्मक विनाश, प्रतिस्पर्धा और नवाचार, आदि के संदर्भ में व्यवसायों पर प्रभाव;

(ङ.) देनदारों और लेनदारों के बीच व्यवहार परिवर्तन, देनदारों में लेनदारों का विश्वास, मेरिटोक्रैटिक उधार, गैर-अवलोकनीय प्रभाव, मानवीय सोच और संहिता के सक्रिय/निवारक प्रभाव; तथा

(च) राष्ट्र के रोजगार और आर्थिक विकास पर समग्र प्रभाव।

परिणामों में सुधार

आईबीसी के परिणामों को ट्रैक करने के लिए मेट्रिक्स का संस्थानीकरण करने में अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि, परिणामों के संदर्भ में कुछ विवरण उपलब्ध हैं जैसे कि संकल्पों और परिसमापन की संख्या, दिवाला प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्तियां, और प्रक्रियाओं में शामिल समय और लागत, जिन्हें इस रिपोर्ट के संबंधित खण्डों में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस तरह के परिणाम पूर्व-आईबीसी दिनों की तुलना में बेहतर हैं, फिर भी इनमें और सुधार की गुंजाइश है। परिणामों की तीन व्यापक आलोचनाएँ हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है :

(क) अधिक परिसमापन

यह तर्क दिया जाता है कि मार्च, 2021 तक 1277 सीआईआरपी परिसमापन में समाप्त हो गए, जबकि केवल 348 में ही समाधान हो पाया है। जो केवल अंतिम परिणाम देखता है, वह लगभग 1600 मामलों को अंतिम परिणाम तक पहुंचता हुआ देखता है। हालांकि, 18,000 से अधिक मामलों को या तो दाखिल करने से पहले या बाद में, लेकिन अंतिम परिणाम तक

पहुंचने से पहले बंद कर दिया गया था। यदि आईबीसी को स्पर्श करने वाली कंपनियों के पूरे विश्व पर विचार किया जाए, तो परिसमापन के लिए आगे आने वाली कंपनियों का प्रतिशत नगण्य है। अंतिम गेम में भी, बचाई गई तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य मायने रखता है। मूल्य के संदर्भ में, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की 70% राशि वाली कंपनियों को बचाया गया था, जबकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की 30% राशि वाली कंपनियों परिसमापन के लिए आगे बढ़ीं।

इसके अलावा, परिसमापन के लिए आगे बढ़ने वाली कंपनियों में से तीन-चौथाई निष्क्रिय थीं, और बचाई गई कंपनियों में से एक तिहाई निष्क्रिय थीं। इसका मतलब यह है कि अंतिम परिणाम तक पहुंचने वाली कंपनियों में से दो-तिहाई आरंभिक स्थिति में ही बंद हो गई थीं। परिसमापन के साथ समाप्त होने वाली कंपनियों के पास आईबीसी में प्रवेश करने पर, उनके खिलाफ दावों का औसतन लगभग 7% मूल्य की परिसंपत्ति थी। यदि कोई कंपनी वर्षों से बीमार है, और उसकी परिसंपत्ति काफी कम हो गई है, तो बाजार में इसे समाप्त करने की संभावना अधिक रहती है। संहिता दो तरह से पुनर्गठन का प्रावधान करती है, पहला समाधान योजना द्वारा, जिसमें विफल रहने पर, परिसमापन द्वारा। यह बाजार ही है जो चुनाव करता है, और विधि केवल एक प्रवर्तक है। परिसमापन अंत नहीं है, बल्कि संसाधनों के कुशल पुनर्चक्रण का एक साधन है। फिर भी, परिसमापनों की संख्या को कम करने की संभावना रहती है।

(ख) विशाल हेयरकट

कुछ लोग मानते हैं कि आईबीसी हेयरकट का उपकरण बन गया है। यह स्वयंसिद्ध है कि आईबीसी में आने वाली कंपनी के पास अपने सभी लेनदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति नहीं है। जिन कंपनियों को मार्च, 2021 तक आईबीसी के माध्यम से बचाया गया है, उनके पास आईबीसी में प्रवेश करने पर लेनदारों की देय राशि का औसतन 20% मूल्य था। इसका मतलब यह है कि लेनदारों को शुरुआत में 80% हेयरकट की उम्मीद थी। आईबीसी ने न केवल इन कंपनियों को बचाया, बल्कि एफसी के लिए हेयरकट को घटाकर 61% कर दिया। आईबीसी में शून्य से लेकर 100% तक का हेयरकट देखने में आया है। सवाल उठता है कि आईबीसी एक मामले में शून्य हेयरकट और दूसरे में 100% हेयरकट क्यों देता है? यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार चक्र, बाजार की भावना और विपणन प्रयास शामिल हैं। हालांकि, यह गंभीर रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी तनाव के किस चरण में आईबीसी में प्रवेश करती है। यदि रोगी ऐसी स्थिति में अस्पताल में आता है तो अस्पताल ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। आईबीसी-पूर्व लीगेसी का निपटानोतर महत्वपूर्ण है, चूंकि आईबीसी अपेक्षाकृत 'नवीन' मामलों को ही देखती है, इससे शायद हेयरकट बेहतर दिखेगा।

हेयरकट आम तौर पर दावे की राशि के संबंध में वसूली गई राशि है। वसूली की राशि में अक्सर वह राशि शामिल नहीं होती है जो समाधानोतर इक्विटी होल्डिंग, और परिहार लेनदेन की वापसी और प्रत्याभूतिदाताओं के दिवाला समाधान के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। दावे की राशि में अक्सर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और ऐसे एनपीए पर ब्याज शामिल होता है, जिसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया हो सकता है। इसमें ऋण के साथ-साथ ऐसे ऋणों के विरुद्ध प्रत्याभूति भी शामिल हो सकती है। दावे मार्केट-टू-मार्केट नहीं हैं। ये वास्तविक हेयरकट से अधिक दर्शाते हैं।

जमीन पर उपलब्ध परिसंपत्तियों के संबंध में कटौती देखना उचित हो सकता है न कि लेनदारों के दावों के आधार पर। पूर्ववर्ती कथन बेहतर समझ में आता है, क्योंकि बाजार एक कंपनी के संबंध में वह मूल्य प्रदान करता है जो वह कंपनी टेबल पर लाती है, न कि इस बात पर कि उस कंपनी पर

लेनदारों का कितना बकाया है। आईबीसी प्रक्रिया के प्रारंभ में परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता है, न कि उन परिसंपत्तियों को जो संभवतः पहले से मौजूद थीं। चूंकि यह जारी कंसर्न के अधिशेष के हिस्से को भुनाता है, इसलिए बचाव को मौजूदा परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का औसतन 188% प्राप्त हो रहा है, जिससे हेयरकट के बजाय 88% बोनस उत्पन्न होता है। वास्तव में, यह सीडी के उचित मूल्य का औसतन लगभग 100% प्राप्त कर रहा है। कंपनी को बचाने के अलावा, आईबीसी लेनदारों के लिए उपलब्ध विकल्पों में से, प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक उगाही करता है। फिर भी, तथाकथित हेयरकट कम होने की संभावना है।

(ग) अपेक्षाकृत लंबा समय

आईबीसी समयबद्ध समाधान का वादा करता है और यह सीआईआरपी के समापन के लिए वाद के समय सहित, 330 दिनों में निपटान को निर्धारित करता है। आईबीसी के आने से पहले के दिनों की तुलना में तो यह परिणाम बहुत अच्छा है, उस समय इसमें चार साल से अधिक समय लगा करता था। हालांकि, विधायी मंशा की तुलना में, यह इतना अच्छा नहीं है। इस पैरामीटर पर प्रदर्शन में सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है।

प्रक्रियाओं में सुधार

सीआईआरपी ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहाँ कई घटकों की विशिष्ट भूमिकाएँ होती हैं। एए, आईपीज, लेनदार और लेनदार समिति (सीओसी), सीडी और उसके पूर्व प्रबंधन, समाधान आवेदकों (आरए), और आईपी द्वारा नियुक्त वृत्तियों को उनकी सहायता के लिए सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। यदि उनमें से कोई भी सहयोग नहीं करता है या सक्रिय असहयोग या दुर्भावनापूर्ण कार्यों का सहारा लेता है, तो प्रक्रिया समय पर समाप्त नहीं होगी और न ही इष्टतम परिणाम देगी। उदाहरण के लिए, यदि सफल आरए, एए द्वारा इसके अनुमोदन के बाद, समाधान योजना को लागू नहीं करता है, तो सीआईआरपी पूरी तरह से निरर्थक हो सकती है। मेरा मानना है कि यदि हितधारक अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाते हैं, जैसा कि संहिता में परिकल्पित है, तो परिणाम कहीं बेहतर होंगे। जैसा कि नीचे सुझाव दिया गया है, घटकों द्वारा थोड़ी अधिक देखभाल परिणामों में काफी सुधार कर सकती है।

(i). आईबीसी हितधारकों के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सही मामले में, सही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। उन्हें तनाव के शुरुआती दिनों में इसका उपयोग करना चाहिए, जब कंपनी का मूल्य लगभग बरकरार रहता है, और मूल्य में और गिरावट आने से पहले प्रक्रिया को जल्दी से बंद कर देना चाहिए, ताकि परिसमापन की संभावना को कम किया जा सके या यहां तक कि समाधान योजना में कटौती से बचा जा सके। तनावग्रस्त सीडी को तत्काल राहत की जरूरत है। यह जितना अधिक समय तक तनाव में रहता है, इसके मूल्य का नुकसान उतना ही अधिक होता है। सीआईआरपी शुरू करने या इसके प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी होने पर इसका मूल्य कम हो जाता है। यदि प्रक्रिया को समाप्त करने और एए के अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने में देरी होती है तो इसका मूल्य और कम हो जाता है। यदि एए में समाधान योजना के अनुमोदन में देरी होती है तो मूल्य और कम हो जाता है। समय बीतने के साथ, समाधान योजना द्वारा तनाव के समाधान की संभावना कम हो जाती है या समाधान योजना से बड़े हेयरकट हो जाते हैं। यदि प्रक्रिया में बहुत देर हो जाती है, जब व्यापार परिदृश्य बदल गया है, तो सफल आरए समाधान योजना के कार्यान्वयन को व्यवहार्य नहीं पाता है। यदि उसे अव्यवहार्य योजना को लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह पहली बार में समाधान योजना प्रस्तुत करने से परहेज करेगा। इससे आरए के अभाव में परिसमापन हो सकता है। हितधारक आईबीसी

का उपयोग करने से बच सकते हैं यदि उन्हें प्रक्रिया शुरू होने या समाप्त होने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़े। यदि सीआईआरपी की शुरुआत की जाती है और तेजी से निष्कर्ष निकाला जाता है, तो पूर्व वर्णित तीनों आलोचनाओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।

(ii). आईबीसी का लक्ष्य सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। यदि सीआईआरपी से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो परिसमापन या हेयरकट की संभावना कम हो जाती है। प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने और समाप्त करने के अलावा, कई अन्य उपाय मूल्य प्राप्ति को बढ़ा सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं : (क) आईबीसी समाधान योजना के माध्यम से मूल्य अधिकतमीकरण की परिकल्पना करता है। यह समाधान योजना को परिभाषित करता है जो जारी कंसर्न के रूप में सीडी के दिवाला का समाधान करता है। इसमें विलय, समामेलन या डीमर्जर के माध्यम से पुनर्गठन सहित समाधान योजना के माध्यम से समाधान की असीमित संभावनाओं की परिकल्पना की गई है। समाधान योजना प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, या उत्पाद पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों, व्यवसाय या उपकरणों का अधिग्रहण या निपटान संगठन, व्यवसाय मॉडल, स्वामित्व, या बैलेंस शीट का पुनर्गठन टर्न-अराउंड, बाय-आउट, अधिग्रहण या अधिग्रहण की रणनीति और इसी तरह से बदलाव ला सकती है। सीआईआरपी विनियमनों का विनियम 37 उपायों की उदाहरणात्मक सूची प्रदान करता है जो समाधान योजना प्रदान कर सकता है। सीओसी, जो समाधान योजनाओं के आमंत्रण के माध्यम से खेल के नियमों को निर्धारित करता है, को समाधान की कई संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मूल्य को बढ़ा सकते हैं; (ख) सीडी, आईपी और सीओसी की सभी सूचनाओं तक पहुंच है और इसलिए वे सीडी की क्षमता को जानते हैं। आईपी और सीओसी को सीडी के संभावित मूल्य की कल्पना करने और संभावित आरए के ध्यान में इस तरह के मूल्य को लाने की जरूरत है, जिस तरह से प्रवर्तक किसी कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में करते हैं। आईबीसी सीओसी को बाजार से सर्वश्रेष्ठ समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहले के तंत्र के विपरीत जो लेनदारों को केवल मौजूदा प्रवर्तकों के साथ समाधान पर बातचीत करने की अनुमति देता था। सीओसी को सीडी के अंतर्निहित मूल्य को नोटिस करने के लिए बाजार को प्रेरित करना चाहिए और कई प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं के साथ आना चाहिए; (ग) आईबीसी परिहार लेनदेन के माध्यम से मूल्य की पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करता है। यदि ऐसे लेन-देन पूर्ववत कर दिए जाते हैं और ह्रासित मूल्य को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, तो सीडी का मूल्य अधिक हो जाता है। आईपी को ऐसे लेनदेन की पहचान करने और पुनर्प्राप्ति के लिए एए पर आवेदन करने की आवश्यकता है, और एए को समाधान योजना पर विचार करने से पहले ऐसे आवेदनों का निपटान करने की आवश्यकता है। लेनदारों और पूर्व निदेशकों और सीडी के प्रवर्तकों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है; (घ) बाजार एक गैर-परिचालन व्यवसाय की तुलना में एक परिचालन व्यवसाय के लिए उच्च मूल्य प्रदान करता है। आईपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीडी पूरे सीआईआरपी में एक सतत चिंता का विषय बना रहे। इसके लिए पूर्ववर्ती प्रबंधन, लेनदारों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता है; और (ङ) सीआईआरपी खर्चों को न्यूनतम रखना महत्वपूर्ण है। आईपी और सीओसी दोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि बीमार सीडी परिहार्य खर्चों का बोझ नहीं है।

(iii). आईबीसी हितधारकों को व्यतिक्रम की दहलीज राशि की सीमा आते ही सीआईआरपी शुरू करने का अधिकार देता है ताकि तनाव को अनियंत्रित अनुपात में बढ़ने से रोका जा सके। व्यतिक्रम के शुरुआती दिनों में, उद्यम मूल्य आम तौर पर परिसमापन मूल्य से अधिक होता है और इसलिए हितधारकों को इसे समाप्त करने के बजाय फर्म के दिवाला को हल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीडी तनाव को नोटिस करने वाला पहला

व्यक्ति है। इसे तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि लेनदार सतर्क हैं, तो वे भी पहल कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं और यदि वे इसे सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं तो सीआईआरपी शुरू कर सकते हैं। कई उपाय सीआईआरपी के शीघ्र प्रारंभ की सुविधा प्रदान कर सकते हैं : (क) सीआईआरपी के प्रारंभ में सीडी द्वारा तुच्छ आधारों पर प्रतिरोध के कारण आम तौर पर देरी हो जाती है। इस तरह के प्रतिरोध को हतोत्साहित करना आवश्यक है। आईबीसी की धारा 66(2), दिवलाइट जोन के दौरान उत्पन्न होने वाले लेनदारों के नुकसान के लिए सीडी के निदेशकों को उत्तरदायी ठहराती है। गोधूलि क्षेत्र उस समय से शुरू होता है जब निदेशक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि जब तक कंपनी समाधान प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करती है, तब तक समाधान प्रक्रिया शुरू होने से बचने की कोई उचित संभावना नहीं है। इस अवधि के दौरान, निदेशक के पास देय कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए परिश्रम और वह इस तरह के नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यदि आईपी प्रत्येक सीआईआरपी के मामले में धारा 66(2) के अधीन आवेदन फाइल करता है और एए इसे तुरंत निपटा देता है, तो सीडी के प्रवेश का विरोध करने की संभावना नहीं है; (ख) अत्यधिक लीवरेज वाली कंपनियों के बोर्ड में आमतौर पर लेनदारों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए, अन्य हितधारकों की तुलना में लेनदारों को सीडी में तनाव का शुरुआती संकेत मिल सकता है। एफसी, विशेष रूप से बैंकों को ऐसे मामलों में प्रारंभिक चरण में सीआईआरपी शुरू करना चाहिए; (ग) यदि एए को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है तो प्रवेश की गति तेज हो सकती है। आईबीसी इस उद्देश्य के लिए आईयू की परिकल्पना करता है। एक सीमा से अधिक ऋण वाले लेनदारों और देनदारों के लिए वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करना और आईयू के साथ इसे प्रमाणित करना अनिवार्य हो सकता है। एक बार व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होने के बाद, प्रवेश स्वचालित होना चाहिए; और (घ) एए की पीठ क्षमता को अपने कार्यभार से मेल खाते हुए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोई भी आवेदन वैधानिक रूप से अनुमत 14 दिनों से अधिक के लिए लंबित न रहे। आईबीसी यह भी स्पष्ट कर सकता है कि एए को केवल सीडी द्वारा सीआईआरपी में आवेदन के प्रवेश के लिए दहलीज कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के बारे में संतुष्ट होने की जरूरत है, किसी और चीज की नहीं।

(iv). एफसी सीडी के भाग्य की कुंजी रखते हैं। वे सीडी के जीवन को बचा सकते हैं और अपने व्यावसायिक कौशल के आधार पर हेयरकट को कम कर सकते हैं। उन्हें सीडी के व्यवसाय और ऑपरेटिंग वातावरण को समझना चाहिए और शीघ्र उपाय करना चाहिए जैसे : (क) उन्हें किसी भी आसन्न तनाव को महसूस करना चाहिए और समय पर उचित उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। व्यवसाय के अपने मूल्यांकन के आधार पर, उन्हें शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि सीआईआरपी शुरू करना है या नहीं; (ख) सीओसी को बाजार में सीडी के मूल्य को नोटिस करने और कई प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं की पेशकश करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी; (ग) एए ने, कुछ मामलों में, सीओसी के आचरण को अस्वीकार्य पाया है। सीओसी को अपनी सौंपी गई भूमिका अत्यंत अनुशासन के साथ निभानी चाहिए। इसे आईपी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह तय करने के लिए उद्यम नहीं करना चाहिए कि लेनदार एफसी है या नहीं। यह उन चीजों को करने के लिए आईपी को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो अनुमेय नहीं हैं; और (घ) सीओसी का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो सक्षम हैं और एफसी से किसी आंतरिक अनुमोदन के लिए निर्णयों को स्थगित किए बिना मौके पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

(v) आईबीसी राज्य की न्यूनतम भूमिका के साथ बाजार प्रक्रिया प्रदान

करता है। सीआईआरपी के लिए प्रवेश आवेदनों, कई विविध आवेदनों के निपटान और समाधान योजनाओं के अनुमोदन के मामले में एए को त्वरित होना चाहिए। यदि बाजार सहभागियों द्वारा अपनी-अपनी भूमिका निभाने के बावजूद इन पहलुओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह आईबीसी में विफल हो जाएगा। एए की क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं : (क) कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों की सभी प्रकार की दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं से निपटने के लिए एक समर्पित, अनन्य एए हो सकता है; (ख) पीठ क्षमता/सदस्यों की संख्या आज की तुलना में कई गुना होनी चाहिए; (ग) पीठ में केवल एक सदस्य हो सकता है, यह देखते हुए कि कार्यवाही प्रतिकूल नहीं है; (घ) पीठ में करियर दिवाला सदस्य हो सकते हैं, जो करियर के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे; (ड.) स्थगन की संख्या को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसलिए एए के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए एक पार्टी के लिए उपलब्ध समय होना चाहिए; (च) एए केवल आवश्यक पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और मामूली विविध आवेदनों को दाखिल करने को हतोत्साहित कर सकता है। यह समाधान योजना को मंजूरी देते समय निर्णयों के विज्ञापनों पर गौर नहीं करेगा या सीआईआरपी में आवेदन स्वीकार करते समय व्यक्तिगत रूप से अलावा अन्य कारकों पर विचार नहीं करेगा। यह अदालतों के जाल से बच सकता है; और (छ) समर्थन प्रणाली को बढ़ाने की जरूरत है। पीठ के पास पर्याप्त विधिक और शोध समर्थन हो सकता है। मामलों के प्रबंधन और उनकी समय-सारणी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशासन सटीकता, पूर्णता और आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवेदनों / फाइलिंग की जांच कर सकता है, ताकि पीठ द्वारा निपटान तेज हो जाए। साथ ही, नई शुरुआत और स्वैच्छिक परिसमापन जैसी सरल प्रक्रियाएं, जिनमें कई विवाद नहीं होते हैं, को एए के बाहर प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। एए पर कार्य-भार कम करने के लिए समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह का उपयोग किया जा सकता है।

(vi). दिवाला प्रक्रिया की अखंडता के लिए आईपी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रतिष्ठा आज खतरे में है क्योंकि कुछ आईपी ने अपमानजनक/स्वच्छ रूप से अवैध कार्यों की अनुमति दी है या उनमें पक्षकार रहे हैं। आईपी को अपनी क्षमता और नैतिक मानकों को काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें सीआईआरपी के किसी पक्ष/हितधारक का पक्ष नहीं लेना चाहिए या किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और बिना किसी डर या पक्षपात के सेवाएं देनी चाहिए।

(vii). सीडी, एफसी और सीओसी और यहां तक कि आरए के प्रवर्तकों और निदेशकों की ओर से कदाचार के कई उदाहरण हैं। ऐसी स्थितियों में, आईबीबीआई जितना अधिक कर सकता है, वह उनके खिलाफ विशेष अदालत में शिकायत दर्ज करना है। आवश्यक साक्ष्य के अभाव में शिकायत सफल नहीं हो सकती है, जिसे आईबीबीआई उपयुक्त अधिकार क्षेत्र के अभाव में एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकता है। संहिता के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारक नियामक अनुशासन के अधीन हों। उन्हें आईबीबीआई के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है। एक समानांतर बिंदु को स्पष्ट कर सकता है। अपने शुरुआती दिनों में, सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने में बहुत प्रभावी नहीं माना जा रहा था। यह अनिवार्य रूप से इसलिए था क्योंकि प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह अपने प्रयासों को केवल लीड मैनेजर्स और मर्चेंट बैंकर्स पर निर्देशित कर रहा था, जो बिचौलियों और प्रॉस्पेक्टस के हस्ताक्षरकर्ता हैं, उन्हें कंपनियों की ओर से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। यहां तक कि इसे न्यायालयों में चुनौती दी जा रही थी, क्योंकि इसे सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जा रहा था। इस दुर्बलता को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संबोधित किया गया था, जिसने सेबी अधिनियम, 1992 में पूंजी जारी करने, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित

मामलों में सेबी के नियामक क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिए धारा 11क (जिसे 2002 में और सुदृढ़ किया गया) को शामिल किया।

(viii). संहिता का प्रमुख उद्देश्य संकटग्रस्त सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तत्व तुलना और सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए संपत्ति के मूल्य का पारदर्शी और विश्वसनीय निर्धारण है। मूल्यांकन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिसमें परिसमापन शामिल है, और उस विकल्प का चयन जो फर्म और परिणामस्वरूप हितधारकों के भाग्य का फ़ैसला करता है। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो व्यवहार्य फर्म का परिसमापन किया जा सकता है और गैर-लाभकारी फर्म का पुनर्वास किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हैं। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ढांचा तैयार किया गया था जो आईबीबीआई को मूल्यांकन व्यवसाय को तैयार करने में सक्षम बनाता है। व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, विशेषज्ञों की समिति ने मूल्यांकन व्यवसाय के विनियमन और विकास को चलाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है। इसके अलावा, एक अन्य समिति ने परिसंपत्ति वर्ग विशिष्ट मूल्यांकन मानकों की सिफारिश की है। मूल्यांकक अधिनियम के अधिनियमन और मूल्यांकन मानकों की अधिसूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ix) व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की दृष्टि से, देश तनाव के समाधान के लिए कई विकल्प प्रदान करने और मौजूदा विकल्पों को मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ समृद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समूह दिवाला और सीमा पार दिवाला के समाधान के लिए स्पष्ट उपबंध कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं को और भी महत्वपूर्ण बनाएंगे।

(x) भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली, ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था है। सभी महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सूचकांक और नवाचार के लिए सूचकांक में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार के सामने, यह स्वाभाविक है कि कुछ व्यवसायों को संकट का अनुभव होगा। अर्थव्यवस्था के आकार और इसकी विकास क्षमता को देखते हुए, संकटग्रस्त संपत्तियों का बाजार में निरंतर प्रवाह होगा। बाजार में पर्याप्त गहराई होनी चाहिए ताकि हर संकटग्रस्त संपत्ति के लिए कई समाधान योजनाएं हों। परिणामों की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करते हुए दुनिया भर के निवेशकों को बाजार में भाग लेने की अनुमति देने के संदर्भ में नियमों को संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार को बढ़ावा देना चाहिए। वे ऐसे मंचों को बढ़ावा दे सकते हैं जहां संकटग्रस्त परिसंपत्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए उपलब्ध हों।

(xi) यह देखते हुए कि भारत की दिवाला व्यवस्था अभी भी नवजात और अद्वितीय है, दिवाला के संबंध में डेटा सिस्टम अभी उभर रहे हैं। पूर्व-पश्च मूल्यांकन के लिए एक पूर्व-रणनीति होने का महत्व मूल्यांकन की डेटा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है और ऐसा करने से, आवश्यक जानकारी के शीघ्र संग्रह की अनुमति मिलती है। संहिता के अधीन उत्पन्न किए जा रहे डेटा का उपयोग करने और संहिता के मापन योग्य प्रभावों को समझने का समय आ गया है। संहिता के परिणामों की निगरानी और मापन के लिए संकेतकों का स्पष्ट रूप से परिभाषित ढांचा होना अनिवार्य है, जिन्हें उद्देश्यों/मानदंडों के खिलाफ नियमित आधार पर ट्रैक और रिपोर्ट किया जाता है। यह नीतियों पर सूचित सार्वजनिक बहस की सुविधा प्रदान करेगा और इस तरह अच्छी नीति प्रतिक्रिया के लिए विचारों की क्राउडसोर्सिंग में मदद करेगा। डेटा आधारित विश्लेषण न केवल नीति-निर्माता के टूलकिट को सुदृढ़ नीति निर्माण के लिए समृद्ध करेगा, जिसका संहिता के लाभार्थियों या हितधारकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रणालियों की निगरानी, या सामान्य

मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल के लिए भी उपयोगी होगा।

(xii) मैंने आईबीबीआई के लिए किसी सुधार का सुझाव नहीं दिया है। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आईबीबीआई को किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मेरे विचारों के पक्षपाती होने की संभावना है, इसलिए मैं पाठकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों पर छोड़ता हूँ कि वे आईबीबीआई के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दें। ऐसा करने में उनकी मदद करने के लिए, मैं आईबीबीआई के कुछ संरचनात्मक डिजाइन पहलुओं पर ध्यान दिलाता हूँ।

आईबीबीआई : अद्वितीय नियामक

आईबीबीआई नियामक दुनिया में हाल ही में जोड़ा गया है। हालाँकि, यह एक नया प्रयोग प्रतीत होता है, जिसका न तो भारतीय नियामक परिवेश में और न ही दिवाला क्षेत्र में कोई समानांतर है। मैं आईबीबीआई की भूमिका और इसके कामकाज के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं समझता हूँ, जो इसे एक विशिष्ट नियामक बनाते हैं।

भूमिका के पहलू

आईबीबीआई के पास संहिता के अधीन (क) दिवाला क्षेत्र में वृत्तिक और संबंधित संस्थान – आईपी, आईपीए, आईपीई और आईयू, और (ख) दिवाला प्रक्रिया – सीआईआरपी, प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान, कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, नई शुरुआत, दिवाला समाधान और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता पर नियामक निगरानी है।

एक में तीन नियामक : व्यवसाय का नियामक व्यवसाय को विकसित और विनियमित करता है। यह उन बाजारों को विनियमित नहीं करता है जहां ये व्यावसायिक सेवा करते हैं। न ही यह बाजार में/लेनदेन के लिए उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निर्दिष्ट करता है। बाजारों का नियामक, बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देता है। यह उन वृत्तियों को विकसित और विनियमित नहीं करता है, जो इन बाजारों में सेवाएं प्रदान करते हैं। उपयोगिताओं का नियामक प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को दूर करने और उपयोगिताओं के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए मानक निर्धारित करता है और टैरिफ तय करता है। आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय को विकसित और नियंत्रित करता है। यह बाजार में /लेनदेन के लिए आईपी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निर्दिष्ट करता है और उन बाजारों को भी नियंत्रित करता है जहां आईपी सेवा करते हैं। यह आईयू की सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है और प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने का प्रयास करता है। यह व्यवसाय के नियामक, बाजारों के नियामक और उपयोगिताओं के नियामक के कर्तव्यों को संमिश्रित करता है, हालांकि इसकी भूमिका इनमें से किसी से भी बहुत अलग है।

प्राधिकार का दायरा : सेबी के पास प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए वैधानिक उद्देश्य हैं। इसे अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय करने का अधिकार है। इसे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका अधिकार क्षेत्र प्रतिभूति बाजारों में सभी प्रतिभागियों तक फैला हुआ है, जिसमें प्रतिभूतियों के जारीकर्ता और उनकी प्रतिभूतियों के व्यापार के संबंध में शामिल हैं। दूसरी ओर, आईबीबीआई के विशिष्ट वैधानिक कार्य हैं, जो सरकार के सामान्य निर्देश के अधीन हैं। इसे संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका अधिकार क्षेत्र सेवाप्रदाताओं (आईपी, आईपीए, और आईयू) पर लागू है, न कि बाजार सहभागियों (देनदार और लेनदार, प्रवर्तक, सीओसी और आरए) पर। बाजार नियामक की तुलना में आईबीबीआई के प्राधिकार का दायरा अलग है।

नियामक बनाम अधिकरण : नियामक प्रवर्तन और न्यायिक कार्यों के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए विनियमों को लागू करता है और उनकी व्याख्या करता है। इस तरह के कार्यों और व्याख्याओं को अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जाती है। हालांकि, नियामक के अर्ध-विधायी या कार्यकारी कार्यों के संबंध में अधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। इसके विपरीत, आईबीबीआई को सेवा प्रदाताओं के संबंध में छोड़कर, अपने द्वारा बनाए गए विनियमों को लागू करने और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हितधारक और आईपी विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं और अनुमोदन के लिए एए को प्रस्तुत करते हैं। एए अपने निर्णयों के माध्यम से विनियमों सहित कानून को लागू करता है और व्याख्या करता है। हालांकि, यह आईबीबीआई के कार्यों के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। चूंकि भारत में या कहीं ओर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आईबीबीआई और एए जैसे दो समानांतर संस्थान नहीं हैं, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में एक-दूसरे की भूमिका की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है।

दिवाला क्षेत्र में द्वितीय : अधिकांश दिवाला न्यायाधिकारों में विनियमन के पदानुक्रम में दो लेयर होती हैं, अर्थात्, दिवाला से निपटने वाला सरकारी विभाग और दिवाला व्यवसायियों को विनियमित करने वाले सदस्यता संगठन। जहां कहीं बीच में कोई अन्य एजेंसी है, ऐसी एजेंसी दिवाला के लिए समर्पित नहीं है। इसके विपरीत, भारतीय क्षेत्राधिकार में पदानुक्रम में तीन लेयर होती हैं जिसमें आईबीबीआई सरकार और आईपीए के बीच अंतरित होता है। आईबीबीआई को कार्य सौंपे जाते हैं, जिनमें से कुछ या तो सरकार के दायरे में होते हैं या अन्य अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक निकाय होते हैं। चूंकि भारत में या कहीं ओर से सीखने के लिए कोई तुलनीय नियामक नहीं है, आईबीबीआई अपनी भूमिका के संदर्भ में एक विकसित प्रयोग है।

कामकाज के पहलू

अपने वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करते हुए, आईबीबीआई ने अधिकांश अन्य नियामकों की तुलना में थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है, यद्यपि यह कानून की अनुमेय सीमाओं के भीतर है।

जवाबदेही : गति संहिता का सार है। संहिता का निर्माण होने के कारण आईबीबीआई ने पहले दिन से ही गति को आत्मसात कर लिया। इसे 01 अक्टूबर 2016 को स्थापित किया गया था। इसे 01 दिसंबर 2016 तक कारपोरेट दिवाला शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए किसी चमत्कार से कम की आवश्यकता नहीं थी। इसके तत्काल कार्यों में निम्नांकित शामिल थे: आईपीए स्थापित करने के लिए बाजार को स्वैच्छिक सेवाएं देना; आईपीए के साथ पंजीकरण और आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले, सही क्षमता वाले व्यक्तियों का पता लगाना; आईपी, आईपीए, सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित विनियम लागू करना संहिता के संदेश को फ़ैलाने में सहयोग करना और हितधारकों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना और आईबीबीआई को इन पर काम करने की क्षमता पैदा करना। सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ, आईबीबीआई ने इन सभी को निष्पादित किया, जिससे 01 दिसंबर 2016 को सीआईआरपी का कार्यकरण संभव हो गया। तब से तत्परता इसकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रही है।

नियामकों को, चिंताओं को सक्रिय रूप से या चिंता के सामने आने के तुरंत बाद कम से कम इसे संबोधित करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय कार्यवाहियों के दो उदाहरण हैं : (क) जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के सीआईआरपी में, 24 अगस्त, 2017 तक दावों की मांग करते हुए 10 अगस्त, 2017 को सार्वजनिक घोषणा की गई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या एफसी और परिचालन लेनदार (ओसी) के रूप में भू-संपदा परियोजना का

आवंटी दावा प्रस्तुत करेगा या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 24 अगस्त, 2017 तक दावे प्रस्तुत किए गए हैं, आईबीबीआई ने 16 अगस्त, 2017 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया ताकि आवंटियों द्वारा दावों को प्रस्तुत किया जा सके। समय के साथ, ऐसे आवंटियों को वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पष्ट रूप से विचार करने के लिए 06 जून, 2018 को संहिता में संशोधन किया गया था। (ख) संहिता के अधीन पहली समाधान योजना 02 अगस्त, 2017 को अनुमोदित की गई, जिसके अधीन सिनर्जीज डोरे ऑटोमोटिव लिमिटेड को एक समूह की कंपनी के साथ मिला दिया गया, जबकि लेनदारों ने 94% की कटौती की थी। यह उन प्रवर्तकों को पुरस्कृत करने जैसा प्रतीत होता है, जिन्होंने लेनदारों की कीमत पर कंपनी को जमीन पर चला दिया था। सीआईआरपी की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए, आईबीबीआई ने 07 नवंबर, 2017 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया, जिसमें आरए और उससे जुड़े व्यक्तियों के पूर्ववृत्त – दोशसिद्धि, आपराधिक कार्यवाही, जानबूझकर व्यतिक्रम, निष्कासन – के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है ताकि इस तरह के आवेदकों की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके। इसके बाद, 23 नवंबर, 2017 को संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें ऐसे पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

एए एक प्रक्रिया का संचालन करने के लिए आईपी नियुक्त करता है। जब हितधारकों ने आईपी की पहचान की है, तो एए को उसे नियुक्त करने से पहले आईबीबीआई से आईपी की साख को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आईबीबीआई एए के पास सभी योग्य आईपी का डेटाबेस पहले से उपलब्ध कराती है ताकि वह आईपी को तुरंत नियुक्त कर सके। इसी तरह, जहां हितधारकों ने आईपी का प्रस्ताव नहीं दिया है, एए को सिफारिश के लिए आईबीबीआई को संदर्भ बनाने की जरूरत है। आईबीबीआई अग्रिम रूप से एए के साथ अनुशंसित आईपी का पैनल उपलब्ध कराता है, जो नियुक्तियों के लिए तत्काल समाधान के रूप में कार्य करता है। संहिता ने शुरू में आईआरपी की नियुक्ति के लिए 14 दिनों की परिकल्पना की थी। हालाँकि, इस अभिनव समाधान ने नियुक्तियों को तात्कालिक बना दिया है। इसे मान्यता देते हुए, दिवाला विधि समिति (आईएलसी) ने आईआरपी की नियुक्ति के लिए 14 दिनों की अवधि को समाप्त करने की सिफारिश की और धारा 16(1) को तदनुसार दिसंबर, 2019 में संशोधित किया गया।

शासन : एक नियामक में शक्तियों के एकीकरण से उत्पन्न होने संबंधी चिंताएं हैं। इसे संबोधित करने के लिए, आईबीबीआई ने खुद को तीन अलग-अलग विंग में संरचित किया है, अर्थात्, अनुसंधान और विनियमन विंग, रजिस्ट्रीकरण और अनुश्रवण विंग, और प्रशासनिक विधि विंग और इनमें से प्रत्येक विंग का नेतृत्व, पृथक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाता है, ताकि अंतर-संस्थागत और सार्वजनिक विधिक चिंता से बचा जा सके।

संहिता स्पष्ट रूप से आईबीबीआई और उसके गवर्निंग बोर्ड (जीबी) के बीच अंतर नहीं करती है। हालांकि, 7 अक्टूबर 2016 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, जीबी ने उन व्यवसायों की पहचान की, जिन्हें अकेले ही औपचारिक विनियमों को लंबित करते हुए लेनदेन करना चाहिए। औपचारिक विनियमों को 31 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें जीबी द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को निर्धारित किया गया था। यह विनियम जीबी के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीबी इस तरह से आचरण करता है जो अपने जनादेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता है या सदस्यों की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता में जनता के विश्वास को कम करता है। जीबी के गैर-कार्यकारी सदस्य दिवाला शासन के कामकाज पर प्रत्यक्ष और स्वतंत्र प्रतिक्रिया के लिए वर्ष में एक बार आईबीबीआई और अन्य हितधारकों के अधिकारियों से मिलते रहे हैं।

जीबी शुरु से ही अपने प्रदर्शन के प्रति सचेत रहा है। यह मूल्यांकन करने के लिए 2018-19 से स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या यह बाहरी जांच की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और संगठनात्मक और बोर्ड के प्रदर्शन दोनों में सुधार कर रहा है और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ताकत, कमजोरियों और अवसरों की पहचान कर रहा है। आईबीबीआई जीबी के मूल्यांकन से स्वतंत्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। स्व-मूल्यांकन की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, जीबी ने एक बाहरी एजेंसी द्वारा आईबीबीआई के प्रदर्शन के मूल्यांकन का निर्देश दिया, जो संहिता से अलग है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को मूल्यांकन करने के लिए कमीशन किया गया है। जीबी अब बदलते समय और आने वाली चुनौतियों के साथ आईबीबीआई की फिर से कल्पना करने की इच्छा के साथ जब्त कर लिया गया है। यह आईबीबीआई के अधिकार की नए सिरे से जांच कर रहा है कि क्या आईबीबीआई द्वारा निगरानी की जा रही प्रक्रियाओं के परिणामों के आलोक में इसके निरंतर अस्तित्व की प्रत्याभूति है और क्या ये अंततः उन्नत आर्थिक प्रदर्शन की ओर ले जा रहे हैं।

आईबीबीआई ने हमेशा हर संभव प्रारूप में हितधारकों के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। यह उनके साथ व्यापक परामर्श के बाद, गोलमेज में, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और कार्य समूहों और सलाहकार समितियों की सलाह के बाद विनियम बनाता है। किसी भी हितधारक को पूरे वर्ष के दौरान किसी भी नए विनियमन की तलाश करने या मौजूदा नियमों में किसी भी बदलाव का सुझाव देने में सक्षम बनाने के लिए इसकी स्थायी व्यवस्था है। यह प्रत्येक हितधारक को नियामक के स्थान पर रखता है और विचारों और दृष्टिकोणों को क्राउडसोर्स करता है। नतीजतन, नियामक के पास उपलब्ध विचारों का दायरा बहुत बड़ा है और अधिक अनुकूल नियामक ढांचे की संभावना बहुत अधिक है।

निर्माण व्यवसाय : आईबीबीआई दो उभरते हुए व्यवसायों, नामतः दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय का पालन-पोषण कर रहा है। व्यवसायों के निर्माण के लिए मानक टूलबॉक्स का उपयोग करते हुए, आईबीबीआई ने कुछ नवाचार किए हैं।

आईबीबीआई ने दिवाला व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए स्नातक दिवाला कार्यक्रम (जीआईपी) की अवधारणा के लिए उद्योग पहल का नेतृत्व किया। यह दुनिया में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है जो उच्च गुणवत्ता वाले आईपी का उत्पादन करता है जो विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह युवा व्यावसायिकों, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन अनुभव की कमी है, को दिवाला व्यवसाय अपनाने का अवसर प्रदान करता है। यह 24 महीने का कार्यक्रम है जिसमें 12 महीने के गहन आवासीय कक्षा घटक और 12 महीने के प्रेक्टिस का व्यावहारिक इंटरनशिप घटक शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में जीआईपी शुरु किया। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एनएलआईयू, भोपाल) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से जीआईपी शुरु करने वाला है।

किसी व्यवसाय की विश्वसनीयता उसके सदस्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अधिकांश अन्य व्यवसायों की तुलना में दिवाला व्यवसाय (मूल्यांकन व्यवसाय) की एक विशिष्ट आवश्यकता यह है कि यह केवल उन व्यक्तियों को अनुमति देता है, जिनको इस व्यवसाय पर गर्व होगा, और उन व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है, जिनके पूर्ववृत्त संदिग्ध या उन पर प्रश्नचिह्न हैं। यह केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देता है जो 'फिट और उचित' हैं और उन्हें निरंतर रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में 'फिट और उचित' रहने की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति 'फिट और उचित' है या नहीं, आईबीबीआई विभिन्न पहलुओं पर

विचार करता है, जिसमें (क) अखंडता, प्रतिष्ठा और चरित्र, (ख) दोषसिद्धि और संयम आदेशों की अनुपस्थिति, और (ग) क्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

आईबीबीआई दो नए व्यवसायों के संबंध में अपनी भूमिका को देखते हुए ज्ञान संगठन बनने का प्रयास करता है। आईपीए के सहयोग से, यह उभरते हुए ज्ञान का उत्पादन और कब्जा करने और प्रवेश के समय और निरंतर आधार पर व्यावसायिकों की क्षमता बनाने के लिए शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के साथ जुड़ रहा है। यह तीन परिसंपत्ति वर्गों, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी और प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों और व्यवसायों में प्रवेश के लिए दिवाला परीक्षा के लिए मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसने इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। इनमें से, मूल्यांकन अध्ययन केंद्र, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित संयंत्र और मशीनरी, और भूमि और भवन के लिए अध्ययन सामग्री, दुनिया भर में कई मूल्य निर्धारण संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है। आईबीबीआई और आईपीए कई प्रकाशन और शोध अध्ययन लाते हैं और ऐसा करने के लिए अकादमिक जगत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

संस्थागत वैधता : जो चीज किसी संगठन को संस्था से अलग करती है, वह है इसकी वैधता। एक संगठन को केवल अपने वैधानिक अधिदेश के लिए नहीं बल्कि हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह क्या करता है और कैसे करता है। इसके लिए संगठन को वर्षों या दशकों तक लगातार आचरण और प्रदर्शन द्वारा सामाजिक पूंजी का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। मेरी समझ से आईबीबीआई ने वैधता की यात्रा शुरु कर दी है।

शायद अपनी भूमिका और प्रदर्शन की मान्यता में, आईबीबीआई को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय नियामक मंच, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, आईएलसी और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर्स जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर जगह मिलती है। इसने दिवाला क्षेत्र में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान पर आईएलसी की उप-समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों जैसे मूल्यांकन व्यावसायिकों के विनियमन और विकास के लिए संस्थागत ढांचे पर विशेषज्ञों की समितियों और प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया पर आईएलसी की उप-समिति को नेतृत्व प्रदान किया।

आईबीबीआई के एक विशिष्ट आगंतुक ने एक बार इसे 'स्टार्ट-अप' के रूप में वर्णित किया था। मैं काफी हद तक सहमत हूँ और चाहता हूँ कि या ऐसा ही बना रहे। आईबीबीआई में एक स्टार्ट-अप की सभी विशेषताएं हैं, अर्थात् यह युवा है, नवाचार कर रहा है, लचीला है, चुस्त है, और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। टीम आईबीबीआई, अपने जीबी के नेतृत्व में, स्थापित विधिक ढांचे की चार दीवारी के भीतर किसी भी हितधारक की वैध चिंता को संबोधित करने में मदद करने के लिए हमेशा सतर्क और उपलब्ध रहती है।

निष्कर्ष

अपने पांचवें वर्ष में, देश में दिवाला सुधारों ने मील के कई महत्वपूर्ण पथर पार कर लिए हैं और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिणाम भी दिए हैं। मैं कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस सुधार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने हेतु धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं आईबीबीआई के जीबी के सभी सदस्यों का ऋणी हूँ जिन्होंने कम समय में देश में एक कुशल और प्रभावी दिवाला व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए आईबीसी और आईबीबीआई को अपना अथक समर्थन प्रदान किया।

(डॉ. एम. एस. साहू)



समीक्षाधीन वर्ष

वृहत् आर्थिक संदर्भ

जैसे-जैसे वर्ष 2019-20 समाप्त हो रहा था, कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत कर दीं। इसका सभी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आर्थिक रुझानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हो गए, अनेक नौकरियां समाप्त हो गईं और कारपोरेट सॉल्वेंसी चुनौतियां पेश आईं। सरकारों और नीति निर्माताओं ने लगभग 10 ट्रिलियन अमरीकी डालर के राजकोषीय और मौद्रिक पैकेजों के साथ स्वास्थ्य संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए तेजी से कार्य किया, जो कि 2008-09 के वित्तीय संकट¹ की प्रतिक्रिया से किए गए कार्य से तीन गुना अधिक है। आईएमएफ ने 2020² में वैश्विक आर्थिक विकास में -3.1 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया, इस प्रकार यह दर्शाता है कि वर्तमान स्वास्थ्य संकट महामंदी के बाद से सबसे खराब मंदी है, और वैश्विक वित्तीय संकट से भी बदतर है।

हालांकि, कई अर्थव्यवस्थाओं में वैक्सीन की मंजूरी और प्रशासन के साथ-साथ सरकारों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता ने 2021 में आर्थिक सुधार की उम्मीद जगाई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब 2021 में 5.9 प्रतिशत और 2022³ में 4.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, देश और क्षेत्र अलग-अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं। समय बीतने के साथ, जैसा कि कुछ क्षेत्र कम संपर्क-गहन गतिविधियों के 'नए सामान्य' के अनुकूल होंगे और आईएमएफ के अनुसार, टीकों के रोल से संपर्क-गहन गतिविधियों को फिर से मजबूत करने का रास्ता अपनाएं, 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक सुधार को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अर्थव्यवस्थाओं को अभी भी संक्रमण (वायरस के नए रूपों सहित), लॉकडाउन, वैक्सीन वितरण में देरी, और कारपोरेट और देशीय दिवाला⁴ में संभावित उछाल के कारण रोजगार और आय के खतरे से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि निरंतर वसूली सुनिश्चित की जा सके। और 2020 में तीव्र संकुचन से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाएं। दिवाला अधिस्थगन जैसे नीतिगत उपायों की समय-सीमा समाप्त होने के साथ, दिवाला होने और ऋण व्यतिक्रम की लहर शुरू हो सकती है, जिससे ऋण पुनर्गठन⁵ के लिए फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ दिवाला व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

वित्त वर्ष 21 भारत के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हुआ और साथ ही वर्ष के अंत में धीमी गति से बहाली देखी गई। मार्च, 2020 के अंत तक

लॉकडाउन की शुरुआत और महामारी से पैदा हुई अनिश्चितताओं ने सभी आर्थिक गतिविधियों को अचानक रोक दिया। घटती आय और खपत ने चल रहे संकुचन में वृद्धि की। वर्ष के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक चरांकों पर करीब से नजर डालने से विकास में गिरावट के अंतर्निहित कारणों का पता चलता है।

वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में सकल देशीय उत्पाद (जीडीपी) 24 प्रतिशत⁶ गिर गया। इसी तिमाही में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) भी 22 फीसदी गिर गया। गंभीर संकुचन का अनुभव करने वाले क्षेत्र विनिर्माण, निर्माणकार्य और विद्युत् थे। महामारी का कृषि और वानिकी पर नगण्य प्रभाव पड़ा, वास्तव में, यह वह क्षेत्र है जिसने सकारात्मक विकास दर सूचित की। लॉकडाउन के कारण कृषि गतिविधियों में व्यवधान न होना सकारात्मक दरों की व्याख्या करता है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र होटल, परिवहन और संचार था जो पिछले वित्त वर्ष⁷ की तुलना में 47 प्रतिशत तक कम हो गया। नकारात्मक निवेश भावनाओं और खपत व्यय में गिरावट ने मंदी को बढ़ा दिया और दूसरी तिमाही में बहुत कम या कोई सुधार नहीं होने की गुंजाइश बची। हालांकि गिरावट का मार्जिन कम हुआ, लेकिन क्षेत्रीय विकास काफी हद तक नकारात्मक था।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा परिलक्षित निवेश, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में सकल देशीय उत्पाद का 24.4 प्रतिशत था, जबकि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में सकल देशीय उत्पाद का 31.6 प्रतिशत था। निवेश में सालाना 12 फीसदी की कमी ने सुस्त रिकवरी को और बढ़ा दिया। वित्त वर्ष जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ वित्त वर्ष 2020 में 32.5 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 30.9 प्रतिशत रह गया। कम निवेश के अलावा, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीडी) द्वारा कब्जा की गई खपत की मांग भी वित्त वर्ष 2021 में 09 प्रतिशत कम हो गई। नौकरी छूटने और वेतन कटौती ने गिरती घरेलू मांग को प्रभावित किया। वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण क्षेत्र ने 40.1 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। वित्त वर्ष 2021 में यह घटकर 27.4 मिलियन रह गया। भू-संपदा और निर्माण क्षेत्रों ने सूट का पालन किया। इसने वित्त वर्ष 2020⁸ में 60.9 मिलियन लोगों की तुलना में 53.7 मिलियन लोगों को रोजगार दिया।

सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से जूझने के बाद, वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में सुधार के संकेत मिले। प्रतिबंधों में ढील और उद्योगों को आधी क्षमता पर भी परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति ने भारत को अपने विकास पथ पर वापस ला दिया। टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी आर्थिक स्वास्थ्य के तेजी से पुनरुद्धार के लिए एक उज्ज्वल चित्र चित्रित

¹ "द +10 ट्रिलियन रेस्क्यू: सरकार प्रभाव कैसे पैदा कर सकती है", मक्कीनसे एंड कंपनी रिपोर्ट, जून 2020, https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Public/percent20Sector/Our_percent20Insights/The_percent2010_percent20trillion_percent20dollar_percent20rescue_percent20How_percent20governments_percent20can_percent20deliver_percent20impact/The-10-trillion-dollar-rescue-How-governments-can-deliver-impact-vf.pdf

² विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर 2021, आईएमएफ।

³ विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर 2021, आईएमएफ।

⁴ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अपडेट, जनवरी 2021, आईएमएफ।

⁵ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अपडेट, अप्रैल 2021, आईएमएफ।

⁶ आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

⁷ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस नोट, 2020-2021

⁸ भारद्वाज, ए. (2021)। विनिर्माण रोजगार 5 साल में आधा। सीडीडी-सीएमआई बुलेटिन।

किया। प्रोत्साहन पैकेज के रूप में बड़े समर्थन ने बाजारों में खोए हुए विश्वास को बहाल कर दिया। सकल देशीय उत्पाद में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीडी) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 में 10.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 11.8 प्रतिशत हो गई। इन निवेशों और सरकारी व्यय में वृद्धि के गुणक प्रभाव हैं और चौथी तिमाही में प्रदर्शित धीमी लेकिन सकारात्मक विकास दर में देखा गया था। तीसरी में 2.8 प्रतिशत के संकुचन के बाद पीएफसीडी चौथी में 2.7 प्रतिशत बढ़ा। तीसरी और चौथी में जीवीए क्रमशः 01 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत रहा। नकारात्मक विकास दर के कई मुकाबलों के बाद, जीडीपी चौथी तिमाही⁹ में 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

जैसा कि किसी भी मंदी के दौर में होता है, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति की पूरक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2020 में रेपो दर में 05 प्रतिशत से अधिक की कटौती के साथ मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखा है। विस्तारक उपायों के आलोक में, अर्थव्यवस्था का राजकोषीय स्वास्थ्य दबाव में रहा है। भले ही राजकोषीय घाटा 9.3 प्रतिशत पर बंद हुआ, वित्त वर्ष 2021¹⁰ के संशोधित अनुमान 9.5 प्रतिशत से कम, दूसरी लहर की छाया बनी रहने और अनुमानों पर ऊपर की ओर दबाव डालने के लिए बाध्य है।

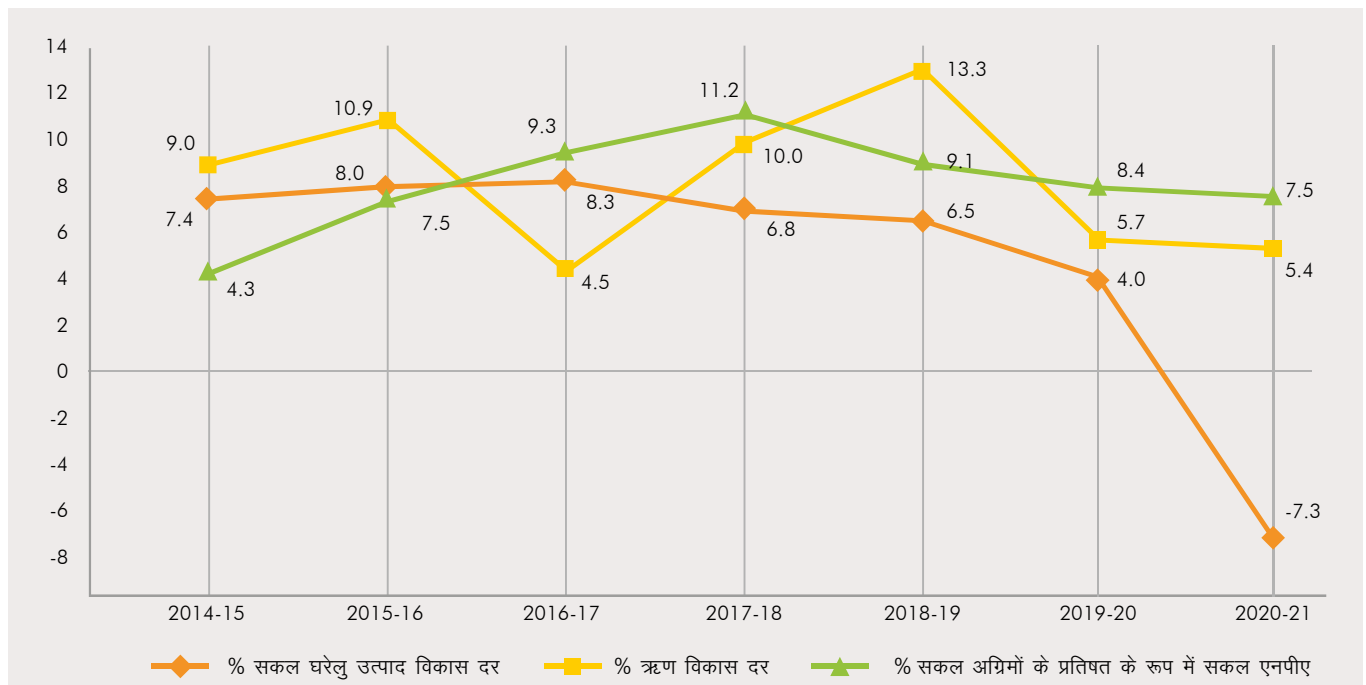
जबकि देशीय मांग कम रही, वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत के बाहरी क्षेत्र को लाभ हुआ। महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने आयात की समग्र मांग को कम कर दिया। हालांकि, रुकी हुई मांग और संभवतः बचत ने वित्त वर्ष 2021 की अंतिम दो तिमाहियों में इस प्रवृत्ति को उलट दिया। जीडीपी के हिस्से के रूप में निर्यात वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में 19.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा। सकल देशीय उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं की हिस्सेदारी के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 20.4 प्रतिशत पर रहा, जिससे भारत शुद्ध आयातक बन गया। हालांकि, मार्च-अप्रैल 2021 के महीने में भारत के निर्यात में वृद्धि

हुई है, जो वैश्विक मांग में उछाल के कारण है। निर्यात में यह उछाल बेरोजगारी और कम आय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अति आवश्यक तंत्र प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार, कुल मिलाकर, भारत का वास्तविक सकल देशीय उत्पाद वित्त वर्ष 2020 में 4.0 प्रतिशत (एक साल पहले 6.1 प्रतिशत) तक गिर गया, और वित्त वर्ष 2021 में 7.3 प्रतिशत कम हो गया। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय को छोड़कर, देशीय मांग के सभी घटकों को कम कर दिया गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में सकल देशीय उत्पाद का 11.7 प्रतिशत था, जिसने कुल मांग को निरंतर समर्थन प्रदान किया। आपूर्ति पक्ष पर, क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं के कारण विनिर्माण, निर्माण और परिवहन में गतिविधि में गिरावट देखी गई। घटते आत्मविश्वास और लॉकडाउन लागू होने से गैर-जरूरी वस्तुओं की मांग घट गई। वित्त वर्ष 2020 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 0.8 प्रतिशत सिकुड़ गया, जो वित्त वर्ष 2019 में 3.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021 में 8.6 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र में, जो उद्योग के तीन-चौथाई हिस्से का गठन करता है, 23 उद्योग समूहों में से 22 (फार्मेस्यूटिकल, औद्योगिक, और वनस्पति उत्पाद अपवाद हैं) ने संकुचन दर्ज किया। 2019-20 में ऋण वृद्धि घटकर 5.7 प्रतिशत और 2020-21 में 5.4 प्रतिशत रह गई। 2020-21 में जीएनपीए अनुपात 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया।

जैसा कि भारत मार्च, 2021 से दूसरी लहर से जूझ रहा है, वसूली की चुनौती जारी है। जबकि पहली दो तिमाहियों ने अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दी, तीसरी और चौथी तिमाही में प्रदर्शित विकास क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी लहर ने निश्चित रूप से विकास योजनाओं में देरी की है, आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी विकास अनुमानों को अनुमानित 12 प्रतिशत से संशोधित कर 9.5 प्रतिशत

चित्र 1: जीडीपी, क्रेडिट और जीएनपीए की वृद्धि



स्रोत : एनएसओ और आरबीआई डेटाबेस

⁹ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटाबेस

¹⁰ सीजीए वित्तीय रिपोर्ट, 2020-21

कर दिया गया है। वैश्विक उत्पादन वसूली के अनुरूप, आईएमएफ ने 2021 में भारत की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो देशव्यापी लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद 2020 में उम्मीद से अधिक मजबूत सुधार और 2022¹¹ में 8.5 प्रतिशत होने का संकेत है।

व्यवसायों पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने दुनिया को चौंका दिया। लोग आसानी से शिकार हो गए और दुनिया भर में सरकारी प्रतिष्ठान चौकन्ना हो रहे गए। दुनिया भर में सरकारों की पहली प्रतिक्रिया जान बचाने की थी। इसके बाद पूरे देश में अभूतपूर्व "लॉकडाउन" हुए जब लोगों की जान बचाई जा रही थी, आजीविका गायब हो रही थी, जिससे वायरस के अलावा अन्य कारणों से जान गंवाने का डर और बढ़ गया। व्यवसाय, जो किसी भी आर्थिक प्रणाली की जीवन रेखा हैं, को इन व्यवसायों पर निर्भर जीवन को बचाने के लिए असाधारण मौतों से बचाने की आवश्यकता है। दुनिया भर के देशों ने व्यवसायों को बचाने के लिए उनके लिए उपलब्ध सभी नीतिगत हथियारों—वित्तीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण का सहारा लिया। जापान में सकल देशीय उत्पाद के 21 प्रतिशत से लेकर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज; कनाडा में 16 फीसदी और ऑस्ट्रेलिया में 14 फीसदी से लेकर कई देशों में 5-6 फीसदी की घोषणा करके कार्यान्वित किया जा चुका है।

जैसे ही वित्त वर्ष 2021 शुरू हुआ, दुनिया भर के कई देशों में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए तालाबंदी की गई। कई आर्थिक गतिविधियों के लगभग पूरी तरह से बंद होने, कारोबार बंद होने, आपूर्ति श्रृंखला टूटने, गैर-जरूरी चीजों की मांग घटने और कार्यशील पूंजी के सूखने के साथ, कई व्यवसाय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यह देखते हुए कि कई देश यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं और कुछ वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, रेस्तरां, खुदरा व्यवसाय और आतिथ्य उद्योग जैसे उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दिवाला के लिए आवेदन करने वाली बड़ी कंपनियों के कुछ उदाहरण दुनिया भर में देखे गए।

भारत में कोविड-19 के प्रसार में तुलनात्मक रूप से देरी हुई और लॉकडाउन को जल्दी लागू करने के कारण तुलनात्मक रूप से नियंत्रित किया गया। महामारी की पहली लहर सितंबर, 2020 में अपने चरम पर पहुँच गई। हालांकि, देश में व्यवसायों पर इसका प्रभाव गंभीर था। एयरलाइंस से लेकर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग फर्मों तक, सभी क्षेत्रों पर लॉकडाउन का विपरीत प्रभाव पड़ा, मांग घट गई और आपूर्ति की श्रृंखला टूट गई। कई कंपनियों, उनमें से कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की शीर्ष पंक्ति में कमी आ गई। वर्ष के दौरान कोविड-19 स्वास्थ्य आपातकाल के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से उद्योग पर उत्पन्न आर्थिक तनाव वायरस के प्रसार और सरकार द्वारा किए गए संबंधित रोकथाम उपायों के साथ-साथ बढ़ता चला गया।

जनवरी, 2021 की आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) बताती है कि निजी कारपोरेट व्यवसाय क्षेत्र महामारी से पहले भी प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव कर रहा था। यह कोविड-19 के प्रकोप के साथ और तेज हो गया। हालांकि, महामारी के प्रभाव का खामियाजा मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में केंद्रित था। वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में रिकवरी के संकेत दिखाई देने लगे। सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों के लिए बिक्री में (-) 4.3 प्रतिशत का संकुचन पिछली तिमाही में 41.1 प्रतिशत की भारी गिरावट के बावजूद महत्वपूर्ण सुधार था। जैसा कि बिक्री के सापेक्ष खर्चों में बड़ी कमी से परिलक्षित होता है, लागत में कटौती करने से, विनिर्माण क्षेत्र में परिचालन लाभ और ऋण सेवा में सुधार देखा गया,

बाद वाला उनके ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) में सुधार से परिलक्षित हुआ। दूसरी ओर, पहली छ:माही: वित्त वर्ष 2021 के दौरान आईटी क्षेत्र में बिक्री वृद्धि लचीली बनी रही। हालांकि सभी क्षेत्रों में लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, विनिर्माण कंपनियों ने पिछली छ:माही और बिल्ट-अप एहतिताती नकदी की स्थिति के मुकाबले पहली छ:माही : वित्त वर्ष 21 के दौरान लीवरेज को कम कर दिया, जैसा कि 1249 सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों की अलेखापरीक्षित तुलन पत्र से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, अचल परिसंपत्तियों में उनका निवेश कम रहा।

व्यवसायों पर महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिवाला विधि में बदलाव के संदर्भ में दुनिया भर में सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित और लगभग समान तर्ज पर थी। **बॉक्स 1** में विवरण दर्शाया गया है।

दुनिया भर की सरकारों द्वारा घोषित व्यवसायों और व्यक्तियों के दर्द को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का प्रभाव अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वह यह है कि कुछ व्यवसायों को अस्थायी रूप से फांसी का सामना करने से बचा लिया गया है। कॉरपोरेट्स को बचाने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में किस तरह के नीतिगत हस्तक्षेपों से मदद मिलेगी आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है। जी 30, 15 दिसंबर, 2020 को जारी अपनी रिपोर्ट 'कारपोरेट सेक्टर पोस्ट-कोविड: डिजाइनिंग पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन'¹² में, नीति निर्माताओं द्वारा किए जा सकने वाले हस्तक्षेपों का क्या, कब और कैसे एक खाका प्रदान करता है (**बॉक्स 2**)।

प्रमुख नीतिगत घटनाएँ

समीक्षाधीन वर्ष में वैश्विक महामारी की घटना सहित विभिन्न नवीन विकास देखे गए, जो दुर्लभ स्वान घटना है। समय सामान्य नहीं है। पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में है, जिसका कोई त्वरित समाधान नजर नहीं आ रहा है। फिर भी संकट में पड़ी सीडी को बचाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन उभरते हुए मुद्दों के जवाब में, वर्ष के दौरान अपनी यात्रा में विभिन्न विकासों को शामिल करते हुए संहिता को तदनुसार विकसित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की रूपरेखा यहां दी गई है।

सरकार द्वारा सुविधाएँ

आत्मनिर्भर भारत अभियान

केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री ने 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत, भाग V : सरकारी सुधार और समर्थक' का बयान देते हुए, व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित आईबीसी से संबंधित उपायों का प्रस्ताव दिया :

- दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपये बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है जो एमएसएमई को बड़े पैमाने पर इंसुलेट करती है;
- संहिता की धारा 240क के अधीन एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान ढांचा अधिसूचित किया जाएगा;
- महामारी की स्थिति के आधार पर एक वर्ष तक दिवाला कार्यवाही की नई शुरुआत का निलंबन; तथा
- दिवाला को ट्रिगर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को संहिता के अधिनियम "व्यतिक्रम" की परिभाषा से कोविड-19 से संबंधित ऋण को निष्कासित करने के लिए सशक्त करना।

¹¹ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, अक्टूबर, 2021, आईएमएफ

¹² <https://group30.org/publications/detail/4820>

बॉक्स 1 : कोविड-19 के प्रति दिवाला विधि प्रतिक्रिया

ये सामान्य समय नहीं हैं। दुनिया कोविड-19 की चपेट में है, जिसका कोई त्वरित समाधान नजर नहीं आ रहा है। यह तेजी से आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। कुछ का मानना है कि यह सबसे गहरी स्वास्थ्य महामारी (1918 स्पेनिश फ्लू), सबसे खराब आर्थिक आपदा (1930 महामंदी), या सबसे विनाशकारी वित्तीय दुर्घटना (2008 वित्तीय संकट) से भी गहरी चोट पहुंचा सकता है, या हो सकता है, इन सभी को मिलाकर जितना बड़ा संकट था, उतना बड़ा संकट हो सकता है।

दुनिया भर में, भारत में भी, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव गंभीर रहा है। मुख्य रूप से दो बाहरी कारकों, कोविड-19 और देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मांग संकुचन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के मद्देनजर, कई कंपनियों की शीर्ष रेखा और निचली रेखा घट सकती है और उनमें से कुछ ऋण दायित्वों को पूरा करने में व्यतिक्रम कर सकती हैं।

जबकि अर्थव्यवस्था पर बाहरी चरों का प्रभाव बहुत गहरा है, अतीत में तुलनात्मक रूप से कम तीव्रता के समान झटकों ने पूरी दुनिया में कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला में तेज वृद्धि देखी है। हमारी हालिया स्मृति में, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप मांग में गिरावट, बाहरी वित्त की उपलब्धता में कमी, निवेश में गिरावट, दुनिया भर की फर्मों को दिवाला और शोधन अक्षमता¹³ का सामना करना पड़ा था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

इस तरह की दुर्लभ 'काला हंस' घटना को 'जीवन' बचाने के लिए मानवता से एक समान प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, जिसके लिए 'आजीविका' को बचाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए फर्मों के जीवन को बचाने की आवश्यकता थी। दुनिया भर की सरकारों ने उदार रुख अपनाया और कारपोरेट्स और व्यक्तियों को दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए मजबूर होने से रोकने के लिए तेजी से काम किया है। ऋण चुकौती पर स्थगन, क्षेत्र विशिष्ट सहनशीलता, वित्तीय रूप से संकटग्रस्त फर्मों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता का संचार, परिसंपत्ति वर्गीकरण बैंकिंग मानदंडों में राहत, दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए निदेशक के दायित्वों में लचीलापन, विशिष्ट विधिक दायित्वों के अनुपालन से राहत जैसे उपाय। आदि स्थिति से निपटने के लिए लिया गया है।

विश्व बैंक और आईएमएफ¹⁴ दोनों ने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक चुनौतियों और प्रमुख प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध किया है ताकि अर्थव्यवस्थाओं को महामंदी जैसे भाग्य का सामना करने से रोका जा सके। वे अर्थव्यवस्था को ग्राफ के सकारात्मक पक्ष की ओर सुचारु रूप से बदलने में मदद करने के लिए उन प्रतिक्रियाओं को तीन-चरणीय दृष्टिकोण में लागू करने का सुझाव देते हैं। पहले चरण में, दिवाला और ऋण प्रवर्तन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रचुर अंतरिम उपायों की आवश्यकता है। दूसरे चरण में, जब दिवाला की बड़ी लहर की आशंका होती है, तो इसे संक्रमणकालीन उपायों जैसे कि दिवाला के 'वक्र को समतल' करने के लिए विशेष आउट-ऑफ-कोर्ट वर्कआउट द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तीसरे चरण में शेष ऋण ओवरहैंग को संबोधित करने और मध्यम अवधि में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए नियमित ऋण समाधान उपकरण की मांग की गई है। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर तीन चरणों में प्रमुख चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं :

चरण	प्रमुख चुनौतियां	महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं
चरण 1 : अंतरिम उपाय करके स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति के तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए "प्रीज" चरण।	व्यवहार्य फर्मों को समय से पहले दिवालिया होने से रोकना।	सीमित समय के लिए एक या अधिक असाधारण उपायों को लागू करना : <ul style="list-style-type: none"> लेनदार द्वारा शुरू की गई दिवाला फाइलिंग के लिए बाधाओं को बढ़ाना; फाइल करने और संबद्ध दायित्व के लिए निदेशक के कर्तव्य को निलंबित करना; ऋण चुकौती आपातकालीन उपायों के साथ पूरकता सुनिश्चित करना।
चरण 2 : महामारी कम होने और आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने के बाद प्रतिक्रिया के लिए "संक्रमण" चरण।	उन फर्मों की बढ़ी हुई संख्या से निपटना जो दिवाला से गुजरे बिना बच नहीं पाएंगी।	वर्कआउट और ऋण पुनर्गठन तंत्र के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करना जैसे : <ul style="list-style-type: none"> अदालत के बाहर अनौपचारिक या हाइब्रिड कसरत ढांचे की स्थापना करना; ब्रिज फाइनेंसिंग के माध्यम से व्यापार बचाव को सुगम बनाना; एक सीमित अवधि के लिए प्रक्रियात्मक समय सीमा का विस्तार करना; पुनर्गठन के दौरान देनदार की व्यावसायिक गतिविधि बंद हो जाने पर परिसमापन के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता को निलंबित करना; दिवाला मामलों में ई-फाइलिंग, आभासी अदालती सुनवाई और अदालत के बाहर समाधान को प्रोत्साहित करना।
चरण 3 : "कर्ज की अधिकता से लड़ना" उस चरण के दौरान जब स्थिति स्थिर हो जाती है और इससे निपटने के लिए बाद के प्रभाव होते हैं।	संकट से उत्पन्न व्यक्तिगत वित्तीय संकट को संबोधित करना।	<ul style="list-style-type: none"> आधुनिक उपभोक्ता शोधन अक्षमता ढांचे को लागू करना; यह सुनिश्चित करना कि ऋण पुनर्निर्धारण और पुनर्भुगतान योजनाओं के लिए लचीले विकल्प हैं; एक नई शुरुआत की सुविधा के लिए ऋण माफी तंत्र या मुक्ति को सक्षम करना महत्वपूर्ण है।

भारत में प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह टुकड़ा केवल दिवाला के क्षेत्र में उपायों पर चर्चा करता है। जब हर फर्म, हर उद्योग और हर अर्थव्यवस्था तनाव में है, एक असफल फर्म को बचाने के लिए एक सफेद शूरीर खोजने की संभावना दूर है। यदि सभी विफल फर्मों को दिवाला कार्यवाही से गुजरना पड़ता है, तो उनमें से अधिकांश को बचाने के लिए बचावकर्ताओं की कमी के कारण परिसमापन के साथ समाप्त हो सकता

¹³ वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5448, "दि चैलेंजेज ऑफ द बैंकरप्सी रिफॉर्म", अक्टूबर, 2010

¹⁴ विश्व बैंक समूह, वित्तीय श्रृंखला, कोविड-19 नोट्स, "कोविड-19 का प्रकोप : कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला पर प्रभाव", अप्रैल, 2020 और कोविड-19 पर आईएफ की विशेष श्रृंखला, "महामारी के मद्देनजर निजी ऋण समाधान उपाय, मई, 2020.

है। इस तरह के परिसमापन पर, फर्मों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, जबकि परिसंपत्तियों की बिक्री में कमी होगी, जो कि बहुत कम है। फर्मों के जीवन को बचाना संहिता का मुख्य उद्देश्य है, इसका उपयोग इन असामान्य समय के दौरान समय से पहले उनकी जान लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इस अभूतपूर्व स्थिति ने एक और प्रयोग की मांग की, जिसमें दो प्रतिस्पर्धी नीति विकल्पों के बीच एक विकल्प की आवश्यकता होती है, अर्थात्, संहिता के संचालन को निलंबित करना या हमेशा की तरह इसके संचालन को जारी रखना। यदि पहले विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो बाजार एक अव्यवहार्य फर्म का परिसमापन करने में विफल हो जाएगा। यह एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसे अगली तिमाही या अगले वर्ष में ठीक किया जा सकता है। यदि दूसरे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो बाजार एक व्यवहार्य फर्म को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जिसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक व्यवहार्य फर्म को बचाना एक अव्यवहार्य फर्म को समाप्त करने में विफल रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कंपनियों, जो केवल कोविड-19 के कारण विफल हो रही हैं, सामान्य स्थिति बहाल होते ही अपने आप वापस उछाल सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, वे कम से कम अपने संचालन और व्यवसायों को 'बिल्कुल नए सामान्य' के लिए पुनर्रचना करेंगी। इसलिए, विकल्प पहले विकल्प पर गिर गया, जो फर्मों के लिए सांस लेने का समय प्रदान करता है और संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

पहले विकल्प में दो उप-विकल्प हैं, अर्थात्, संहिता को पूरी तरह से निलंबित करना या कुछ तत्वों को निलंबित करना, जैसा कि आवश्यक हो। पहला उप-विकल्प एक असफल फर्म के परिसमापन की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह कोविड-19 से पहले अव्यावहारिक हो या इसके कारण अव्यवहार्य हो। यह एक असफल फर्म के बचाव की अनुमति भी नहीं देगा, भले ही वह कोविड-19 से पहले व्यवहार्य हो या इसके बावजूद व्यवहार्य बनी रहे। एक व्यवहार्य फर्म के बचाव में देरी से उसका बचाव असंभव हो सकता है। इसलिए, नीति को उन फर्मों की रक्षा करनी चाहिए जो महामारी के शिकार हैं, न कि अयोग्य लोगों की रक्षा करना। इसलिए, विकल्प दूसरे उप-विकल्प पर गिर गया, जो किसी भी अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी अवधि के लिए, जो परिस्थितियों में आवश्यक हैं, संहिता के केवल ऐसे प्रावधानों को निलंबित करता है।

अध्यादेश कंपनी को कोविड-19 डिफॉल्ट से मुक्त नहीं करता है। यह इस तरह के व्यतिक्रम को संहिता के अधीन व्यतिक्रम के दायरे से बाहर भी नहीं करता है। कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य को छोड़कर, इस तरह की व्यतिक्रम संहिता के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए एक व्यतिक्रमबनी हुई है। उदाहरण के लिए, इस तरह की व्यतिक्रम एक दिवाला कार्यवाही में दावा प्रस्तुत करने या किसी पीजी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आधार हो सकती है।

कोविड-19 संकट दुनिया को प्रभावित करने वाला पहला संकट नहीं है। दुनिया ने अतीत में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन पर विजय प्राप्त की है। यह भी बीत जाएगा, मानव जाति को भविष्य में और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करना। इस युद्ध में दिवाला क्षेत्र में कई योद्धा हैं – सरकार, नियामक, सेवा प्रदाता (आईपीए, आईपी, आईयू, आरवीओ, आरवी) और एए। चूंकि सरकार लंबी अवधि में कोविड-19 के बाद के चरण के लिए देश के दिवाला परिदृश्य को तैयार कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि लघु और मध्यम अवधि में किए गए उपाय कंपनियों के जीवन और संकटग्रस्त व्यक्तियों की आजीविका के संरक्षण में सफल होंगे। हालाँकि, इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कोविड-19 से प्रभावित सभी फर्मों के तनाव से निपटने के लिए दिवाला कानून रामबाण नहीं है। हालाँकि, यह एक मूल्यवान साँस लेने की जगह प्रदान करता है, जबकि कंपनियों और साथ ही अधिकारी महामारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक व्यापक रणनीति बना सकते हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

भारत के राष्ट्रपति ने 05 जून, 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रख्यापित किया, ताकि 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यतिक्रम के लिए सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाने के लिए संहिता में और संशोधन किया जा सके। छह महीने या ऐसी आगे की अवधि, ऐसी तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। यह उन कंपनियों को रोकेगा जो अभूतपूर्व स्थिति के कारण संकट का सामना कर रही हैं, उन्हें दिवाला कार्यवाही में धकेलने से रोका जा सकता है, जब उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में समाधान आवेदक मिलना मुश्किल है। अध्यादेश स्पष्ट करता है कि 25 मार्च, 2020 से पहले किए गए व्यतिक्रम के लिए सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दायर किए जा सकते हैं। यह आगे प्रावधान करता है कि व्यतिक्रम के संबंध में सीडी की संपत्ति में योगदान के लिए देयता के संबंध में आरपी द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया जाएगा। जिसके खिलाफ सीआईआरपी की शुरुआत को निलंबित कर दिया गया है। यह सीडी के निदेशकों को लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए उचित परिश्रम के अभ्यास से निपटने वाली संहिता की धारा 66 (2) के अधीन दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

इसके अलावा, अध्यादेश को बदलने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 23 सितंबर, 2020 को अधिनियमित किया गया।

सीआईआरपी की शुरुआत का निलंबन

सरकार ने 5 जून, 2020 को संहिता में एक संशोधन के माध्यम से, 25 मार्च, 2020 से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी व्यतिक्रम के संबंध में, धारा 7, 9 और 10 के अधीन सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करना निलंबित कर दिया था। संहिता की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस निलंबन को 24 सितंबर, 2020 की अधिसूचना और 22 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के अधीन दो बार और तीन-तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया। तदनुसार, निलंबन 24 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया।

एमएसएमई की परिभाषा

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन 01 जून, 2020 की अधिसूचना के अधीन एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया है :

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) एक छोटा उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; तथा

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

बॉक्स 2 : जीवन और आजीविका बचाने के लिए व्यवसायों को बचाना: जी 30 के नीतिगत नुस्खे

जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, लोगों के आसानी से शिकार हो जाने के कारण लोग सतर्क हो गए, दुनिया भर में सरकारों की पहली प्रतिक्रिया लोगों की जान बचाने की थी। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने "जान है तो जहान है" मंत्र दिया। वायरस के प्रसार को रोकने और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अभूतपूर्व "लॉकडाउन" लगाया गया, "लॉकडाउन" शब्द ज्यादातर लोगों के लिए "बिलियंस के लिए एकीकरण का अनुभव" और एक के लिए "वर्ष का सार" के साथ कोलिनस डिक्शनरी के लिए वर्ष 2020 का विजेता शब्द बन गया।

जब लोगों की जान बचाई जा रही थी, आजीविका गायब हो रही थी, जिससे वायरस के अलावा अन्य कारणों से जान गंवाने का डर और बढ़ गया। मंत्र बदलकर "जान भी और जहान भी" कर दिया गया। व्यवसाय, जो किसी भी आर्थिक व्यवस्था की जीवनदायिनी हैं, उन पर आश्रित जीवन को बचाने के लिए असामयिक मौतों से बचाने की जरूरत है। तरलता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से राजकोशीय और मौद्रिक प्रतिक्रियाओं का पालन किया गया। इन प्रोत्साहन पैकेजों का पूर्ण प्रभाव अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रासंगिक नीतिगत प्रश्न जिन पर सरकारों और थिंक टैंकों को विचार करने की आवश्यकता हो सकती है — ये प्रोत्साहन पैकेज कितने और कितने समय तक जारी रहने चाहिए? ऐसे पैकेजों की लागत कौन वहन करेगा? व्यवसायों को बचाने, पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक योजना क्या होनी चाहिए? ऐसे बचाव उपाय करते समय नैतिक खतरे के मुद्दे से कैसे निपटा जाए? ये भारत में, साथ ही दुनिया भर में सरकारों के लिए प्रमुख नीतिगत विचार हैं।

जी 30, विभिन्न क्षेत्रों से तैयार किए गए आर्थिक और वित्तीय नेताओं का एक स्वतंत्र वैश्विक निकाय है, ने इस बात का खाका प्रदान किया है कि नीति निर्माता "कारपोरेट क्षेत्र के बाद के कारपोरेट क्षेत्र को पुनर्जीवित और पुनर्गठन" के लिए क्यों, कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। डॉ. रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, आरबीआई, और डॉ. मारियो ड्रैगी, पूर्व अध्यक्ष, ईसीबी जैसे दिग्गजों के साथ इस रिपोर्ट के सह-अध्यक्ष के रूप में, यह देखना उपयोगी है कि इसमें क्या अंतर्दृष्टि है।

स्वास्थ्य संकट के लंबे समय तक चलने और आर्थिक ठहराव की धमकी के साथ बढ़ते कारपोरेट ऋण शोधन क्षमता संकट से निपटने के लिए सरकारों को तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द कारपोरेट सॉल्वेंसी संकट अपना सिर उठाएगा, दुनिया भर में किए गए कई त्वरित उपायों, जैसे कि दिवाला कानूनों में अस्थायी समायोजन, घरों के उपभोग स्तर को बनाए रखना आदि द्वारा कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया गया है। चलनिधि केंद्रित नीतिगत उपायों के इस पहले चरण ने कारपोरेट दिवाला की बाढ़ को रोकने में अपनी भूमिका निभाई है। अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ हस्तक्षेपों को फिर से उन्मुख करने का समय आ गया है। भविष्य केंद्रित हो और सार्वजनिक ऋण के बढ़ते स्तर के प्रति सचेत रहें जो आसानी से अस्थिर हो सकता है।

जिस तरह से शुरुआत में सबसे कमजोर आबादी को कोरोना वायरस वैकसीन की दुर्लभ उपलब्ध कराए जाने के लिए लक्षित किया जा रहा है, उसी तरह दुर्लभ आर्थिक संसाधनों को भी एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर सबसे ज्यादा जरूरत वाले व्यवसायों को लक्षित किये जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में उन फर्मों के लक्षित समूह की पहचान करने के लिए नीतिगत लक्ष्यों की वर्तनी का सुझाव दिया गया है जो बचाने के योग्य हैं और जॉबी वित्तपोषण की समस्या को रोकते हैं। प्राथमिकताओं की पहचान करने और कुछ प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता है— क्या यह बड़े कारपोरेट या छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) हैं जिन पर अधिक ध्यान दिया जाता है? क्या हमें नौकरी के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए या "रचनात्मक विनाश" की अनुमति देनी चाहिए? सरकार के पास कितना वित्तीय हेडरूम है? क्या कारपोरेट्स को समर्थन देने के लिए निजी वित्तपोषण विदेशी स्रोतों को जुटाया जा सकता है?

लक्षित करने के लिए फर्मों का अच्छा समूह वह होगा जहां कोविड-19 महामारी के कारण बाजार की विफलता की बहुत अधिक सामाजिक लागत हो। इसमें एसएमई, आर्थिक रूप से मजबूत बड़ी फर्म और गैर-एसएमई फर्म जिनका अन्यथा लिवरेज कम होता है लेकिन अनिश्चित टिकाऊ व्यापारिक मॉडल हो, शामिल होंगी। अंतर्निहित ढांचे के आधार पर, रिपोर्ट ट्राइएज फर्मों को आगे बढ़ती है और आर्थिक व्यवहार्यता, उत्तोलन की डिग्री और वित्तीय बाधाओं की प्रकृति जैसे मापदंडों के आधार पर नीतिगत फोकस का सुझाव देती है। इस अभ्यास से पाँच श्रेणी की फर्में प्राप्त होती हैं, अर्थात् स्वस्थ फर्म वित्त पोषण की विवशता वाली फर्म नकदी की चुनौती वाली फर्म शोधन क्षमता की चुनौती वाली फर्म और संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ फर्म। रिपोर्ट में इन फर्म श्रेणियों के लिए उपयुक्त चार प्रकार की सहायता की सिफारिश करती जिन्हें ऋण की सबसे अधिक आवश्यकता होगी (क) फर्मों को सहायता देने के लिए बेहतर लक्ष्य क्रेडिट; (ख) व्यावहार्य फर्मों में इविटी अथवा इविटी जैसे निवेश को बढ़ावा देना; (ग) पुनर्संरचना और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं को सही स्थान पर रखना जिससे इविटी के लिए ऋण का तीव्र विनिमय, ऋण अवधियों की पुनर्संरचना सुनिश्चित हो और (घ) दीघावधि में संकार द्वारा समर्थित बीमा के माध्यम से भावी महामारी व्यापार समर्थन तैयार किया जा सके।

इन सभी उपकरणों का एक साथ या संयोजन में एक अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उपयुक्त के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हस्तक्षेप की रूपरेखा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों, संस्थागत क्षमताओं और सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। शुरु किए गए किसी भी हस्तक्षेप को नैतिक खतरे की समस्याएं पैदा करने के खतरे का संज्ञान होना चाहिए, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए जो महामारी के आने से पहले से ही उच्च उत्तोलन के स्तर पर थीं। इसके अलावा, एमएसएमई के लिए हस्तक्षेप डिजाइन को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट इनमें से प्रत्येक पहलू पर विस्तृत सिफारिशें करती है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के तुलन-पत्रों में वास्तविक क्षेत्र के संकट के फैलने की संभावना को रिपोर्ट द्वारा संभावित माना गया है। यह इस संकट के उत्पाद के रूप में बड़ी मात्रा में अशोध्य ऋण से निपटने के कुशल और प्रभावी तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाइयों का सुझाव देता है। इनमें खराब संपत्ति खरीदने या गारंटी देने वाली सरकारें शामिल हैं "बैड बैंक" संरचनाओं की स्थापना और एनपीए को लेने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

संक्षेप में, रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए महामारी के बाद कारपोरेट क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी नीति प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांतों की सिफारिश करती है: तत्काल कार्य करें; ध्यान से लक्ष्य; नई व्यावसायिक वास्तविकताओं के अनुकूल; केवल बाजार विफलता आवंटन को संबोधित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का दोहन व्यापार समर्थन उपायों के साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों को संतुलित करना; जोखिमों को कम करना और हानियों को साझा करना; नैतिक खतरे के मुद्दों का ख्याल रखना; हस्तक्षेपों के समय, मंचन और दीर्घायु पर काम करना और वित्तीय क्षेत्र में स्पिल ओवर का अनुमान लगाना और उसके अनुसार तैयारी करना।

आगे बढ़ते हुए, एक बार महामारी पर नियंत्रण हो जाने के बाद, राष्ट्रों को प्रयास करना चाहिए कि आजीविका की कमी के कारण लोगों की जान न जाए। उस महामारी के बाद की दुनिया के लिए अब जमीन तैयार करने के लिए उन व्यवसायों को बचाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए रोटी और मकखन प्रदान करते हैं। यह दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन और विकास के लिए भी आवश्यक है।

मूल्यांकन व्यावसायिक संबंधी विशेषज्ञ समिति

मूल्यांकन व्यावसायिकों के विनियमन और विकास के लिए संस्थागत ढांचे की आवश्यकता की जांच करने के लिए डॉ एम एस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति (सीओई) ने 02 अप्रैल, 2020 को सरकार को 'मूल्यांकन विधेयक, 2020' के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीओई ने हितधारकों – आरवीओ, आरवी, अन्य मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य वृत्तियों, व्यावसायिक संस्थानों, व्यापार और उद्योग, और शिक्षाविदों के साथ व्यापक परामर्श किया। इसने मूल्यांकन व्यावसायिकों के विकास और विनियमन के लिए संस्थागत व्यवस्था और मूल्यांकन सेवाओं के आसपास विधिक और नियामक आवश्यकताओं दोनों के संदर्भ में भारत में मूल्यांकन परिदृश्य का अध्ययन किया। इसने उन्नत क्षेत्राधिकारों में मूल्यांकन व्यावसायिकों के लिए संस्थागत ढांचे, भारत में इस तरह के ढांचे को प्रदान करने के लिए अतीत में किए गए प्रयास, और भारत में अन्य व्यवसायों के संबंध में संस्थागत / नियामक ढांचे का अनुभव पर विचार किया। इसने बाजारों और व्यवसायों के संबंध में नियामक राज्य की भूमिका और नियामक वास्तुकला के डिजाइन पर समकालीन विचारों का अन्वेषण किया। इसने कम से कम विघटनकारी, लेकिन आधुनिक और मजबूत, संस्थागत ढांचे की सिफारिश की है जो आज और कल की चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत और विदेशों में और भारत में अन्य व्यवसायों के मूल्यांकन व्यवसाय के अनुभव से सीखे और मूल्यांकन व्यावसायिकों के लिए सम्मान और मूल्यांकन सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करे।

सीओई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में मूल्यांकन सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने और मूल्यांकनों के व्यवसाय और मूल्यांकन सेवाओं के लिए बाजार को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान (एनआईवी) की स्थापना के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिश की है। इससे यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि मूल्यांकन अपनी सेवाओं के लिए जवाबदेह होने के साथ-साथ हितधारकों के बीच गहरी प्रतिष्ठा का आनंद लें, और जो अन्य व्यवसायों के लिए मॉडल बनें। हितधारकों को मूल्यांकन सेवाओं का उपयोग करना चाहिए

क्योंकि वे मूल्य पाते हैं, न कि विधिक जनादेश के कारण।

सीमा पार दिवाला नियम संबंधी समिति

सीमा पार दिवाला से संबंधित कार्यान्वयन प्रावधानों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से नियमों और नियामक ढांचे को प्रस्तावित करने हेतु सरकार द्वारा डॉ. केपी कृष्णन की अध्यक्षता में गठित सीमा पार दिवाला नियम और विनियमन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 15 जून, 2020 को प्रस्तुत की। समिति, उद्यम समूह दिवाला हेतु यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल विधि का अध्ययन और विश्लेषण करने और संहिता के संदर्भ में सिफारिशें करने के विस्तारित क्षेत्राधिकार पर काम कर रही है।

बैंकों को सलाह

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने 26 अगस्त, 2020 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि पीजी से सीडी के दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में संहिता के उपबंध 01 दिसंबर, 2019 से लागू हो गए हैं, जो लेनदारों को एनसीएलटी के समक्ष पीजी के विरुद्ध सीडी में दिवाला आवेदन दाखिल करने का अधिकार देते हैं। उसी के अनुरूप, इसने बैंकों को उन मामलों की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दी, जिनमें पीजी के विरुद्ध सीडी में एनसीएलटी के समक्ष व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे सभी मामलों में पीजी से सीडी के संबंध में डेटा एकत्रित करने के लिए आईटी प्रणाली स्थापित करनी होगी।

प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया

आईएलसी की उप-समिति ने 31 अक्टूबर, 2020 को प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) पर अपनी रिपोर्ट एमसीए को सौंप दी। दिवाला सुधारों में प्रगति, देश में दिवाला से संबंधित प्रणाली और प्रैक्टिस की परिपक्वता और अन्य क्षेत्राधिकारों में प्री-पैक्स के अनुभव से सीखने को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने संहिता के बुनियादी ढांचे के भीतर भारतीय बाजार के लिए प्री-पैक फ्रेमवर्क तैयार किया है। सीआईआरपी की तुलना में प्रस्तावित प्री-पैक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

मापदंड	सीआईआरपी	प्रस्तावित प्री-पैक
प्रयोजन	समाधान योजना के माध्यम से समाधान	समाधान योजनाके माध्यम से समाधान
विधिक ढांचा	संविधि में अपेक्षाकृत अधिक और विनियमनों में कम	संविधि में अपेक्षाकृत कम और विनियमनों में अधिक
अनुपयुक्तता	कंपनियों और एलएलपी	कंपनियों और एलएलपी
प्रक्रिया का प्रारंभ	कोविड-19 व्यतिक्रम को छोड़कर 1 करोड़ रुपये से अधिक व्यतिक्रम	व्यतिक्रम तनाव से पहले और बाद का तनाव, जिसमें कोविड-19 व्यतिक्रम भी शामिल है। चरणबद्ध तरीके से, यदि आवश्यक हो
द्वारा आरम्भ	एफसी, ओसी, अथवा सीडी	सीडी, असंबद्ध एफसी के बहुमत की सहमति से
सीडी का प्रबंधन	लेनदार-नियंत्रण के साथ आईपी-स्वामित्व में	लेनदार-नियंत्रण में के साथ देनदार-स्वामित्व में
आईपी की भूमिका	आवेदक द्वारा नियुक्त आईआरपी और फिर सीओसी द्वारा नियुक्त आरपी	आरपी, असंबंधित एफसी के बहुमत की सहमति से नियुक्त किया जाएगा
	सीडी के कार्यों का प्रबंधन और प्रक्रिया का संचालन	प्रक्रिया का संचालन
दावा मिलान	आईआरपी आमंत्रित करने और मिलान करने के लिए	सीडी उपलब्ध कराना है। सत्यापन के लिए आर.पी.
सूचना ज्ञापन	आरपी द्वारा तैयार	सीडी द्वारा तैयार ड्राफ्ट और आरपी द्वारा अंतिम रूप दिया गया
अधिस्थगन	धारा 14 के अधीन अधिस्थगन	अतिस्थगन
अंतरिम वित्त	हां	हां
परिहार लेन-देन	हां	हां

मूल्यांकन	दो मूल्यांककों द्वारा	दो मूल्यांककों द्वारा
आईआरपीसी	ओपरेशन संचालन की लागत शामिल	ओपरेशन संचालन की लागत शामिल नहीं
समाधान योजना के लिए आमंत्रण	सार्वजनिक प्रक्रिया	प्रवर्तकों को प्रथम अधिकार की पेशकश, स्विस चुनौती
समाधान योजना के लिए अपात्रता	धारा 29क लागू	धारा 29क लागू होनी है
प्रक्रिया का शीघ्र समापन	धारा 12ए के अधीन आवेदक के अनुरोध पर	66% मतदान हिस्से की मंजूरी के साथ, वर्तमान और मतदानय सीओसी द्वारा स्वतः संज्ञान
सीओसी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन	मतदान हिस्से का 66%	मतदान हिस्से के 66%, अनुमोदन के साथ वर्तमान और मतदान
प्रक्रिया समापन के परिणाम	कोई समाप्ति की अनुमति नहीं है	परिसमापन, सीओसी के 75% मतदान हिस्से के साथ
प्री-पैक की विफलता के परिणाम	परिसमापन	समापन
बाध्यकारी परिणाम	समाधान योजना बाध्यकारी	समाधान योजना बाध्यकारी
नियामक लाभ	हां	हां
साफ ब्लेट, समाधान पध्दात	हां	हां
आईपी और एए की भूमिका	अपेक्षाकृत अधिक	अपेक्षाकृत कम
समय-सीमा	एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन तक 180 दिन	एए के साथ समाधान योजना दाखिल करने के लिए 90 दिन और एए को इसे स्वीकृत करने के लिए 30 दिन
कूलिंग ऑफ	दो सीआईआरपी के बीच में 12 माह	दो प्री-पैक के बीच में तीन साल

खनन नियम

खान मंत्रालय ने 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। संहिता के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकरण या न्यायालय द्वारा आशय पत्र (हस्तांतरणकर्ता) के मूल धारक के मामले में दिवाला, परिसमापन या शोधन अक्षमता की कार्यवाही का निश्कर्ष।

नियामकों द्वारा सुविधाएं

भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई ने अन्य उपायों के अलावा, 17 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन समाधान समयसीमा की समीक्षा की। विवेकपूर्ण ढांचे के संदर्भ में, ऋणदाताओं को 30 दिनों की समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर व्यतिक्रम वाली से संस्थाओं के संबंध में समाधान योजना लागू करने की आवश्यकता होती है। समीक्षा करने पर, आरबीआई ने 01 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि को 30-दिवसीय समीक्षा अवधि की गणना से बाहर रखा, उन खातों के संबंध में जो 01 मार्च, 2020 तक समीक्षा अवधि के भीतर थे। सभी के संबंध में ऐसे खाते, शेष समीक्षा अवधि 01 जून, 2020 से फिर से शुरू होगी, जिसके समाप्त होने पर ऋणदाताओं के पास समाधान के लिए सामान्य 180 दिन होंगे। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में जहां समीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 180 दिन की समाधान अवधि 01 मार्च, 2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, उन मामलों में समाधान के लिए समय सीमा उस तारीख से 90 दिनों तक बढ़ाई जाएगी जिस पर 180 दिन की अवधि मूल रूप से समाप्त होने के लिए निर्धारित है। नतीजतन, विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन आवश्यक 20 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता को विस्तारित समाधान अवधि समाप्त होने पर ट्रिगर किया जाएगा।

आरबीआई ने एक और समीक्षा करने पर, 23 मई, 2020 की अन्य अधिसूचना के माध्यम से, उन खातों के संबंध में जो समीक्षा अवधि के भीतर थे, 01

मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि को 01 मार्च, 2020 को 30-दिन की समीक्षा अवधि की गणना से बाहर कर दिया। ऐसे सभी खातों के संबंध में, शेष समीक्षा अवधि 01 सितंबर, 2020 से फिर से शुरू होगी, जिसके समाप्त होने पर ऋणदाताओं के पास समाधान के लिए सामान्य 180 दिन होंगे। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में जहां समीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन 180 दिन की समाधान अवधि 01 मार्च, 2020 तक समाप्त नहीं हुई थी, समाधान की समय सीमा को 180 दिन की मूल रूप से निर्धारित अवधि के समाप्त होने की तारीख से 180 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा। नतीजतन, विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन आवश्यक 20 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता को विस्तारित समाधान अवधि समाप्त होने पर ट्रिगर किया जाएगा।

वित्तीय तनाव कम करने के उपाय

कोविड-19 के कारण होने वाले वित्तीय तनाव को और कम करने के लिए, आरबीआई ने 22 मई, 2020 को विकास और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की :

(क) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को पहले 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी ऋणों के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के लिए अनुमति दी थी। लॉकडाउन के विस्तार और कोविड-19 के कारण जारी व्यवधानों को देखते हुए, आरबीआई ने उन्हें 01 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक आवधिक ऋण की किश्तों पर स्थगन का विस्तार करने की अनुमति दी। तदनुसार, चुकौती समय सीमा और बाद की सभी देय तिथियां, साथ ही ऐसे ऋणों के लिए अवधि, सभी मामलों में एक और तीन महीने के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में 1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के तीन माह की अवधि के लिए 1 मार्च, 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर 27 मार्च, 2020 को तीन महीनों के लिए ब्याज के आस्थगन की अनुमति दी।

(ग) आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को आस्थगन अवधि (31 अगस्त,

2020 तक) में कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि के ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति दी, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च, 2021) के पहले तक चुकाने योग्य होगा। इससे एक बार में संचित ब्याज को चुकाने में उधारकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी।

(घ) चूंकि स्थगन/आस्थगन विशेष रूप से उधारकर्ताओं को कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जा रहा है, इसे उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच ऋण समझौतों में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड नहीं होगा। यह अधिस्थगन ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रम के रूप में भी योग्य नहीं होगा।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता

आरबीआई ने अपने साथ पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सलाह दी कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) को अपने हितधारकों के साथ और उनके संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 16 जुलाई, 2020 को अपने संचार के माध्यम से रखें। एफपीसी से न्यूनतम नियामक अपेक्षा निर्दिष्ट की। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए, एआरसी सार्वजनिक रूप से नीलामी में भागीदारी की मांग करेगा और संभावित खरीदारों से निपटने में संहिता की धारा 29ए की भावना का पालन करेगा। यह ऋण की वसूली में देनदार के उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वसूली एजेंटों को, विशेष रूप से कॉल करने के घंटों, ग्राहक जानकारी की गोपनीयता आदि जैसे पहलुओं में उनकी जिम्मेदारियों को देखभाल और संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

कोविड-19 तनाव के लिए समाधान ढांचा

कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजे ने पूरे बोर्ड में उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव पैदा कर दिया है जो संभावित रूप से आर्थिक रूप से अन्यथा व्यवहार्य कई फर्मों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के व्यापक प्रभाव से पूरी वसूली प्रक्रिया खराब हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा हो सकते हैं। वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने और अंतिम उधारकर्ताओं पर प्रभाव को कम करने के इरादे से इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, ऐसे एक्सपोजर को मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय, स्वामित्व में परिवर्तन के बिना, कोविड-19 के कारण तनाव में रहने वाले कारपोरेट उधारकर्ताओं को समाधान योजना लागू करने में सक्षम बनाने के लिए आरबीआई ने 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन विंडो प्रदान की। केवल वे खाते जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 01 मार्च, 2020 तक किसी भी ऋण देने वाली संस्था के साथ 30 दिनों से अधिक के लिए व्यतिक्रम नहीं था (अर्थात्, एसएमए-0 से अधिक नहीं) और जो समाधान प्रक्रिया के आह्वान तक मानक बने हुए हैं, पात्र हैं। आरबीआई वित्तीय मानकों की सूची और इस तरह के मानकों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क रेंज की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन करेगा, जो उनकी राय में, प्रत्येक समाधान योजना में जाने वाली धारणाओं में शामिल होना आवश्यक होगा।

कोविड-19 तनाव के लिए वित्तीय मानदंड

विशेषज्ञ समिति, जैसा कि कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान ढांचे के अधीन परिकल्पित है, ने 04 सितंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने 07 सितंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी ऋण देने वाले संस्थान। पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देते समय प्रमुख अनुपात, अर्थात् कुल बाहरी देयताएं / समायोजित मूर्त निवल मूल्य, कुल ऋण / एबिटडा वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात अनिवार्य रूप से विचार करें। 26 क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक प्रमुख अनुपात के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को सेक्टर-विशिष्ट थ्रेसहोल्ड (छत या फर्श) पर विचार करने की भी आवश्यकता है। ऋण देने वाली संस्थाएं संकल्प मान्यताओं को अंतिम रूप देते समय अन्य वित्तीय मानकों पर भी विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए छूट

सेबी ने 22 जून, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अधिमार्ग मुद्दों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंडों को शिथिल करने के लिए सेबी (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में विनियम 164क सम्मिलित किया। विनियम 164ए प्रदान करता है कि शेयरों की कीमत संबंधित इक्विटी शेयरों के संबंधित तारीख से पहले के दो सप्ताह के दौरान साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा भारत औसत कीमतों के औसत से कम नहीं होनी चाहिए। यह छूट किसी कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयर जारी करने के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानदंडों को पूरा करती है :

(क) जारीकर्ता ने ब्याज के भुगतान / ऋण पर मूल राशि की चुकौती पर सभी व्यतिक्रमों का खुलासा किया है और इस तरह के व्यतिक्रम होने के बाद कम से कम 90 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है;

(ख) आरबीआई (दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) दिशा-निर्देश, 2019 दिनांक 07 जून, 2019 के संदर्भ में एक अंतर-ऋणदाता समझौता है; तथा

(ग) सूचीबद्ध कंपनी के वित्तीय लिखतों (सूचीबद्ध या असूचीबद्ध), क्रेडिट लिखतों/उधारों (सूचीबद्ध या असूचीबद्ध) की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर "घ" कर दिया गया है।

सेबी ने 22 जून, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिनीकरण) विनियमन, 2011 में सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के विनियमन 164क के अधीन ओपन ऑफर दायित्वों से अधिमार्ग मुद्दे के माध्यम से शेयरों या मतदान अधिकारों के किसी भी अधिग्रहण को छूट देने के लिए संशोधन किया।

आरवी द्वारा मूल्यांकन

सेबी ने 03 नवंबर, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से, 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित किया, जो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की योजना (एसओए) की रूपरेखा तैयार करता है। संशोधन के लिए सभी सूचीबद्ध संस्थाओं को एसओए में आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आरवी एक ऐसा व्यक्ति है, जो आरवी का सदस्य होने के नाते, नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार आईबीबीआई के साथ पंजीकृत है।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता

सेबी ने उन कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पुनर्गणना करने का निर्णय लिया, जो संहिता के अधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद भी सूचीबद्ध रहती हैं। ऐसी कंपनियों के पास स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग में प्रवेश के समय कम से कम 5 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, ऐसी कंपनियों को उस तारीख से 12 महीने के भीतर 10 प्रतिशत की सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करनी होगी, जिस तारीख से कंपनी के ऐसे शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए और 36 महीने में उक्त तारीख से 25 प्रतिशत की सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। समाधान योजना के अधीन आए को आवंटित इक्विटी शेयरों पर लॉक-इन अवधि 12 महीनों के भीतर 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने की सीमा तक लागू नहीं होगी।

लिस्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व

सेबी ने 8 जनवरी, 2021 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिविगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 में संशोधन किया। रेगुलेशन में संहिता के अधीन एए द्वारा अनुमोदित रेजोल्यूशन प्लान की विशिष्ट विशेषताओं और विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें वाणिज्यिक शामिल नहीं है। रहस्य, अर्थात्, कंपनी के पूर्व और बाद के निवल मूल्य, सीआईआरपी के बाद कंपनी की संपत्ति का विवरण, कंपनी पर लगाए गए अन्य भौतिक दायित्व, कंपनी में निवेशित धन का

सारणी 1 : नीतिगत और नियामक घटनाओं का समयक्रम 2020-21

तारीख	घटना
02.04.20	सीआई ने भारत में मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थान की स्थापना और अन्य उपायों के लिए एक विशेष कानून के अधिनियमन की सिफारिश करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
17.04.20	आरबीआई ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन समाधान टाइमलाइन की समीक्षा की।
20.04.20	आईबीबीआई ने प्रेक्टिस हेतु असाइनमेंट प्राधिकरण (एएफए) प्राप्त करने में आईपी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आईबीबीआई (आदर्श उपनियम और दिवाला व्यवसायिक अभिकरण शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
20.04.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें जमा करने की नियत तारीख के बाद सीआईआरपी फॉर्म भरने की तारीख, चाहे वह सुधार, अद्यतन या अन्यथा के लिए हो, बढ़ा दी गई है।
20.04.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में समयसीमा के अनुपालन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।
23.04.20	आईबीबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया कि प्रवर्तक संगठन का कोई सदस्य, जिसने आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ का स्वतंत्र निदेशक बनने के योग्य नहीं होगा।
05.05.20	सरकार ने अधिसूचित किया कि आईआरपी/आरपी को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन सीडी का विशिष्ट व्यक्ति माना जाएगा और उन राज्यों या संघ शासित राज्यों में से प्रत्येक में नया रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा जहां पूर्व में सीडी रजिस्ट्रीकृत की गई थी।
12.05.20	एनसीएलटी ने निर्देश दिया कि संहिता की धारा 7 के अधीन आवेदन आईयू से व्यतिक्रम रिकॉर्ड के साथ फाइल किए जाने चाहिए।
17.05.20	केंद्र सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत, भाग V : सरकारी सुधार और समर्थक' के हिस्से के रूप में आईबीसी से संबंधित विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा।
23.05.20	तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों को देखते हुए, आरबीआई ने 'कोविड-19 नियामक पैकेज - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अधीन समाधान टाइमलाइन की समीक्षा' के अधीन समयसीमा की समीक्षा की।
01.06.20	सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अधीन एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित परिभाषा को अधिसूचित किया।
02.06.20	आईबीबीआई ने 01 जुलाई, 2020 से 25 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के सामान्य पैनेल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम समाधान व्यवसायिक, परिसमापक, समाधान व्यवसायिक और दिवाला ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए।

विवरण, लेनदारों का भुगतान और व्यापार रणनीति का संक्षिप्त विवरण। विनियमों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कदमों के प्रकटीकरण, ऐसी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने की स्थिति का त्रैमासिक प्रकटीकरण और समाधान योजना में अनुमोदित डीलिंग योजनाओं, यदि कोई हो, के विवरण की भी आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

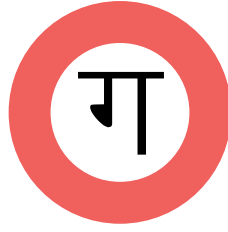
योग्य वित्तीय अनुबंध

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 2 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, योग्य वित्तीय अनुबंध अधिनियम, 2020 के द्विपक्षीय नेटिंग के अधीन योग्य वित्तीय अनुबंध (व्यूएफसी) की एक विस्तृत और विस्तृत परिभाषा पेश की। अधिसूचना ने व्यूएफसी को किसी भी निजी तौर पर परिभाषित किया। एक स्टॉक एक्सचेंज के बाहर निष्पादित द्विपक्षीय वित्तीय अनुबंध, जिसमें किसी भी ऐसे वित्तीय अनुबंध में संदर्भ द्वारा शामिल किए गए किसी भी नियम और शर्तें शामिल हैं, जिसके अनुसार बाजार मूल्य वाले भुगतान या वितरण दायित्वों को एक निश्चित समय पर या एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना है। इनमें से कुछ अनुबंध मुद्रा, क्रॉस-करेंसी या ब्याज दर स्वैप हैं; क्मोडिटी स्वैप; और प्रतिभूति अनुबंध आदि।

सारणी 1 2020-2021 के दौरान महत्वपूर्ण नीति और नियामक विकास का वर्णन है।

05.06.20	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यतिक्रम के लिए छह महीने की अवधि या ऐसी तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं, सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करने पर रोक लगाने के लिए प्रख्यापित किया गया था।
15.06.20	सीमा पार दिवाला नियमों और विनियमों पर समिति ने सीमा पार दिवाला से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
22.06.20	सेबी ने सेबी (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 में संशोधन किया ताकि सेबी (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 के विनियमन 164 क के अधीन अधिमाम्य मुद्दे के माध्यम से शेयरों या मतदान अधिकारों के किसी भी अधिग्रहण को दायित्वों की खुली पेशकश से छूट दी जा सके।
22.06.20	सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा तरजीही मुद्दों के लिए मूल्य निर्धारण मानदंडों में ढील देने के लिए सेबी (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 में संशोधन किया है।
30.06.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में संशोधन किया, ताकि आईपीई को किसी भी आईपी को सहायता सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मिल सके।
10.07.20	आईबीबीआई ने आईपीए और आरवीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी को नियंत्रित करने के लिए आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए।
16.07.20	भारतीय रिजर्व बैंक ने एआरसी के लिए उचित व्यवहार संहिता के बारे में परिपत्र जारी किया जिसमें एआरसी को सलाह दी गई कि वे अपने हितधारकों के साथ और उनके संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित व्यवहार संहिता लागू करें।
05.08.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया, ताकि एक कारपोरेट व्यक्ति को परिसमापक को बदलने के लिए सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के संकल्प द्वारा परिसमापक के रूप में किसी अन्य आईपी को नियुक्त किया जा सके।
05.08.20	आईबीबीआई ने यह स्पष्ट करने के लिए आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है कि जहां परिसमापक को किसी भी राशि की वसूली होती है, लेकिन वह उसे वितरित नहीं करता है, वह उसके द्वारा वसूल की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा।
05.08.20	आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करते समय आईपी द्वारा उपयोग के लिए एए, एनसीएलएटी और उच्च न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों से महत्वपूर्ण निर्देशों और टिप्पणियों को सूचीबद्ध करते हुए एक सुविधा नोट जारी किया।
06.08.20	आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क पर परिपत्र जारी किया, ताकि उधारदाताओं को स्वामित्व में बदलाव के बिना, कोविड-19 के कारण तनाव वाले कारपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके, जबकि ऐसे एक्सपोजर को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मानक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
07.08.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आईआरपी द्वारा एआर को कार्य करने के लिए पेश किए गए तीन आईपी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से होने चाहिए, जिसमें विशिष्ट वर्ग में लेनदारों की संख्या सबसे अधिक है बैटक के कार्यवृत्त के परिचालित होने के बाद ही एआर मतदान निर्देश मांगेगा और तदनुसार मतदान करेगा और सीओसी सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगा।
13.08.20	एनसीएलटी ने 12 मई, 2020 के अपने आदेश को संशोधित किया, जिसमें आईयू से, संहिता की धारा 7 के अधीन फाइल की गई नई याचिकाओं के साथ, आईयू के पास, जहां भी उपलब्ध हो, व्यतिक्रम रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
26.08.20	सरकार ने सभी राष्ट्रीय बैंकों को उन मामलों की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए एक परामर्श जारी किया, जिनके लिए पीजी के खिलाफ सीडी में व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है और उसी के लिए डेटा एकत्र करने के लिए आईटी प्रणाली स्थापित करनी पड़ सकती है।
07.09.20	आरबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें ऋण देने वाली सभी संस्थाओं को विभिन्न प्रमुख वित्तीय अनुपातों पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जैसा कि कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान ढांचे पर समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा की गई है।
23.09.20	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
24.09.20	केंद्र सरकार ने संहिता की धारा 10क के अधीन 25 सितंबर, 2020 से तीन महीने की और अवधि के लिए संहिता का निलंबन अधिसूचित किया।
09.10.20	आईबीबीआई ने अनुशासन समिति और आरवीओ के अपीलीय पैनल की बैठकों के संचालन और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर परिपत्र जारी किया।
29.10.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा की उपलब्धता के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसमें आवेदकों को सीआईआरपी की शुरुआत के लिए फाइल किए गए आवेदन की प्रति बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
31.10.20	आईएलसी की उप-समिति ने पीपीआरआईपी पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें भारतीय बाजार के लिए संहिता की मूल संरचना के भीतर तैयार किए गए प्री-पैक ढांचे की सिफारिश की गई है।
03.11.20	सेबी ने 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित करते हुए परिपत्र जारी किया जिसमें सभी सूचीबद्ध संस्थाओं को व्यवस्था की योजनाओं (एसओए) ढांचे के अधीन आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
13.11.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017 में संशोधन किया है ताकि संहिता के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा को वित्तीय जानकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जा सके और आईयू के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक घोषणा के प्रसार की आवश्यकता हो, जो दिवाला कार्यवाही से गुजर रहे सीडी के लेनदार हैं।

13.11.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि दो 'अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के साक्ष्य' को निर्दिष्ट किया जा सके और समाधान योजना के अधीन ऋण के भुगतान के लिए उसके द्वारा प्रत्येक दावेदार, सिद्धांत या सूत्रों को आईबीबीआई वेबसाइट पर प्रसार और सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आरपी द्वारा लेनदारों की सूची प्रस्तुत करने का प्रावधान किया जा सके।
13.11.20	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया ताकि परिसमापक को हितधारकों की परामर्श समिति (एससीसी) के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को 'तुरंत वसूली योग्य संपत्ति' सौंपने या स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया जा सके।
23.11.20	आईबीबीआई ने जनवरी-जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के क्षेत्र-वार पैनल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम समाधान व्यवसायिक, परिसमापक, समाधान व्यवसायिक और दिवाला ट्रस्टी (सिफारिश) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए।
27.11.20	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें आईबीबीआई वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आईआरपी या आरपी द्वारा लेनदारों की सूची दाखिल करने या उसी को अद्यतन करने की आवश्यकता जताई गई।
16.12.20	सेबी ने उन कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों की पुनर्गणना की, जो संहिता के अधीन समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद भी सूचीबद्ध रहती हैं।
22.12.20	केंद्र सरकार ने संहिता की धारा 10क के अधीन 25 दिसंबर, 2020 से तीन महीने की और अवधि के लिए संहिता का निलंबन अधिसूचित किया।
24.12.20	एनसीएलटी ने अपनी सभी पीठों को 1 जनवरी, 2021 से स्वचालित केस नंबर जनरेशन के साथ ई-कोर्ट के दूसरे चरण का कार्यान्वयन शुरू करने की सलाह दी।
06.01.21	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें आईपी को उनके द्वारा संचालित सीआईआरपी के सभी रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए और सभी रिकॉर्ड्स की एक फिजिकल कॉपी को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया।
08.01.21	सेबी ने सेबी (देयताओं का सूचीयन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में संशोधन किया है, जिसमें संहिता के अधीन एए द्वारा अनुमोदित, विशिष्ट विशेषताओं और अन्य बातों के साथ-साथ, समाधान योजना के विवरण, जिसमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल नहीं हैं, का प्रकटीकरण अनिवार्य है।
14.01.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ताकि किसी व्यक्ति के लिए आईपी के शासी बोर्ड में शेयरधारक निदेशक बनने के लिए पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए जा सकें।
02.02.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसमें आवेदकों को पीजी से सीडी में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए फाइल आवेदन की प्रति बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
02.02.21	आईएफएससीए ने अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध अधिनियम, 2020 के द्विपक्षीय नेटिंग के अधीन अर्हताप्राप्त वित्तीय अनुबंध की व्यापक और विस्तृत परिभाषा पेश की।
04.03.21	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें परिसमापक को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर परिसमापन के अधीन संबंधित सीडी के हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता थी।
04.03.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है, जिसमें परिसमापक को बोर्ड की वेबसाइट पर समय-समय पर संशोधित हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है।
09.03.21	आईबीबीआई ने 01 अप्रैल, 2021 से प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति की सुविधा के लिए सेबी (निवेशकों को निधि प्रतिदाय के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
11.03.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन प्रदायगी) दिशानिर्देश, 2020 की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।
15.03.21	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है ताकि दिवाला शुरू होने की तारीख (आईसीडी) और निर्दिष्ट गतिविधियों के बाद लेनदार द्वारा दावे को अद्यतन करने का प्रावधान किया जा सके, जिसे पूरा नहीं करने पर नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर सीआईआरपी फॉर्म 7 के माध्यम से आरपी/ आईआरपी फाइल करना होगा।
18.03.21	आईबीबीआई ने आईपीज को यह निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया कि वे प्ररूप सीआईआरपी 7 के माध्यम से जारी सीआईआरपीज की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



नीतियाँ, कार्यक्रम और कार्यकलाप

संहिता के अधीन दिवाला ढांचा महत्वपूर्ण संस्थानों से युक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर टिका है। यह कारपोरेट प्रशासन को बढ़ावा देता है और आईपीए, आईपी और आईयू जैसे विभिन्न सेवा प्रदाताओं की मदद से समयबद्ध दिवाला समाधान को सक्षम बनाता है। संहिता ने पिछले चार वर्षों में एक ठोस पथ बनाने और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी संरचना को तेजी से पॉलिश करके सकारात्मक प्रगति की है। यह खंड संहिता के अधीन सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान जारी किए गए नियामक उपायों, दिशानिर्देशों, सलाह और परिपत्रों का विवरण प्रस्तुत करता है। यह खंड हितधारकों को शिक्षित करने और संहिता के उद्देश्यों और उपयोग, इसके अधीन विभिन्न नियमों के पीछे तर्क, उभरती हुई सर्वोत्तम प्रथाओं और देश के दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में आगे क्या है, के बारे में आईबीबीआई के समर्थन प्रयासों को विस्तृत करता है। आईपी और आरवी जैसे सेवा प्रदाताओं को मजबूत करने के लिए बोर्ड की विभिन्न क्षमता निर्माण पहल, सीओसी की संस्था की क्षमता वृद्धि और सरकार के विभिन्न विभागों का विवरण इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

ग.1 सेवा प्रदाता

संहिता विभिन्न दिवाला समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हितधारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई सेवा प्रदाताओं का प्रावधान करती है। उन्हें संहिता के अधीन निहित समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बनाना अनिवार्य है। जबकि संहिता ने कुछ नए पेशों और संबद्ध संस्थानों, जैसे, आईपी, आईपीई और आईपीए का निर्माण किया है, इसने कुछ अन्य लोगों, जैसे कि मूल्यांकक, लेखाकार, दिवाला और शोधन अक्षमता में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ताओं को भी पुनर्निर्मित किया है। समय के साथ संहिता के उपयोग में वृद्धि के साथ, इन व्यावसायिकों की मांग और उनकी सेवाओं के परिष्कार में वृद्धि हुई है। यह खंड सेवा प्रदाताओं अर्थात् आईपी, आईपीई, आईपीए, आरवी, आरवीओ और आईयू के लिए नियामक क्षेत्र में विकास का वर्णन करता है। यह इन व्यवसायों के विकास की स्थिति को भी प्रस्तुत करता है।

दिवाला व्यावसायिक

आईपी दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्तंभ है। वह कई अलग-अलग भूमिकाएँ निभाता है, अर्थात्, सीआईआरपी में आईआरपी या आरपी, परिसमापन प्रक्रियाओं में परिसमापक, व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाओं में आरपी और शोधन अक्षमता की कार्यवाही में शोधन अक्षमता ट्रस्टी (बीटी)। पूर्ववर्ती व्यवस्था के विपरीत, संहिता इसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्यावसायिक सेवाओं का प्रावधान करती है। आईपी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, दिवाला कानून सुधार समिति (बीएलआरसी), जिसने संहिता की अवधारणा की थी, ने कहा : "यह पूरी दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया विनियमित और लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक द्वारा प्रबंधित की जाती है, अर्थात् दिवाला

वृत्तिक या आईपी, न्यायनिर्णायक द्वारा नियुक्त किया जाता है। कानून द्वारा संचालित दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया में न्यायनिर्णायक द्वारा न्यायिक निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जांच और लेखांकन के साथ-साथ उचित प्रक्रिया का संचालन भी होता है जो आईपी द्वारा किया जाता है। दिवाला व्यावसायिक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिस पर प्रभावी, समय पर कामकाज के साथ-साथ दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के पूरे भवन की विश्वसनीयता टिकी हुई है।"

इस प्रकार, आईपी महत्वपूर्ण स्तंभ है जो संपूर्ण सीआईआरपी के प्रभावी, समय पर और विश्वसनीय कामकाज के लिए जिम्मेदार है। समाधान परिणामों को प्रशासित करने में, आईपी की भूमिका में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कानून की प्रक्रिया का पालन करना, साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन और वित्त संबंधी कार्य शामिल हैं। आईपी को संहिता के अधीन अपने दायित्वों का पालन करते हुए एक सख्त आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना कि उसके या उसकी टीम द्वारा किसी भी चल रहे सीआईआरपी पर तैनात और लागू की गई पर्याप्त प्रक्रियाएँ और नीतियाँ हैं। आईपी लेनदार-नियंत्रण में प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और एए, सीओसी और अन्य हितधारकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। निदेशक मंडल की शक्ति के साथ निहित होने और सीडी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होने के कारण, आईपी सीआईआरपी के जीवनचक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपी को व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों पर काम करना है, प्रदर्शन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है, और हर समय आईपीए, जिसके वे व्यावसायिक सदस्य हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उचित देखभाल और परिश्रम करते हैं, के उप-नियमों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ संहिता और नियमों के उपबंधों का पालन करना है।

संहिता किसी भी व्यक्ति को आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित और आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत हुए बिना आईपी के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है। इस प्रकार, आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय के प्रमुख नियामक के रूप में कार्य करता है, जबकि आईपीए अग्रिम पंक्ति के नियामक हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (आईपी विनियमन) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड), 2016 विनियमन के साथ पठित संहिता के उपबंध, दिवाला व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं।

आईबीबीआई दिवाला व्यवसाय को सक्रिय रूप से तैयार और विनियमित कर रहा है। यह कई कौशल विकास पहलों के माध्यम से व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इसने व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक स्नातक दिवाला कार्यक्रम (जीआईपी) को बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों का विवरण रिपोर्ट के खंड घ में प्रस्तुत किया गया है।

आईपी विनियमन

आम बोलचाल में, एक व्यावसायिक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार होता है। व्यवसाय का एक नियामक (राज्य, वैधानिक नियामक, या स्व-नियामक) किसी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया का पालन करने और उस व्यक्ति की योग्यता और साख से संतुष्ट होने के बाद, व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति नियामक की देखरेख में व्यवसाय का अभ्यास करता है, जो उसके अधिकार को छीन सकता है, अगर वह इसका दुरुपयोग करता पाया जाता है या एक 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' का दर्जा खो देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभ्यास को विनियमित करने का अधिकार लोगों के अपनी सुरक्षा के अधिकार से आता है।¹⁵ इसलिए, केवल उन व्यक्तियों के लिए व्यवसाय के अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाना महत्वपूर्ण है जो व्यवसाय के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। व्यक्ति व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार के लायक होने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। वह आमतौर पर ऐसा पाठ्यक्रम करता है जो उसे ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता से लैस करता है जो व्यवसाय के सदस्य के पास अधिकार की मांग करने से पहले होना चाहिए।

व्यावसायिक गतिविधि और वाणिज्यिक गतिविधि के बीच एक मूलभूत अंतर है। विनियमन व्यवसाय को वाणिज्य से अलग करते हैं और हितधारकों के हित में व्यावसायिक मानकों को निर्धारित और बनाए रखते हैं। व्यावसायिक गतिविधि व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत कौशल और बुद्धिमत्ता से की जाती है।¹⁶ इसमें वाणिज्यिक गतिविधि के मुकाबले कुछ निश्चित मात्रा में कौशल शामिल है जहां यह कुछ बातों या व्यापारिक गतिविधि से अधिक महत्व रखती है। वाणिज्यिक गतिविधि में कोई लाभ या लाभ के लिए काम करता है और इसके विपरीत, व्यवसाय में, अपनी आजीविका के लिए काम करता है।¹⁷ नियामक व्यवसाय के सदस्यों के लिए व्यावसायिक और नैतिक आचरण के मानकों को निर्धारित करता है।

23 नवंबर, 2016 को अधिसूचित आईपी विनियमन में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईपी के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और निरीक्षण का प्रावधान करते हैं। 01 दिसंबर 2016 को संहिता के प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए एक तत्काल उपाय के रूप में, आईपी विनियमनों में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों, लागत लेखाकारों और अधिवक्ताओं को आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की अनुमति दी गई, जो 15 वर्षों से अभ्यास कर रहे थे। हालांकि, रजिस्ट्रीकरण के लिए यह विंडो 31 दिसंबर, 2016 तक उपलब्ध थी और इस तरह के रजिस्ट्रीकरण छह महीने की सीमित अवधि के लिए, यानी 30 जून, 2017 तक वैध थे। इसने नियमित व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। आईपी विनियमनों में अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों और लागत लेखाकारों को 10 साल की सदस्यता के बाद के अनुभव (अभ्यास या रोजगार) और स्नातकों को 15 साल के बाद योग्यता प्रबंधकीय अनुभव के साथ सीमित दिवाला परीक्षा इतिहास) पास करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की अनुमति दी गई।

उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आईबीबीआई ने समय-समय पर आईपी विनियमनों में संशोधन किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपी और आईपीई को कोविड-19 के मद्देनजर आईपी विनियमनों में निर्धारित विभिन्न समय-सीमा का पालन करना मुश्किल हो सकता है, इसने आईपी नियमों में संशोधन किया और 28 मार्च, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अंतिम तिथि बढ़ा दी। 30 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020

तक वर्ष 2019-20 के लिए शुल्क का भुगतान। इसने आईपीई को बोर्ड को अपने निदेशकों/भागीदारों की नियुक्ति की तारीख से नियुक्ति और समाप्ति के बारे में ऐसी नियुक्ति/या समाप्ति सूचित करने के लिए 30 दिनों तक का समय दिया।

सुविधा नोट्स

परिसमापन प्रक्रिया आयोजित करने वाले आईपी हेतु

परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करने वाले आईपी के लिए एए, एनसीएलएटी और उच्च न्यायालयों ने अपने आदेशों और निर्णयों के माध्यम से परिसमापकों को परिसमापन प्रक्रिया के संचालन में निर्देशित किया है। आईबीबीआई ने 05 अगस्त, 2020 को एक सुविधा नोट जारी किया, जिसमें इन आदेशों और निर्णयों से कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों और टिप्पणियों को सूचीबद्ध किया गया था, जो एक आईपी को उपयोगी लग सकता है। इन्हें छह व्यापक श्रेणियों अर्थात्, परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करना, परिसमापन संपत्ति का दायरा, संपत्ति की बिक्री, संलग्नक, मामलों का प्रबंधन, और शक्तियां और कर्तव्य के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

परिहार लेनदेन संबंधी आईपी हेतु

विनियमनों के साथ पठित संहिता आरपी और परिसमापक को यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य करती है कि क्या सीडी पूर्व में अधिमान्य लेनदेन, धोखाधड़ी लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, और जबरन लेनदेन जैसे परिहार लेनदेन के अधीन है, और यदि ऐसा है, तो उस पर एक दायित्व डालता है उचित दिशा-निर्देशों के लिए एए को आवेदन फाइल करें। परिहार लेनदेन के संबंध में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए एक आईपी की मदद करने के लिए, आईबीबीआई ने 07 अगस्त, 2020 को 'परिहार लेनदेन - लाल ध्वजा' के बारे में सुविधा नोट जारी किया ताकि आईपी को उन स्थितियों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके जो परिहार लेनदेन की समीक्षा और परिणामी आवेदन के लिए योग्यता होगी। ए.ए. यह नोट लाल ध्वजों को छह व्यापक श्रेणियों अर्थात्, (क) इकाई, समूह और संचालन, (ख) पुस्तकों और अभिलेखों का रखरखाव, (ग) नियामक अनुपालन और वाद, (घ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट, (ड.) वित्तीय विवरण और बोर्ड रिपोर्ट, और (च) धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग (जैसा कि आरबीआई मास्टर निर्देशों के अधीन कवर किया गया है) के अधीन रखता है।

आईपी द्वारा की गई गलतियाँ

आईबीबीआई और आईपीए को सीआईआरपी के संचालन में कुछ आईपी द्वारा की जा रही कुछ गलतियों का पता चला है। ये गलतियाँ सीडी और अर्थव्यवस्था की लागत हैं, और अक्सर कानून के उपबंधों का उल्लंघन होती हैं। इनमें से अधिकांश शायद अनजाने में होते हैं और थोड़ी अधिक सतर्कता, देखभाल और परिश्रम से इनसे बचा जा सकता है। आईबीबीआई ने 13 नवंबर, 2020 को सुविधा नोट जारी किया, जिसमें सीआईआरपी के संचालन में आईपी द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों को इस उम्मीद के साथ सूचीबद्ध किया गया था कि ऐसी गलतियाँ नहीं की जाएंगी।

आईपी का पैनेल

जून, 2017 से, आईबीबीआई द्वारा आईआरपी और परिसमापक के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी के छह-मासिक बैंच-वार पैनेल तैयार कर रहा

¹⁵ ब्राउन, लियोनेल, (1935), "राज्य द्वारा व्यवसायों का विनियमन - विनियमन का अधिकार, इसके कारण, उपयोग में तरीके, और नियामक निकायों और न्यायालयों के दृष्टिकोण, संबंध के साथ", कैल वेस्ट मेड।, अगस्त, 43 (2), पीपी. 119-23.

¹⁶ उच्चतम न्यायालय, अध्यक्ष, म.प्र. इलेक्ट्रिक बोर्ड और बनाम। शिव नारायण और अन्य, अपील (2000 का सिविल संख्या 1065)।

¹⁷ उच्चतम न्यायालय, एलएम चीतला बनाम श्रम आयुक्त (एआईआर 1964 मद्रास 131, 133)।

है और दिशानिर्देशों के अनुसार इसे एए के साथ अग्रिम रूप से साझा कर रहा है। एए सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया के लिए आईआरपी या परिसमापक की नियुक्ति के लिए पैनल से कोई भी नाम ले सकता है। इससे दिवाला प्रक्रिया में काफी समय की बचत होती है।

आईबीबीआई ने 01 जुलाई, 2020 से 25 नवंबर, 2020 तक नियुक्तियों के लिए जोन-वार पैनल तैयार करने के लिए 02 जून, 2020 को दिवाला व्यावसायिकों की जगह अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2019 के रूप में काम करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों को जारी किया। तदनुसार, आईपी का पैनल 25 जून, 2020 को तैयार किया गया। 26 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक नियुक्तियों के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन आईपी का एक और पैनल 23 नवंबर, 2020 को तैयार किया गया।

आईबीबीआई ने जनवरी-जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए जोन-वार पैनल की तैयारी को नियंत्रित करने के लिए 23 नवंबर, 2020 को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों को जारी किया।

सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति का प्रावधान है। अप्रैल, 2019 से, आईबीबीआई हर छह महीने में प्रशासकों के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी के क्षेत्र-वार पैनल तैयार कर रहा है और दिशानिर्देशों के अनुसार इसे सेबी के साथ अग्रिम रूप से साझा कर रहा है। इसने अक्टूबर, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के पैनल की तैयारी के लिए 5 सितंबर, 2020 को सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन प्रशासक के रूप में दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसी तरह, इसने 9 मार्च, 2021 को अप्रैल-सितंबर, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी के पैनल तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

पूर्व रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम

आईपीएज अपने सदस्यों के लिए पूर्व-रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर, यात्रा प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण आईपीएज के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम देना और कक्षा मोड के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा जारी रखना मुश्किल हो गया था। आईबीबीआई ने शुरू में आईपीए और संभावित आईपी के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए आईपीए को ऑनलाइन पाठ्यक्रम देने की अनुमति दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी शिक्षा के क्लास-रूम डिलीवरी के रूप में प्रभावी है, आईबीबीआई ने 10 जुलाई, 2020 को आईबीबीआई (इन्वॉल्वमेंट प्रोफेशनल एजेंसियों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन डिलीवरी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए, जो 31 मार्च, 2021 तक लागू थे। ये दिशानिर्देश तकनीकी आवश्यकताओं, प्रशासन और अनुपालन जिम्मेदारी जैसे विभिन्न पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। इसके अलावा, इसने महामारी की स्थिति को देखते हुए 11 मार्च, 2021 की अधिसूचना के अधीन इन दिशानिर्देशों को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।

दिवाला व्यावसायिक एंटीटीज

आईपीई एक संस्थागत व्यवस्था है जो आईपीज को संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करने के लिए सक्षम बनाता है ताकि इस शर्त के अध्यक्षीन कि आईपीई संयुक्त रूप से अथवा समस्त रूप से आईपी के रूप में इसके साझेदारों अथवा निदेशकों की भूल-चूक के लिए उत्तरदायी होगी, इनमें से किसी एक को समर्थन सेवाएं प्रदान कर सके। संहिता के अधीन, कोई आईपीई, आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। एक एलएलपी जो रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म और कंपनी है, को आईपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि (क) इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी आईपीज को सहारा प्रदान करना है जो इसकी साझेदार अथवा निदेशक हैं, (ख) इसका निवल मूल्य एक करोड़ रुपये से कम नहीं है; (ग) इसके अधिकांश शेयर आईपीज द्वारा धारित हैं, जो इसके निदेशक हैं, अथवा अधिकांश पूंजीगत योगदान आईपीज द्वारा किया जाता है जो इसके साझेदार हैं; (घ) इसके अधिकांश साझेदार अथवा निदेशक आईपीज हैं; (ङ) यदि यह कंपनी है तो इसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक आईपीज हैं; और (च) इसका कोई साझेदार या निदेशक, किसी अन्य आईपीई का साझेदार या निदेशक नहीं है।

आईबीबीआई ने आईपीई के संबंध में आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर आईपी विनियमनों में संशोधन किए हैं। इसने किसी आईपीई को किसी अन्य आईपी को समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 30 जून, 2020 की अधिसूचना द्वारा आईपी विनियमनों में संशोधन किए हैं। इस संशोधन से पूर्व, आईपीई केवल ऐसे आईपीजको समर्थन सेवाएं प्रदान कर सकती थी, जो उसका साझेदार या निदेशक था। इससे दिवाला सेवाओं का व्यावसायीकरण करने और आईपीज की पहुंच विनियमित समर्थन सेवाओं तक हो जाएगी।

दिवाला व्यावसायिक अभिकरण

दिवाला व्यवस्था में आईपी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, संहिता में दो-स्तरीय विनियमित स्व-विनियमन की परिकल्पना की गई है, जिसमें आईपीए, फ्रंट-लाइन नियामक के रूप में और आईबीबीआई, आईपी के प्रमुख नियामक के रूप में शामिल हैं। आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां) विनियमन, 2016 (आईपीए विनियमन) आईपीए के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन को नियंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के पास आईपीए के कार्यों को करने का एकमात्र उद्देश्य है और न्यूनतम निवल मूल्य रु 10 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 5 करोड़ आईपीए बनने के योग्य हैं। आईपीए की शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के पास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, आईपीए में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेगा। हालांकि, कुछ संस्थाएँ, अर्थात्, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, प्रति व्यक्ति आईपीए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 15 प्रतिशत तक का अधिग्रहण या धारण कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सांविधिक नियामक किसी आईपीए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या धारण कर सकते हैं। आईपीए, उसके प्रवर्तकों, उसके निदेशकों और शेयरधारकों को 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति होने की आवश्यकता है।

उप-नियमों के विनियमनों के लिए आदर्श उप-नियमों के अनुरूप उप-नियमों को अपनाने के लिए आईपीए की आवश्यकता होती है। एक

आईपीए के जीबी में एमडी, स्वतंत्र निदेशक और शेयरधारक निदेशक होते हैं। एमडी को या तो एक स्वतंत्र निदेशक या शेयरधारक निदेशक के रूप में नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अधिकतम दो कार्यकालों के लिए तीन वर्ष या उसके भाग के लिए, या पचहत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा कर सकता है। एक आईपीए, आईबीबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, योग्यता और अनुभव, नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति के नियम और शर्तें और एमडी के चयन और नियुक्ति से जुड़ी अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का निर्धारण करता है। एमडी की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण और सेवा की समाप्ति आईबीबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी। एमडी सदस्यता समिति, निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति और अनुशासन समिति (डीसी) के एक पदेन सदस्य हैं।

वर्तमान में आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत तीन आईपीए अर्थात् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई), आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईसीएसआई आईआईपी) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईपीए आईसीएआई) का आईपीए हैं।

आईबीबीआई ने 28 मार्च, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से मॉडल उप-नियम विनियमनों में संशोधन किया, जिससे आईपी) को उसी के लिए आवेदन करने की तारीख से एक महीने के भीतर एएफए जारी करने की अनुमति मिली। इसने इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर एएफए आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के समय में और ढील दी। इसने 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से आईपीए विनियमनों में और संशोधन किया, जिससे आईपीए के जीबी को किसी व्यक्ति के शेयरधारक निदेशक बनने के लिए पात्रता मानदंड निदिष्ट करने में सक्षम बनाया गया। यह साल के बंद होने के तीन महीने के भीतर हर साल जीबी के स्व-मूल्यांकन का प्रावधान करता है। यह आवश्यक है कि एक आईपीए एक अनुपालन अधिकारी को नामित या नियुक्त करेगा, जो संहिता के प्रावधानों और नियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और उसके अधीन जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह, तुरंत और स्वतंत्र रूप से, बोर्ड को प्रावधानों के गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करेगा।

आईबीबीआई हर महीने की 7 तारीख को विषय विशिष्ट बैठकों के अलावा, विकास को साझा करने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईपीए के एमडी से बैठक करता है। आईपीए अपने सदस्यों के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी कर रहे हैं और अपने सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जो संहिता/विनियमनों के उपबंधों का पालन नहीं करते हैं।

सूचना उपयोगिताएं

दिवाला कार्यवाही की सफलता गंभीर रूप से देनदार के बारे में पूर्ण, सही और अद्यतित जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह जानकारी प्रत्येक हितधारक के पास समान माप में उपलब्ध नहीं हो सकती है। जानकारी की अनुपलब्धता समाधान में बाधा डाल सकती है और मूल्य अधिकतमकरण के उद्देश्य से समझौता कर सकती है, जबकि सूचना की विशमता मूल्य के असमान बंटवारे में योगदान कर सकती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आईयू को देनदारों के बारे में वित्तीय जानकारी के भंडार के रूप में परिकल्पित करता है। वित्तीय जानकारी के संबंध में मुख्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आईयू की आवश्यकता होती है। आईयू, जैसा कि संहिता के अधीन कल्पना और कार्यान्वित किया गया है, दुनिया में कहीं भी समानांतर नहीं है।

विभिन्न प्रक्रियाओं में एक आईयू की सेवाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आईयू विनियमनों के साथ पठित संहिता आईयू के रूप में पंजीकरण के लिए कड़े मानदंड प्रदान करता है। आईयू के पास : (क) संहिता के अधीन मुख्य सेवाएं प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य, (ख) रुपये का न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य, (ग) प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के रूप में 'उचित और समुचित' व्यक्ति, (घ) स्वतंत्र निदेशक जो जीबी के 50 प्रतिशत से कम नहीं हैं, (ङ.) निर्दिष्ट शेयरधारिता मानदंड (च) व्यापार निरंतरता योजनाओं के साथ सूचना प्रवाह के लिए विश्वसनीय और वसूली योग्य सुरक्षित प्रणाली, (छ) डेटा प्रक्रिया प्रणाली जो अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण या सूचना के प्रसार को रोकती है, (ज) जानकारी की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने की कार्यक्षमता और (झ) तकनीकी मानकों के अनुपालन में इसका संचालन होना चाहिए।

जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने और दावों और व्युत्क्रमों के बारे में विवादों को रोकने के लिए, संहिता अनिवार्य करती है कि ऐसी जानकारी संबंधित पक्षों द्वारा प्रमाणित की जाए। तकनीकी मानकों का सेट, सूचना प्रस्तुत करने, सूचना के प्रमाणीकरण, डेटा अखंडता आदि पर लागू होता है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आईयू के साथ जानकारी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। व्यतिक्रम की जानकारी की स्थिति दर्ज करने के बाद, आईयू रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रमाणीकरण की स्थिति के बारे में बताता है, जो हैं: (क) देनदार के लेनदार जिन्होंने व्यतिक्रम किया है, और (ख) पक्षों और जमानत, यदि कोई हो, में ऋण के लिए जिसके संबंध में व्यतिक्रम की सूचना प्राप्त हुई है।

संहिता 'वित्तीय जानकारी' को कुछ रिकॉर्ड और 'ऐसी अन्य जानकारी जिसे निदिष्ट किया जा सकता है' के लिए परिभाषित करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, आईबीबीआई ने वित्तीय जानकारी के रूप में संहिता के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा को निर्दिष्ट करने के लिए 13 नवंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017 (आईयू विनियमन) में संशोधन किया। इसने आईयू को अपने रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक घोषणा का प्रसार करने के लिए अनिवार्य किया, जो दिवाला कार्यवाही से गुजर रहे सीडी के लेनदार हैं। यह विनियमनों में आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों और वेबसाइटों में सार्वजनिक घोषणा को प्रकाशित करने के अतिरिक्त है।

तकनीकी मानक

आईयू विनियमन, आईबीबीआई को तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, आईयू द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए दिशानिर्देशों के माध्यम से तकनीकी मानकों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तकनीकी मानक आईयू द्वारा संग्रहीत की जाने वाली वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तदनुसार, बोर्ड ने 4 मई, 2017 को एक तकनीकी समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने 13 दिसंबर, 2017 को तकनीकी मानकों को निर्धारित किया। ये मानक सेवा की शर्तों से संबंधित हैं; उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण; प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता; जानकारी प्रस्तुत करना; व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन; सूचना का प्रमाणीकरण; सूचना का सत्यापन; आंकड़ा शुचिता; तीसरे पक्ष को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति ढांचा; प्रणाली की सुरक्षा; सूचना की सुरक्षा; जोखिम प्रबंधन ढांचा; सूचना का संरक्षण; और जानकारी का शुद्धिकरण। 31 मार्च, 2021 को तकनीकी समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क) डॉ. आर. बी. बर्मन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, अध्यक्ष के रूप में

(ख) डॉ. नंद लाल सारदा, एमेरिटस फेलो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

(ग) डॉ. पुलक घोष, प्रोफेसर, आईआईएम, बैंगलोर, और

(घ) श्री वी.जी. कन्नन, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)।

तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, जमाकर्ता को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, और आधार पत्र/

कार्ड या ई-आधार (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पत्र) प्रदान करने का विकल्प दिया जाता है।

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य द्वारा प्रवर्तित एनईएसएल को 25 सितंबर, 2017 को आईबीबीआई द्वारा आईयू के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया। सारणी 2 31 मार्च, 2021 तक एनईएसएल द्वारा रखी गई जानकारी का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 2 : एनईएसएल के पास जानकारी का विवरण

(संख्या, यथावर्णित को छोड़कर)

वर्ष/माह के अंत में	एनईसीएल के साथ समझौते वाले लेनदार		सूचना प्रस्तुत करने वाले लेनदार		देनदार जिनकी सूचना द्वारा प्रस्तुत की गई है		द्वारा ऋण रिकार्ड दर्शाए गए		शेष ऋण की राशि (करोड़ रुपये)		प्रयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण	देनदार द्वारा प्रत्याशित ऋण रिकार्ड		देनदार द्वारा व्यतिक्रम प्रमाणित
	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	वित्तीय	संक. गिरीत	देनदारों की संख्या	रिकॉर्ड की संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	
2018-19	173	उ. न.	114	169	1266445	230	1955230	316	4114988	16224	15148	13799	48,428	54
जून, 2019	209	उ. न.	160	231	2531930	570	3911146	52766	4910552	20455	23565	22363	73,706	374
सितंबर, 2019	226	उ. न.	218	297	2737049	1764	4421280	86766	5625318	28016	32177	35621	83,686	586
दिसंबर, 2019	246	उ. न.	321	408	2926030	2121	4803931	125526	6919463	32038	48551	68766	93,852	82,824
मार्च, 2020	267	उ. न.	381	543	6551739	6191	9417317	167719	7873689	31910	73332	109726	118428	2,40,075
जून, 2020	269	उ. न.	456	574	7464854	8336	10721829	204568	9855538	33151	106840	149533	299294	3,38,585
सितंबर, 2020	276	उ. न.	548	635	8228576	8979	12126772	206957	12299081	34374	120896	186091	373678	4,27,226
दिसंबर, 2020	284	उ. न.	587	654	8572919	9024	13666166	253955	12875496	35803	129839	215015	451935	4,35,774
मार्च, 2021	289	उ. न.	621	675	8988348	9066	14565545	292206	13195075	36770	139908	283839	499957	4,42,584

उ. न. : उपलब्ध नहीं

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 (मूल्यांकन नियम) मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं, हालांकि इसका प्रेषण संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक मूल्यांकन तक सीमित है। हालांकि, यह ढांचा, कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के अधीन मूल्यांकन के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। 01 फरवरी, 2019 से, एक आईपी द्वारा केवल आरवी को संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन किसी भी मूल्यांकन का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

मूल्यांकन नियम मोटे तौर पर दिवाला व्यवसाय के मॉडल का पालन करते हैं। निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को आरवीओ के साथ नामांकन करने, आरवीओ द्वारा संचालित शैक्षिक पाठ्यक्रम को पूरा करने, आईबीबीआई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने और बाद में आईबीबीआई के साथ मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता है। एक इकाई (साझेदारी फर्म और कंपनी) भी मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। मूल्यांकन नियम आरवी के लिए मूल्यांकन मानकों और आचार संहिता का भी प्रावधान करते हैं। आईबीबीआई मूल्यांकन नियमों के अधीन प्राधिकरण के कार्य करता है। यह आरवीओ को पहचानता है और मूल्यांककों को रजिस्ट्रीकृत करता है और उन पर निगरानी रखता है। इसने सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और

मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए हितधारकों के परामर्श से मूल्यांकन परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति को प्रकाशित किया है। यह 31 मार्च, 2018 से सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए देश भर के कई स्थानों से हर दिन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसमें तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया गया है, जो आरवीओ के सदस्य के लिए मूल्यांकन परीक्षा लेने से पहले पूरा करना आवश्यक है। जबकि कुछ विश्वविद्यालय मूल्यांकन में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, आईबीबीआई ने दो परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन और (ख) संयंत्र और मशीनरी के लिए विस्तृत, विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री जिसे सेंटर फॉर वैल्यूएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन (सीवीएसआरटीए) द्वारा तैयार किया गया था, उपलब्ध कराई थी। अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं द्वारा मुफ्त डाउनलोड के लिए। इसने आईओवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स फाउंडेशन द्वारा 14 मई, 2019 को अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं द्वारा मुफ्त डाउनलोड के लिए तैयार की गई संपत्ति वर्ग, प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई।

13 अगस्त, 2019 को, आईबीबीआई ने दोहराया कि (क) 01 फरवरी, 2019 को या उसके बाद आरवी के अलावा किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन किसी भी मूल्यांकन का संचालन करने के लिए अवैध है और कानून का उल्लंघन है; और (ख) किसी भी मूल्यांकन के लिए आरवी के अलावा किसी भी व्यक्ति को भुगतान, चाहे शुल्क के रूप में या अन्यथा, आईआरपीसी या परिसमापन लागत का

हिस्सा नहीं होगा। आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2019 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है जिसके अधीन हितधारकों के तैयार संदर्भ के लिए आरवी द्वारा मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

मूल्यांकन रिपोर्ट में चेतावनियों, सीमाओं और अस्वीकरणों का उपयोग

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2016 में कहा गया है कि आरवी उस सीमा तक 'चेतावनी, सीमाएं और अस्वीकरण' बताएंगे, जिस सीमा तक वे मूल्यांकक को पेश आई सीमाओं की व्याख्या या उन्हें स्पष्ट करते हैं, लेकिन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए उनकी जिम्मेदारी को सीमित नहीं करेंगे। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई अस्वीकरण नहीं है, जिसमें आरवी की जिम्मेदारी को कम करने या मूल्यांकन को उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बनाने की क्षमता है जिसके लिए इसे आयोजित किया गया था।

आईबीबीआई ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और आरवीओ के परामर्श से, 01 सितंबर, 2020 को आईबीबीआई (मूल्यांकन रिपोर्ट में चेतावनी, सीमाएं और अस्वीकरण का उपयोग) दिशानिर्देश, 2020 जारी किये ताकि आरवी को 'चेतावनी' के उपयोग में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। मूल्यांकन रिपोर्ट की विश्वसनीयता के हित में, सीमाएं और अस्वीकरण'। ये चेतावनियों, सीमाओं और अस्वीकरणों की एक उदाहरणात्मक सूची भी प्रदान करते हैं जिनका उपयोग मूल्यांकन रिपोर्ट में नहीं किया जाएगा। 01 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद आरवी द्वारा पूरा किए जाने वाले मूल्यांकन की मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में दिशानिर्देश लागू हुए।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 03 नवंबर, 2020 के माध्यम से 10 मार्च, 2017 के अपने परिपत्र को संशोधित किया, जो सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यवस्था की योजनाओं (एसओए) के लिए रूपरेखा तैयार करता है। संशोधन के लिए सभी सूचीबद्ध संस्थाओं एस ओ ऐ में आरवी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आरवी एक ऐसा व्यक्ति है, जो आरवीओ का सदस्य होने के नाते, नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है।

शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा

मूल्यांकन नियमों की आवश्यकता है कि एक आरवीओ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करेगा। इसके अनुसरण में, आईबीबीआई, प्राधिकरण होने के नाते, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है और समय-समय पर इसकी समीक्षा करता रहा है। इसने निर्दिष्ट किया है कि, 01 अप्रैल, 2019 से मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए प्रभावी, शैक्षिक पाठ्यक्रम एक आरवीओ द्वारा कक्षा मोड में कम से कम 50 घंटे में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, नियमों को अपने सदस्यों को सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आरवीओ की आवश्यकता होती है। 07 फरवरी, 2019 को आयोजित आरवीओ के सीईओधर्मडी की 12वीं मासिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सतत शिक्षा कक्षा मोड में आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के मद्देनजर विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी की गई सलाह ने आरवीओ के लिए कक्षा सत्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा देना मुश्किल बना दिया। आरवी और मूल्यांकक सदस्यों के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए, आईबीबीआई ने निर्णय लिया कि ऑनलाइन पूर्ण किए गए शैक्षिक पाठ्यक्रम, और ऑनलाइन जारी शिक्षा को वैध माना जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिजीवरी शिक्षा के क्लास-रूम डिजीवरी के रूप में प्रभावी है, आईबीबीआई ने 10 जुलाई, 2020 को आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और सतत व्यावसायिक शिक्षा की ऑनलाइन डिजीवरी) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए, जो 31 मार्च, 2021 तक लागू था। ये दिशानिर्देश तकनीकी आवश्यकताओं, प्रशासन और अनुपालन जिम्मेदारी जैसे विभिन्न पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। इसके अलावा, इसने महामारी की स्थिति को देखते हुए 11 मार्च, 2021 की अधिसूचना के अधीन इन दिशानिर्देशों को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

मूल्यांकन नियमों में मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए आरवीओ को अग्रिम पंक्ति के नियामकों के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। वे आरवी के निरीक्षण, विकास और विनियमन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करते हैं। वे मूल्यांककों को सदस्यता प्रदान करते हैं जो मूल्यांकन नियमों में प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों का पालन करते हैं, मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और सीओपी जारी होने से पहले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे व्यावसायिक आचरण के मानक भी निर्धारित करते हैं और मानकों के पालन के लिए अपने सदस्यों की निगरानी करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके सदस्यों द्वारा मूल्यांकन नियमों के अनुपालन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

सदस्यता का अंतरण

मूल्यांकन नियम आरवीओ के एक प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करते हैं, जहां वे उपयोगकर्ताओं और मूल्यांकन सेवाओं के अन्य हितधारकों के हित में अपने व्यावसायिक सदस्यों के माध्यम से बेहतर मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनमें यह भी परिकल्पना की गई है कि एक सदस्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अधीन सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे में अंतरित सकता है। मूल्यांकन नियमों में अपने सदस्यों के नामांकन और विनियमन के लिए उचित, उचित, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं को नियोजित करने के लिए एक आरवीओ की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह देखा गया था कि कुछ आरवीओ लंबी रणनीति, अनुचित हस्तांतरण शुल्क आदि का उपयोग करके सदस्यता के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर रहे थे। आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2020 के परिपत्र के माध्यम से एक आरवीओ से दूसरे में सदस्यता के हस्तांतरण, और आरवी और आरवीओ द्वारा विशिष्ट कार्रवाइयों के लिए समय-सीमा की प्रक्रिया को रेखांकित किया। यदि स्थानांतरण के लिए आवेदन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, तो आरवीओ आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति जारी करेगा। यदि आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आरवीओ-1 से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आरवीओ ने सदस्यता के हस्तांतरण पर अनापत्ति जारी की है।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की शासन संरचना

मूल्यांकन नियम आरवीओ के जीबी की संरचना और उसकी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन के तरीके को निर्धारित करते हैं। आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तक संगठन का कोई सदस्य, जिसने आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ का स्वतंत्र निदेशक बनने के योग्य नहीं होगा। एक प्रवर्तक संगठन में इसके सदस्य हो सकते हैं – प्रवर्तक एक कंपनी के मामले में शेरधारक सदस्य, प्रवर्तक के मामले में ट्रस्टी व्यक्तियों / ट्रस्ट, या एक व्यावसायिक सदस्य के मामले में प्रवर्तक एक व्यावसायिक निकाय है –

जीबी पर निदेशक के रूप में आरवीओ की। हालांकि, ऐसे निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

आरवीओ की अनुशासनात्मक समिति और अपीलीय पैनल

अनुशासन समिति (डीसी) और अपीलीय पैनल (एपी) की बैठकों के संचालन में आरवीओ विभिन्न प्रथाओं का पालन कर रहे थे। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आरवीओ को सलाह दी गई थी कि डीसी और एपी की बैठकें तभी आयोजित की जाएं जब बैठक के लिए कोई एजेंडा होय बैठकें वीसी के माध्यम से अधिमानतः आयोजित की जानी चाहिए, बैठक के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाना चाहिए, बैठक के दौरान उपस्थित समिति

के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे आईबीबीआई के नामितों का कार्यकाल सामान्यतः नियुक्ति आदि की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा।

परिपत्र

बोर्ड समय-समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी के लिए परिपत्र जारी करता है ताकि इसके निगरानी कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके, संहिता और विनियमनों के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके, या विनियमनों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट या समझाया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 3 में सूचीबद्ध हैं।

सारणी 3 : बोर्ड द्वारा 2020-21 में जारी परिपत्र

तारीख	सामग्री
23.04.20	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की शासन संरचना परिपत्र एक स्वतंत्र निदेशक की योग्यता को स्पष्ट करता है कि प्रवर्तक संगठन का एक सदस्य, जिसने एक आरवीओ को बढ़ावा दिया है, आरवीओ के एक स्वतंत्र निदेशक होने के योग्य नहीं होगा।
09.10.20	आरवीओ की अनुशासनात्मक समिति और अपीलीय पैनल परिपत्र डीसी और एपी की बैठकों के संचालन में आरवीओ के बीच सामान्य अभ्यास सुनिश्चित करता है।
29.10.20	बोर्ड को सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की प्रति प्रस्तुत करना। दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायिक प्राधिकारी के लिए आवेदन) नियम, 2016 के नियम 4(3), 6(2) और 7(2) के अधीन आवेदक को अन्य बातों के साथ-साथ आईबीबीआई को सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन की एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया गया है। आवेदकों की सुविधा के लिए, आईबीबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, आवेदक को पावती मिलेगी।
27.11.20	लेनदारों की सूची दाखिल करना। सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 13 के उप-विनियमन (2) के खंड (सीए) में आईआरपी या आरपी को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए आईबीबीआई के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदारों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। उसी के अनुसरण में, आईबीबीआई ने लेनदारों की सूची दाखिल करने के साथ-साथ उसके अद्यतन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध कराया। प्लेटफ़ॉर्म आईआरपी या आरपी द्वारा कई फाइलिंग की अनुमति देता है जब और जब लेनदारों की सूची उसके द्वारा अपडेट की जाती है।
06.01.21	सीआईआरपी से संबंधित अभिलेखों का प्रतिधारण। विनियमनों के साथ पठित संहिता को उसके द्वारा किए गए असाइनमेंट के संबंध में कई रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक आईपी की आवश्यकता होती है। सीआईआरपी विनियमनों का विनियमन 39क आईआरपी और आरपी को आईपीए के परामर्श से बोर्ड द्वारा सूचित रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार सीआईआरपी से संबंधित रिकॉर्ड की एक भौतिक और साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति संरक्षित करना अनिवार्य करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईपीए के परामर्श से, आईबीबीआई ने आईपी को कम से कम आठ साल की अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड की भौतिक प्रति संरक्षित करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि आईपी सीआईआरपी की उस अवधि से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करेगा जब उसने आईआरपी या आरपी के रूप में कार्य किया, भले ही उसने इसके प्रारंभ से असाइनमेंट नहीं लिया था या इसके समापन तक असाइनमेंट जारी रखा था। इसके अलावा, आईपी सुरक्षित स्थान पर रिकॉर्ड को संरक्षित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अनधिकृत व्यक्तियों की उस तक पहुंच न हो। भंडारण के स्थान और तरीके के बावजूद, आईपी को संहिता और विनियमनों के अधीन आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
02.02.21	पीजी के लिए सीडी को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड को आवेदन की प्रति उपलब्ध करना। दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 9 में अपेक्षित है कि आवेदक के साथ साथ, बोर्ड को इसके रिकॉर्ड के लिए सीडी के लिए पीजी की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदकों की सुविधा के लिए, आईबीबीआई ने बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए अपनी वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई है।
04.03.21	हितधारकों की सूची दाखिल करना। आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के लिए परिसमापक को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता है। परिपत्र के माध्यम से आईपी को संबंधित सीडी के हितधारकों की सूची तैयार करने या उसके संशोधन के तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में परिसमापन और संशोधन के अधीन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। सुविधा के लिए, बोर्ड ने हितधारकों की सूची दाखिल करने के साथ-साथ इसे अद्यतन करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक सुविधा उपलब्ध कराई है।
18.03.21	प्रारूप सीआईआरपी 7 के माध्यम से जारी सीआईआरपी की स्थिति की रिपोर्टिंग। सीआईआरपी विनियमनों का विनियमन 40क, सीआईआरपी में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए मॉडल समयरेखा प्रदान करता है। इसके अलावा, सीआईआरपी विनियमनों के सीआईआरपी विनियमन 40ख की प्रगति की निगरानी के लिए विशिष्ट गतिविधियों के पूरा होने के सात दिनों के भीतर आईआरपी / आरपी को प्रपत्रों का एक सेट (सीआईआरपी 1 से सीआईआरपी 6) दाखिल करने की आवश्यकता होती है। परिपत्र आईआरपी/आरपी फाइल प्रारूप सीआईआरपी 7 को नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर निर्देशित करता है, जहां सार्वजनिक घोषणा, आरपी की नियुक्ति, सूचना ज्ञापन जारी करना (आईएम), समाधान योजना के लिए अनुरोध (आरएफआरपी), और संहिता और विनियमनों में निहित समय-सीमा के भीतर सीआईआरपी को बंद नहीं किया गया है।

ग.2 : प्रक्रियाएं

संहिता में कारपोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए चार प्रक्रियाओं का प्रावधान है, अर्थात् सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और भाग-II के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया। ये प्रक्रियाएं 2016 और 2017 में लागू हुई हैं। यह व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता के लिए तीन प्रक्रियाएं, अर्थात् भाग-III के अधीन नई शुरुआत प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया भी प्रदान करता है। केवल पीजी से सीडी तक दिवाला समाधान प्रक्रिया और दिवाला प्रक्रिया लागू हुई है। यह उप-खंड समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में नियामक विकास को सूचीबद्ध करता है।

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

सीआईआरपी बाजार को समाधान योजना के माध्यम से तनाव को हल करने का पहला प्रयास करने में सक्षम बनाती है जिससे कंपनी जीवित रहती है। जब बाजार यह निश्कर्ष निकालता है कि कंपनी को बचाने के

लिए कोई व्यवहार्य और व्यवहार्य समाधान योजना नहीं है या बचाव की तुलना में परिसमापन मूल्य को अधिकतम करता है, तो कंपनी परिसमापन के लिए आगे बढ़ती है। इस प्रकार, संहिता तनाव के समाधान के दो तरीकों को सक्षम बनाता है, पहला एक समाधान योजना द्वारा, जिसमें विफल होने पर, परिसमापन द्वारा। बाजार आमतौर पर एक व्यवहार्य कंपनी को बचाता है और एक अव्यवहार्य कंपनी को समाप्त कर देता है। परिसमापन या बचाव बाजार की ताकतों का परिणाम है। कानून केवल विकल्प देने वाला और मूल्य अधिकतम करने वाले परिणामों की ओर संकेत करने वाला है। हितधारक निर्णय लेते हैं कि क्या समाधान लेना है और यदि हां, तो समाधान का तरीका। वे विभिन्न विकल्पों का वजन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प चुनते हैं।

सीआईआरपी विनियमन, जो 01 दिसंबर 2016 से परिचालन में हैं, कारपोरेट व्यक्तियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हितधारकों के परामर्श से बाजारों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर इनमें संशोधन किया गया है। सारणी 4 2020-21 में सीआईआरपी विनियमनों में विभिन्न संशोधनों और उसी के औचित्य को प्रस्तुत करती है।

सारणी 4 : 2020-21 के दौरान सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन

अधिसूचना की तारीख	संशोधन
20.04.20	<p>प्ररूप भरने की तारीख का विस्तार : संशोधन में जमा करने की नियत तारीख के बाद प्ररूप भरने की तारीख को 30 सितंबर, 2020 तक सुधार, अद्यतन या अन्यथा बढ़ाने का प्रावधान है। 01 अक्टूबर, 2020 के बाद प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए प्रति प्ररूप 500 रुपये के शुल्क के साथ जमा किया जाएगा।</p> <p>लॉकडाउन की अवधि : आईबीबीआई ने प्रक्रिया का संचालन जारी रखने के लिए सीओसी के सदस्यों के लिए बैठकों में भाग लेने के लिए और संभावित आरए के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाधान योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आईपी के लिए कठिनाइयों का संज्ञान लिया। इसलिए, सीआईआरपी विनियमनों में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सीआईआरपी के दौरान विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। कठिनाई को दूर करने के लिए, इसने सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन किया ताकि यह प्रदान किया जा सके कि कोविड-19 के प्रकोप के महेंजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को किसी भी गतिविधि के लिए समयरेखा के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा, जो इस कारण से लॉकडाउन, सीआईआरपी के संबंध में, संहिता में प्रदान की गई समय-सीमा के अधीन पूरा नहीं हो सका।</p>
07.08.20	<p>अधिकृत प्रतिनिधि (एआर) की नियुक्ति : (ए) संहिता एक वर्ग में एफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एए द्वारा एआर की नियुक्ति का प्रावधान करती है। इस प्रयोजन के लिए, विनियमनों के लिए आईआरपी को सार्वजनिक घोषणा में तीन आईपी की पसंद की पेशकश करने की आवश्यकता होती है, और एक वर्ग में लेनदारों को अपने एआर के रूप में कार्य करने के लिए उनमें से एक को चुनने की आवश्यकता होती है। संशोधन में प्रावधान है कि आईआरपी द्वारा पेश किए गए तीन आईपी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से होने चाहिए, जिसमें सीडी के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ग में लेनदारों की संख्या सबसे अधिक है। इससे एआर और लेनदारों के बीच उस वर्ग में समन्वय और संचार में आसानी होगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।</p> <p>मतदान निर्देश : विनियमनों में परिकल्पना की गई है कि एआर दो चरणों में एक वर्ग में लेनदारों से मतदान निर्देश मांगेगा, अर्थात् (i) बैठक से पहले, और (ii) बैठक के कार्यवृत्त के परिचालित होने के बाद। संशोधन में प्रावधान है कि एआर बैठक के कार्यवृत्त के संचालन के बाद ही मतदान निर्देश मांगेगा और तदनुसार मतदान करेगा। हालाँकि, वह एजेंडा को परिचालित करेगा, और वह बैठक से पहले कक्षा में लेनदारों के प्रारंभिक विचारों की तलाश कर सकता है, ताकि वह बैठक में प्रभावी रूप से भाग ले सके।</p> <p>सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान : विनियमनों में प्रावधान है कि सीओसी मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी अनुपालन समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगा ताकि उनमें से सर्वश्रेष्ठ की पहचान की जा सके और इसे अनुमोदित किया जा सके। विनियमन में संशोधन, यह प्रदान करता है कि मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सभी अनुपालन समाधान योजनाओं के मूल्यांकन के बाद, सीओसी सभी अनुपालन समाधान योजनाओं पर एक साथ मतदान करेगा। समाधान योजना, जिसे उच्चतम मत प्राप्त होते हैं, लेकिन कम से कम 66% मत प्राप्त होते हैं, को अनुमोदित माना जाएगा।</p>
13.11.20	<p>व्यतिक्रम का साक्ष्य : एफसी, आवेदन के साथ, 'सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज व्यतिक्रम का रिकॉर्ड या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के सबूत के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है' प्रस्तुत करना आवश्यक है। आईबीबीआई ने दो 'अन्य रिकॉर्ड या व्यतिक्रम के साक्ष्य' को निर्दिष्ट करने के लिए विनियमनों में संशोधन किया, अर्थात्, (i) बैंकर्स बुक में संबंधित खाते में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति, और (ii) एक अदालत या ट्रिब्यूनल का आदेश जिसने निर्णय दिया है एक ऋण का भुगतान न करना।</p> <p>लेनदारों की सूची दाखिल करना : विनियमन प्रदान करते हैं कि आईआरपी/आरपी प्रत्येक दावे को सत्यापित करेगा और आगे लेनदारों की एक सूची बनाए रखेगा और इसे अद्यतन करेगा। उसे एए के पास लेनदारों की सूची दाखिल करनी होगी और इसे सीडी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित करना होगा। विनियमन में संशोधन, यह प्रदान करता है कि आईआरपी/आरपी को अपनी वेबसाइट पर प्रसार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदारों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।</p> <p>प्रत्येक दावेदार को सूचना : संशोधित विनियमनों में आरपी को निर्देश दिया गया है कि वह समाधान योजना के अधीन ऋण के भुगतान के लिए एक समाधान योजना, सिद्धांत, या सूत्रों के अधीन प्रत्येक दावेदार को उक्त समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एए के आदेश के 15 दिनों के भीतर सूचित करे।</p>

15.03.21	<p>लेनदारों के दावे का अद्यतनीकरण : संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले लेनदारों द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। संशोधन के लिए एक लेनदार को अपने दावे को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है जब और जब दावा संतुष्ट हो, आंशिक रूप से या पूरी तरह से, किसी भी स्रोत से, किसी भी तरह से, दिवाला शुरू होने की तारीख के बाद।</p> <p>प्ररूप सीआईआरपी 7 फाइल करना : संशोधनों में आईआरपी/आरपी को नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर प्ररूप सीआईआरपी 7 फाइल करने की आवश्यकता होती है, जहां संहिता और विनियमनों में निहित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक घोषणा, आरपी की नियुक्ति, आईएम जारी करना, आरएफआरपी और सीआईआरपी को बंद करने जैसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है।</p>
----------	---

फास्ट ट्रेक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

हालांकि यह संभावना है कि लेनदारों और देनदारों ने स्वयं व्यतिक्रम के लिए अधिकतम अवधि की तुलना में कम अवधि में बातचीत को बंद करने का विकल्प चुना, बीएलआरसी का विचार था कि उन मामलों के लिए स्पष्ट उपबंध बनाया जाना उचित है जहां सीआईआरपी को सबसे जटिल मामले की तुलना में कम समय अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना है। इन मामलों को फास्ट ट्रेक सीआईआरपी के अधीन अंजाम दिया जा सकता है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 55 से 58, जो फास्ट-ट्रेक प्रक्रिया से संबंधित है, एक निश्चित सीमा से नीचे की संपत्ति और आय वाली ऐसी सीडी पर या लेनदारों के ऐसे वर्ग या ऋण की ऐसी राशि या कारपोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होती है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। एमसीए ने इस प्रक्रिया के लिए सीडी की श्रेणियों को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रेक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियमन, 2017 (फास्ट ट्रेक विनियमन) पात्र सीडी के दिवाला समाधान की शुरुआत से लेकर फास्ट-ट्रेक प्रक्रिया के अधीन एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के साथ इसके निष्कर्ष तक की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

कारपोरेट परिसमापन

चार परिस्थितियों में सीडी के सीआईआरपी के बाद परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता है :

- (क) एए समाधान योजना को अस्वीकार करता है, जिसे आरपी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए;
 - (ख) एए को सीआईआरपी के पूरा होने के लिए अनुमत समय के भीतर सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है;
 - (ग) सीओसी ने सीआईआरपी अवधि के दौरान किसी भी समय, सीडी को समाप्त करने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ निर्णय लिया है और आरपी ने एए को इसकी सूचना दी है; या
 - (घ) जहां एक परिसमापन आदेश के लिए सीडी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एए को आवेदन किया गया है, इस आधार पर कि संबंधित सीडी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया गया है।
- परिसमापन विनियमन, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 33 के अधीन परिसमापन आदेश जारी करने से लेकर धारा 54 के अधीन विघटन आदेश तक की गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है। सारणी 5 में 2020-21 में परिसमापन विनियमनों में विभिन्न संशोधन और उसी के औचित्य को प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5 : 2020-21 के दौरान परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों में संशोधन

अधिसूचना की तारीख	संशोधन
20.04.20	<p>लॉकडाउन की अवधि का बहिष्करण : संशोधित नियमों में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को, किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में। किसी भी कार्य के लिए समय-सीमा के अनुपालन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा, जिसके कारण पूरा नहीं किया जा सका।</p>
05.08.20	<p>परिसमापक को देय शुल्क : परिसमापन विनियमनों के लिए परिसमापक को देय शुल्क तय करने के लिए सीओसी की आवश्यकता होती है। यदि सीओसी द्वारा शुल्क तय नहीं किया गया है, तो विनियमनों में वसूल की गई राशि और परिसमापक द्वारा वितरित राशि के प्रतिशत के रूप में शुल्क का प्रावधान है। संशोधित नियम स्पष्ट करते हैं कि जहां एक परिसमापक किसी भी राशि का एहसास करता है, लेकिन उसे वितरित नहीं करता है, संशोधित विनियमनों में यह प्रावधान है कि परिसमापक उसके द्वारा वसूल की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा। इसी तरह, जहां एक परिसमापक किसी भी राशि का वितरण करता है, जो उसके द्वारा वसूल नहीं किया जाता है, वह उसके द्वारा वितरित की गई राशि के अनुरूप शुल्क का हकदार होगा।</p>
13.11.20	<p>आसानी से वसूली योग्य नहीं होने वाली परिसंपत्तियों का आवंटन : संहिता में परिसमापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द बंद करने की परिकल्पना की गई है ताकि सीडी की संपत्ति को वैकल्पिक उपयोग के लिए तेजी से जारी किया जा सके। हालांकि, प्रक्रिया में अधिक समय लगता है जहां परिसमापन परिसंपत्ति में 'आसानी से वसूली योग्य परिसंपत्ति' शामिल नहीं होती है। संशोधित नियम परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया को त्वरित रूप से बंद करने की सुविधा के लिए एससीसी के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को 'तुरंत वसूली योग्य परिसंपत्ति' आवंटित या अंतरित करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, 'आसानी से वसूली योग्य संपत्ति' का अर्थ है परिसमापन परिसंपत्ति में शामिल कोई भी परिसंपत्ति जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता है और इसमें आक्रामक या विवादित परिसंपत्ति, और अधिमान्य, कम मूल्यांकन, जबरन वसूली और धोखाधड़ी लेनदेन के लिए अंतर्निहित कार्यवाही शामिल है। इस प्रकार, एक परिसमापक पहली बार में परिसंपत्ति को बेचने का प्रयास करेगा, जिसमें विफल होने पर वह एससीसी के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को परिसंपत्ति सौंप सकता है या स्थानांतरित कर सकता है, और विफल होने पर वह हितधारकों के बीच अप्रचलित परिसंपत्ति को मंजूरी के साथ वितरित कर सकता है।</p> <p>लेनदारों के कारण ऋण का हस्तांतरण : एक लेनदार हो सकता है जो अपने ऋण की वसूली के लिए परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा करने को तैयार न हो। संशोधित विनियमन एक लेनदार को इस तरह के असाइनमेंट या ट्रांसफर से निपटने के लिए लागू कानूनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को इसके कारण ऋण को सौंपने या अंतरित करने में सक्षम बनाता है।</p>
04.03.21	<p>हितधारकों की सूची दाखिल करना : संशोधित विनियमनों में परिसमापक को बोर्ड की वेबसाइट पर समय-समय पर संशोधित हितधारकों की सूची दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यह संशोधन समाचार पत्रों में एए के साथ हितधारकों की सूची दाखिल करने की घोषणा की आवश्यकता को समाप्त करता है।</p>

कारपोरेट परिसमापन खाता

परिसमापन विनियमनों के लिए आईबीबीआई को भारत के सार्वजनिक खातों में कारपोरेट लिक्विडेशन अकाउंट कहे जाने वाले खाते को बनाए रखने और संचालित करने की आवश्यकता होती है। यह आगे प्रावधान करता है कि जब तक कारपोरेट परिसमापन खाता भारत के सार्वजनिक खातों के हिस्से के रूप में संचालित नहीं होता है, तब तक आईबीबीआई दावा न किए गए लाभांश की राशि, यदि कोई हो, और अवितरित आय, यदि कोई हो, जमा करने के लिए, परिसमापन प्रक्रिया में अनुसूचित बैंक के साथ अलग बैंक खाता खोलेगा। इस उद्देश्य के लिए, इसने पीएनबी के साथ दो अलग-अलग बैंक खाते (एक परिसमापन प्रक्रिया के लिए और दूसरा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए) खोले, और 9 जनवरी, 2020 और 20 जनवरी, 2020 के परिपत्र के माध्यम से विवरण की जानकारी दी।

परिसमापन विनियमनों के लिए एक परिसमापक की भी आवश्यकता होती है कि वह दावा न किए गए लाभांश की राशि, यदि कोई हो, और अविभाजित आय, यदि कोई हो, परिसमापन प्रक्रिया में, उस पर अर्जित किसी भी आय के साथ, कारपोरेट परिसमापन खाते में कॉर्पोरेट व्यक्ति विघटन के लिए एक आवेदन जमा करने से पहले जमा करें। यह हितधारक को उक्त खाते से निकासी की मांग करने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। मार्च, 2021 के अंत में इन खातों का विवरण सारणी 6 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट परिसमापन खाते

(राशि लाख रुपये में)

अवधि	आंशिक षष्ठ	अवधि के दौरान	वर्ष के दौरान निकाले गए	अवधि के अंत में षष्ठ
2019 - 20	0.00	476.26	0.21	476.05
अप्रैल- जून, 2020	476.05	41.40	0.00	517.45
जुलाई - सितंबर, 2020	517.45	9.60	0.00	527.05
अक्टूबर -दिसंबर, 2020	527.05	56.66	0.00	583.71
जनवरी - मार्च, 2021	583.71	8.52	0.00	592.23

स्वैच्छिक परिसमापन

संहिता की धारा 59 में व्यवस्था है कि एक कारपोरेट व्यक्ति जो स्वेच्छा से खुद को समाप्त करने का इरादा रखता है और कोई व्यक्तिगत नहीं करता है, वह संहिता के अध्याय V के उपबंधों के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है। स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन में कारपोरेट व्यक्ति-कंपनियों, एलएलपी और सीमित देयता वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन की शुरुआत और इसके विघटन तक की प्रक्रिया की व्यवस्था प्रदान करते हैं।

संहिता कारपोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है यदि उसके पास कोई ऋण नहीं है या वह परिसम्पत्ति की आय से अपने ऋणों का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम होगा। कारपोरेट व्यक्ति आईपी को परिसमापक के रूप में नियुक्त करता है ताकि सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के समाधान द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का संचालन किया जा सके। हालांकि, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनके लिए परिसमापक के रूप में किसी अन्य आईपी की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है। आईबीबीआई ने 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से स्वैच्छिक परिसमापन विनियमनों में संशोधन किया, ताकि कारपोरेट व्यक्ति को परिसमापक के रूप में अन्य आईपी को सदस्यों या भागीदारों, या योगदानकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, के प्रस्ताव द्वारा परिसमापक को बदलने में सक्षम बनाया जा सके।

स्वैच्छिक परिसमापन विनियमनों के लिए एक परिसमापक को कॉर्पोरेट व्यक्ति विघटन के लिए आवेदन जमा करने से पहले कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में किसी भी आय के साथ स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो, और अविभाजित आय, यदि कोई हो, जमा करने की आवश्यकता होती है। यह हितधारक को उक्त खाते से निकासी की मांग करने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। मार्च, 2021 के अंत में इन खातों का विवरण सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते

(राशि लाख रुपये में)

अवधि	आंशिक षष्ठ	अवधि के दौरान	वर्ष के दौरान निकाले गए	अवधि के अंत में षष्ठ
2019 - 20	0.00	109.70	0.00	109.70
अप्रैल- जून, 2020	109.70	8.35	0.00	118.05
जुलाई - सितंबर, 2020	118.05	28.46	0.00	146.51
अक्टूबर -दिसंबर, 2020	146.51	56.27	0.00	202.78
जनवरी - मार्च, 2021	202.78	18.98	0.00	221.76

वित्तीय सेवा प्रदाता

सीआईआरपी से संबंधित संहिता के प्रावधान, सीडी के लिए परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुछ संशोधनों के अधीन, एफआईएसपी के लिए एक प्रक्रिया पर लागू होते हैं। इसलिए, सीडी के लिए इन प्रक्रियाओं से संबंधित नियम एफआईएसपी की प्रक्रिया पर भी लागू होते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा एफआईएसपी की शुरुआत सीआईआरपी के लिए पहला आवेदन फाइल किया गया था। श्री आर सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशासक के समान कर्तव्य, कार्य, दायित्व, उत्तरदायित्व, अधिकार और एक आईपी के अधिकार, जो संहिता के अधीन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं।

व्यक्तिगत दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

संहिता चरणबद्ध तरीके से व्यक्तिगत दिवाला के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए व्यक्तियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् पीजी से सीडी, साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म, और अन्य व्यक्ति। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 01 दिसंबर, 2019 को पीजी से सीडी से संबंधित संहिता के प्रावधानों को शुरू करने की तारीख के रूप में नियुक्त किया। इसने दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 और दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 को भी एक ही तारीख को अधिसूचित किया। इन नियमों में पीजी के खिलाफ सीडी में दिवाला समाधान और दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और रूपों, ऐसे आवेदनों को वापस लेने, लेनदारों से दावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस के लिए प्रपत्र आदि प्रदान किए गए हैं।

इसके बाद, 20 नवंबर, 2019 को आईबीबीआई ने आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2019 (पीजी से सीडी विनियमनों के लिए आईआरपी) को (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन

अक्षमता प्रक्रिया) विनियमन, 2019 (शोधन अक्षमता विनियमन) पीजी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया का विवरण सीडी को प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया ताकि पीजी से सीडी और आईबीबीआई के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का विवरण निर्दिष्ट किया जा सके।

पीजी से सीडी विनियमन के लिए आईआरपी (क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी के रूप में कार्य करने की योग्यता; (ख) लेनदारों के दावों की प्राप्ति और सत्यापन का तरीका; (ग) लेनदारों की सूची तैयार करने, लेनदारों की बैठक आयोजित करने और बैठक में मतदान करने का तरीका (घ) चुकौती योजना की सामग्री; और (ड.) सेवामुक्ति आदेश आदि जारी करने के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है।

शोधन अक्षमता विनियमन (क) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए बीटी के रूप में कार्य करने की योग्यता; (ख) बीटी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट और समयरेखा तैयार करने का तरीका; (ग) दावों को समेटने और सीओसी के गठन, समिति की बैठकें आयोजित करने और बैठक में मतदान करने का तरीका; और (घ) दिवाला और उसके वितरण, आदि की संपत्ति की वसूली का तरीका निर्दिष्ट करते हैं।

सी.3 समर्थन और जागरूकता

जबकि सरकार और नियामक अर्थव्यवस्था में कुछ लेनदेन के लिए नीति तैयार कर सकते हैं या कानूनी ढांचा प्रदान कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें हितधारकों को अवगत कराया जाए और नीति या कानूनी ढांचे को और अधिक परिष्कृत करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए। किसी भी सुधार के शुरुआती दिनों में, हितधारकों तक नीति और विनियमनों के संदेश को ले जाने और उन्हें संभावित उपयोगों और उपयोग के तरीके से अवगत कराने के लिए इस तरह की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, समर्थन नीति या कानून में बदलाव को बढ़ावा देने या सुदृढ़ करने के लिए महत्व रखती है। यह ऐसे परिवर्तनों के लिए हितधारकों का समर्थन प्राप्त करने के तरीके के रूप में भी कार्य करता है। दिवाला सुधारों के संदर्भ में, हितधारकों को संहिता, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित होने की आवश्यकता है, ये सभी भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत नए हैं।

सारणी 8 में बोर्ड द्वारा आयोजित समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों और उन कार्यक्रमों का सनैपशॉट प्रस्तुत है जिनमें बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया।

सारणी 8 : बोर्ड के समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आईपी के लिए कार्यशाला	1	2	7	15	3
बाजार सहभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	9	2	3	3
हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन	8	45	25	20	19
समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम	-	-	10	105	48
अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम जहां सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया	36	78	82	66	85
कुल	45	134	126	209	158

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) और आईबीबीआई के अधिकारियों ने 85 आयोजनों (संगोश्टी, सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, अध्ययन मंडल, कार्यशाला, आदि) में विभिन्न क्षमताओं (संकाय, पैनलिस्ट, वक्ता, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, आदि) में भाग लिया। दिवाला और शोधन अक्षमता पर, देश भर में कई संस्थानों द्वारा आयोजित, जैसा कि सारणी 9 में प्रस्तुत है। इन घटनाओं का विवरण सारणी 10 में प्रस्तुत है।

सारणी 9 : आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी

अधिकारी	कार्यक्रमों की संख्या				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	45	83	86	63	38
डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष	0	9	0	उ.न.	उ.न.
श्रीमती सुमन सक्सेना, डब्ल्यूटीएम	0	13	14	11	9
डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम	उ.न.	20	14	17	14
डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2	7
श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम	0	9	12	104	17
अन्य अधिकारी	45	134	126	197	85

उ.न. : लागू नहीं

सारणी 10 : 2020-21 के दौरान कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण

क्र. सं.	तारीख	एलवी	विषय	भागीदारी
1	11.04.20	आईआईसीए	जीआईपी प्रॉस्पेक्टस	अध्यक्ष
2	11.04.20	आईआईसीए	आईबीसी का इंटरफेस और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002	अध्यक्ष
3	11.04.20	आईआईआईपीआई	आईबीसी शासन पर कोविड-19 का प्रभाव	अध्यक्ष
4	13.04.20	आईपीए	आईपीज का निरीक्षण	अध्यक्ष
5	13.04.20	आईसीएसआई आईआईपी	रेजिस्ट्रीकरण – पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम	श्री साजी कुमार, ईडी
6	20.04.20	आईसीएसआई आईआईपी	रेजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम	श्री साजी कुमार, ईडी
7	20.04.20	आईआईआईपी आईसीएसआई	आईपी: क्राइसिस मैनेजर और मैनेजर इन क्राइसिस	श्री साजी कुमार, ईडी

8	21.04.20	फिक्की	रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम	अध्यक्ष
9	21.04.20	एसोचोम	आईबीसी सुधार	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
10	24.04.20	आईपीए आईसीएआई	कोविड-19: आईबीसी पर राहत	श्री साजी कुमार, ईडी
11	28.04.20	आईसीएआई आरवीओ	एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष उपस्थिति - कोर्ट क्रापट	अध्यक्ष
12	29.04.20	पीवीएआई आरवीओ	मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
13	01.05.20	पीवीएआई आरवीओ	मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020	अध्यक्ष
14	08.05.20	पीएचडीसीआई	स्टार्ट-अप मूल्यांकन और एबीसीडीआरआई	श्री पवन कुमार, ईडी
15	09.05.20	आईओवी आरवीएफ	दिवाला पर कोविड-19 का प्रभाव	श्री पवन कुमार, ईडी
16	12.05.20	आरआईसीएस	मूल्यांकन मानक	अध्यक्ष
17	16.05.20	आईओवी आरवीओ	नया मूल्यांकक विधेयक-एक खेल परिवर्तक	अध्यक्ष
18	23.05.20	एसोचोम	मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020	श्री पवन कुमार, ईडी
19	26.05.20	आईआईआईपीआई आईसीएआई	कारपोरेट पुनर्गठन, एम एंड ए और संयुक्त उद्यम	अध्यक्ष
20	26.05.20	आईओवी आरवीएफ	शासी बोर्ड का संबोधन	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
21	27.05.20	आईसीएआई आरवीओ	मूल्यांकन व्यावसाय में विकास वैश्विक परिप्रेक्ष्य	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
22	28.05.20	डीटीआरटीआई, चंडीगढ़	मसौदा मूल्यांकक विधेयक, 2020	श्री पवन कुमार, ईडी
23	31.05.20	आईबीबीआई और एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल	गुणवत्ता मूल्यांकन	श्री साजी कुमार, ईडी
24	06.06.20	नीति आयोग	मूट कोर्ट प्रतियोगिता	अध्यक्ष
25	09.06.20	इनसोल इंडिया	ऑनलाइन विवाद समाधान	अध्यक्ष
26	12.06.20	आईआईआईपीआई आईसीएआई	आईपी को 'नव सामान्य' से कैसे निपटना चाहिए?	श्री साजी कुमार, ईडी
27	20.06.20	एन्क्यूब	दिवाला समाधान: लोक हित और नैतिकता	अध्यक्ष
28	24.06.20	आईआईसीए	दिवाला पर कोविड-19 का प्रभाव और आगे की राह	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
29	24.06.20	आईआईआईपीआई आईसीएआई और आईएफसी, विश्व बैंक	नियामक नीति और विनियमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	डॉ गुरु, ईडी
30	24.06.20	डीटीआरटीआई, चंडीगढ़	दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव- वैश्विक और भारतीय प्रतिक्रियाएं	श्री पवन कुमार, ईडी
31	25.06.20	लंदन शहर	गुणवत्ता मूल्यांकन	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
32	27.06.20	आईसीएआई का आईआईआरसी	महामारी पर रोक लगाना - दिवाला और शोधन अक्षमता नीति, 2020 और उससे आगे	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
33	01.07.20	आईआईसीए	क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं?	अध्यक्ष
34	17.07.20	इकोनॉमिक टाइम्स	जीआईपी के दूसरे बैच का उद्घाटन	अध्यक्ष
35	23.07.20	आरबीएसए	शोधन अक्षमता से निपटना: जर्जर स्थिति से पुनर्गठन	अध्यक्ष
36	25.07.20	आईआईसीए	मूल्यांकन	अध्यक्ष
37	01.08.20	पीवीएआई वीपीओ	प्रति आईपी असाइनमेंट	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
38	04.08.20	आईसीएलएस अकादमी	मूल्यांकन	अध्यक्ष
39	12.08.20	फिक्की	आईसीएलएस अधिकारियों के लिए आईबीसी	अध्यक्ष
40	14.08.20	सहयोगी पेशेवर	तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्री-पैक	अध्यक्ष
41	21.08.20	एसोचैम	आईबीसी: व्यापार करने में आसानी से आर्थिक विकास के लिए वर्तमान विकास और आगे का मार्ग	अध्यक्ष
42	10.09.20	एसोचैम	हितधारकों पर कोविड-19 और एक वर्ष के निलंबन का प्रभाव	अध्यक्ष
43	21.09.20	आईआईआईपीआई	इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टीवर्डशिप	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
44	25.09.20	आईसीएआई	आईबीसी - एनपीए समाधान के लिए एक वरदान: मिथक बनाम वास्तविकताएं	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
45	12.10.20	इनसोल	आईबीबीआई और व्यावसायिकों से अपेक्षाएं	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम

46	13.10.20	जीएनएलयू	संकट से उत्पन्न व्यावहारिक चुनौतियाँ	श्री चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक
47	14.10.20	फिक्की	आईबीसी 2016,आईबीबीआई, आईपीए और आईयू का अवलोकन	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
48	16.10.20	इनसोल	भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए निवेश के अवसर	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
49	24.10.20	आईआईआईपीआई	एसएमई पर महामारी का प्रभाव	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
50	25.10.20	आईआईआईपीआई	दिवाला समाधान प्रतिमान: वैश्विक प्रतिकूलताएं और प्रतिक्रियाएं	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
51	24.10.20	आईआईआईपीआई	अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रबंधन सीमा पार दिवाला	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
52	11.11.21	भारतीय बैंक संघ	समूह दिवाला ढांचा: प्रारंभिक सबक	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
53	12.11.20	आईसीएसआई डब्ल्यूआईआरसी का	आईबीबीआई: भारतीय बैंक संघ के सदस्यों के साथ मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	श्री दास, उप महाप्रबंधक
54	11.12.20	आईओवी आरवीएफ	व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला और शोधन अक्षमता	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
55	12.12.20	ईबीसी प्रकाशन	आईओवी कांग्रेस	अध्यक्ष
56	19.12.20	आईसीएसआई आईआईपी	आईबीसी पुस्तक विमोचन	अध्यक्ष
57	29.12.20	आईसीएसआई आईआईपी	भू-संपदा में दिवाला	श्री दास, उप महाप्रबंधक
58	30.12.20	आईआईसीए	कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता	अध्यक्ष
59	05.01.21	बीसीआईसी	कैपस्टोन कार्यवाही	अध्यक्ष
60	07.01.21	एनएलयूडी और अन्य	आईबीसी की चार वर्ष की यात्रा: मील के पत्थर	अध्यक्ष
61	07.01.21	एनएलयूडी और अन्य	दिवाला समाधान, महामारी के बाद उद्यमिता को बढ़ावा देना	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
62	10.01.21	इनसोल और अन्य	शोधन अक्षमता को लागू करना, दिवाला पूर्व कार्यवाही को एकीकृत करना, कानूनी व्यवस्था में प्री-पैक्स	अध्यक्ष
63	19.01.21	आईआईसीए	दिवाला मूट	अध्यक्ष
64	21.01.21	पीएनबी	जीआईपी	अध्यक्ष
65	22.01.21	आईईजी	आईबीबीआई: मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	अध्यक्ष
66	22.01.21	एसोचैम	दिवाला सुधार	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
67	22.01.21	एलआईसी	आत्म निर्भर भारत के लिए उद्योग जगत की सोच और मंथन पर राष्ट्रीय ई-शिखर सम्मेलन	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
68	27.01.21	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	आईबीबीआई: मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	श्री शुक्ला, ईडी
69	30.01.21	पीएचडीसीसीआई	आईबीबीआई: मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
70	04.02.21	नेशनल डिफेंस कॉलेज	आईबीसी और एमएसएमई: द अनफिनिश्ड स्टोरी	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
71	05.02.21	एनईएसएल	भारत का संविधान: निर्माण और विकास और नया भारत	अध्यक्ष
72	08.02.21	एफओआईआर	दिवाला कार्यवाही के लिए आईयू का लाभ उठाना	अध्यक्ष
73	12.02.21	आईडीबीआई बैंक और अन्य	प्रभावी विनियमन और हितधारकों की भागीदारी	श्री शुक्ला, ईडी
74	17.02.21	आईआईआई और अन्य	आईबीबीआई: मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	अध्यक्ष
75	18.02.21	आईआईआईपीआई	भारत में पूर्व-व्यवस्थित दिवाला कार्यवाही: यूएसए और यूके से सीखें गए सबक	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
76	23.02.21	आईआरडीएआई और अन्य	आईपी/आईबीसी का क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
77	24.02.21	आईएफसीए	आईबीबीआई: मूल्यांकन व्यवसाय का संरक्षण	अध्यक्ष
78	08.03.21	आईसीएमएआई आरवीओ	वित्तीय क्षेत्र के सुधार, विनियमन और उभरती चुनौतियाँ	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
79	09.03.21	फिक्की	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: मूल्यांकन पर परिप्रेक्ष्य	अध्यक्ष
80	10.03.21	सीआईआई और अन्य	भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यथित ऋण	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
81	19.03.21	आईसीएमएआई और अन्य	आईबीसी के अधीन कार्यवाही पर कोविड-19 का प्रभाव	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम
82	20.03.21	ईटीसीएफओ और अन्य	आईबीसी के अधीन आईपी की भूमिका	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
83	26.03.21	सीआईआई	चौराहे पर आईबीसी – आगे क्या?	अध्यक्ष
84	26.03.21	सीआईआई	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	श्री शुक्ला, डब्ल्यूटीएम
85	27.03.21	एमसीसीआई और अन्य	प्री-पैक फ्रेमवर्क	डॉ विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम

कार्यक्रम

विभिन्न आयोजनों के अलावा जहां आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबीबीआई ने स्वयं या सरकार/अन्य संस्थानों के सहयोग से कई जागरूकता और वकालत कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से कुछ घटनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्य

भारत में तनावग्रस्त परिस्थितियों में निवेश के अवसर

आईबीबीआई ने फिक्की और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से 17 सितंबर, 2020 को 'भारत में तनावग्रस्त संपत्तियों में निवेश के अवसर' के बारे में सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन से संभावित निवेशकों, फाइनेंसर्स, कानूनी और अन्य सलाहकारों आदि को एक साथ लाने में सफलता मिली। भारत में तनावग्रस्त परिस्थितियों में निवेशकों के लिए अवसरों पर चर्चा और अमेरिका में बड़े संस्थागत निवेशकों के समुदाय को भारत में उपलब्ध टर्नअराउंड अवसरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

जागरूकता कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यक्रम

कोविड-19 के मद्देनजर, यह महसूस किया गया कि सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण शैक्षिक पाठ्यक्रम और कक्षा मोड के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा जारी रखना मुश्किल होगा। तदनुसार, बोर्ड ने उक्त पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति दी। बोर्ड ने आईआईआईपीआई के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के मद्देनजर दो इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए। पहला सत्र आईआरपी/आरपी के साथ था और दूसरा सत्र परिसमापकों के साथ क्रमशः 6 मई, 2020 और 9 मई, 2020 को महामारी के दौरान उनके सामने आने वाले मुद्दों पर था। इसने 15 मई, 2020 को "आईबीसी के अधीन मूल्यांकन - कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर प्रभाव" पर कार्यक्रम भी आयोजित किया। वेबिनार ने संहिता के अधीन मूल्यांकन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा को कवर किया।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 05 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया था, जो 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले व्यतिक्रम के संबंध में संहिता की धारा 7, 9 और 10 के प्रचालन को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और इसे अधिसूचित किए जाने वाली तारीख से अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी हितधारकों और अध्यक्ष, आईबीबीआई के लिए 07 जून, 2020 को उक्त अध्यादेश पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम

संहिता के विभिन्न पहलुओं और संहिता के संबंध में राज्य एजेंसियों के अधिकारियों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए, संहिता के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने वर्ष के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के लिए 10 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तारीख (तारीखें)	प्रतिभागी
1	04.08.20 से 05.08.20	इंडियन कोरपोरेट लॉ सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारी
2	03.11.2020	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारी
3	10.11.2020	ओडिशा सरकार के अधिकारी
4	19.11.2020	डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी
5	25.11.2020	ओडिशा सरकार के केंद्रीय कर और वस्तुएं एवं सेवाएं कर विभाग के अधिकारी
6	22.12.2020	डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी
7	08.01.2021	मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी
8	18.01.2021	झारखंड सरकार के अधिकारी
9	14.02.21 से 19.02.21	भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी
10	04.03.2021	बिहार सरकार के अधिकारी

आईपी कार्यशालाएं

आईबीबीआई गहन कक्षा सत्रों के माध्यम से विशिष्ट और गहन स्तर की शिक्षा देने के उद्देश्य से आईपी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इसने 21 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन 'संहिता के अधीन परिसमापन के दौरान बिक्री के रूप में बिक्री' विषय पर आईपी के लिए 7वीं उन्नत कार्यशाला का आयोजन किया। 8वीं उन्नत कार्यशाला का आयोजन 'वित्तीय विवरणों का विश्लेषण' विषय पर किया गया था। 14 दिसंबर, 2020 को सीडी और उनके व्यक्तिगत गारंटर्स की। इसने 17 मार्च, 2021 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आईपी के लिए 19वीं बुनियादी कार्यशाला का भी आयोजन किया।

पत्रकारों के लिए आईबीसी पर कार्यक्रम

आईबीबीआई ने वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालयों के प्रेस रिलेशन और सूचना प्रभाग के सहयोग से 18 अगस्त, 2020 को संहिता के उपबन्धों के औचित्य और दृष्टिकोण को समझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता के एक मात्र उद्देश्य के लिए 'आईबीसी - पत्रकारों के लिए' के बारे में एक वरच्युल संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में पांच सत्र थे, बड़ी तस्वीर और चार वर्ष की यात्रा आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र; कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाएं; मिथक और परिणाम; और हाल के परिवर्तन और आगे का रास्ता। डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई; डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई; श्री के. आर. साजी कुमार, ईडी, आईबीबीआई; श्री पवन के. कुमार, ईडी, आईबीबीआई डॉ अनुराधा गुरु, ईडी, आईबीबीआई और श्री मिथिल उन्नीकृष्णन, महाप्रबंधक, आईबीबीआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

सीओसी कार्यशालाएं

आईबीबीआई बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सीओसी के सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष भी, इसने 29 जनवरी, 2021, 03 फरवरी, 2021 और 11 फरवरी, 2021 को श्रृंखला में पांचवीं, छठी और सातवीं श्रृंखला में तीन ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसका विषय 'लेनदारों की समिति: सार्वजनिक ट्रस्ट का संस्थान' था। 15 एससीबी और वित्तीय संस्थानों (एफआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 वरिष्ठ अधिकारियों (जीएम और ऊपर) ने कार्यशाला में भाग लिया।

ये कार्यशालाएं एसबीआई और आईबीए के सहयोग से ई-मोड में आयोजित

की गई। इन कार्यशालाओं के शिक्षकों में माननीय न्यायमूर्ति बी.एस.वी. प्रकाश कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष, एनसीएलटी; श्री राजेश वर्मा, सचिव, एमसीए; डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई; श्री जी. के. सिंह संयुक्त सचिव, एमसीए; श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, एसबीआई; श्री सी.एस. सेट्टी, एमडी, एसबीआई; श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, आईबीए; श्री एस.एस. मल्लिकार्जुन राव, एमडी, पंजाब नेशनल बैंक; श्री संजीव कृष्ण, अध्यक्ष, पीडब्ल्यूसी इंडिया; श्री सुमंत बत्रा, मैनेजिंग पार्टनर, केसर दास बी. एंड एसोसिएट्स; श्री बहराम वकील, मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी और पार्टनर्स; श्री मोहित सराफ, सीनियर पार्टनर, एल एंड एल पार्टनर्स; श्री शैलेंद्र अजमेरा, पार्टनर, ईवाई; श्री राशेश शाह, अध्यक्ष, एडलवाइस समूह; और श्री शार्दुल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास शामिल थे।

वेबिनार

जारी कंसर्न के रूप में कारपोरेट देनदार का प्रबंधन - संचालन प्रबंधन

आईबीबीआई ने आईसीएसआई आईआईपी के सहयोग से 'जारी कंसर्न के रूप में कारपोरेट देनदार का प्रबंधनय संचालन प्रबंधन' के बारे में 22 मई, 2020 को वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में सीडी को जारी कंसर्न के रूप में प्रबंधित करने में आईपी, विशेष रूप से संचालन प्रबंधन में पेश आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा को कवर किया गया।

आईबीसी में समकालीन विकास

आईबीबीआई ने सेंटर फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल के सहयोग से 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में समकालीन विकास' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार ने भारतीय दिवाला परिदृश्य में नवीनतम विकास को समझने के लिए चर्चा को कवर किया, विशेष रूप से संहिता की धारा 7, 9 और 10 के अस्थायी निलंबन के आलोक में। इसमें आईबीसी के संकटग्रस्त संपत्तियों और आगे आने वाली चुनौतियों पर पढ़ने वाले प्रभाव पर चर्चा शामिल थी।

परिसमापन प्रक्रिया में पेश आए मुद्दे और यूके में परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता

आईबीबीआई ने ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से 23 अक्टूबर, 2020 को 'ब्रिटेन में परिसमापन प्रक्रिया में पेश आए मुद्दे और परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और उन्हें कम करना था। केस स्टडी की मदद से परिसमापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान परिसमापकों द्वारा सामना किया जा रहा है। वेबिनार ने यूके में परिसमापन ढांचे का एक सिंहावलोकन प्रदान करने की मांग की और भारत में परिसमापन की कार्यवाही के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों को लागू करने का प्रयास किया।

आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण

आईबीबीआई ने विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ), यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 05 फरवरी, 2021 को 'आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। प्रतिभागियों को परिहार लेनदेन का अवलोकन दिया गया और नियामक परिदृश्य जो लेनदेन लेखा परीक्षा को प्रभावित करता है। परिहार लेन-देन का पता लगाने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि के साथ व्यावहारिक उदाहरण

और केस स्टडी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले सूचना स्रोतों को भी शामिल किया गया था।

प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया

आईबीबीआई ने दिवाला समाधान के अतिरिक्त यन्त्र के रूप में 19 मार्च, 2021 को 'प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया: आईएलसी की उप-समिति की रिपोर्ट' पर वेबिनार का आयोजन किया, जो पीपीआईआरपी पर आईएलसी की उप-समिति की रिपोर्ट पर आधारित था।

परिसमापन प्रक्रिया के अधीन बिक्री और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाएं

आईबीबीआई ने, ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से, 23 मार्च, 2021 को आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लाभ के लिए संयुक्त रूप से 'बिक्री के अधीन परिसमापन प्रक्रिया और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाओं' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनलिस्टों ने प्रभावी बिक्री प्रक्रिया और व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में बताया जो आमतौर पर परिसमापकों द्वारा सामना की जाती हैं। यूके में बिक्री प्रक्रिया, भारतीय संदर्भ में लागू की जा सकने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों पर भी चर्चा की गई।

आईबीबीआई : मूल्यांकन व्यवसाय का परिरक्षण

मूल्यांकन नियमों के अधीन मूल्यांकन के नए शासन की वकालत के प्रयास के रूप में, 'आईबीबीआई: शेफर्डिंग वैल्यूएशन प्रोफेशन' विषय पर पांच वेबिनार आयोजित किए गए थे। ये वेबिनार 21 जनवरी, 2021 को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के लाभ के लिए आयोजित किए गए थे। 22 जनवरी, 2021 को जीवन बीमा निगम; 27 जनवरी, 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; 12 फरवरी, 2021 को आईडीबीआई बैंक, आईआईएफसीएल, केनरा बैंक और एक्विज बैंक; और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआई) 23 फरवरी, 2021 को आयोजित किये गए थे।

शैक्षणिक नियोजन

स्नातक दिवाला कार्यक्रम

आईआईसीए ने 01 जुलाई, 2019 को जीआईपी का पहला बैच शुरू किया। जीआईपी एक 24 महीने का कार्यक्रम है जिसमें 12 महीने का आवासीय क्लास-रूम घटक और 12 महीने के अभ्यास में अत्याधुनिक इंटरशिप घटक शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले आईपी का एक संवर्ग प्रदान करना है जो आईपी, परिसमापक या अन्य क्षमताओं के रूप में विश्व स्तर की सेवाएं प्रदान कर सकता है। जीआईपी पूरा करने वाला छात्र आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा। जीआईपी के पहले बैच में 37 छात्र शामिल थे। 41 छात्रों के अगले बैच ने 01 जुलाई, 2020 को अपनी कक्षाएं शुरू कीं।

दिवाला विवाद

आईबीबीआई ने एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल के नॉलेज पार्टनर के रूप में 28-31 मई, 2020 तक पहली इनोविस-एलएनसीटी आईबीसी ई-मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसने देश के कानून के छात्रों को तकनीकी से निपटने के मामले में एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। और कारपोरेट कानून के कानूनी पहलू, विशेष रूप से आईबीसी, और एक आभासी ऑनलाइन वातावरण में अपने विचार कौशल का अभ्यास करने के लिए। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 34 टीमों ने भाग

लिया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला की टीम, जिसमें श्री प्रियांक पांडे, श्री वैभव मुखरैया और सुश्री आशीश पाजीवाल शामिल थे, विजेता रही। आईसीएफआई लॉ स्कूल, हैदराबाद की टीम जिसमें श्री अपूर्व गुप्ता, श्री आकाश कृष्णन और सुश्री पूजा गांधी शामिल थे, उपविजेता रही। श्री के.आर. साजी कुमार, ईडी, आईबीबीआई ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और प्रतियोगिता के अंतिम दौर का निर्णय लिया।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने आईबीबीआई, इनसोल इंडिया, सोसाइटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया और युएनसटीआरएएल रीजनल सेंटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सहयोग से 2017 में दिवाला और शोधन अक्षमता (आईबीएमसी) पर एक मूट प्रतियोगिता का आयोजन किया। कानून विश्वविद्यालयों और प्रबंधन और अर्थशास्त्र के स्कूलों में छात्रों को एनसीएलटी के समक्ष वास्तविक कार्यवाही के जितना संभव हो सके, एक दूसरे से सामंजस्य के साथ दिवाला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के साथ संलग्न करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। आईबीएमसी का चौथा संस्करण वस्तुतः 08-10 जनवरी, 2021 तक आयोजित किया गया। दुनिया भर के संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 50 टीमों ने रजिस्ट्रीकरण कराया और प्रतियोगिता में भाग लिया। स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को मूट का विजेता घोषित किया गया, जबकि राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ उपविजेता रहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई ने आईबीएमसी के लिए जूरी की अध्यक्षता की और समापन सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समापन भाषण दिया।

निबंध प्रतियोगिता

आईबीबीआई ने उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया। भारत में विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों (जैसे आईसीएआई, आईसीएमआई और आईसीएसआई) में किसी भी विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आईबीबीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले छात्र को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार, और उस छात्र को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार जारी कर रहा है जिसने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है। दूसरा सबसे अच्छा निबंध लिखा। वर्ष के दौरान तीन निबंध प्रतियोगिताएं (i) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, (ii) गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी के सहयोग से संपन्न हुईं।

आईबीसी पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी

आईबीबीआई ने MyGov-in के सहयोग से, देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 01-31 जुलाई, 2020 से 'शोधन अक्षमता और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी' का आयोजन किया। आईबीबीआई में काम करने वाले व्यक्तियों, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को छोड़कर, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रश्नोत्तरी खुली थी। प्रश्नोत्तरी को 1,25,781 प्रतिभागियों के साथ छात्रों, व्यावसायिकों और कर्मचारियों सहित हितधारकों

की एक विस्तृत श्रृंखला से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसमें हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिभागी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिभागियों में से 15.7% के साथ सबसे अधिक भागीदारी थी, इसके बाद महाराष्ट्र में 11.7% और दिल्ली में 6.9% था। शीर्ष 10% प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। प्रश्नोत्तरी में तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित थे :

रैंक	नाम	पुरस्कार
सर्वोत्तम निष्पादक	श्री अरित्रा साहा	स्वर्ण पदक
द्वितीय सर्वोत्तम निष्पादक	श्री पवन खडेलवाल	रजत पदक
तृतीय सर्वोत्तम निष्पादक	सुश्री वाकार्ती वेंकट गनुशा	कांस्य पदक

आईसीएलएस और आईईएस परिवीक्षाधीनों का प्रशिक्षण

आईबीबीआई ने भारतीय कारपोरेट विधि अधिकारियों (आईसीएलएस) के 2018 बैच के अधिकारियों के लिए 04-05 अगस्त, 2020 से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने अधिकारियों को संहिता, संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, इसके परिणामों, सेवा प्रदाताओं से व्यापक रूप से अवगत कराया। और सीमावर्ती क्षेत्र जैसे सीमा पार दिवाला, व्यक्तिगत दिवाला और समूह दिवाला। अध्यक्ष, आईबीबीआई और आईबीबीआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

आईबीबीआई ने 15-19 फरवरी, 2021 तक 30 भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारियों के 2019 बैच के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने अधिकारियों को दिवाला सुधारों, इसके कार्यान्वयन और परिणामों, पारिस्थितिकी तंत्र, मुद्दों और व्यापक रूप से उजागर किया। चुनौतियां, और आगे की राह। उन्हें परीक्षा देने का विशेष अवसर भी प्रदान किया गया। श्री अंशुमन कामिला, सुश्री अर्चना कुमारी और सुश्री सोम्या गौतम नाम के तीन सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

प्रख्यात बाहरी संकाय में डॉ. के.पी. कृष्णन, आईईपीएफ चेयर प्रोफेसर, एनसीईआरए डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री बी. श्रीराम, पूर्व एमडी, आईडीबीआई बैंक; डॉ. (सुश्री) अपर्णा रवि, पार्टनर, संवाद पार्टनर्स; श्री अशोक हल्दिया, अध्यक्ष, आईआईआईपीआई; श्री एस. रमन, एमडी, एनईएसएल; डॉ. सुभाशीश गंगोपाध्याय, अनुसंधान निदेशक, आईडीएफ; श्री अनुराग दास, एमडी, इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी; श्री सतीश कुमार गुप्ता, आईपी; डॉ. (सुश्री) रेणुका साने, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईपीएफपी और सुश्री श्रीप्रिया कुमार, आईपी शामिल थे।

न्यूजलैटर

जबकि आईबीबीआई हितधारकों के साथ नीति निर्माण में उनके इनपुट प्राप्त करने के लिए शामिल रहता है, उन्हें नियामक सहित दिवाला शासन के कामकाज के बारे में रिपोर्ट करना भी महत्वपूर्ण है, किए जा रहे कार्यों और प्रक्रियाओं के परिणामों की सूचना देना। इस प्रयास में, आईबीबीआई अपनी स्थापना के समय से ही त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। इनमें से पहला समाचार पत्र अक्टूबर-दिसंबर, 2016 की तिमाही के लिए प्रकाशित किया गया। समाचार पत्रों की सॉफ्ट प्रतियां व्यापक प्रसार के लिए आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। न्यूजलेटर कानूनी और नियामक विकास को समाहित करता है; संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति तिमाही के दौरान आईबीबीआई द्वारा क्षमता निर्माण की पहल और हिमायत और जागरूकता पैदा करने की गतिविधियां।

इस वर्ष के दौरान बेहतर पढ़ने और शोध अनुभव के लिए ई-बुक प्रारूप और एमएस एक्सेल प्रारूप में समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।

सी.4 अनुसंधान

दिवाला और शोधन अक्षमता जैसे उभरते हुए क्षेत्र में, भविष्य की नीति निर्माण को सूचित करने के लिए साहित्य और बाजार की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आईबीबीआई आईपीए और शिक्षाविदों के माध्यम से अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा दे रहा है। इसका एक अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग है जो (क) प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित डेटा का मिलान और विश्लेषण, (ख) त्रैमासिक न्यूजलेटर और ब्रोशर प्रकाशन, (ग) वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन, और (घ) केस स्टडीज के लिए बाहरी शोधकर्ताओं के साथ समन्वय, अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन आदि करता है।

आईबीबीआई अनुसंधान पहल

आईबीबीआई, अनुसंधान को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में – कानूनी, आर्थिक और अंतःविशय – और सामान्य रूप से विकसित दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रवचन, और भारत में, 01 जुलाई, 2019 को आईबीबीआई अनुसंधान पहल, 2019 की घोषणा की। इस पहल को 31 जुलाई, 2020 को अपडेट किया गया है शोधकर्ता एक शोध प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जिसे आईबीबीआई द्वारा जांचा गया है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह उचित रूप से संरचित है और पहल के अधीन कवर किया गया है। मानदंड पर एक बाहरी रेफरी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी: (क) क्या प्रस्ताव भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है और (ख) क्या प्रस्ताव उक्त मुद्दे को हल करने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली प्रदान करता है। यदि बाहरी रेफरी की सलाह पर आईबीबीआई द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो शोधकर्ता को छह महीने के भीतर शोध पत्र जमा करना होगा। शोध पत्र की समीक्षा बाहरी रेफरी द्वारा समान रूप से की जाती है।

श्री एम. पी. राम मोहन और सुश्री विशाखा राज नाम के दो शोध विद्वानों ने 'आईआरपी के लिए विलय नियंत्रण: क्या संकटग्रस्त फर्मों के अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा की जांच जरूरी है?' विशय पर शोध पत्र पूरा किया। पेपर में पाया गया है कि जहां समाधान योजनाओं को स्वतः अनुमोदन देने के लिए ग्रीन चैनलिंग दिवाला प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को आसान बना देगा, वहीं समाधान योजनाओं के अधीन संयोजनों के प्रभाव को दिवाला शासन से परे महसूस किया जा सकता है और इसका विस्तार हितधारकों तक हो सकता है जैसे कि उपभोक्ताओं, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों, आदि, यह ग्रीन चैनलिंग के विकल्प के रूप में दो शासनों के बीच समन्वय के मौजूदा तंत्र का सुझाव देता है।

डॉ. (सुश्री) नीति शिखा और सुश्री उर्वशी शाही द्वारा 'कोर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन टाइमलाइन का आकलन' विषय पर एक अन्य शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। यह पेपर सीआईआरपी में चरणवार देरी और क्षेत्रीय भेदभाव और सीडी के ऋण आकार में देरी के संबंध की जांच करता है। अध्ययन में पाया गया है कि सीआईआरपी में देरी सीडी द्वारा असहयोग, सीडी द्वारा सूचना के उचित दस्तावेज की कमी, एनसीएलटी की अपर्याप्त क्षमता और दबावग्रस्त संपत्तियों के विपणन में कठिनाई जैसे कारणों से हो रही है।

वार्षिक प्रकाशन

विचारों, समाचारों और राय को साझा करके जागरूकता विकसित करने और प्रामाणिकता के साथ संरचित तरीके से विस्तृत जानकारी का प्रसार करने के लिए, और संहिता की समझ में सुधार करने के लिए, आईबीबीआई ने वार्षिक प्रकाशन को दिवाला और शोधन अक्षमता ढांचा पर ज्ञान के साथ लेखों के संग्रह के रूप में पेश किया। ढांचा। आईबीबीआई ने अपना दूसरा प्रकाशन 'इनसॉल्वेंसी एंड बैकरोपी रिजिम इन इंडिया: ए नैरेटिव' शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसका अनावरण 01 अक्टूबर, 2020 को श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किया गया। प्रकाशन में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दिवाला, शोधन अक्षमता, वित्त और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर लिखे गए 36 व्यावहारिक लेख शामिल हैं। यह प्रेक्टीशनरों, नीति निर्माताओं, विशय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के विचारों और दृष्टिकोणों, जो आईबीसी की यात्रा के बारे में विचार को स्पष्ट और उत्तेजित करते हैं और आगे के मार्ग को प्रस्तुत करता है। यह दिवाला कानून के इर्द-गिर्द एक विद्वतापूर्ण बहस और नीतिगत विमर्श उत्पन्न करने का एक प्रयास है।

उभरते न्यायशास्त्र का संग्रह

एक गतिशील और प्रगतिशील आर्थिक कानून के रूप में, संहिता को समृद्ध न्यायशास्त्र से संपन्न किया गया है। हितधारकों के लाभ के लिए, आईबीबीआई ने '31 मार्च, 2021 तक आईबीसी पर खंड-वार न्यायशास्त्र' प्रकाशित किया, जो कारपोरेट दिवाला कार्यवाही में न्यायशास्त्रीय विकास पर उपयोगकर्ता के अनुकूल मार्गदर्शन प्रदान करता है।

'अंडर्सटैंडिंग दा आईबीसी - की ज्युरिसप्रयुडेंस एंड प्रक्टिकल कंसिडरेशन' पर हैंडबुक

आईबीबीआई ने आईबीबीआई के साथ किए गये एक सहयोग समझौते के अनुसरण में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार किए गए 'अंडर्सटैंडिंग दा आईबीसी: की ज्युरिसप्रयुडेंस एंड प्रक्टिकल कंसिडरेशन' शीर्षक से आईपी के लिए एक हैंडबुक जारी की। हैंडबुक अपनी सभी बारीकियों के साथ दिवाला के विकसित अनुशासन को पकड़ती है और इसका उद्देश्य आईपी और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करना है, जो कानून और व्यवहार के इस उभरते हुए क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं।

आईपी के लिए नैतिकता पर हैंडबुक

डॉ. नवरंग सैनी, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई, सुश्री नताली टॉम्स, चीफ इकॉनॉमिस्ट एंड काउंसलर, ब्रिटिश उच्चायोग की उपस्थिति में, 19 मार्च, 2012 को आयोजित वेबिनार में "हैंडबुक ऑन एथिक्स फोर इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स : एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क" शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया। ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से आईबीबीआई द्वारा तैयार की गई हैंडबुक यूनाइटेड किंगडम में आईपी द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के इनपुट पर आधारित है और इसका उद्देश्य आईपी के बीच नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करना है। यह हैंडबुक नैतिक आचार संहिता को आत्मसात करने और प्रेक्टिस करने के लिए दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में आईपी और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए तैयारशुदा रेकनर और उपकरण के रूप में कार्य करती है।

आईपी के लिए न्यायशास्त्र पर हैंडबुक

आईबीबीआई के साथ सहयोग समझौते के अनुसरण में अंतराष्ट्रीय वित्तीय निगम, विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार की गई 'आईबीसी को समझना: प्रमुख न्यायशास्त्र और व्यावहारिक विचार' शीर्षक वाली आईपी के लिए एक हैंडबुक 01 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई थी। हैंडबुक दिवाला के विकसित अनुशासन को दर्शाती है। इसकी सभी बारीकियों के साथ और आईपी, और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में सेवा करने का इरादा है, जो कानून और अभ्यास के इस उभरते क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं।



बोर्ड के कार्य

बोर्ड संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप, संहिता आईबीबीआई को कई वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों का प्रभार सौंपती है। यह दिवाला व्यवसाय के साथ-साथ दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह आईपी, आईपीए, आईपीई और आईयू पर नियामक निगरानी रखता है। इसे संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे कि कारपोरेट दिवाला समाधान, फास्ट ट्रैक समाधान, कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, नई शुरुआत, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके पास संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए, और आईयू और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देने और उनके कार्यकाज और प्रथाओं को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। यह देश में मूल्यांकक व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए मूल्यांकन नियमों के अधीन 'प्राधिकरण' भी है।

एक नियामक आम तौर पर खेल के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, सेवा प्रदाताओं के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी करता है और नियमों का अनुपालन करता है, और फिर उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति करें। यह विनियमनों की 'मेक-ऑपरेट-रिव्यू' के चक्र में कार्य करता है। संहिता की धारा 196 बोर्ड के 'मेक-ऑपरेट-रिव्यू' कार्यों की गणना करती है, जिसे मोटे तौर पर तीन सेटों में बांटा जा सकता है, अर्थात्,

(क) अर्ध-विधायी कार्य : बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है;

(ख) कार्यकारी कार्य : बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सीपीई के माध्यम से व्यावसायिक विकास के उपाय करता है तथा

(ग) अर्ध-न्यायिक कार्य : बोर्ड उनके व्यवस्थित कार्यकाज को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों पर निर्णय लेता है। इन कार्यों में से प्रत्येक को आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों को इस खंड में सूचीबद्ध किया गया है।

अर्ध-विधायी कार्य

नियामक को नियामक नीति को नियामक उपकरणों में विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इसमें हस्तक्षेप के उद्देश्य की पहचान करना और कार्रवाई के लिए मामले का आकलन करना, पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, उनमें से प्रत्येक का

मूल्यांकन करना और चुनाव करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह नियामक प्रभाव मूल्यांकन (आरआईए) अभ्यास है जिसे किसी मौजूदा विनियमन/समीक्षा करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

संहिता आईबीबीआई को दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर नियम और निदेश निर्देश बनाने और आईपीए, आईपी और आईयू को निदेश निर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है। संहिता की धारा 240 आईबीबीआई को इस शर्त के अधीन विनियमन बनाने में सक्षम बनाती है कि विनियमन: (क) संहिता के प्रावधानों को पूरा करेंगे, (ख) संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे (ग) आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किए जाएंगे, और (घ) यथा-संभव, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिनों के लिए रखे जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि यह कम से कम संभव लागत पर बाजार की चिह्नित विफलता को संबोधित करता है और यह अत्यधिक नहीं है। बोर्ड का प्रयास एक संरचित व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने का रहा है जो विनियमन बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाता है। नियामक प्रक्रिया में जनता, विशेष रूप से हितधारकों और विनियमित की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि विनियमनों में रुचि रखने वालों और नियमों से प्रभावित लोगों की वैध जरूरतों से विनियमनों को सूचित किया जाता है। यह किसी भी हित समूह के अनुचित प्रभाव की धारणा को दूर करते हुए लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है।

प्रक्रिया आमतौर पर एक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) के साथ मसौदा विनियमन बनाने के साथ शुरू होती है। मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करने और विनियमनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए डब्ल्यूजी की स्थापना की प्रथा का उपयोग सरकार द्वारा संहिता के प्रावधानों को लागू करने के प्रारंभिक चरणों में किया गया था। इस अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई नियामक मुद्दों में गहराई से जाने और मसौदा नियमों का सुझाव देने के लिए डब्ल्यूजी का गठन करता है। इसके बाद यह उन मुद्दों की समझ को फिर से सत्यापित करने के लिए हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में मसौदा नियमों पर चर्चा करता है, और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसे नियमों की उपयुक्तता। यह प्रत्येक मसौदा विनियमन और उप-विनियमन पर इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से जनता की टिप्पणियां प्राप्त करता है, और मसौदा विनियमनों पर संबंधित एसी की सलाह प्राप्त करता है। विनियमन बनाने की प्रक्रिया जीबी को अंतिम रूप देने और नियमों को मंजूरी देने, जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, गोलमेज पर प्राप्त प्रतिक्रिया और एसी की सलाह के साथ समाप्त होती है। आईबीबीआई ने नियम बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए 22 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 जारी किया है।

सर्वोत्तम प्रयासों और इरादों के बावजूद, एक नियामक के पास हमेशा जमीनी हकीकत पर, खासकर गतिशील वातावरण में, जितना अधिक और जितना जल्दी हितधारक कर सकते हैं, पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं हो सकता है। इसलिए, हितधारक नियम बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे खाली समय में, मौजूदा नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकते हैं जो लेनदेन में बाधा डालते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए वैकल्पिक समाधान प्रदान करते हैं। निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तावित विनियमनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सामान्य परामर्श के अलावा, आईबीबीआई हितधारकों को उनके लिए आवश्यक विनियमनों का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। यह विचारों के क्राउडसोर्सिंग के समान है। यह हर विचार को नियामक तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। नतीजतन, नियामक के पास उपलब्ध विचारों का दायरा बहुत बड़ा है और अधिक अनुकूल नियामक ढांचे की संभावना बहुत अधिक है। आईबीबीआई ने अप्रैल, 2019 में मौजूदा विनियमनों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। इसने दिसंबर, 2019 तक प्राप्त टिप्पणियों को संसाधित किया और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए, मार्च, 2020 तक विनियमनों को आवश्यक सीमा तक संशोधित किया।

बोर्ड ने 2016-17 में दस विनियमनों को अधिसूचित किया था। इसने 2017-18 में चार नए विनियमनों और 2018-19 में एक को अधिसूचित किया। 2019-20 में, बोर्ड ने दो नए विनियमनों को अधिसूचित किया। 2020-21 में कोई नया नियम अधिसूचित नहीं किया गया था। हालांकि, समय-समय पर कुछ मौजूदा विनियमनों में संशोधन किए गए, जैसा कि सारणी 11 में बताया गया है। इन विनियमनों और संशोधनों में से प्रत्येक का विवरण रिपोर्ट के खंड ग के संबंधित उप-अनुभागों के अधीन प्रदान किया गया है।

सारणी 11 : 2020-21 में अधिसूचित विनियमन

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	विनियमन
1	20.04.20*	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2020
2	20.04.20**	आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियमन, 2020
3	20.04.20**	आईबीबीआई (आदर्श उप-कानून और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2020
4	20.04.20^	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2020
5	20.04.20	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020
6	30.06.20	आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020
7	05.08.20	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2020
8	05.08.20	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2020
9	07.08.20	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2020
10	13.11.20	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2020
11	13.11.20	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियमन, 2020

12	13.11.20	आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएं) (संशोधन) विनियमन, 2020
13	14.01.21	आईबीबीआई (आदर्श उप-कानून और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2021
14	04.03.21	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2021
15	15.03.21	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2021

नोट: *25 मार्च, 2020 से प्रभावी **28 मार्च, 2020 से प्रभावी ^ 29 मार्च, 2020 से प्रभावी

विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा विनियमनों/नीतियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई स्वयं या उद्योग, व्यावसायिक संस्थानों, आईपीए और आरवीओ के सहयोग से, अपने नियमों को अंतिम रूप देने से पहले पूरे भारत में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि में आयोजित ऐसे गोलमेज सम्मेलनों की सूची खंड सी की सारणी 10 में प्रदान की गई है। सारणी 12 विभिन्न विशयों के लिए गोलमेजों की संख्या का सारांश है।

सारणी 12 : विद्ययवार गोलमेज आयोजन

विद्यय	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
संहिता के अधीन सेवा प्रदाता	04	02	--	01	02	07
कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाएं - दिवाला समाधान, फास्ट ट्रेक समाधान, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन	04	11	07	03	08	33
व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रियाएं	--	10	01	02	-	13
मूल्यांकन	--	18	--	11	-	29
सीमा पार दिवाला	--	--	03	--	-	03
जारी कंसर्न बिक्री और समूह दिवाला	--	--	04	--	-	04
प्री-पेक्स/एमएसएमई	--	--	--	--	04	04
अन्य	--	04	10	07	05	26
कुल	08	45	25	24	19	121

सलाहकार समितियां

नियामकों की स्थापना करने वाले अधिकांश कानून आम तौर पर उभरते विचारों के लिए एक साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करने और नियामक को व्यावसायिक ज्ञान और डोमेन ज्ञान देने के लिए स्थायी एसी के गठन के लिए प्रदान करते हैं। कई नियामकों ने स्वेच्छा से एसी का गठन किया है। आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 (सलाहकार समिति विनियमन) के अनुसार तीन स्थायी एसी का गठन किया है। इन समितियों में सदस्यों के दो समूह शामिल हैं, अर्थात् व्यावसायिक सदस्य जो संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद और व्यवसायी हैं, और सामान्य सदस्य जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिनका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, मोटे तौर पर 2:1 के अनुपात में। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक

एसी का सदस्य नहीं हो सकता है और एक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होता है, हालांकि उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है। एक एसी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर बोर्ड को सलाह दे सकता है और बोर्ड के अनुरोध पर अपने दायरे में किसी भी मुद्दे पर सलाह देगा और व्यवसायवर सहायता प्रदान करेगा।

(क) सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति : इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार समिति के विनियमनों के जारी होने के साथ, समिति को 30 अगस्त, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 26 मई, 2020 को पुनर्गठित किया गया था। 31 मार्च, 2021 को इसकी संरचना सारणी 13 में दी गई है।

सारणी 13: सेवा प्रदाताओं सम्बंधी सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और पद	समिति में स्थिति
1	श्री टी. वी. मोहनदास पाई, अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज	अध्यक्ष
2	एमसीए के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3	श्री अखिल गुप्ता, अध्यक्ष, भारती इंफ्रास्टेल लिमिटेड	सदस्य
4	डॉ. बिमल एन. पटेल, महानिदेशक, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय	सदस्य
5	डॉ. बिनाय जे. कट्टाडियिल, एमडी, आईसीएसआई के आईआईपी	सदस्य
6	श्री चिन्ना वीरप्पन राजेंद्रन, एमडी और सीईओ, सीएसबी बैंक	सदस्य
7	श्री जे. रंगनायकुलु, पूर्व ईडी, सेबी	सदस्य
8	श्री पी. आर. रमेश, पूर्व अध्यक्ष, डेलॉइट इंडिया	सदस्य
9	डॉ. पूनम सहगल, पूर्व डीन और प्रोफेसर, आईआईएम, लखनऊ	सदस्य
10	डॉ समीर शर्मा, डीजी और सीईओ, आईआईसीए	सदस्य
11	श्री श्रीकृष्ण कुलकर्णी, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईएम, कलकत्ता	सदस्य
12	श्री वेल्लयन सुब्बैया मुरुगप्पा, एमडी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड।	सदस्य

(ख) सलाहकार समिति कारपोरेट दिवाला और परिसमापन : इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार समिति के विनियमनों के जारी होने के साथ, समिति को 25 अगस्त, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 26 सितंबर, 2020 को पुनर्गठित किया गया था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इसकी संरचना सारणी 14 में दी गई है।

सारणी 14 : कारपोरेट दिवाला और परिसमापन पर सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और पद	समिति में स्थिति
1	श्री उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी, कोटक महिंद्रा बैंक	अध्यक्ष
2	एमसीए के एक प्रतिनिधि	सदस्य

3	श्री आशीश कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड	सदस्य
4	सुश्री आशु सुयश, एमडी और सीईओ, क्रिसिल	सदस्य
5	श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड	सदस्य
6	श्री निर्मल मोहंती, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सदस्य
7	प्रो (डॉ.) रणबीर सिंह, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
8	श्री आर के नायर, पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, आईआरडीएआई	सदस्य
9	श्री आर. शंकर रमन, पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	सदस्य
10	राशेश शाह, चेयरमैन और सीईओ, एडलवाइस ग्रुप	सदस्य
11	श्री सोमशेखर सुंदरसन, कानूनी परामर्शदाता	सदस्य
12	अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ	सदस्य
13	आईसीएआई के एमडी, आईपीए	सदस्य

(ग) व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता सलाहकार समिति : इसका गठन 15 सितंबर, 2017 को तीन साल की अवधि के लिए किया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था।

कार्यकारी कार्य

ऑपरेटिंग विनियमन अधिसूचित विनियमनों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू करने की प्रक्रिया है। विनियमनों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, कई गतिविधियाँ, जो कार्यकारी कार्यों की प्रकृति की होती हैं, की जाती हैं।

दिवाला व्यावसायिक

31 दिसंबर, 2016 तक, 977 व्यक्तियों को आईपी विनियमनों के विनियमन 9 के अधीन छह महीने की सीमित अवधि के लिए आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर, 2016 से, जिन व्यक्तियों के पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, और एक आईपीए (01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी) के एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के बाद पूर्व-रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। इस श्रेणी में, 31 मार्च, 2021 तक 3520 व्यक्तियों को आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जिनमें से चार व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, दो पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे और 10 की मृत्यु हो गई। आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति को पहले आईपीए के साथ नामांकित होना आवश्यक है। 31 मार्च, 2021 को तीन आईपीए रजिस्ट्रीकृत किए गए थे। आईपी के रजिस्ट्रीकरण का विवरण, आईपीए वार, सारणी 15 में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2021 को रजिस्ट्रीकृत आईपी का क्षेत्रवार वितरण सारणी 16 में प्रस्तुत किया गया है।

आईपी को 01 जनवरी, 2020 से संहिता के अधीन असाइनमेंट लेने के लिए एएफए की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने संबंधित आईपीए को एएफए जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और आईपीए को सक्षम करने के लिए आईपी को सक्षम करने के लिए ऐसे अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। 31 मार्च, 2021 तक 2532 आईपी को एएफए जारी किया गया।

सारणी 15 : आईपी के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण का निरस्तन

तिमाही	तिमाही/वर्ष के दौरान				तिमाही के अंत में रजिस्ट्रीकृत			
	रजिस्ट्रीकृत	के कारण निरस्त			आईआईआईपीआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईपीए आईसीएआई	कुल
		अनुशासनात्मक कार्यवाही	पात्रता मानकों को पूरा करने में विफल	मौत				
अक्तूबर- दिसंबर, 2016'	977	0	0	0	713	221	43	977
2016-17	96	0	0	0	33	51	12	96
2017-18	1716	0	0	0	1069	509	138	1812
2018-19	648	4	0	0	418	173	53	2456
2019-20	554	0	1	5	338	164	46	3004
अप्रैल- जून, 2020	120	0	1	1	79	29	10	118
जुलाई-सितंबर, 2020	61	0	0	1	38	13	9	60
अक्तूबर-दिसंबर, 2020	129	0	0	2	74	32	21	127
जनवरी-मार्च, 2021	196	0	0	1	131	45	19	195
कुल	3520	4	2	10	2180	1016	308	3504

'ये पंजीकरण 30 जून, 2017 को समाप्त हो गए।

आईपी को 01 जनवरी, 2020 से संहिता के अधीन असाइनमेंट लेने के लिए एएफए की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने संबंधित आईपीए को एएफए जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और आईपीए को सक्षम करने के लिए आईपी को सक्षम करने के लिए ऐसे अनुप्रयोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। 31 मार्च, 2021 तक 2532 आईपी को एएफए जारी किया गया।

सारणी 16 : 31 मार्च, 2021 को आईपी का वितरण

(संख्या)

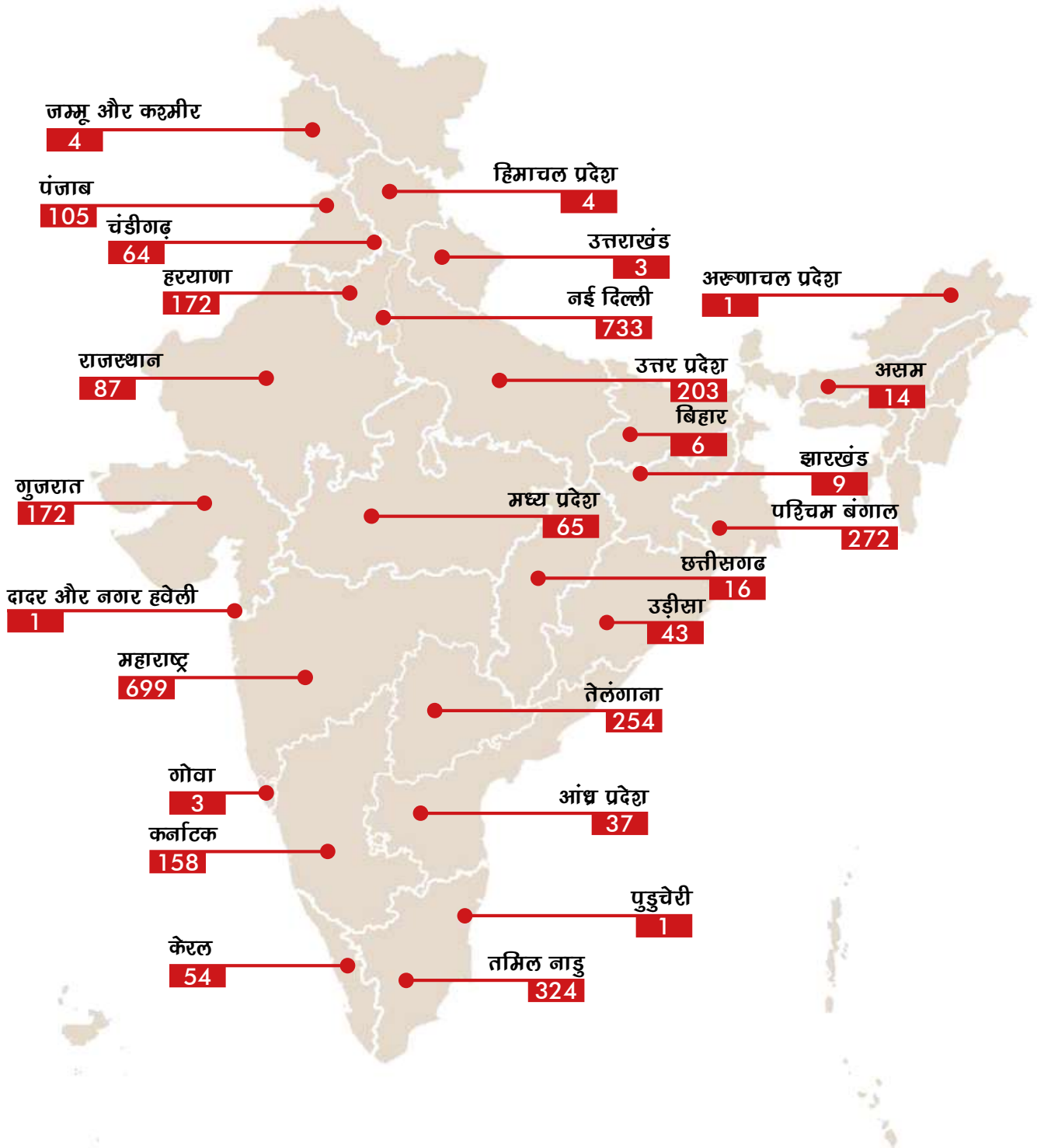
शहर/क्षेत्र	आईआईआईपीआई	आईसीएसआई आईआईआईपी	आईपीएआईसीएआई	कुल
नई दिल्ली	407	255	75	737
शेष उत्तरी क्षेत्र	396	188	59	643
मुंबई	377	140	34	551
शेष पश्चिमी क्षेत्र	266	105	38	409
चेन्नई	129	83	12	224
शेष दक्षिणी क्षेत्र	350	197	62	609
कोलकाता	199	36	22	257
शेष पूर्वी क्षेत्र	60	23	7	90
कुल रजिस्ट्रीकृत	2184	1027	309	3520
निरस्त और समाप्त	7	7	2	16
कुल	2177	1020	307	3504

आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएआई (लागत) या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति या प्रबंधन में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। सारणी 17 31 मार्च, 2021 को उनकी योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण प्रस्तुत करती है (एक आईपी एक से अधिक संस्थानों का सदस्य हो सकता है)। 3504 आईपी में से, 318 आईपी, रजिस्ट्रीकृत आईपी के लगभग 9 प्रतिशत महिला हैं। सारणी 18 31 मार्च, 2021 को रजिस्ट्रीकृत आईपी की आयु प्रोफाइल प्रस्तुत करती है।

सारणी 17 : 31 मार्च, 2021 को योग्यता के अनुसार आईपी का वितरण

पात्रता	आईपीज की संख्या		
	पुरुष	स्त्री	कुल
आईसीएआई के सदस्य	1748	157	1905
आईसीएसआई के सदस्य	523	101	624
आईसीएआई के सदस्य (लागत)	168	15	183
बार काउंसिल के सदस्य	204	24	228
प्रबंधकीय अनुभव	543	21	564
कुल	3186	318	3504

चित्र 2 : 31 मार्च, 2021 को आईपी का भौगोलिक वितरण ।



सारणी 18 : 31 मार्च, 2021 को आईपी की आयु प्रोफाइल

आयु समूह (वर्षों में)	रजिस्ट्रीकृत आईपीज				एफए वाली आईपीज			
	आईआईआईपीआई	आईसीएसआईआईआईपी	आईपीएआईसीएआई	कुल	आईआईआईपीआई	आईसीएसआईआईआईपी	आईपीएआईसीएआई	कुल
≤ 40	255	63	6	324	174	49	4	227
> 40 ≤ 50	775	363	50	1188	564	272	40	876
> 50 ≤ 60	684	277	78	1039	497	211	55	763
> 60 ≤ 70	429	288	163	880	312	224	130	666
> 70 ≤ 80	30	26	8	64	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
> 80 ≤ 90	3	3	2	8	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
> 90	1	0	0	1	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
कुल	2177	1020	307	3504	1547	756	229	2532

उ. न. : लागू नहीं

दिवाला व्यावसायिक एंटीडीज

एक आईपीई उन आईपी को सहायता सेवाएं प्रदान करता है जो इसके भागीदार या निदेशक हैं। 31 मार्च, 2021 तक 83 आईपीई थे। आईपीई की मान्यता का तिमाही विवरण सारणी 19 में दिया गया है।

सारणी 19 : 31 मार्च, 2021 को मान्यता प्राप्त आईपीई

वर्ष/तिमाही	आईपीईज की संख्या		
	मान्यता प्राप्त	गैर-मान्यता प्राप्त	तिमाही के अंत में
2016-17	3	0	3
2017-18	73	1	75
2018-19	13	40	48
2019-20	23	2	69
अप्रैल-जून, 2020	4	0	73
जुलाई-सितंबर, 2020	1	0	74
अक्टूबर-दिसंबर, 2020	3	0	77
जनवरी-मार्च, 2021	6	0	83
कुल	126	43	83

आरपी के साथ आईआरपी का प्रतिस्थापन

संहिता की धारा 22(2) में प्रावधान है कि सीओसी अपनी पहली बैठक में, एफसी के वोटिंग शेयर के कम से कम 66 प्रतिशत के बहुमत से, या तो आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त करने या बदलने का संकल्प ले सकती है। आरपी के रूप में कार्य करने के लिए दूसरे आईपी द्वारा आईआरपी। संहिता की धारा 22(4) के अधीन, एए संहिता की धारा 22(3)(बी) के अधीन सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम को इसकी पुष्टि के लिए आईबीबीआई को अग्रशित करेगा और इस तरह की पुष्टि के बाद ऐसी नियुक्ति करेगा। हालांकि, इस तरह के संदर्भ में समय बचाने के लिए, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सभी आईपी का एक डेटाबेस एए के साथ साझा किया गया है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि क्या उनके खिलाफ और उनके एफए की स्थिति के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। जबकि डेटाबेस वर्तमान में एए के विभिन्न पीछों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, कुछ मामलों में, आईबीबीआई को एए से संदर्भ प्राप्त होते हैं और एए को तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। 31 मार्च, 2021 तक कुल 3538 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि

सारणी 20 में दिखाया गया है।

सारणी 20: 31 मार्च, 2021 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापित करना

सीआईआरपी द्वारा शुरू किया गया	सीआईआरपीज की संख्या	
	जहां आरपी नियुक्त किया गया है	जहां आरपी आईआरपी से भिन्न है
कारपोरेट आवेदक	259	111
परिचालन लेनदार	1621	557
वित्तीय लेनदार	1658	338
कुल	3538	1006

आईपी का पैनेल

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान निम्नानुसार चार पैनेल तैयार किए :

(i). आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिकों को आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटीज के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) निदेश -निर्देश, 2020 के अनुसार, 01 जुलाई, 2020 - 25 नवंबर, 2020 के दौरान नियुक्तियों के लिए बेंच-वार पैनेल तैयार किया।

(ii) आईबीबीआई ने दिवाला व्यावसायिक के अनुसार आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटीज को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (सिफारिश) निदेश -निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करने के लिए, 26 नवंबर, 2020 - 30 जून, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए जोन-वार पैनेल तैयार किया।

(iii) सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन प्रशासक के रूप में दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निदेश निर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने अक्टूबर, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान प्रशासकों के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी का पैनेल तैयार किया; तथा

(iv) सेबी (निवेशकों को धन वापसी के लिए प्रशासक और प्रक्रिया की नियुक्ति) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति के लिए निदेश निर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने अप्रैल-सितंबर, 2021 के दौरान नियुक्तियों के लिए आईपी का एक पैनेल तैयार किया।

पैनेल में शामिल होने की प्रक्रिया स्वचालित है जिससे आईपी पैनेल में

शामिल होने के लिए ऑनलाइन अपनी मंशा व्यक्त करते हैं। इन पैनलों का विवरण सारणी 21 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 21 : 2020-21 के दौरान तैयार किए गए आईपी के पैनल

क्र. सं.	पैनल की तारीख	के अधीन पैनल	पैनल में जोनों की संख्या	पैनल में आईपी की संख्या
1	04.06.20	दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे	15	978
2	24.09.20	सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेश	15	698
3	23.11.20	दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे	15	344

4	26.12.20	दिवाला व्यावसायिक अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (सिफारिश) (द्वितीय) निदेश निर्देश, 2020 के रूप में कार्य करेंगे	15	824
5	30.03.21	सेबी (निवेशकों को धनवापसी के लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेश निर्देश	13	617

क्षमता निर्माण

आईपी और सीओसी के लिए कार्यशालाएं

आईबीबीआई का यह प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के आसपास सेवा प्रदाताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य तत्वों की क्षमता का निर्माण किया जाए। यह आईपी के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करता है, जिसका विवरण सारणी 22 में दिया गया है। आईबीबीआई ने अन्य हितधारकों जैसे छात्रों, सरकारी अधिकारियों, आम जनता के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण सारणी 23 में दिया गया है। आईबीबीआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम एफसी के लिए सारणी 24 में सूचीबद्ध हैं। देश में महामारी की स्थिति को देखते हुए, ये सभी कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे।

सारणी 22 : 2020-21 में आईपी के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	विषय	तारीख
1	वेबिनार	क्या करें और क्या न करें – व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का निरीक्षण और प्रभाव	01.04.20
2	वेबिनार	आईबीसी सीमा में छूट और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव	02.04.20
3	वेबिनार	ऑनलाइन सीआईआरपी फॉर्म और संबंध प्रकटीकरण और ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस पर आईबीसी का प्रभाव	03.04.20
4	वेबिनार	आईबीसी प्रक्रिया पर लॉकडाउन के दौरान और बाद में प्रभाव और व्यावहारिक मुद्दे और ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस पर आईबीसी का प्रभाव	07.04.20
5	वेबिनार	दिवाला समाधान और पीजी से सीडी तक शोधन अक्षमता और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव	08.04.20
6	वेबिनार	आईपी के लिए आचार संहिताय अनुशासनात्मक कार्यवाही और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव	11.04.20
7	वेबिनार	पीजी से सीडी तक दिवाला और शोधन अक्षमता और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव	14.04.20
8	वेबिनार	दिवाला कार्यवाही में मध्यस्थता का दायरा और व्यवसाय करने में आसानी पर आईबीसी का प्रभाव	17.04.20
9	वेबिनार	आईआरपी/आरपी के साथ संवादात्मक सत्र – सीआईआरपी में कोविड-19 महामारी के संबंध में उनके सामने आने वाली समस्याएं	06.05.20
10	वेबिनार	परिसमापकों के साथ संवादात्मक सत्र – कोविड-19 महामारी के संबंध में परिसमापन में उनके सामने आने वाले मुद्दे	09.05.20
11	वेबिनार	सूचना उपयोगिता – आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख स्तंभ, हाल ही हुए परिवर्तन	12.05.20
12	वेबिनार	श्री आर सुब्रमण्यकुमार, प्रशासक, डीएचएफएल के साथ अनुभव साझा करने के लिए सत्र	13.05.20
13	वेबिनार	आईबीसी के अधीन मूल्यांक कोविड-19 महामारी के कारण प्रभाव	15.05.20
14	वेबिनार	सीआईआरपी के दौरान सीडी का प्रबंधन जारी कंसर्न के रूप में संचालन प्रबंधन	22.05.20
15	वेबिनार	आईबीसी के अधीन परिहार्य लेन-देन की समीक्षा करना और उन्हें चुनौती देना : संपत्ति को अधिकतम कैसे करें	28.05.20
16	वेबिनार	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020	07.06.20
17	आईपी कार्यशाला	संहिता के अधीन परिसमापन के दौरान जारी कंसर्न के रूप में बिक्री पर 7वीं उन्नत आईपी कार्यशाला	21.08.20
18	वार्ता	सीआईआरपी: उभरते मुद्दों और चुनौतियों को समझना	19.09.20
19	वेबिनार	दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान: आगे का मार्ग	26.09.20
20	वेबिनार	परिसमापन प्रक्रिया में आने वाले मुद्दे और यूके में परिसमापन ढांचे का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में प्रयोज्यता	23.10.20

21	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईबीसी के अधीन आईपी के लिए आचार संहिता पर व्यावसायिक नैतिकता और विनियमनों पर ई-व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	21.11.20 & 22.11.20
22	वेबिनार	आईपी के लिए बातचीत कौशल का महत्व	26.11.20
23	वेबिनार	कारपोरेट बचाव के तंत्र के रूप में प्री-पैक दिवाला समाधान	30.11.20
24	आईपी कार्यशाला	आईपी के लिए 8वीं उन्नत कार्यशाला	14.12.20
25	वेबिनार	आईपी के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखने का महत्व	16.12.20
26	सम्मेलन	दिवाला कानून और सीआईएसजी @	18.12.20
27	वेबिनार	आईबीसी के अधीन परिहार लेनदेन का निर्धारण	05.02.21
28	वेबिनार	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी	08.03.21
29	आईपी कार्यशाला	आईपी के लिए 19वीं बुनियादी कार्यशाला	17.03.21
30	वेबिनार	प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया: आईएलसी की उप-समिति की रिपोर्ट	19.03.21
31	वेबिनार	परिसमापन प्रक्रिया के अधीन बिक्री और हितधारकों के लिए बेहतर प्राप्ति के लिए यूके की सर्वोत्तम प्रथाएं	23.03.21

सारणी 23 : 2020-21 में अन्य हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाएं, वेबिनार, सम्मेलन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	विषय	तारीख
1	वेबिनार	आईबीसी पर आईबीसी और राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी	19.07.20
2	वेबिनार	आईबीसी में समकालीन विकास	20.07.20
3	वेबिनार	आईबीसी के अधीन आजीविका के अवसर	23.07.20
4	वेबिनार	आईबीसी	10.08.20
5	वेबिनार	पत्रकारों के लिए आईबीसी	18.08.20
6	सम्मेलन	भारत में दबावग्रस्त आस्तियों में निवेश के अवसरों पर सम्मेलन	17.09.20
7	प्रशिक्षण कार्यक्रम	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	03.11.20
8	प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओडिशा सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	10.11.20
9	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	19.11.20
10	वेबिनार	आईबीसी और नियामक: आगे की राह	20.11.20
11	प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओडिशा सरकार के सीटी और जीएसटी विभाग के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	25.11.20
12	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों के लिए आईबीसी पर संवादात्मक सत्र	22.12.20
13	संगोष्ठी	आईबीसी	07.01.21
14	प्रशिक्षण कार्यक्रम	मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	08.01.21
15	प्रशिक्षण कार्यक्रम	झारखंड सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	18.01.21
16	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए आईबीसी पर उन्मुखीकरण सत्र	04.03.21

सारणी 24 : 2020-21 में आयोजित सीओसी कार्यशाला

क्र. सं.	तारीख	विषय	के साथ साझेदारी
1	29.01.21	सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान	एसबीआई
2	03.02.21	सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान	एसबीआई
3	11.02.21	सीओसी – पब्लिक ट्रस्ट का एक संस्थान	एसबीआई

आईपीए भी अपने सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। सारणी 25 उनके द्वारा 2020-21 में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है। आईपीए द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकाशनों का विवरण सारणी 26 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 25 : 2020-21 में आईपीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या				लाभार्थियों की संख्या
	आईपीए आईसीएआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईआईआईपीआई	कुल	
प्रारंभिक पाठ्यक्रम	2	6	1	9	181
रजिस्ट्रीकरण-पूर्व पाठ्यक्रम	2	5	7	14	658
वेबिनार	38	19	33	90	82,483
कार्यशालाएं	4	16	2	22	3682
गोल मेज	6	7	10	23	1383
सेमिनार/सम्मेलन	1	-	6	6	255
कुल	53	53	59	164	88,642

सारणी 26 : 2020-21 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण

क्र. सं.	प्रकाशन की प्रकृति	प्रकाशन का नाम	सावधिकता	में प्रकाशित किया गया	अंकों की संख्या
आईपीए आईसीएआई					
1	ई-पत्रिका	दिवाला व्यावसायिक: आपका अंतर्दृष्टि जर्नल	मासिक	अप्रैल, 2020- मार्च, 2021	12
2	दैनिक नवीनतम जानकारी	आईबीसी-एयु कौरंट	दैनिक (सोमवार- शुक्रवार)	अप्रैल, 2020- मार्च, 2021	249
3	केसबुक	केसबुक	साप्ताहिक	अप्रैल, 2020- मार्च, 2021	36
4	केस कानून	आईबीसी डोजियर	साप्ताहिक	अप्रैल, 2020- मार्च, 2021	52
आईसीएसआई आईआईपी					
1	बेयर एक्ट	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 - नियमों और विनियमनों के साथ	जब भी अपडेट किया गया	2020	6
2	पुस्तिका	अंतरिम समाधान व्यावसायिक- एक पुस्तिका, तीसरा संस्करण	जब भी अपडेट किया जाता है	2019	3
3	पुस्तिका	स्वैच्छिक परिसमापन- एक पुस्तिका	जब भी अपडेट किया जाता है	2019	1
4	पुस्तक, टीका	दिवाला कानून के व्यावहारिक पहलू, चौथा संस्करण	जब भी अपडेट किया जाता है	2019	4
5	केस लॉ संकलन	एनसीएलएटी के 100 ऐतिहासिक फैसले	जब भी अपडेट किया जाता है	2019	1
6	केस लॉ संकलन	हितधारकों के लिए आईबीसी न्यायिक नियामक नियम, दूसरा संस्करण	जब भी अपडेट किया जाता है	2019	2
7	केस लॉ संकलन	आईबीसी लर्निंग कर्व्स संकलन	जब भी अपडेट किया जाता है	2020	1
8	केस लॉ संकलन	आईबीसी क बारे में अंतिम शब्द	जब भी अपडेट किया जाता है	2020	1
9	पुस्तक	एलआईई प्रिपरेटरी गाइड	जब भी अपडेट किया जाता है	2020	1
10	पत्रिका	रिजोल्व:आईबीसी जर्नल	मासिक	2018 से	
11	ज्ञान पहल	आईबीसी लर्निंग कर्व्स संकलन	मासिक	2019 से	25
12	ज्ञान पहल	आईबीसी लर्निंग कर्व	दैनिक	2019 से	524
13	प्रतिवेदन	रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के सीआईआरपी पर प्रदर्शन विश्लेषण रिपोर्ट।	एक बार	2021	1
आईआईआईपीआई					
1	पत्रिका	समाधान व्यावसायिक (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट वर्जन)	त्रैमासिक	अक्तूबर, 2020 और जनवरी, 2021	2
2	समाचार	आईआईआईपीआई न्यूजलेटर (सॉफ्ट कॉपी)	साप्ताहिक	अप्रैल 2020 - मार्च 2021	41
3	केस कानून	आईबीसी केस स्निपेट्स (19 मार्च 2021 से आईबीसी केस लॉ कैप्सूल का नाम बदला गया) (सॉफ्ट कॉपी)	साप्ताहिक	अप्रैल 2020 - मार्च 2021	39
4	सीआईआरपी केस स्टडीज/आईपी की सफलता की कहानियां	केस स्टडी : बिनानी सीमेंट लिमिटेड का प्रदर्शन विश्लेषण।	कभी कभी	अक्तूबर, 2020	2
		एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का केस स्टडी (सॉफ्ट कॉपी)	कभी कभी	फरवरी, 2020	
5	अनुसंधान अध्ययन	आईबीसी के तहत मुकदमेबाजी की समयबद्धता और प्रभावशीलता पर अनुसंधान-सह अध्ययन	कभी कभी	अक्तूबर, 2020	3
		समूह दिवाला के प्रक्रियात्मक और मूल पहलू: व्यावहारिक अनुभवों से सीख (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण)	कभी कभी	मार्च, 2021	
		आईबीसी के तहत सीआईआरपी में सीओसी की भूमिका: सर्वोत्तम प्रथाओं पर सिफारिशें (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण)	कभी कभी	मार्च, 2021	
6	प्रतिवेदन	24-25 अक्टूबर, 2020 को आईआईआईपीआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट करें (सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट संस्करण)	कभी कभी	नवम्बर, 2020	1
7	इलेक्ट्रॉनिक निर्णय संदर्भ	ई-न्यायशास्त्र	त्रैमासिक	जून, 2020	1

सतत व्यावसायिक शिक्षा निदेश निर्देश

एक आईपी को प्रासंगिक बने रहने और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सीपीई के माध्यम से खुद को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है। आईपी विनियमन तदनुसार प्रदान करते हैं कि एक आईपी को अपना रजिस्ट्रीकरण वैध रखने के लिए सीपीई से गुजरना होगा। आईबीबीआई ने आईपीए के परामर्श से आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिकों के लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा) निदेश निर्देश, 2019 को 6 अगस्त, 2019 को जारी किया। ये निदेश निर्देश 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी हैं। हालांकि, ये उन आईपी पर लागू नहीं होते हैं जिन्होंने पेंसठ वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है। इन्हें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सीपीई के न्यूनतम 10 क्रेडिट घंटे और तीन कैलेंडर वर्षों के प्रत्येक रोलिंग ब्लॉक में सीपीई के न्यूनतम 60 क्रेडिट घंटे करने के लिए एक आईपी की आवश्यकता होती है। एएफए किसी ऐसे आईपी को जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जो इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। आईपीए को अपने व्यावसायिक सदस्यों के संबंध में आईपी और बोर्ड के लिए सुलभ तरीके से सीपीई के रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना आवश्यक है। आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटों का विवरण सारणी 27 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 27 : 31 मार्च, 2021 को आईपी द्वारा निष्पादन सीपीई घंटे

अवधि	के सदस्यों द्वारा अर्जित सीपीई घंटों की संख्या			
	आईआईआईपीआई	आईएसएसआईआईआईपी	आईपीए आईसीएआई	कुल
जनवरी – मार्च, 2020	1160	695	320	2175
अप्रैल – जून, 2020	8198	5575	2373	16139
जुलाई – सितंबर, 2020	778	527	344	1649
अक्टूबर – दिसंबर, 2020	5675	1584	885	8103
जनवरी – मार्च, 2021	3814	1060	800	3749
कुल	19625	9441	4722	31815
प्रति रजिस्ट्रीकृत आईपी औसत सीपीई घंटे	9.01	9.26	15.38	9.08

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आरवीओ आरवी के लिए फ्रंटलाइन नियामक हैं। वे आरवी के व्यवसाय के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। 31 मार्च, 2021 के अंत में, 16 संस्थाओं को आरवीओ के रूप में मान्यता दी गई थी। एसेट क्लास लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में प्रत्येक में 14 आरवीओ और सिक्वोरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स में 15 आरवीओ हैं। एक व्यक्ति जो 'उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करता है और एक आरवीओ के साथ एक मूल्यांकक सदस्य के रूप में नामांकित है और उसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है और उसने संबंधित परिसंपत्ति वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। 31 मार्च, 2021 को आरवी, आरवीओ-वार का विवरण सारणी 28 में दिया गया है। 31 मार्च, 2021 तक तिमाही-वार आरवी का रजिस्ट्रीकरण सारणी 29 में दिया गया है।

सारणी 28 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी

(संख्या)

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन संगठन	परिसंपत्ति वर्ग			कुल
	भूमि और भवन	संयंत्र और मशीनरी	प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां	
आरवीओ एस्टेट प्रबंधक और मूल्यांकक फाउंडेशन	58	12	13	83
आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन	1245	199	148	1592
आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	0	0	161	161
आईआईवी इंडिया रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन	140	40	47	227
आईसीएमएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	21	16	244	281
आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	उ.न.	उ.न.	782	782
पीवीएआई मूल्यांकन व्यावसायिक संगठन	280	49	82	411
सीवीएसआरटीए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संघ	189	57	उ.न.	246
प्रमाणित मूल्यांकन और विश्लेषक संघ	उ.न.	उ.न.	2	2
सीईवी इंटीग्रल अप्रेजर्स फाउंडेशन	77	24	2	103
दिव्य ज्योति फाउंडेशन	24	8	28	60
नंददीप वैल्यूअर्स फाउंडेशन	0	0	0	0
अखिल भारतीय मूल्यांकन संस्थान फाउंडेशन	2	2	9	13
इंटरनेशनल बिजनेस वैल्यूअर्स एसोसिएशन	1	0	4	5

ऑल इंडिया वैल्यूअर्स एसोसिएशन	0	0	0	0
मूल्यांकनकर्ता और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन	0	0	0	0
कुल	2037	407	1522	3966

उ. न. : लागू नहीं है क्योंकि आरवीओ को एसेट क्लास के लिए मान्यता नहीं मिली है।

सारणी 29 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी का पंजीकरण

(संख्या)

वर्ष/तिमाही	भूमि और भवन संयंत्र	संयंत्र और मशीनरी	प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
2017 - 2018	0	0	0	0
2018 - 2019	781	121	284	1186
2019 - 2020	848	204	792	1844
जून, 2020	20	8	72	100
सितंबर, 2020	149	27	104	280
दिसंबर, 2020	130	22	185	337
मार्च, 2021	110	25	85	220
कुल	2038	407	1522	3967

टिप्पणी : 1 व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण फरवरी, 2021 में रद्द कर दिया गया था।

आरवी को मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इकाई (साझेदारी / कंपनी) बनाने की अनुमति है। 31 मार्च, 2021 को आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकृत 40 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसा कि सारणी 30 में प्रस्तुत किया गया है। सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए 18 संस्थाएं, दो परिसंपत्ति वर्गों में 4 संस्थाएं और एक परिसंपत्ति वर्ग में 18 संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत हैं।

सारणी 30 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकरण मूल्यांकक संस्थाएं

(संख्या)

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की संख्या	परिसंपत्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकरण		
		भूमि और भवन	संयंत्र व मशीनरी	प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां
आरवीओ एस्टेट प्रबंधक और मूल्यांकक फाउंडेशन	3	3	2	2
आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता फाउंडेशन	15	12	9	12
आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	1	0	0	1
आईआईवी इंडिया रजिस्ट्रीकृत वैल्यूअर्स फाउंडेशन	1	1	1	1
आईसीएमआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	6	3	4	6
आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	8	0	0	8
पीवीआई मूल्यांकन व्यावसायिक संगठन	2	2	2	2
अखिल भारतीय मूल्यांकन संस्थान फाउंडेशन	1	1	1	1
सीईवी इंटीग्रल अप्रेजर्स फाउंडेशन	1	1	1	0
दिव्य ज्योति फाउंडेशन	2	1	1	2
कुल	40	24	21	35

31 मार्च, 2021 तक रजिस्ट्रीकृत आरवी में से 1075 आरवी (रजिस्ट्रीकृत कुल आरवी का 27 प्रतिशत) महानगरों से हैं जबकि 2891 आरवी गैर-मेट्रो स्थानों (सारणी 31) से हैं। 31 मार्च, 2021 को आरवी का भौगोलिक वितरण चित्र 3 में प्रस्तुत किया गया है।

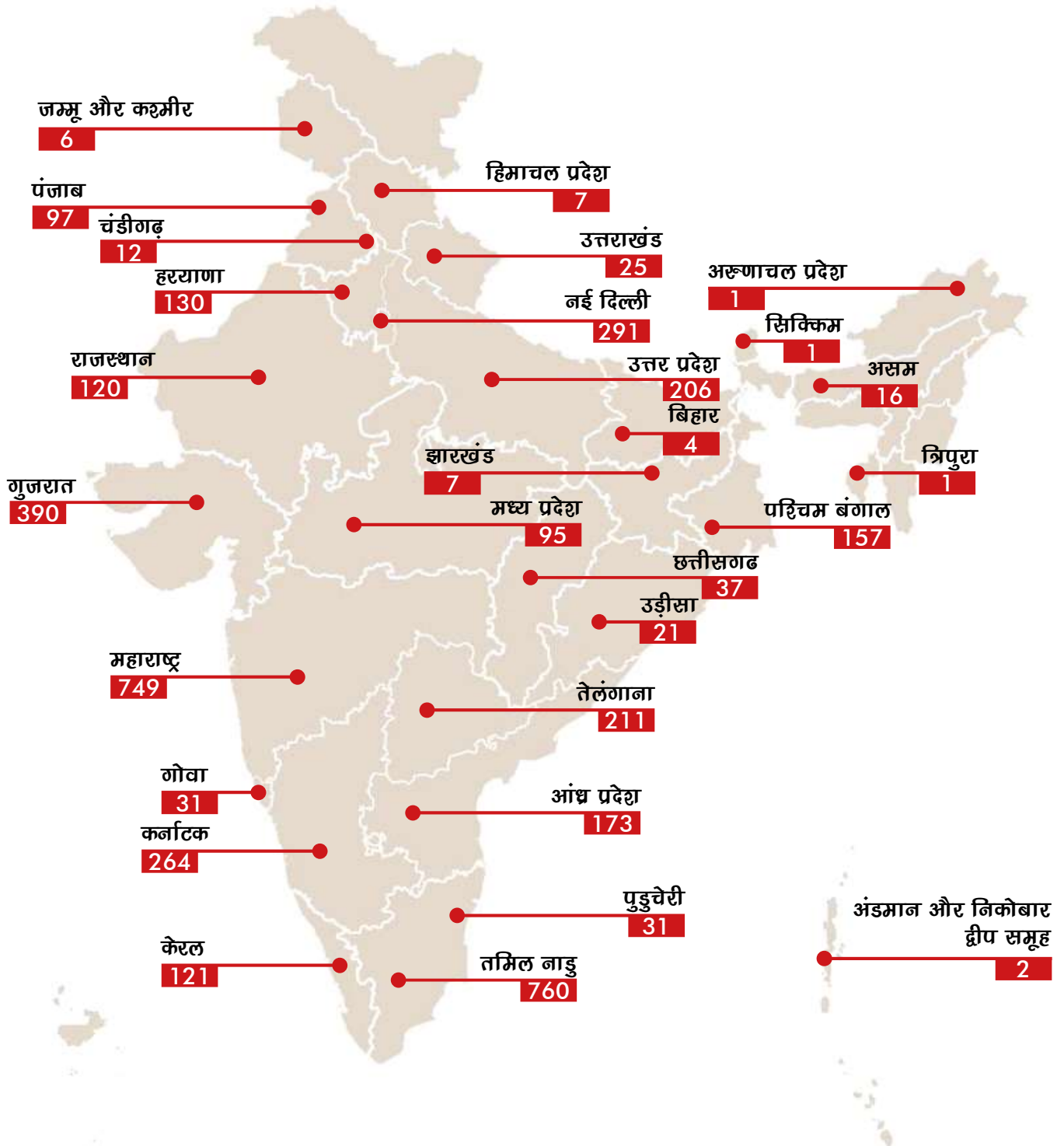
सारणी 31 : 31 मार्च, 2021 मार्च की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार आरवी

(संख्या)

शहर/ क्षेत्र	भूमि और भवन	संयंत्र व मशीनरी	प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
नई दिल्ली	69	33	186	288
शेष उत्तरी क्षेत्र	312	56	253	621

मुंबई	104	48	237	389
शेष पश्चिमी क्षेत्र	561	107	244	912
चेन्नई	110	36	120	266
शेष दक्षिणी क्षेत्र	828	106	361	1295
कोलकाता	23	14	95	132
शेष पूर्वी क्षेत्र	30	7	26	63
कुल	2037	407	1522	3966

चित्र 3 : 31 मार्च, 2021 को आरबी का भौगोलिक वितरण



31 मार्च, 2021 तक सभी परिसंपत्ति वर्गों में आरवी की औसत आयु 47 वर्ष थी। यह भूमि और भवन के लिए 49 वर्ष, संयंत्र और मशीनरी के लिए 53 वर्ष और प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 43 वर्ष थी (सारणी 32)। 3967 आरवी में से 372 आरवी (कुल आरवी का लगभग नौ प्रतिशत) महिलाएं हैं।

सारणी 32 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरवी की आयु प्रोफाइल

आयु समूह (वर्षों में)	भूमि और भवन	संयंत्र व मशीनरी	प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
≤ 30	117	6	103	226
> 30 ≤ 40	288	57	609	954
> 40 ≤ 50	511	93	451	1055
> 50 ≤ 60	856	123	243	1222
> 60 ≤ 70	230	86	113	429
> 70 ≤ 80	34	40	3	77
> 80	1	2	0	3
कुल	2037	407	1522	3966

(संख्या)

सीमित दिवाला परीक्षा

अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यक्षीन, एक व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है यदि उसने अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आईपी के साथ नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि को प्रकाशित करता है और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार इसकी समीक्षा करता है। इसने 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा शुरू की। परीक्षा का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा चरण, प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ, क्रमशः 01 जुलाई 2017, 01 जनवरी 2018, 01 नवंबर 2018, 01 जुलाई, 2019 और 01 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ऑनलाइन (एक अनुमानित वातावरण में कंप्यूटर आधारित) आयोजित की जाती है। यह देश भर के कई स्थानों से उपलब्ध है।

31 मार्च, 2021 तक कुल 12,893 उम्मीदवारों ने 35,526 नामांकन किए। इन 12,893 उम्मीदवारों में से 10,913 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और कुल 27,259 प्रयास किए, जिनमें से 4913 प्रयास (18.02 प्रतिशत प्रयास या 38.11 प्रतिशत उम्मीदवार) सफल रहे। इनमें से 476 पूर्वी जोन से, 1869 उत्तरी जोन से, 1412 पश्चिम जोन से और 1156 दक्षिण जोन से हैं। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 33 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 33 : 31 मार्च, 2021 तक क्षेत्रवार सीमित दिवाला परीक्षा

चरण	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
प्रथम चरण (दिसंबर, 2016-जनवरी 2017)	758	1952	1581	1038	5329	160	434	391	216	1201
द्वितीय चरण (जुलाई, 2017-दिसंबर, 2017)	528	2204	1699	1806	6237	86	401	316	309	1112
तीसरा चरण (जनवरी, 2018-अक्तूबर, 2018)	557	2338	1778	1671	6344	86	389	286	252	1013
चौथा चरण (नवंबर, 2018-जून, 2019)	252	1201	798	774	3025	45	218	127	115	505
पांचवा चरण (जुलाई, 2019-दिसंबर, 2020)	514	2162	1485	1699	5860	95	397	279	245	1016
छठा चरण (जनवरी, 2021-मार्च, 2021)	34	182	118	130	464	4	30	13	19	66
कुल	2643	10039	7459	7118	27259	476	1869	1412	1156	4913

टिप्पणी : कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 26 मई, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

मूल्यांकन परीक्षा

आईबीबीआई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन 'प्राधिकरण' होने के नाते, सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियां या वित्तीय संपत्तियां के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति को प्रकाशित करता है। इसने 31 मार्च, 2018 को तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यांकन परीक्षा शुरू की। मूल्यांकन परीक्षा का दूसरा और तीसरा चरण, प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ, क्रमशः 1 अप्रैल, 2019 और 01 जून, 2020 को शुरू हुआ। ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं और देश भर के कई स्थानों से उपलब्ध हैं।

भूमि और भवन

31 मार्च 2021 तक कुल 4777 उम्मीदवारों ने 20,690 नामांकन किए। 4777 उम्मीदवारों में से 4618 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए और 159 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हुए। 4618 उम्मीदवारों ने कुल 17,282 प्रयास किए, जिनमें से 2460 प्रयास सफल रहे। मूल्यांकन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 34 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 34 : संपत्ति वर्ग भूमि और भवन में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा

चरण	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
चरण 1 (मार्च '18-मार्च '19)	271	1162	2482	5554	9469	46	231	568	*903	1748
चरण 2 (अप्रैल '19-मई '20)	314	1143	902	1421	3780	23	138	96	*123	380
चरण 3 (जून '20- मार्च '21)	170	1080	1049	1734	4033	10	97	104	121	332
कुल	755	3385	4433	8709	17282	79	466	768	1147	2460

* एक उम्मीदवार ने दो बार परीक्षा उत्तीर्ण की।

नोट : कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

संयंत्र और मशीनरी

31 मार्च 2021 तक कुल 1066 उम्मीदवारों ने 3976 नामांकन किए। 1066 उम्मीदवारों में से 1010 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 56 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इन 1010 उम्मीदवारों ने कुल 3415 प्रयास किए, जिनमें से 488 प्रयास सफल रहे। मूल्यांकन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 35 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 35: संपत्ति वर्ग संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा

चरण	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
चरण 1 (मार्च '18-मार्च '19)	95	267	564	739	1665	16	61	136	111	324
चरण 2 (अप्रैल '19-मई '20)	98	204	184	271	757	10	28	24	33	95
चरण 3 (जून '20- मार्च '21)	99	254	306	334	993	6	20	23	20	69
कुल	292	725	1054	1344	3415	32	109	183	164	488

नोट : कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

प्रतिभूतियां या वित्तीय परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2021 तक कुल 4761 उम्मीदवारों ने 17,201 नामांकन किए। 4761 उम्मीदवारों में से 4392 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए और 369 उम्मीदवार मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इन 4392 उम्मीदवारों ने कुल 13,709 प्रयास किए, जिनमें से 1796 प्रयास सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 36 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 36 : परिसंपत्ति वर्ग प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों में क्षेत्रवार मूल्यांकन परीक्षा

चरण	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
चरण 1 (मार्च '18-मार्च '19)	450	1052	1198	1796	4496	58	159	225	265	707
चरण 2 (अप्रैल '19-मई '20)	461	1848	1126	1360	4795	46	241	*201	168	656
चरण 3 (जून '20- मार्च '21)	387	1249	1214	1568	4418	43	119	138	133	433
कुल	1298	4149	3538	4724	13709	147	519	564	566	1796

* एक उम्मीदवार ने दो बार परीक्षा उत्तीर्ण की।

नोट : कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण परीक्षा 23 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी।

रजिस्ट्रीकरण देने से इंकार

आईबीबीआई ने 2020-21 में आरवी के लिए 6 आवेदकों को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर दिया (सारणी 37)। इसने पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर एक आईपी का रजिस्ट्रीकरण भी वापस ले लिया।

सारणी 37 : आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की अस्वीकृति

वर्ष	आईबीबीआई द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या		पात्रता को पूरा करने में विफल रहने पर आईपी का रजिस्ट्रीकरण वापस ले लिया गया	पात्रता को पूरा करने में विफल रहने पर आईपी की मान्यता वापस ले ली
	आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए	आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए		
2016-17	3	0	शून्य	शून्य
2017-18	6	0	शून्य	1
2018-19	3	1	शून्य	38*
2019-20	3	3	1	2
2020-21	शून्य	6	1	शून्य

*इसके अतिरिक्त, दो आईपी ने स्वेच्छा से अपना मान्यता प्रमाण पत्र वापस कर दिया है।

शिकायतें और परिवाद

आईबीबीआई (शिकायत और परिवाद प्रबंधन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 आईबीबीआई द्वारा शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान के लिए

सारणी 38 : 31 मार्च, 2021 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान

(संख्या)

वर्ष/तिमाही	प्राप्त हुई शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमनों के अधीन		सीपीजीआरएएमएस/ पीएमओ/एमसीए/ अन्य प्राधिकरणों के माध्यम से		अन्य मोड के माध्यम से		प्राप्त किए गये	निपटाए गये	जांचाधीन
	प्राप्त किए गये	निपटाए गये	प्राप्त किए गये	निपटाए गए	प्राप्त किए गये	निपटाए गये			
2017 - 18	18	0	6	0			46	2	44
2018 - 19	111	51	333	290	713	380	1157	721	480
2019 - 20	153	177	239	227	1268	989	1660	1393	747
2020 - 21	268	260	358	378	990	1364	1616	2002	361
कुल	550	488	936	895	2993	2735	4479	4118	361

यह देखा गया है कि 87.22 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 12.78 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में शिकायतें हैं। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 प्रक्रियाओं में कुल शिकायतों का 58.64 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 41.36 प्रतिशत शिकायतें हैं।

यह देखा गया है कि 72.98 प्रतिशत आईपी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने कोई प्रक्रिया की है। केवल 27.02 प्रतिशत आईपी के संबंध में शिकायतें हैं। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 आईपी में कुल शिकायतों का 59.34 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 40.66 प्रतिशत शिकायतें हैं। यह देखा गया है कि ज्यादातर शिकायतें सीडी के प्रवर्तकों और निदेशकों से प्राप्त होती हैं, जबकि अधिकांश शिकायतें घर खरीदारों से प्राप्त होती हैं।

उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है, जो शरारती सेवा प्रदाता को माफ नहीं करता है, लेकिन निर्दोश सेवा प्रदाता को परेशान नहीं करता है। हितधारक शिकायत दर्ज कर सकता है जिसमें सेवा प्रदाता के आचरण का विवरण होगा जिससे पीड़ित को पीड़ा हुई है या पीड़ा का विवरण, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, पीड़ित व्यक्ति को भुगतान पड़ा है या सेवा प्रदाता का आचरण पीड़ित की पीड़ा का कारण बनाय सेवा प्रदाता से शिकायत निवारण के लिए उसके प्रयासों का विवरण और शिकायत का निवारण कैसे किया जा सकता है। यह 2500 रुपये के शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्ररूप में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत में संहिता के किसी प्रावधान, या नियमों, या विनियमनों, या उसके अधीन बनाए गए निदेश -निर्देशों या आईबीबीआई द्वारा सेवा प्रदाता या उससे जुड़े व्यक्तियों को जारी किए गए परिपत्रों या निर्देशों के कथित उल्लंघन के विवरण का विवरण देना आवश्यक है या सेवा प्रदाता या उससे जुड़े व्यक्तियों के कथित आचरण, ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान के साथ, गतिविधि का विवरण, जो कानून के उपबंधों का उल्लंघन है और ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान के साथ, ऐसे आचरण या गतिविधि की तारीख और स्थान का विवरण देना अपेक्षित है। यदि शिकायत तुच्छ नहीं है, तो शुल्क वापस कर दिया जाता है। जहां आईबीबीआई की राय है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है, वह निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकता है या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

इसके अलावा, शिकायतें और परिवाद केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), एमसीए, अन्य प्राधिकरणों और जनता से प्राप्त होती हैं। 31 मार्च, 2021 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण का विवरण सारणी 38 में दिया गया है।

निरीक्षण और जांच

निरीक्षण और जांच कानून के लागू उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए मानक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के सत्यापन के आधार पर, यदि आवश्यक हो, उचित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाती है। चूंकि निरीक्षण और जांच में सेवा प्रदाताओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, इसके अलावा उन पर लागत भी लगाई जाती है और इस तरह के निरीक्षण और जांच के परिणाम एक प्रवर्तन कार्रवाई हो सकते हैं, धारा 196(1)(ड) के अधीन आवश्यक अनुचित प्रवर्तन कार्रवाइयों से बचाने के लिए संबंधित हितधारकों को निरीक्षण और जांच की पीड़ा को कम करने के लिए स्पष्ट शासन सिद्धांत होने चाहिए। आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 (निरीक्षण विनियमन) निरीक्षण और जांच की शुरुआत, आचरण और समाप्त करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से बदल कर मेसर्स मरप्पर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। हालांकि, एए के पास फाइल आवेदन में नाम और पते के परिवर्तन में संशोधन नहीं किया गया था। एए ने टिप्पणी की कि आवेदन के लंबित निपटान के लिए सीडी और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम में परिवर्तन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो कार्यवाही के रूप में, यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए बाध्यकारी होगा। हितधारक, जो आवेदन के पक्षकार नहीं हैं, अपने दावे दाखिल करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वे सीडी को उसके नए नाम से पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। इसने सुझाव दिया कि दुरुपयोग से बचने के लिए धारा 10 को कड़ा किया जाए ताकि जब कोई कंपनी धारा 10 के अधीन आवेदन दाखिल करना चाहे तो उसे आवेदन दाखिल करने की तारीख के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। एए ने आवेदन को निरस्त कर दिया क्योंकि वह पृथिवराज स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी का आदेश पारित नहीं कर सकता जो आज की तारीख तक अस्तित्व में नहीं है।

मांग नोटिस

मांग नोटिस का अर्थ है ओसी द्वारा सीडी को दिया गया नोटिस जिसमें परिचालन ऋण के भुगतान की मांग की गई है, जिसके संबंध में व्यक्तिगत हुआ है। संहिता की धारा 9 के अनुसार, धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से 10 दिनों की समाप्ति पर ओसी सीडी के विरुद्ध सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

राजेंद्र भाई पांचाल बनाम मेसर्स जय मानक स्टील्स एंड अन्य⁹⁰ मामले में एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि डिमांड नोटिस में गलती का मतलब यह नहीं है कि यह दोषपूर्ण है, और यदि कोई सीडी मांग की वैधता पर सवाल उठाना चाहती है तो उसे यह दिखाना होगा कि दोष के परिणामस्वरूप उसे कोई पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा। इसने आगे कहा कि यदि मांग में कोई गलती है, लेकिन लेनदार पर स्पष्ट रूप से वैधानिक न्यूनतम आंकड़ा या अधिक बकाया है, तो यह तथ्य कि ऋण की राशि गलत है, मांग को स्वचालित रूप से अमान्य नहीं कर सकता है।

श्री जी. श्रीनिवास राव बनाम वैश्ववी इंफ्राटेक लिमिटेड⁹¹ मामले में एनसीएलएटी ने माना कि जहां सीडी ने नोटिस की डिलीवरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, एए के लिए यह निश्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सीडी को नोटिस नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में एकमात्र निश्कर्ष यह है कि सीडी को परिणामों के बारे में पता था, और उसने जानबूझकर नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गलती सीडी के हिस्से में है जिसके लिए इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। एनसीएलएटी ने आदेश को रद्द कर दिया और धारा 9 के अधीन आदेश पारित करने के लिए मामले को एए को भेज दिया।

शुभम जैन बनाम गगन फेरोटेक लिमिटेड और अन्य⁹² मामले में, एनसीएलएटी ने माना कि संहिता की धारा 8 के अधीन जनादेश को पूरा किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मांग नोटिस को कार्यात्मक पते पर और साथ ही सीडी के निदेशक को विधिवत तामील किया गया था। यह भी कहा गया कि दावा न किए गए डिमांड नोटिस को भी वैध रूप से दिया गया नोटिस माना जाएगा। इसने यह भी कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (59) के अधीन, निदेशक एक अधिकारी होता है और अधिनियम की धारा

20 के अधीन, किसी कंपनी या उसके अधिकारी को दिए गए दस्तावेज को नोटिस माना जाएगा। इसलिए, सीडी के निदेशक को भेजा गया नोटिस संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और यह वैध होगा।

प्रत्यक्ष विघटन

मंदार वाघ, मेसर्स सायन्यू स्टील प्राइवेट लिमिटेड के आईआरपी⁹³ मामले में आरपी ने बताया कि सभी एफसी संबंधित पक्ष हैं और इसलिए वह सीओसी का गठन करने में सक्षम नहीं है। 729 रुपये के नकद शेष के अलावा कोई आस्त नहीं है। और इसलिए आरपी सीआईआरपी का संचालन करने में असमर्थ है। पिछले तीन वर्षों में कोई व्यवसाय नहीं है और इसलिए कोई राजस्व नहीं है। पूरी पूंजी छिन्न-भिन्न हो गई है। परिसमापन विनियमनों की धारा 33(2), 54 और विनियमन 14 और एनसीएलएटी विनियमनों के नियम 11 में तथ्यों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एए ने टिप्पणी की कि सीडी को सीआईआरपी के अधीन रखने या इसे परिसमापन प्रक्रिया के अधीन रखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसने सीडी को भंग करने की अनुमति दे दी।

⁹⁰ सीए (एटी) (इंस) संख्या 592/2020

⁹¹ सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 880

⁹² सीए (एटी) (इंस) संख्या 2020 का 1008

⁹³ सीपी (आईबी) संख्या 96/बीबी/2020

संहिता समाधान और परिसमापन के बीच संतुलन बनाकर मूल्य को अधिकतम करती है। यह ज्यादातर मामलों में समाधान को प्रोत्साहित करती है और सुविधा प्रदान करती है जहां लेनदारों को कम से कम उतना ही प्राप्त होगा जितना वे परिसमापन में प्राप्त करेंगे। यह तब होगा जब उद्यम मूल्य परिसमापन मूल्य से पर्याप्त रूप से अधिक हो। ऐसे मामलों में, समाधान एक जारी कंसर्न के रूप में उद्यम मूल्य को संरक्षित और अधिकतम करता है। शेष मामलों में, संहिता परिसमापन की सुविधा प्रदान करती है क्योंकि यह हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करती है। हालांकि मुख्य उद्देश्य समाधान है, तथापि, संहिता यह मानती है कि कुछ परिस्थितियों में, लेनदारों के लिए परिसमापन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसी फर्में हो सकती हैं जो निष्क्रिय हैं, या उन्होंने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या अन्य वसूली/पुनर्गठन ढांचे में अपनी स्थिति में बिना किसी सुधार के कई साल बिताए हैं और मूल्य काफी सीमा तक कम हो गया है।

समाधान समय

संहिता में कहा गया है कि सीआईआरपी को 330 दिनों (2019 का संशोधन अधिनियम) में पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें समय के किसी भी विस्तार के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही के कारण समय का कोई भी बहिष्कार शामिल है। समाधान के लिए समय कम करने के लिए, संहिता में आईयू के प्रतिस्पर्धी उद्योग, पूरे देश में फैले एए की कई पीठ और दिवाला सेवाओं के व्यावसायीकरण की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावों को पूरा करने और परिसमापन के लिए लिया गया औसत समय अधिक है और एए की क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सारणी 68 : संहिता के अधीन प्रक्रिया को पूरा करने का औसत समय

क्र. सं.	मापदंड	कवर की गई प्रक्रियाओं की संख्या	समय (दिनों में)
कोरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं			
1	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजनाओं का अनुमोदन	348	459
2	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा परिसमापन के लिए आदेश	1277	351
परिसमापन			
3	परिसमापन के लिए अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति	240	410
4	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति	400	383

औसत समाधान लागत

विश्व बैंक की ड्रूंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, यह संहिता पूर्ववर्ती व्यवस्था की तुलना में सीआईआरपी की कुल लागत को कम करने में सफल रही है, जिसमें कुल लागत कंपनी के संपत्ति मूल्य के 9 प्रतिशत के बराबर थी।

322 सीडी से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिनका समाधान किया गया है, दिवाला प्रक्रिया के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करने और प्रक्रिया के लिए बैठकें आयोजित करने की लागत, परिसमापन मूल्य का औसतन 0.92% और समाधान मूल्य का 0.49% है। विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार के विकास और समाधान के लिए समय में कमी के साथ लागत और कम हो सकती है।

निष्कर्ष

सीआईआरपी के माध्यम से परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि संहिता से बेहतर वित्तीय संगठन और अनुशासन का वातावरण बनाया है और हितधारकों के व्यवहार में सुधार हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के दिवाला कानून पर विधायी गाइड प्रदान करता है कि: 'जब कोई देनदार अपने ऋण और अन्य देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो अधिकांश कानूनी प्रणालियां देनदार की संपत्ति (चाहे मूर्त या अमूर्त) से बकाया दावों की सामूहिक संतुष्टि को संबोधित करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करती हैं। उस कानूनी तंत्र द्वारा हितों की श्रृंखला को समायोजित करने की आवश्यकता है ... आम तौर पर, तंत्र को न केवल इन हितधारकों के विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, बल्कि इन हितों और प्रासंगिक सामाजिक, राजनीतिक और अन्य नीतिगत विचारों के बीच भी संतुलन बनाना चाहिए, जिनका दिवाला कार्यवाही के आर्थिक और कानूनी लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है।'

संहिता एक सक्रिय, गतिशील और समयबद्ध दिवाला व्यवस्था है जो गंभीर खतरे में किसी कंपनी के जीवन को बचाने में विश्वास करती है। चल रहे कार्यों को समयबद्ध दिवाला समाधान पर मुख्य ध्यान देने के साथ नवीन संभावनाओं के साथ दिवाला शासन को परिष्कृत करके 'शोधन अक्षमता का समाधान' और 'व्यापार करने में आसानी' में सुधार करने के लिए रखा जा रहा है। इसके अलावा, संहिता के अधीन तनाव के समाधान के लिए नई पहल की योजना बनाई जा रही है ताकि संहिता की प्रभावशीलता और दक्षता को और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में इस दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है।



बोर्ड का कार्य निष्पादन

भारत में आर्थिक सुधारों ने सरकार के विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे बाजारों के विनियमन से विशेष नियामकों द्वारा निगरानी के लिए अंतरित करने की अभिकल्पना की। नियामकों को अधीनस्थ विधान लिखने के लिए विधायी शक्तियाँ, लाइसेंसिंग और जांच के लिए कार्यकारी शक्ति और उनके क्षेत्राधिकार में विनियमित संस्थाओं के आचरण पर न्यायिक शक्तियाँ दी गई। इस प्रकार नियामक कई अर्थों में सरकारों के समान होते हैं। वे जनता के हित में सरकार के समान सार्वजनिक सामान प्रदान करते हैं। उनके उत्तरदायित्वों में सरकार द्वारा निर्वहन के समान उपभोक्ता संरक्षण, विकास और विनियमन शामिल हैं। उनके पास सरकार के समान विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ हैं। वे कई अर्थों में सरकार से मिलते-जुलते हैं, फिर भी वे 'सरकार' नहीं हैं। वे, एक अर्थ में, सरकार के भीतर की सरकारें हैं, और सरकार की ओर से पूर्व-निर्धारित ढाँचे में शासन करती हैं। हालाँकि, सरकार अंततः नियामकों के माध्यम से शासन के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से, नियामक संसद के अधीनस्थ विधान, उनके कार्यकलापों और निष्पादन का विवरण देने वाली वार्षिक रिपोर्ट, और सीएजी द्वारा लेखा-परीक्षित खातों के विवरण सदन के पटल पर रखते हैं। विभागीय स्थायी समितियाँ अपनी अनुदान माँग या अपने प्रशासनिक मंत्रालयों की अनुदान माँग, जैसी भी स्थिति हो, का अनुमोदन करते समय उनके क्रियाकलापों की जाँच करती हैं।¹⁰⁴ यह वास्तव में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जाँच और संतुलन हैं कि नियामक सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित अपने कार्यों के दायरे में काम करे।

संहिता की धारा 196 आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों की गणना करती है। यह अनूठा नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय के साथ-साथ दिवाला प्रक्रियाओं सहित सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करता है। संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए, और आईयू और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देने और उनके कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। यह देश में मूल्यांकनों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी कार्य करता है। प्राधिकरण के रूप में, यह आरवी और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत और नियंत्रित करता है। इन उत्तरदायित्वों में धारा 196 में वर्णित कार्यों को करने के लिए अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करना शामिल है।

रिपोर्ट के विभिन्न खंडों में आईबीबीआई के कामकाज के कई पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। खंड घ अपने कार्यकारी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक कार्यों में आईबीबीआई के परिचालन निष्पादन को प्रस्तुत करता है, जबकि खंड ज अपने शासी बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन प्रस्तुत

करता है। वित्तीय प्रदर्शन, कानूनी और वैधानिक दायित्वों का अनुपालन, और बोर्ड के संगठनात्मक निष्पादन को क्रमशः खंड झ, ज और ट में चित्रित किया गया है। इस खंड में बोर्ड के कामकाज को समाहित करने का प्रयास है जिसका बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता और उसके परिणाम पर असर पड़ता है। अच्छे नियामक शासन को कुछ वांछनीय तत्वों, अर्थात् प्रभावी और उत्तरदायी विनियमन उपयुक्त संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के साथ प्रभावी जुड़ाव, समय-समय पर संस्थागत निष्पादन का आकलन और अन्य एजेंसियों के साथ अपने अधिदेश को पूरा करने में समन्वय पर आधारित माना गया है। इन पहलुओं के संदर्भ में बोर्ड की निष्पक्षता को यहां प्रस्तुत किया गया है।

क. प्रभावी और उत्तरदायी विनियमन

विनियमन बनाना नियामक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विनियमन कानूनी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक-दूसरे के साथ निरंतर जुड़ाव में कई इच्छुक पक्षों को शामिल करने वाले मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी, हितधारकों की पहचान करना या विनियमनों के प्रभाव को मापना संभव नहीं होता है। इस प्रकार, नियामक की भूमिका में, विकसित वातावरण में पूरी स्थिति से अवगत होना, मामले को हल करने के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करना और केवल बाजार की विफलता को बढ़ावा देने वाले विनियमन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस प्रकार, विनियमन बनाना कला से कुछ अधिक है: जिसमें मानक 'एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त' हमेशा काम नहीं करता है। नियामक को बदलते प्रचालक वातावरण और बाजार की विफलताओं के अनुकूल होने, अलग-अलग रणनीतियाँ और दृष्टिकोण उपलब्ध होने, उपयुक्त विनियमन तैयार करने की आवश्यकता है जो बिना या नगण्य अनपेक्षित परिणामों के साथ विभिन्न बाजार विफलताओं को संबोधित करे। संक्षेप में, इसे लचीला होना चाहिए और इसमें ऐसे परिवर्तनों का आकलन करने और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियमनों को संशोधित करने की क्षमता होनी चाहिए।

उत्तरदायी नियामक प्रतिभागियों की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किए बिना, बाजार की बदलती जरूरतों के साथ सक्रिय रूप से विनियमनों को डिजाइन और संशोधित करता है। हालाँकि बाजार की विफलता को दूर करने के लिए मानक विनियमनों का होना संभव नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन बनाने के लिए एक मानक प्रक्रिया होना आवश्यक है कि विनियमन प्रभावी होने के साथ-साथ उत्तरदायी हैं, फिर भी अत्यधिक नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई ने विनियम बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 लागू किया है।

विनियमन की प्रभावशीलता और जवाबदेही पर साहित्य विनियमनों के

¹⁰⁴ साहू, एम. एस., (2019), "नियामक राज्य में सुधार करना", जरनल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी, खंड 31, सं. 3, जुलाई- सितंबर

प्राप्त करने की अनुमति देता है क्योंकि बाजार की गतिशीलता बदलती है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक हितधारक को विनियमन बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने का अवसर मिले, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिले। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया जाता है।

(क) प्रस्तावित विनियमनों पर टिप्पणियाँ : आईबीबीआई अपनी वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चर्चा पत्रों, विनियमनों और उप-विनियमनों के अनुसार प्रस्तावित विनियमनों या प्रस्तावों पर जनता की टिप्पणियाँ प्राप्त करता है। इसे 2020-21 में हितधारकों से कुल 1470 टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

(ख) मौजूदा विनियमनों पर सुझाव : आईबीबीआई के पास निरंतर आधार

पर मौजूदा विनियमनों पर हितधारकों और विनियमित लोगों सहित जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था (अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म) है। इन टिप्पणियों/सुझावों को एक साथ संसाधित किया जाता है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, विनियमनों को आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक संशोधित किया जाता है। आईबीबीआई को 2020-21 में इस मार्ग के अधीन कुल 734 टिप्पणियाँ मिलीं।

(ग) सामान्य प्रतिक्रिया : आईबीबीआई को एक समर्पित ईमेल (feedback@ibbi.gov.in) के माध्यम से संहिता, नियमों और विनियमनों के विभिन्न प्रावधानों पर सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इसे 2020-21 में 457 फीडबैक ईमेल मिले हैं। उपरोक्त मार्ग क ख और ग के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक को सारणी 72 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 72 : 2020-21 में प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियाँ

हितधारक	संख्या			
	क (टिप्पणियाँ)	ख (सुझाव)	ग (फीडबैक)	कुल
शिक्षाविद	0	0		0
शैक्षणिक	21	86		107
कारपोरेट देनदार	17	23		40
एक कारपोरेट देनदार को लेनदार	35	62		97
उद्योग संघ	0	0		0
सूचना उपयोगिता	0	0		0
दिवाला व्यावसायिक	1072	223		1295
दिवाला व्यावसायिक अभिकरण	34	8		42
दिवाला व्यावसायिक इकाई	62	37		99
निवेशक	5	38		43
निवेशक	0	5		5
वकील / कानून फर्म	0	0		0
अन्य	208	224		432
एक कारपोरेट देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटर	3	5		8
प्रोपराइटरशिप फर्म	10	10		20
साझेदारी फर्म	3	13		16
सेवा उपयोगकर्ता समूह उदाहरण के लिए वित्तीय संस्थान, सरकारी प्राधिकरण आदि	0	0		0
मूल्यांकक	0	0		0
मूल्यांकक संघ	0	0		0
कुल	1470	734	457	2661

(घ) मुद्दों की समझ बनाने और उन्हें सूचित रखने के लिए हितधारकों को जानकारी प्रदान करें

आईबीबीआई अपने हितधारकों को दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर ढेर सारी जानकारी प्रदान करता है। आईबीबीआई ने अपने हितधारकों को सूचित और अद्यतन रखने के लिए निम्नलिखित साधनों को नियोजित किया है:

(क) वेबसाइट : आईबीबीआई वेबसाइट सूचना का खजाना है। सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं का विवरण उपलब्ध है। इसके अलावा, सभी

महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत घटनाक्रमों को वेबसाइट पर दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है। एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एचसी, एससी और अन्य अधिकारियों के आदेश उपलब्ध हैं। मार्च, 2021 के अंत में, वेबसाइट के 42,648 ग्राहक थे, जो अपने ईमेल पर दैनिक अपडेट प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रकाशन : आईबीबीआई अपनी स्थापना के बाद से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रहा है। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आईबीबीआई की वेबसाइट पर व्यापक प्रसार के लिए होस्ट की गई है। न्यूजलेटर कानूनी और नियामक विकास को समाहित करता है, संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति, आईबीबीआई द्वारा की गई क्षमता

बॉक्स 5 : आईबीबीआई: एक स्व-मूल्यांकन

संहिता के अधीन स्थापित होने के पांच साल बाद, आईबीबीआई कहां खड़ा है, इसका आकलन दो बिंदुओं से देखा जा सकता है – आईबीबीआई अपनी नियामक भूमिका में और आईबीबीआई एक संस्थान के रूप में।

आईबीबीआई की नियामक भूमिका

अपनी नियामक भूमिका के संदर्भ में, आईबीबीआई संहिता की धारा 196 के अधीन निर्धारित विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है, जिसे मोटे तौर पर तीन प्रमुखों के अधीन वर्गीकृत किया गया है:

- **अर्ध-विघाटी** – आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2021 तक सत्रह विनियम और 50 से अधिक संशोधन विनियम बनाए हैं।
- **कार्यकारी** – आईबीबीआई निम्नलिखित के कार्यकारी कार्य कर रहा है: (क) दिवाला प्रक्रियाओं के लिए सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और विनियमन और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक विकास और विशेषज्ञता के उपाय, (ख) आईपी और आरवी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना। आईबीबीआई ने इन परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री के विकास की भी सुविधा प्रदान की है, जो मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, (ग) हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, वकालत और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, (घ) संहिता के अधीन चल रही प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के आचरण की निगरानी, ङ) शिकायत और शिकायत निवारण और (च) दिवाला के क्षेत्र में अनुसंधान करना, शोध प्रकाशनों के साथ आना और दिवाला प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं से संबंधित डेटा का प्रसार करना।
- **अर्ध-न्यायिक** – (क) आईबीबीआई के डीसी सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए एससीएन का निपटान कर रहे हैं और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कि मौद्रिक दंड लगाना, या पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना, जैसा कि आवश्यक होय (ख) आईबीबीआई विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष कई मामलों में प्रतिवादी और याचिकाकर्ता/आवेदक/शिकायतकर्ता के रूप में पेश हो रहा है।

संस्था के रूप में आईबीबीआई

आईबीबीआई के निर्माण पर गठित डब्ल्यूजी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, एक संस्थान के रूप में आईबीबीआई की प्रगति को तीन स्तंभों – संगठन, प्रक्रियाओं और शासन ढांचे के पहलू से देखा जा सकता है।

पहला स्तंभ : संगठन: रिपोर्ट ने कुछ डिजाइन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिन पर आईबीबीआई का आयोजन किया जाना चाहिए। आईबीबीआई द्वारा इन सिद्धांतों को जिस तरह से अपनाया गया है, उसके साथ इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

सिद्धांत	आंतरिक और बाहरी समीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना
	<ul style="list-style-type: none"> ○ आईबीबीआई अपनी सामरिक कार्य योजनाओं (एसएपी) के माध्यम से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए एसएपी तैयार किए गए। सभी मंडलों द्वारा अपने मासिक एमआईएस में निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाती है। ○ आंतरिक अंकेक्षण बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इन लेखापरीक्षाओं की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों को विधिवत रूप से जीबी को सूचित किया जाता है। ○ आईबीबीआई के खातों की लेखापरीक्षा सीएण्डएजी द्वारा की जाती है। ○ आईबीबीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे संसद में तैयार करता है और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखता है। ○ आईबीबीआई का जीबी सालाना स्व-मूल्यांकन करता है, जिसके परिणाम, प्रदर्शन में सुधार के लिए सिफारिशों सहित, वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

सिद्धांत	संगठन के कामकाज में सिद्धांत पारदर्शिता
	<ul style="list-style-type: none"> ○ बोर्ड के आंतरिक कामकाज और लिए गए आंतरिक निर्णयों के संबंध में प्रलेखन के मजबूत मानक को बनाए रखा जाता है। कार्यालय लगभग पूरी तरह से ई-ऑफिस प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है। ○ जीबी द्वारा अपनी बैठकों में विचार किए गए एजेंडा नोट्स और उसमें लिए गए निर्णयों को आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। ○ विभिन्न डब्ल्यूजी की रिपोर्ट, बाहरी ऑडिट रिपोर्ट, डीसी के आदेश, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन एफएए के आदेश आदि वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। ○ आंतरिक कार्यों के लिए विभागों द्वारा एसओपी निर्धारित किए गए हैं और ई-ऑफिस में सभी कर्मचारियों के लिए ये आसानी से उपलब्ध हैं।

सिद्धांत	इंटरफेस में सिद्धांत पारदर्शिता
	<ul style="list-style-type: none"> ○ आईबीबीआई विभिन्न स्वरूपों, अर्थात् सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वेबिनार में हितधारकों के साथ व्यापक रूप से और सक्रिय रूप से संलग्न है। ○ आईबीबीआई आईपी और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ○ बोर्ड ने हितधारकों की शिकायतों और शिकायतों से निपटने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इनसे वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटा जा रहा है। ○ सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए आईबीबीआई की एक सुस्थापित प्रक्रिया है। ○ बोर्ड पंजीकरण के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने के कारण (कारणों) के साथ अपना दृष्टिकोण बताता है। आवेदक को यह समझाने का अवसर दिया जाता है कि वह कैसे पंजीकृत होने के योग्य है। एक आवेदन केवल एक तर्कपूर्ण आदेश के साथ खारिज कर दिया जाता है। ○ बोर्ड एक सेवा प्रदाता को एससीएन जारी करता है, जिसने आरोपी के विशिष्ट आचरण और निरीक्षण रिपोर्ट या अन्यथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कानून के विशिष्ट प्रावधान के उल्लंघन का विवरण देने वाले संहिता/विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद, डीसी तर्कसंगत आदेश के माध्यम से एससीएन का निपटान करता है।

- आईबीबीआई अपनी वेबसाइट और त्रैमासिक न्यूजलेटर के माध्यम से संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के परिणामों को साझा करता है। बोर्ड के अन्य प्रकाशनों को भी हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए वेबसाइट पर रखा गया है।
- आईबीबीआई प्रत्येक माह की 7 तारीख को आईपीए, आरवीओ और आईयू के एमडीसीसीओ से उनके शासन और संचालन से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलता है।

सिद्धांत | जवाबदेही

- आईबीबीआई के पास एक स्थायी व्यवस्था है जिससे कि कोई भी हितधारक पूरे वर्ष के दौरान किसी भी नए विनियम या मौजूदा विनियमों में किसी भी बदलाव की मांग कर सकता है।
- प्रस्तावित विनियम के मसौदे के साथ चर्चा पत्र सार्वजनिक डोमेन में रखे जाते हैं और उन पर टिप्पणी मांगी जाती है।
- आईबीबीआई के संचालन प्रभाग के विचारों के साथ हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को निर्णय के लिए आईबीबीआई के जीबी के समक्ष रखा जाता है।
- आईबीबीआई द्वारा की गई परामर्श प्रक्रिया के विवरण और अंतिम निर्णय के आधार को देखने के लिए हितधारकों के लिए जीबीडी के एजेंडा नोट भी वेबसाइट पर रखे गए हैं।
- आईबीबीआई स्वयं या उद्योगध्वंसस्थानों/ध्वंसगठनों के सहयोग से विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न शहरों में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है।
- जहां भी मौजूदा कानूनी स्थिति पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है बोर्ड परिपत्रों के माध्यम से इसे प्रदान करता रहा है।

सिद्धांत | आधुनिक कार्यालय

- आईबीबीआई के पास नई दिल्ली में दो परिसरों में स्थित एक आधुनिक कार्यालय स्थान है – मयूर भवन और जीवन विहार भवन।
- आईबीबीआई ने अपनी स्थापना के समय से ही अपनी सेवाओं के वितरण के लिए आईटी का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:
- ई-ऑफिस
- ई-मीटिंग्स
- वेबसाइट
- सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा
- सेवा प्रदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण
- सीआईआरपी प्रपत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग
- वार्षिक शुल्क की ऑनलाइन फाइलिंग
- एएफएस का ऑनलाइन प्रसंस्करण
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक परामर्श
- एए को उपलब्ध कराए गए आईपी का लाइव डेटाबेस
- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों और अपीलों को ऑनलाइन संसाधित किया गया।
- सीपीजीआरएएमएस में ऑनलाइन प्राप्त शिकायतें।
- पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस का उपयोग।
- भर्ती अधिसूचनाएं और उनके परिणाम आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- आईबीबीआई द्वारा जारी सभी निविदाएं (किसी भी संशोधन सहित) आईबीबीआई की वेबसाइट और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं।
- आईबीबीआई द्वारा अपने हितधारकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दूसरा स्तंभ : प्रक्रियाएं : रिपोर्ट ने कुछ डिजाइन सिद्धांतों का सुझाव दिया है जिन पर प्रक्रियाओं को संगठन में निर्धारित किया जाना चाहिए। इसने "औपचारिक प्रक्रियाओं" को निर्धारित करने की सिफारिश की ताकि यह बाहरी हितधारकों की नजर में एक पूर्वानुमेय तरीके से व्यवहार करे, जो संगठन में मामलों के शीर्ष पर अधिकारियों के हाथों में बदलाव या परिवर्तन से प्रभावित न हो।

सिद्धांत | एक कार्यप्रवाह प्रणाली जहां सब कुछ एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में होता है, किसी भी कागजी फाइलों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, या भौतिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए

- ईमेल और ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है।
- कागज की फाइलें सीमित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
- सीएमएस वाले ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर गतिशील वेब पोर्टल।
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई-साइन इंटीग्रेशन।
- भुगतान गेटवे एकीकरण।
- एसएमएस और ईमेल एकीकरण।
- सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा

- सेवा प्रदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण।
- एफएएस का ऑनलाइन प्रसंस्करण।
- वार्षिक शुल्क की ऑनलाइन फाइलिंग।
- ऑनलाइन सीआईआरपी फॉर्म।
- वेबसाइट के साथ मौजूदा आईपी पंजीकरण मॉड्यूल और डेटाबेस का एकीकरण।
- वेबसाइट के साथ मौजूदा मूल्यांकनकर्ता पंजीकरण मॉड्यूल और डेटाबेस का एकीकरण।
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक परामर्श।
- आरटीआई हैंडलिंग, सीपीजीआरएमएस शिकायतें, ई-मार्केटप्लेस ऑनलाइन।
- आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति।
- पोर्टल के माध्यम से आईपीए द्वारा आईपी की निगरानी।

सिद्धांत

सभी प्रकटीकरण एक वेबसाइट के माध्यम से किए जाने चाहिए, जो कि एजेंसी के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में वास्तविक समय में जितना संभव हो उतना डेटा फीड होना चाहिए।

आईबीबीआई की वेबसाइट रीयल टाइम आधार पर ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित का विवरण प्रदान किया गया है :

- आईबीबीआई के बारे में – जीबी, एसी, तकनीकी समितियां, आईबीबीआई के अधिकारी।
- सेवा प्रदाताओं।
- कानूनी ढांचा – अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, सुविधाएं, अन्य प्राधिकरण।
- परीक्षा।
- अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश।
- आईबीबीआई और आईबीबीआई के डीसी द्वारा पारित आदेश।
- प्रकाशन – न्यूजलेटर, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, सूचना ब्रोशर, वार्षिक प्रकाशन आदि।
- सार्वजनिक टिप्पणी पोर्टल।
- आईपी पोर्टल।
- शिकायतें और शिकायत पोर्टल।
- आरटीआई।
- प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- मीडिया – प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया कवरेज।
- संसाधन – लेख, साक्षात्कार, रिपोर्ट।
- आयोजन।
- भर्ती अधिसूचना।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्रपत्र प्रस्तुत करना।

सिद्धांत

एजेंसी की प्रत्येक प्रक्रिया को एक सहज वेब अनुभव के माध्यम से सक्षम किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन की जा रही प्रक्रियाओं के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक व्यापक आईटी प्रणाली का कार्यान्वयन वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अधीन किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- (क) व्यक्तिगत दिवाला के लिए आवेदन की सूचना।
- (ख) हितधारकों के लिए प्रक्रियाओं का व्यापक प्रदर्शन।
- (ग) आईपीई की ऑनलाइन मान्यता (अंतिम चरणों में)।
- (घ) आईपीए का परिवर्तन।
- (ङ) आईपी द्वारा नवीनीकरण शुल्क।
- (च) प्रोफाइल में बदलाव (आईपी द्वारा ईमेल, पता, फोन नंबर आदि)।
- (छ) आरवीई पंजीकरण।
- (ज) निरीक्षण और जांच मॉड्यूल।
- (झ) आरवी प्रक्रिया के लिए विवरण, अस्थायी समर्पण और अनुशासनात्मक कार्रवाई/निगरानी और सीपीई क्रेडिट संबंधित मॉड्यूल का अद्यतन।
- (ञ) परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन, एमआईएस के निर्माण आदि के लिए निगरानी प्रपत्र और मॉड्यूल।
- (ट) आईपी/सीडी/लगाए गए समय/एनसीएलटी, प्रक्रिया के चरण के आधार पर एमआईएस का सृजन।

- (घ) एमआईएस की प्रक्रियाओं और सूत्रीकरण के बारे में डेटा प्रसार। अनुकूलित एमआईएस वेबसाइट पर लाइव प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ड) जीआईडीडब्ल्यू दिशानिर्देशों (द्विभाषी वेबसाइट आदि) का अनुपालन।

सिद्धांत विधायी कार्य को आंतरिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।

विनियमों में किसी भी विधायी परिवर्तन को लागू करने से पहले हितधारकों के साथ जुड़ने के विभिन्न तरीके मौजूद हैं, जैसे कि ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से इनपुट मांगना आदि। जीबी द्वारा विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले आईबीआई के पास एसी, डब्ल्यूजी और विशेषज्ञ समितियों की पर्याप्त परामर्श प्रक्रिया है।

सिद्धांत एक नियामक के सांख्यिकीय प्रणाली कार्यों को पारदर्शिता और प्रामाणिकता की अवधारणाओं का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखित नियम होने चाहिए जो निजी व्यक्तियों को सभी आवश्यक डेटा की ई-फाइलिंग करने के लिए मजबूर करते हैं, जो नियामक की कोर आईटी प्रणाली में जाता है।

वर्तमान में हितधारकों द्वारा निम्नलिखित ई-फाइलिंग की जा रही है:

- सीपीई मॉड्यूल जिसमें आईपी के पास अपना सीपीई क्रेडिट जमा करने का विकल्प होता है।
- आईपी शुल्क मॉड्यूल (फॉर्म ई)।
- आईपीई शुल्क मॉड्यूल (फॉर्म जी)।
- आईआरपी, आरपी, परिसमापक और दिवाला ट्रस्टी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति मॉड्यूल।
- एए के लिए भूमिका आधारित लॉगिन सुविधा।
- एएफए का निर्गम और नवीनीकरण और समर्पण।
- सीआईआरपी के लिए आवेदन प्रपत्रों की सूचना।
- असाइनमेंट मॉड्यूल।
- आईपी1 और सीआईआरपी प्रपत्रों के माध्यम से रिपोर्टिंग।
- दावा रजिस्टर मॉड्यूल।
- सार्वजनिक घोषणाएं और संकल्प योजनाओं का आमंत्रण।

सिद्धांत हितधारकों के साथ सभी संचार का एक बिंदु स्रोत होना चाहिए। जितना हो सके, इसे नियामक एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से सक्षम किया जाना चाहिए।

हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सिद्धांत सभी डेटा रिलीज व्यापक रूप से एक एपीआई के माध्यम से जनता के लिए किया जाना चाहिए। यह data.gov के खुले सरकारी सिद्धांतों के उदाहरण का उपयोग करके किया जा सकता है।

- डेटा रिलीज आईबीआई प्रकाशनों, अर्थात् त्रैमासिक न्यूजलेटर, और वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है।
- एमआईएस की प्रक्रियाओं और सूत्रीकरण के बारे में डेटा प्रसार के लिए एक नए आईटी पोर्टल की परिकल्पना की गई है।

तीसरा स्तंभ : शासन ढांचा: रिपोर्ट किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के बोर्ड की संरचना के डिजाइन पर एफएसएलआरसी की सिफारिशों पर आधारित है। सुझाए गए डिजाइन सिद्धांत इस प्रकार हैं।

सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण

आईबीआई के अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक कार्यों को शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करने और बेहतर प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए तीन विंगों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- i. अर्ध-विधायी कार्यों को करने के लिए अनुसंधान और विनियमन विंग (आरआरडब्ल्यू),
- ii. कार्यकारी कार्यों को करने के लिए पंजीकरण और निगरानी विंग (आरएमडब्ल्यू), और
- iii. प्रशासनिक कानून विंग (एएलडब्ल्यू) अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने के लिए।

शक्तियों के व्यापक पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विंगों का नेतृत्व डब्ल्यूटीएम द्वारा किया जाता है।

सिद्धांत शक्तियों का प्रत्यायोजन

निम्नलिखित ने बोर्ड को शक्तियां प्रत्यायोजित करने में सहायता की है :

शक्तियों का प्रत्यायोजन : संहिता बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी, उसकी शक्तियों और कार्यों को सौंपने में सक्षम बनाती है। प्रतिनिधिमंडल आदेश, 24 जनवरी, 2017 को जारी किया गया और 25 अप्रैल, 2018 और 2 जुलाई, 2020 को संशोधित किया गया, उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकार दिया है। आईबीआई के सभी डिवीजनों में प्रत्यायोजन आदेश का पालन किया जा रहा है जिससे त्वरित निर्णय लेने और मामलों का तेजी से निपटान हो सके।

कार्यात्मक विशेषज्ञता : संगठन के प्रत्येक विंग के भीतर, अर्थात्, आरआरडब्ल्यू, आरएमडब्ल्यू और एअलडब्ल्यू, ऐसी कार्यात्मक इकाइयाँ या डिवीजन हैं जो उन्हें सौंपे गए कार्यों में विशेषज्ञता रखते हैं, जो शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के आदेश द्वारा निर्देशित होते हैं। इस कार्यात्मक विशेषज्ञता ने समय के साथ मानव पूंजी के विकास को भी सुगम बनाया है।

सलाहकार समितियाँ : बोर्ड को निम्नलिखित तीन एसी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो उभरते विचारों के लिए एक सुदृढ़ बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं और व्यावसायिक ज्ञान और बाजार ज्ञान उधार देते हैं :

- i. सेवा प्रदाताओं पर एसी,
- ii. कारपोरेट दिवाला समाधान पर एसी, और
- iii. व्यक्तिगत दिवाला और दिवालियापन पर एसी।

कार्यकारी समितियाँ : निम्नलिखित समितियाँ बोर्ड को उसके कुछ कार्यकारी कार्यों को करने में सहायता करती हैं:

- i. अनुशासनात्मक समिति : डीसी को निरीक्षण या जांच रिपोर्ट और एससीएन के निपटान पर विचार करने का काम सौंपा गया है।
- ii. लेखा परीक्षा समिति – लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है।

आईबीबीआई ने एक नियामक और एक संस्था के रूप में, चार साल की छोटी सी अवधि में एक लंबा सफर तय किया है। इसने अधिकांश संगठनात्मक तत्वों को स्थापित किया है जिनकी परिकल्पना डब्ल्यूजी द्वारा की गई थी। यद्यपि डब्ल्यूजी द्वारा परिकल्पित की गई वास्तविक चीजों को सूचीबद्ध करके यथासंभव निष्पक्ष रूप से स्व-मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है, फिर भी इसमें व्यक्तिपरक, आत्म-विश्लेषण होने की सीमाएं हैं। फिर भी, एक नवोदित नियामक के रूप में, यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है कि आने वाले वर्षों में सुधार और अधिक मील के पत्थर पार करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

अपने नियमों को बदल दिया है। नियामक समन्वय की सहक्रियाओं का और अधिक उपयोग करने के लिए, बॉक्स 6 अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करता है।

निष्कर्ष

बोर्ड खुद को गतिशील और सक्रिय नियामक के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य संहिता में निर्धारित प्रावधानों के भीतर एक उत्तरदायी नियामक ढांचा प्रदान करके संकटग्रस्त व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बेहतर और न्यायसंगत वित्तीय परिणामों की सुविधा प्रदान करना है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए, आईबीबीआई संहिता के उद्देश्यों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करता है उभरते बाजार की जरूरतों के आधार पर समय पर निर्णय लेता है और व्यवस्थित तरीके से हितधारकों के साथ संवाद करता है।

हमेशा बदलते नियामक वातावरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ, यह अनिवार्य है कि बोर्ड समय-समय पर अपनी स्थिति को पुनः जांचता है ताकि खुद को एक नियामक के रूप में प्रासंगिक, गतिशील और उत्तरदायी बनाए रखा जा सके। इस अनिवार्यता के प्रति सचेत रहते हुए, आईबीबीआई आवश्यक लचीलेपन के साथ संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को निरंतर और सुविधाजनक बना रहा है, आईटी पहल के माध्यम से दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र में सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना, निरंतर जुड़ाव के माध्यम से अपने हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना, दिवाला के क्षेत्र में ज्ञान का निर्माण करना और संहिता के परिणामों के बारे में जानकारी का प्रसार करना। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा तक नियामक रिक्त स्थान के अतिव्यापी होने के कारण नियामकों के बीच बढ़ती अंतर-निर्भरता को देखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, आगे जाकर, सभी नियामकों के बीच समन्वित नियामक प्रयास उनके संबंधित स्थान में कुशल और प्रभावी नियामक परिणामों और नियामकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। संहिता को पहले से ही आरबीआई, सेबी और सीसीआई जैसे नियामकों द्वारा सुगम बनाया जा रहा है जिन्होंने इस रिपोर्ट के खंड बी में प्रस्तुत संहिता के उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर



शासी बोर्ड का कार्य निष्पादन

आईबीबीआई सतत उत्तराधिकार के साथ निकाय कारपोरेट है। यह संपत्ति को धारण करता है और उसका निपटान करता है, अनुबंधों में प्रवेश करता है और वाद संचालित करता है और उसके नाम पर वाद फाइल किए जाते हैं। आईबीबीआई का जीबी इसे रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और प्रबंधन का नियंत्रण और निगरानी करता है। आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (बोर्ड विनियमन) के साथ पठित संहिता जीबी के व्यवसाय और उक्त व्यवसाय के लेन-देन के तरीके को निर्दिष्ट करती है। जीबी के कार्यों में विनियमनों, वार्षिक खातों, वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आदि पर विचार करना और अनुमोदन करना शामिल है।

आईबीबीआई के पास अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक जिम्मेदारियां हैं। अर्ध-विधायी कार्य जीबी का अनन्य अधिकार-क्षेत्र है। अर्ध-न्यायिक कार्य डीसी का अनन्य अधिकार-क्षेत्र हैं जिनमें डब्ल्यूटीएम शामिल हैं। कार्यकारी कार्यों का वितरण आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। बोर्ड विनियमन बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर निर्दिष्ट करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी इस तरह से आचरण करे जो अपने जनादेश को पूरा करने की अपनी क्षमता से समझौता नहीं करता है या सदस्य (सदस्यों) की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता में जनता के विश्वास को कम करता है।

शासी बोर्ड की बैठकें

2020-21 के दौरान जीबी की पांच बैठकें हुईं। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 73 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 73 : शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2020-21 में बोर्ड बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया
डॉ. एम. एस. साहू	अध्यक्ष	5	5
डॉ. नवरंग सेनी	डब्ल्यूटीएम	5	5
डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय	डब्ल्यूटीएम	5	5
श्री सुधाकर शुक्ला	डब्ल्यूटीएम	5	5
डॉ. शशांक सक्सेना	पदेन सदस्य	5	5
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	पदेन सदस्य	5	5
डॉ. राजीव मानिक	पदेन सदस्य	5	5
श्री उन्नीकृष्ण ए.	पदेन सदस्य	5	5

श्री बी. श्रीराम	अंशकालिक सदस्य	5	5
डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम	अंशकालिक सदस्य	5	3

जीबी ने वर्ष के दौरान 15 विनियमनों में संशोधन को मंजूरी दी। इसने सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीए, आईपीई, आईयू, आरवी, और आरवीओ), परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा, सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन के क्षेत्रों में बोर्ड की गतिविधियों और निष्पादन की समीक्षा की। इसने आईपीए और आरवी के लिए निरीक्षण नियमावली को मंजूरी दी। इसने वर्ष 2021-22 के लिए लेखा-परीक्षा समिति और बजट प्रस्तावों की सिफारिश के अनुसार 2019-20 के लिए बोर्ड के वित्तीय विवरणों को स्वीकृति दी।

वर्ष के दौरान, जीबी के गैर-पूर्णकालिक सदस्यों ने 19 जून, 2020 को आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठन और बाजार की चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए अपनी तरह की पहली बातचीत की।

इसके अलावा, उन्होंने 20 अगस्त, 2020 को चुनिंदा सेवा प्रदाताओं (आईपीए के एमडी, आईयू के एमडी, आरवीओ, आईपी और आरवी के सीईओ सहित) के साथ बातचीत की ताकि उनके सामने आने वाले मुद्दों, कठिनाइयों और बाधाओं पर चर्चा की जा सके।

जीबी ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए सरकार को प्रदान किए जाने वाले इनपुट पर चर्चा की। जीबी ने अगले शैक्षणिक सत्र से जीआईपी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल को भी मंजूरी दे दी। जीबी ने आईबीबीआई के लिए भविष्य की कार्यवाही के बारे में भी विचार-विमर्श किया क्योंकि दिवाला का क्षेत्र अब परिपक्व हो गया है, नियामक के रूप में इसकी प्रासंगिकता और नियामक और संस्था के रूप में आईबीबीआई के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, विशेष रूप से उस समय के दौरान जब कोविड-19 महामारी के दौरान शारीरिक रूप से बैठकें करना संभव नहीं था, जीबी ने 2020-21 में अपनी सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित कीं।

निष्पादन का आकलन

जीबी स्व-मूल्यांकन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। जीबी के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक प्रेरणा यह आकलन करने में निहित है कि क्या जीबी बाहरी जांच की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और संगठनात्मक और बोर्ड के निष्पादन दोनों में सुधार कर रहा है। इसके अलावा, बोर्ड मूल्यांकन

जीबी के निष्पादन में सुधार के लिए शक्ति, कमजोरियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। जीबी के निष्पादन का मूल्यांकन मोटे तौर पर तीन आयामों पर किया जा सकता है, अर्थात :

(क) **बोर्ड संरचना और गुणवत्ता**, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति, इसकी बैठकों में बहस और चर्चा की गुणवत्ता और हितधारकों के साथ जुड़ाव जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

(ख) **बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं**, जो बोर्ड की बैठकों की नियमितता और आवृत्ति, कार्य-वृत्तों की सटीकता, रणनीतिक और महत्वपूर्ण मामलों पर लगाए गए समय और बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों पर अनुवर्ती जैसे पहलुओं को कवर करती हैं।

(ग) **बोर्ड के कार्य और विकास**, जिसमें लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना और शीर्ष प्रबंधन के साथ संचार के खुले चैनल जैसे पहलू शामिल हैं।

बेहतर संगठनात्मक निष्पादन के लिए समीक्षा तंत्र स्थापित करने के महत्व को डब्ल्यूजी द्वारा 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का निर्माण' पर मान्यता दी गई थी। डब्ल्यूजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि

'उच्च निष्पादन वाले संगठन को प्राप्त करने के लिए संगठन के अभिकल्प, प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था पर टोस अभिकल्प निर्णयों की आवश्यकता होती है'। तदनुसार, इसने एक 'आंतरिक रूप से सुसंगत रणनीति की सिफारिश की जो इन तीन स्तंभों को इंटरलॉकिंग पूर्णता के रूप में देखती है, जो इस स्थिति में उच्च निष्पादन के लिए प्रेरित करेगी'। पहले स्तंभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिकल्प सिद्धांत, डब्ल्यूजी द्वारा अनुशंसित संगठन अभिकल्प, 'आंतरिक और बाहरी समीक्षा तंत्र को मजबूत करना', 'संगठन के कामकाज में पारदर्शिता' और 'जवाबदेही' थे। ये सिद्धांत जीबी के प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी कामकाज के लिए प्रासंगिक हैं।

समीक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में, आईबीबीआई के जीबी ने एक स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की जिसमें ऊपर बताए गए आयामों और मापदंडों को शामिल किया गया है। जीबी 2018-19 से वार्षिक रूप से अपना स्व-मूल्यांकन कर रहा है और वार्षिक रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट कर रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए, जीबी के सदस्यों ने 1 से 5 के पैमाने पर स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली का जवाब दिया। प्रतिक्रियाओं को सारणीबद्ध किया गया और प्रत्येक आयाम के संबंध में एक समग्र रेटिंग प्राप्त की गई। सारणी 74 प्रश्नावली के सदस्यों के उत्तरों के आधार पर जीबी के निष्पादन को सारांशित करती है।

सारणी 74 : 2020-21 में ग्रासी बोर्ड का निष्पादन

आयाम	मापदंड	50 में से स्कोर	रेटिंग
बोर्ड संरचना और गुणवत्ता	संगठन के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए बोर्ड के पास विशेषज्ञता और अनुभव का उपयुक्त मिश्रण है।	45	उत्कृष्ट
	संगठन रणनीतिक योजना या मापने योग्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के सेट के साथ काम करता है।	48	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सभी सदस्यों को संगठन के दृष्टिकोण, मिशन, इसकी रणनीतिक दिशा और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की स्पष्ट समझ है।	46	उत्कृष्ट
	बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की पहचान की है और उनकी समीक्षा की है और उनके साथ संचार का उचित स्तर है।	46	उत्कृष्ट
	बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में समितियाँ हैं, जिनकी आवश्यकता हो सकती है, अच्छी तरह से परिभाषित संदर्भ शर्तों के साथ, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित।	44	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकें स्वस्थ और संभावित चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित करती हैं।	49	उत्कृष्ट
	बोर्ड स्वयं उद्देश्य निर्धारित करता है और वार्षिक आधार पर उनके विरुद्ध अपने निष्पादन को मापता है।	45	उत्कृष्ट
	बोर्ड अधिकारियों को निदेश देता है कि नीतियों को निर्धारित, संदर्भित या संशोधित करके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए।	42	संतोषजनक
कुल सेवणल स्कोर		365/400 (91%)	उत्कृष्ट
आयाम	मापदंड	50 में से स्कोर	रेटिंग
बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं	बोर्ड पर्याप्त नियमितता के साथ मिलता है और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए पर्याप्त है।	50	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठक का एजेंडा और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात संक्षिप्त हैं और मामले पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता और विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं।	50	उत्कृष्ट
	बैठक के संबंध में सभी जानकारी सदस्यों को समय पर प्रसारित की जाती है।	50	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों का ठीक से पालन किया जाता है और बाद की बोर्ड बैठकों में समीक्षा की जाती है।	48	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण और समयबद्ध तरीके से अनुमोदित होते हैं।	49	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी की पर्याप्तता।	47	उत्कृष्ट

	सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर खर्च किया गया समय पर्याप्त है।	48	उत्कृष्ट
	यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं कि बोर्ड को बैठकों के बीच सभी भौतिक मामलों पर पूरी तरह से सूचित किया जाता है (उपयुक्त बाहरी जानकारी, जैसे, सामग्री नियामक परिवर्तन सहित)।	46	उत्कृष्ट
कुल सेक्शनल स्कोर		388/400 (97%)	उत्कृष्ट
आयाम	मापदंड	50 में से स्कोर	रैटिंग
बोर्ड के कार्य और विकास	बोर्ड संगठन के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करता है।	48	उत्कृष्ट
	संगठन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाता है।	49	उत्कृष्ट
	बोर्ड के पास शीर्ष प्रबंधन और अन्य लोगों के साथ संचार के खुले चैनल हैं और उन्हें ठीक से जानकारी दी गई है।	44	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए, प्रभावी निर्णय लेने और उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है।	47	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और सहयोगात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार महसूस करते हैं।	48	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य ख्याति के महत्वपूर्ण कार्य, अर्थात् संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं का विनियमन, संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।	49	उत्कृष्ट
कुल सेक्शनल स्कोर		285/300 (95%)	उत्कृष्ट
कुल योग		1038/1100 (94%) (उत्कृष्ट)	

जीबी ने पिछले वर्ष की तुलना में तीनों आयामों में निष्पादन में सुधार के साथ 2020-21 में तीनों आयामों में बहुत अच्छा निष्पादन करने के लिए स्वयं का मूल्यांकन किया। जीबी का निष्पादन, विशेष रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इसके प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की समीक्षा करने के पहलुओं में, हितधारकों के साथ संचार का उचित स्तर होने और उद्देश्यों को निर्धारित करने और जीबी के निष्पादन को मापने के लिए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के आधार पर 'संतोषजनक' से सुधार कर 'उत्कृष्ट' हो गया है। जीबी बैठकों के दौरान स्वस्थ और जांच चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस के मामले में इसने विशेष रूप से अच्छा निष्पादन किया। वर्ष के दौरान बोर्ड के 90 प्रतिशत सदस्यों ने बैठकों में 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करते हुए पर्याप्त नियमितता के साथ बैठकों की। बोर्ड की बैठक के कार्यसूची नोट्स, और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात को जीबी द्वारा अच्छी गुणवत्ता के लिए सराहा गया और विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए विस्तृत किया गया। जीबी द्वारा सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर लगाए गए समय का पर्याप्त आकलन किया गया। जीबी के निष्पादन के आकलन ने इसी दौरान कुछ मापदंडों की पहचान करने में मदद की है जिससे इसके निष्पादन में और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जीबी अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले दृष्टिकोण और सिद्धांतों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का निष्पादन करते हुए, अपने जनादेश को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है।

आगामी माग

2020-21 की अंतिम दो तिमाहियों की ओर संकेतक जैसे कि ऑल-टाइम हाई स्टॉक मार्केट, दुनिया भर में रिकवरी के संकेत, अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भारी प्रवाह और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों की पूर्व-महामारी के स्तर पर दिवाला कंपनियों के समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में आरए की उपलब्धता में सुधार ने वापसी का संकेत दिया। हालांकि, जैसा कि बहुत से देश कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहरों से जूझ रहे हैं, कुछ कारकों जैसे नकारात्मक क्षेत्र में, तरलता समर्थन और प्रोत्साहन पैकेजों की कमी, कोविड-19 के आसपास अनिश्चितता और तनाव

का सामना करने के लिए व्यापार की घटती सहनशक्ति ने विश्व अर्थव्यवस्था में भविष्य में कारपोरेट दिवाला की उच्च घटनाओं का संकेत दिया। इस पृष्ठभूमि में, वैश्विक स्तर पर कारपोरेट दिवाला में परिवर्तित होने वाली महामारी के कारण लंबे समय तक कारपोरेट तनाव की संभावना है।

भारतीय संदर्भ में, ज्योंही 25 मार्च, 2021 से संहिता की धारा 7, 9 और 10 का निलंबन हटेगा, दिवाला शुरू करने के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हितधारक निम्नलिखित के माध्यम से तनाव का समाधान करना जारी रखेंगे: (क) कोविड-19 तनाव के अलावा अन्य तनाव के संबंध में सीआईआरपी, (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समझौता या व्यवस्था की योजना, और (ग) आरबीआई का विवेकपूर्ण ढांचा। कई व्यवसाय तनाव से बचने के लिए लागत में कटौती के कई उपाय करते हुए तनाव के समाधान के नवीन विकल्प तलाश रहे हैं। इसके अलावा, (क) महामारी कम होने के बाद व्यवहार्य कंपनियों के पास सामान्य व्यवसाय संचालन होगा, (ख) दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यतिक्रम की उच्च सीमा अधिकांश एमएसएमई को दिवाला कार्यवाही से बाहर रखेगी, और (ग) कोविड-19 अवधि व्यतिक्रम हमेशा के लिए दिवाला कार्यवाही से बाहर रहती है। जैसा कि ये कारक काम में आते हैं, यह संभावना है कि कारपोरेट दिवाला उम्मीद से कम परिमाण में हो सकता है। फिर भी, दिवाला फाइलिंग में संभावित वृद्धि और ई-कोर्ट सिस्टम को मजबूत करने से निपटने के लिए एनसीएलटी की बेंच क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। दिवाला फाइलिंग में संभावित उछाल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यावसायिकों की संख्या और क्षमता भी बढ़ रही है।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और अन्यथा, आईबीसीआई ने संहिता के कार्यान्वयन में सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यवसायों के समयबद्ध बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह नए उत्पादों को जारी रखेगा और मौजूदा उत्पादों में नई सुविधाओं को जोड़ेगा।

बॉक्स 7 : प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया

संहिता ने शुरू करने के लिए एक मानक, सादी वेनिला प्रक्रियाओं लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता के साथ प्रत्याशित परिष्कृत विकल्प परिकल्पना की। इसमें कंपनियों के तनाव के समाधान के लिए सीआईआरपी की परिकल्पना की गई है। हालांकि, सीआईआरपी की सफलता आरए की उपलब्धता पर गंभीर रूप से निर्भर करती है। जब अधिकांश कंपनियाँ, उद्योग और अर्थव्यवस्थाएं महामारी के कारण तनाव का अनुभव करना जारी रखती हैं, तो एक असफल कंपनी को बचाने के लिए आरए खोजने की संभावना कम होती है। यह कुछ समय के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कब कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद भी व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा, 1 करोड़ रुपये से कम के व्यतिक्रम और पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पन्न व्यतिक्रम के संबंध में सीआईआरपी उपलब्ध नहीं है। इसके दो परिणाम हैं – या तो कंपनी बहुत लंबे समय तक तनाव में रहती है या लेनदार अपने बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं। किसी भी मामले में, कंपनी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। इसके लिए ऐसे नए विकल्प तलाशने की आवश्यकता है जो तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं लेकिन आरए के अभाव में परिसमापन नहीं करते हैं।

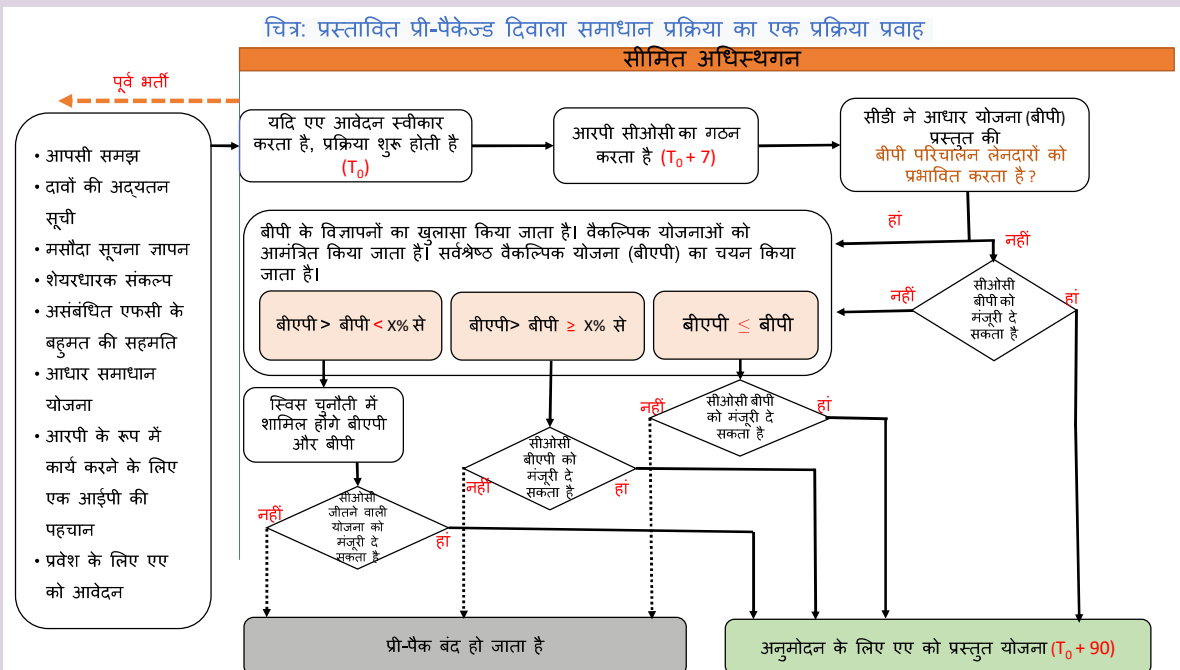
सीआईआरपी की निर्धारित प्रक्रिया है और इसलिए, कुछ मात्रा में अनम्यता, कुछ परिस्थितियों में इसके उपयोग को सीमित कर सकती है। यह कंपनी के नियंत्रण को आईआरपी और फिर आरपी और अंत में सफल आरए में अंतरित कर देता है, जिससे व्यवसाय में व्यवधान हो सकता है। मौजूदा प्रबंधन का विस्थापन कंपनियों को तनाव की स्थिति में स्वेच्छा से सीआईआरपी शुरू करने के लिए हतोत्साहित करता है। यह वर्तमान प्रवर्तकों और प्रबंधन द्वारा आंशिक रूप से असहयोग की व्याख्या करता है, जिससे कुछ मामलों में तीव्र अभियोग होता है। परिहार लेन-देन सहित कई मुद्दों का निर्धारण, एए की सीमित क्षमता के लिए चुनौती रही है, जिसके कारण कुछ सीआईआरपी में समय-सीमा का उल्लंघन हो जाता है।

बाजार अद्वितीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त टेलर-मेड समाधान तैयार करने के लिए लचीलेपन को प्राथमिकता देता है। हालाँकि, यह पूर्ण लचीलापन पसंद नहीं करता है, यह एक निदेशित मार्ग की सराहना करता है और औपचारिक प्रक्रिया के लाभ और शुचिता का लाभ उठाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, बाजार अर्ध-औपचारिक प्रक्रिया को तरजीह देता है जो औपचारिक प्रक्रिया की कठिनाइयों को दूर करती है लेकिन इसके लाभों और शुचिता को बरकरार रखती है। एक अर्थ में, औपचारिक प्रक्रिया और अनौपचारिक प्रक्रिया स्पेक्ट्रम के दो पहलु हैं और विभिन्न प्रकार की अर्ध-औपचारिक प्रक्रियाएं, जो दोनों के तत्वों को मिलाती हैं, हितधारकों की सुविधा के अनुरूप मौजूद हो सकती हैं। सबसे लोकप्रिय अर्ध-औपचारिक विकल्प प्री-पैक है, जो हितधारकों के मध्य अनौपचारिक समझ के साथ शुरू होता है, मध्य में औपचारिक रूप से उनके साथ जुड़ता है, और परिणाम के न्यायिक आशीष के साथ समाप्त होता है। दुनिया भर में दिवाला कानून प्री-पैक का रूप प्रदान करते हैं, हालांकि बारीकियाँ अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में भिन्न-भिन्न होती हैं। भारत में औपचारिक प्रक्रियाओं (सीआईआरपी के अधीन निकासी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समझौता या व्यवस्था और आरबीआई के विवेकपूर्ण ढांचे) में प्री-पैक के कुछ तत्व हैं।

सीआईआरपी की तुलना में, प्रीपैक आमतौर पर अधिक लचीला, लागत प्रभावी, समय प्रभावी, व्यवसाय के लिए कम विघटनकारी और कलंक से रहित और समूह दिवाला के लिए अधिक अनुकूल होता है। यह पुनर्गठन की संभावना को बढ़ाता है और अदालतों और आईपी की सीमित भूमिका निभाता है। हालाँकि, इसमें 'सीरियल प्रीपैकिंग' जैसे सरोकारों का हिस्सा है (नियंत्रण करने वाले पक्ष कंपनी को बचाने की बजाय कर्ज से बचने के लिए कंपनी का अधिग्रहण करते हैं)। औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले हितधारकों के समूह के बीच निजी बातचीत और समझ, जो इसके लाभों में योगदान करती है, अक्सर चिंता का प्रमुख स्रोत होता है। हालांकि बाजार की प्रथाओं से निकला, प्रीपैक औपचारिक होता जा रहा है और चिंताओं को दूर करने के लिए इसे विनियमित किया जा रहा है।

बाजार कुछ समय से प्रीपैक समाधान प्रक्रिया की वकालत और आशा कर रहा है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारत केंद्रित प्री-पैक की सिफारिश करने के लिए आईएलसी की उप-समिति का गठन किया था। संहिता की मूल संरचना के भीतर, उप-समिति ने प्री-पैक प्रक्रिया तैयार की है जहाँ एफसी का व्यापक नियंत्रण होता है, कंपनी प्रक्रिया के दौरान अधिस्थगन का आनंद लेती है, और परिणाम सभी पर बाध्यकारी होता है।

प्रस्तावित प्रीपैक दिवाला समाधान का प्रक्रिया प्रवाह चित्र में प्रस्तुत किया गया है।



संहिता के अंतर्गत दिवाला व्यवस्थाओं के विकास में प्री-पैक की शुरुआत एक स्वाभाविक कदम है। यह तनाव के समाधान के विकल्पों के मेनू को समृद्ध करेगा और भारतीय दिवाला यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएगा।

में दिवाला और शोधन अक्षमता शुरू होना चाहिए क्योंकि इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित है।

व्यक्तिगत दिवाला के संदर्भ में, इसके आर्थिक पहलुओं के अलावा, देनदारों और संबंधित परिवार के सदस्यों पर इसके सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में बड़े और संवेदनशील अर्थ हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें दिवाला समाधान ढांचा संचालित होता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत दिवाला से जुड़ा हुआ है। **बॉक्स 9** दिवाला कानून के व्यापक सामाजिक प्रभाव का विवरण प्रस्तुत है।

मध्यस्थता

मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का रूप है जिसमें तीसरा तटस्थ पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने में विवादित पक्षों की सहायता करने का प्रयास करता है। यह विवाद समाधान का सरलीकृत तरीका है जहां तृतीय पक्ष संचार और बातचीत के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। दिवाला विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह न केवल एए के केसलोड को कम करेगा बल्कि बड़े दिवाला मामलों में जहां प्रक्रियाएं अधिक जटिल हो सकती हैं, मध्यस्थता प्रक्रिया को तेज कर सकती है और इसे और अधिक किफायती बना सकती है, जिससे लेनदारों को संतुष्ट करने के लिए आस्तियों में अधिक मूल्य छोड़ दिया जाता है। सामान्य तौर पर, मध्यस्थता ने पिछले कुछ दशकों में दिवाला विवादों में बड़ा बदलाव देखा है। यह न्यायनिर्णयन का प्रतिकार बन गया है और पक्षों को अभियोग फाइल करने की बजाय ऋण चुकौती पर बातचीत करने की अनुमति देकर दिवाला विवादों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ई-मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में सफल विकल्प बनकर उभरा है। **बॉक्स 10** संहिता के अधीन समाधान के लिए तंत्र के रूप में मध्यस्थता पर चर्चा करता है।

सीमा पार दिवाला

कारपोरेट दिवाला से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, यह अधिक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य, सीमा पार दिवाला व्यवस्था के बारे में सोचने का समय है। सीमा पार दिवाला (मॉडल लॉ) पर युएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और स्वीकार्य है, मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। इसे 46 न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। यह घरेलू कार्यवाही को प्राथमिकता देकर और आदर्श कानून के अधीन राहत से इनकार करने की अनुमति देकर देश के घरेलू दिवाला कानून की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करता है यदि ऐसी राहत देश की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। यह विदेशी कार्यवाही की मान्यता से संबंधित मुद्दों, एक ही देनदार से संबंधित कार्यवाही का समन्वय विदेशी लेनदारों के अधिकारय विदेशी दिवाला प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य, और विभिन्न न्यायालयों में अधिकारियों के बीच सहयोग को संबोधित करता है। इसे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधनों के साथ अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

आईएलसी ने 16 अक्टूबर, 2018 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कारपोरेट एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कारोबार करते हैं और आस्तियां रखते हैं, विश्व स्तर पर स्वीकृत और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सीमा पार दिवाला ढांचे को पेश करने के लिए संहिता में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव किया था। ढांचे के कार्यान्वयन से सीडी

के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित और व्यापक दिवाला ढांचा तैयार होगा, जो वैश्वीकृत वातावरण में आवश्यक है। आईएलसी द्वारा अनुशंसित के रूप में मॉडल कानून को अपनाने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: (क) विदेशी निवेश में वृद्धि (ख) वैश्विक रूप से स्वीकृत ढांचे को अपनाते हुए घरेलू दिवाला कानून के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए लचीलापन; (ग) विदेशी कार्यवाही की मान्यता से इनकार करने या किसी अन्य सहायता के प्रावधान को सक्षम करके घरेलू हितों की सुरक्षा यदि ऐसी कार्रवाई घरेलू सार्वजनिक नीति के विपरीत है; (घ) विदेशी कार्यवाही की तुलना में घरेलू दिवाला कार्यवाही को अधिमानता देते हुए घरेलू कार्यवाही को प्राथमिकता; और (ङ) समवर्ती कार्यवाही के तेज और प्रभावी संचालन की सुविधा के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में और घरेलू स्तर पर अदालतों और आईपी के बीच सहयोग के लिए तंत्र।

भारत में सीमा पार दिवाला शुरू करने पर काम शुरू करने के लिए, सरकार ने डॉ. के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता में सीमा पार दिवाला नियम/विनियमन समिति का गठन किया, जो सीमा पार दिवाला के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमनों का मसौदा तैयार करती है। समिति ने 15 जून, 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।



बोर्ड का वित्तीय कार्य निष्पादन

संहिता के अनुसार आईबीबीआई को उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी&एजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई ने इन नियमों

के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों और बैलेंस शीट का वार्षिक विवरण तैयार किया और उन्हें अनुमोदन के बाद अग्रेषित किया। लेखापरीक्षा समिति और उसके जीबी, लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सी-एजीने इन खातों का लेखापरीक्षा किया और 03 जनवरी, 2022 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की। सारणी 75 और 76 बोर्ड के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती हैं।

सारणी 75 : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आय और व्यय विवरण

(लाख रुपये)

आय	2019-20	2020-21	व्यय* (मैं से)	2019-20	2020-21
सहायता अनुदान –वेतन	1200.00	1458.00	सहायता अनुदान –वेतन	1200.00	1458.00
सहायता अनुदान –पूजी	-	-	सहायता अनुदान –पूजी	123.54	-
सहायता अनुदान – सामान्य	950.00	1200.00	सहायता अनुदान – सामान्य	950.00	1190.15
आंतरिक राजस्व	599.22	690.43	आंतरिक राजस्व	392.38	164.12
कुल	2749.22	3348.43	कुल	2665.92	2812.27

(* वर्ष के दौरान दिए गए अवल आस्तियों में वृद्धि और शुद्ध अग्रिम सहित.)

सारणी 76: 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि

(लाख रुपये में)

शीर्ष	2019-20				2020-21		
	आगे लाया गया	अंतःप्रवाह	बहिर्प्रवाह	षे	अंतःप्रवाह	बहिर्प्रवाह	षे
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7	8=5+6-7
सहायता अनुदान –वेतन	-	1200.00	1200.00	-	1458.00	1458.00	-
सहायता अनुदान –पूजी	123.54	-	123.54	-	-	-	-
सहायता अनुदान – सामान्य	-	950.00	950.00	-	1200.00	1190.15	9.85
आंतरिक राजस्व	339.54	599.22	392.38	546.38	690.43	164.12	1072.69
कुल	463.08	2749.22	2665.92	546.38	3348.43	2812.27	1082.54

आईबीबीआई को सरकार से 2020-21 में 2658.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त आंतरिक राजस्व 690.43 लाख रुपये है जिसमें आईपीए/आईपी/आईयू जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क शामिल है। इसने 2020-21 में कुल 2812.27 लाख रुपये खर्च किए।

2015 में संहिता की अवधारणा करने वाले बीएलआरसी का मानना था कि, एक अच्छे अभ्यास के रूप में, बोर्ड को अपनी विनियमित संस्थाओं से एकत्र की गई फीस से खुद को निधि देना चाहिए। "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का निर्माण" पर कार्य समूह ने माना कि प्रारंभिक चरण में आईबीबीआई के निर्माण के लिए, सरकार से बजटीय अनुदान वित्त

पोषण का मुख्य स्रोत होगा। हालांकि, यह परिकल्पना की गई थी कि कुछ वर्षों में शोधन अक्षमता मध्यस्थता उद्योग की रूपरेखा दिखाई देगी। तब आईबीबीआई को उन सभी आईपी, आईपीए और आईयू पर शुल्क लागू करने में सक्षम होना चाहिए जो इसके खर्चों का भुगतान करेंगे।

वित्तीय पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए आईबीबीआई ने भविष्य के वर्षों के लिए व्यय की आवश्यकता को पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है। नियामक उत्तरदायित्वों में वृद्धि और संगठन क्षमताओं की ताकत बढ़ाने के कारण भविष्य में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। आईबीबीआई की सक्रिय भूमिका और प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान, सीमा-पार दिवाला, समूह दिवाला, दिवाला में

मध्यस्थता का उपयोग और नई शुरुआत प्रक्रिया आदि के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के कारण बोर्ड की नियामक उत्तरदायित्वों का दायरा बढ़ रहा है। विनियामक आवश्यकता के अनुरूप व्यय की आवश्यकता का आकलन करने और निधि के विभिन्न संसाधनों की पहचान करने के बाद, बजटीय सहायता में क्रमिक कमी और आईबीबीआई की वित्तीय पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप विकसित किया जाएगा।



सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन

बोर्ड संविधि का सृजन है। इसे संविधि के उपबंधों के साथ-साथ अन्य अनुप्रयोग्य कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। सारणी 77 बोर्ड द्वारा अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 77 : सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण

संविधि	अनुपालन अपेक्षित	अनुपालन की स्थिति
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	धारा 16 (2) : आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।	बोर्ड ने आईपी की अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है ताकि विलम्ब को दूर किया जा सके। बोर्ड को इस बारे में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
	धारा 16 (4) : बोर्ड एए से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, आईपी के नाम की सिफारिश करेगा, जहां ओसी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है और आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।	बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई-25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर-31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी-30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। 2020-21 के दौरान बोर्ड को इस बारे में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुए।
	धारा 22(4) : बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने एए को आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस बारे में एए से 35 संदर्भ प्राप्त हुए और इन सभी का निर्धारित समय में जवाब दिया गया।
	धारा 34(6) : बोर्ड, एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आईपी के नाम का प्रस्ताव करेगा।	बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई-25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर-31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी-30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020-21 में एए से बोर्ड को 06 निदेश प्राप्त हुए और बोर्ड ने सभी का निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया।
	धारा 97(2) : बोर्ड एए द्वारा निदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने एए को आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त हो गया है। हालांकि, बोर्ड को इस बारे में एए से 06 संदर्भ प्राप्त हुए और इन सभी का निर्धारित समय में जवाब दिया गया।
	धारा 97(4) : बोर्ड, निदेश प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर, व्यष्टिक की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी नामित करेगा, जहां धारा 94 या 95 के अधीन आरपी के माध्यम से नहीं बल्कि देनदार या लेनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवेदन फाइल किया जाता है।	बोर्ड ने 'दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2020 के अधीन और दिवाला व्यावसायिकों के अंतरिम दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता न्यासी (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2020 के अधीन आईआरपी के रूप में नियुक्त करने के लिए क्रमशः 1 जुलाई-25 नवंबर, 2020, 26 नवंबर-31 दिसंबर, 2020 और 01 जनवरी-30 जून, 2021 के दौरान, एए द्वारा बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना नियुक्त करने के लिए आईपी के तीन पेनल तैयार करके साझा किए हैं। हालांकि, बोर्ड को इस संबंध में 2020-21 में एए से बोर्ड को 02 निदेश प्राप्त हुए और बोर्ड ने सभी का निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया।

	<p>आईपी विनियमनों के साथ पठित धारा 207 : आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन यह समझाने का अवसर प्रदान करने के बाद निरस्त किया जा सकता है कि आवेदन को क्यों स्वीकार किया जाए।</p>	<p>बोर्ड ने 2020-21 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया है।</p>
	<p>आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 के साथ पठित धारा 217 : बोर्ड विनियमनों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करेगा और उनका निपटारा करेगा।</p>	<p>बोर्ड को 2020-21 के दौरान 1616 शिकायतें मिलीं और वर्ष के दौरान 2002 शिकायतों का निपटारा किया गया।</p>
	<p>आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 के साथ पठित धारा 218 : बोर्ड संहिता के किसी उपबंध या बनाए गए नियमों या विनियमनों या बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का कथित उल्लंघन के मामले में आईपी, आईपीए या आईयू का निरीक्षण कर सकता है।</p>	<p>बोर्ड ने 2020-21 के दौरान 62 निरीक्षण शुरू किए और वर्ष के दौरान 53 निरीक्षणों का समापन किया।</p>
	<p>आईपी विनियमनों के साथ पठित धारा 220 : डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में तर्कपूर्ण आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का निपटारा करेगा।</p>	<p>अनुपालन किया जा रहा है।</p>
	<p>आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 223 : बोर्ड उचित खाते बनाएगा और ऐसे खातों की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।</p>	<p>बोर्ड ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का फॉर्म) नियम, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपना वार्षिक लेखा तैयार किया। सीएजी ने इसका लेखापरीक्षा किया और 28 अक्टूबर, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की।</p> <p>इसी तरह, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक खाते तैयार किए। सी-एजी ने इसकी लेखापरीक्षा की और अपने दिनांक 03 जनवरी, 2022 के पत्र माध्यम से इस बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की।</p>
	<p>आईबीबीआई (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 229 : बोर्ड, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा-निर्धारित रूप में और समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>बोर्ड ने 2019-20 के दौरान 2016-17 और 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट 30 जून, 2020 को प्रस्तुत की गई थी। 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट 16 जून, 2021 को प्रस्तुत की गई थी।</p>
	<p>धारा 230 : बोर्ड, अपनी शक्तियों और कार्यों में से कुछ को, जैसा वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकता है।</p>	<p>बोर्ड ने 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल) आदेश, 2017 जारी किया। इसने 25 अप्रैल, 2018 को और फिर 02 जुलाई, 2020 को उक्त आदेश में संशोधन किया।</p>
	<p>धारा 236 : बोर्ड शिकायत दर्ज कर सकता है।</p>	<p>बोर्ड ने 2020-21 के दौरान विशेष न्यायालय में 15 शिकायतें दर्ज कीं।</p>
	<p>धारा 240 : बोर्ड के लिए इस खंड में निर्दिष्ट मामलों पर विनियमन बनाना आवश्यक है।</p>	<p>बोर्ड ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से 2019-20 के दौरान 15 संशोधन विनियमन बनाए। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने निम्नांकित तैयार किए हैं :</p> <p>(क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीई, आईपीए और आईयू) को विनियमित करने के लिए छः नियम;</p> <p>(ख) प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए सात विनियमन (सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, सीडी के पीजी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया और सीडी के पीजी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया)</p> <p>(ग) बोर्ड के आंतरिक कार्यकरण को विनियमित करने के लिए चार विनियमन।</p>
	<p>धारा 241 : विनियमन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।</p>	<p>बोर्ड ने 2020-21 में अधिसूचित सभी 15 विनियमनों को 2020-21 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एमसीए को भेजा।</p>

<p>केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)</p>	<p>धारा 37(1) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अगले महीने के दसवें दिन से पहले माल या सेवाओं की जावक आपूर्तियों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p> <p>हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं :</p> <table border="1" data-bbox="358 394 802 625"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल, 2020</td> <td>जुलाई 24, 2020</td> </tr> <tr> <td>मई, 2020</td> <td>जुलाई 28, 2020</td> </tr> <tr> <td>जून, 2020</td> <td>अगस्त 5, 2020</td> </tr> <tr> <td>जुलाई, 2020 – मार्च, 2021</td> <td>अगले माह का 11वां दिन</td> </tr> </tbody> </table>	माह के लिए	अंतिम तारीख	अप्रैल, 2020	जुलाई 24, 2020	मई, 2020	जुलाई 28, 2020	जून, 2020	अगस्त 5, 2020	जुलाई, 2020 – मार्च, 2021	अगले माह का 11वां दिन	<p>बोर्ड ने निम्नानुसार विवरण फाइल किया :</p> <table border="1" data-bbox="959 243 1403 764"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>फाइल करने की तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल, 2020</td> <td>21 मई, 2020</td> </tr> <tr> <td>मई, 2020</td> <td>20 जुलाई, 2020</td> </tr> <tr> <td>जून, 2020</td> <td>22 जुलाई, 2020</td> </tr> <tr> <td>जुलाई, 2020</td> <td>11 अगस्त, 2020</td> </tr> <tr> <td>अगस्त, 2020</td> <td>11 सितंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>सितंबर, 2020</td> <td>11 अक्तूबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>अक्टूबर, 2020</td> <td>11 नवंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>नवंबर, 2020</td> <td>11 दिसंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>दिसंबर, 2020</td> <td>11 जनवरी, 2021</td> </tr> <tr> <td>जनवरी, 2021</td> <td>11 फरवरी, 2021</td> </tr> <tr> <td>फरवरी, 2021</td> <td>11 मार्च, 2021</td> </tr> <tr> <td>मार्च, 2021</td> <td>11 अप्रैल, 2021</td> </tr> </tbody> </table>	माह के लिए	फाइल करने की तारीख	अप्रैल, 2020	21 मई, 2020	मई, 2020	20 जुलाई, 2020	जून, 2020	22 जुलाई, 2020	जुलाई, 2020	11 अगस्त, 2020	अगस्त, 2020	11 सितंबर, 2020	सितंबर, 2020	11 अक्तूबर, 2020	अक्टूबर, 2020	11 नवंबर, 2020	नवंबर, 2020	11 दिसंबर, 2020	दिसंबर, 2020	11 जनवरी, 2021	जनवरी, 2021	11 फरवरी, 2021	फरवरी, 2021	11 मार्च, 2021	मार्च, 2021	11 अप्रैल, 2021
माह के लिए	अंतिम तारीख																																					
अप्रैल, 2020	जुलाई 24, 2020																																					
मई, 2020	जुलाई 28, 2020																																					
जून, 2020	अगस्त 5, 2020																																					
जुलाई, 2020 – मार्च, 2021	अगले माह का 11वां दिन																																					
माह के लिए	फाइल करने की तारीख																																					
अप्रैल, 2020	21 मई, 2020																																					
मई, 2020	20 जुलाई, 2020																																					
जून, 2020	22 जुलाई, 2020																																					
जुलाई, 2020	11 अगस्त, 2020																																					
अगस्त, 2020	11 सितंबर, 2020																																					
सितंबर, 2020	11 अक्तूबर, 2020																																					
अक्टूबर, 2020	11 नवंबर, 2020																																					
नवंबर, 2020	11 दिसंबर, 2020																																					
दिसंबर, 2020	11 जनवरी, 2021																																					
जनवरी, 2021	11 फरवरी, 2021																																					
फरवरी, 2021	11 मार्च, 2021																																					
मार्च, 2021	11 अप्रैल, 2021																																					
	<p>धारा 38(2) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दसवें दिन के बाद लेकिन अगले महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।</p> <p>हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं :</p> <table border="1" data-bbox="358 1031 802 1152"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल, 2020</td> <td>24 जून, 2020</td> </tr> <tr> <td>मई, 2020 – मार्च, 2021</td> <td>अगले माह का 20वां दिन</td> </tr> </tbody> </table>	माह के लिए	अंतिम तारीख	अप्रैल, 2020	24 जून, 2020	मई, 2020 – मार्च, 2021	अगले माह का 20वां दिन	<p>बोर्ड ने निम्नानुसार विवरण फाइल किया :</p> <table border="1" data-bbox="959 846 1403 1367"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>फाइल करने की तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल, 2020</td> <td>21 मई, 2020</td> </tr> <tr> <td>मई, 2020</td> <td>20 जून, 2020</td> </tr> <tr> <td>जून, 2020</td> <td>20 जुलाई, 2020</td> </tr> <tr> <td>जुलाई, 2020</td> <td>19 अगस्त, 2020</td> </tr> <tr> <td>अगस्त, 2020</td> <td>20 सितंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>सितंबर, 2020</td> <td>20 अक्तूबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>अक्तूबर, 2020</td> <td>20 नवंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>नवंबर, 2020</td> <td>18 दिसंबर, 2020</td> </tr> <tr> <td>दिसंबर, 2020</td> <td>18 जनवरी, 2021</td> </tr> <tr> <td>जनवरी, 2021</td> <td>19 फरवरी, 2021</td> </tr> <tr> <td>फरवरी, 2021</td> <td>18 मार्च, 2021</td> </tr> <tr> <td>मार्च, 2021</td> <td>20 अप्रैल, 2021</td> </tr> </tbody> </table>	माह के लिए	फाइल करने की तारीख	अप्रैल, 2020	21 मई, 2020	मई, 2020	20 जून, 2020	जून, 2020	20 जुलाई, 2020	जुलाई, 2020	19 अगस्त, 2020	अगस्त, 2020	20 सितंबर, 2020	सितंबर, 2020	20 अक्तूबर, 2020	अक्तूबर, 2020	20 नवंबर, 2020	नवंबर, 2020	18 दिसंबर, 2020	दिसंबर, 2020	18 जनवरी, 2021	जनवरी, 2021	19 फरवरी, 2021	फरवरी, 2021	18 मार्च, 2021	मार्च, 2021	20 अप्रैल, 2021				
माह के लिए	अंतिम तारीख																																					
अप्रैल, 2020	24 जून, 2020																																					
मई, 2020 – मार्च, 2021	अगले माह का 20वां दिन																																					
माह के लिए	फाइल करने की तारीख																																					
अप्रैल, 2020	21 मई, 2020																																					
मई, 2020	20 जून, 2020																																					
जून, 2020	20 जुलाई, 2020																																					
जुलाई, 2020	19 अगस्त, 2020																																					
अगस्त, 2020	20 सितंबर, 2020																																					
सितंबर, 2020	20 अक्तूबर, 2020																																					
अक्तूबर, 2020	20 नवंबर, 2020																																					
नवंबर, 2020	18 दिसंबर, 2020																																					
दिसंबर, 2020	18 जनवरी, 2021																																					
जनवरी, 2021	19 फरवरी, 2021																																					
फरवरी, 2021	18 मार्च, 2021																																					
मार्च, 2021	20 अप्रैल, 2021																																					
	<p>धारा 44(1) : कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के इकतीसवें दिन या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।</p> <p>धारा 44(2) : इसके लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक खातों की प्रति और समाधान विवरण के साथ वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 2019-20 के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।</p>	<p>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 की रिटर्न 16 फरवरी, 2021 और वित्त वर्ष 2020-21 की रिटर्न 24 दिसंबर, 2021 को फाइल की।</p>																																				

	<p>धारा 51(1) : इसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है।</p> <p>धारा 39(3) : इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, जो ऐसे महीने की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर उस महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसमें कटौती की गई है।</p> <p>टिप्पणी: अप्रैल और मई, 2020 के महीनों के लिए अंतिम तारीख 30 जून, 2020 थी।</p>	<p>बोर्ड ने निम्नानुसार विवरण फाइल किया :</p> <table border="1" data-bbox="927 239 1365 758"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>रिटर्न फाइल करने की तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>अप्रैल, 2020</td><td>15 जून, 2020</td></tr> <tr><td>मई, 2020</td><td>15 जून, 2020</td></tr> <tr><td>जून, 2020</td><td>07 जलाई, 2020</td></tr> <tr><td>जुलाई, 2020</td><td>08 अगस्त, 2020</td></tr> <tr><td>अगस्त, 2020</td><td>09 सितंबर, 2020</td></tr> <tr><td>सितंबर, 2020</td><td>08 अक्तुबर, 2020</td></tr> <tr><td>अक्तुबर, 2020</td><td>09 नवंबर, 2020</td></tr> <tr><td>नवंबर, 2020</td><td>09 दिसंबर, 2020</td></tr> <tr><td>दिसंबर, 2020</td><td>08 जनवरी, 2021</td></tr> <tr><td>जनवरी, 2021</td><td>04 फरवरी, 2021</td></tr> <tr><td>फरवरी, 2021</td><td>08 मार्च, 2021</td></tr> <tr><td>मार्च, 2021</td><td>10 अप्रैल, 2021</td></tr> </tbody> </table>	माह के लिए	रिटर्न फाइल करने की तारीख	अप्रैल, 2020	15 जून, 2020	मई, 2020	15 जून, 2020	जून, 2020	07 जलाई, 2020	जुलाई, 2020	08 अगस्त, 2020	अगस्त, 2020	09 सितंबर, 2020	सितंबर, 2020	08 अक्तुबर, 2020	अक्तुबर, 2020	09 नवंबर, 2020	नवंबर, 2020	09 दिसंबर, 2020	दिसंबर, 2020	08 जनवरी, 2021	जनवरी, 2021	04 फरवरी, 2021	फरवरी, 2021	08 मार्च, 2021	मार्च, 2021	10 अप्रैल, 2021						
माह के लिए	रिटर्न फाइल करने की तारीख																																	
अप्रैल, 2020	15 जून, 2020																																	
मई, 2020	15 जून, 2020																																	
जून, 2020	07 जलाई, 2020																																	
जुलाई, 2020	08 अगस्त, 2020																																	
अगस्त, 2020	09 सितंबर, 2020																																	
सितंबर, 2020	08 अक्तुबर, 2020																																	
अक्तुबर, 2020	09 नवंबर, 2020																																	
नवंबर, 2020	09 दिसंबर, 2020																																	
दिसंबर, 2020	08 जनवरी, 2021																																	
जनवरी, 2021	04 फरवरी, 2021																																	
फरवरी, 2021	08 मार्च, 2021																																	
मार्च, 2021	10 अप्रैल, 2021																																	
<p>आयकर अधिनियम, 1961</p>	<p>धारा 139 : बोर्ड प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए आय कर रिटर्न फाइल करेगा।</p>	<p>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 की रिटर्न 13 अक्तुबर, 2021 को फाइल की।</p>																																
	<p>धारा 200 : बोर्ड वेतन, अनुबंध और व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) काटेगा और जमा करेगा:</p> <table border="1" data-bbox="358 957 803 1108"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल, 2020 – फरवरी, 2021</td> <td>माह के अंत से सात दिनों के भीतर</td> </tr> <tr> <td>मार्च, 2021</td> <td>30 अप्रैल, 2021</td> </tr> </tbody> </table>	माह के लिए	अंतिम तारीख	अप्रैल, 2020 – फरवरी, 2021	माह के अंत से सात दिनों के भीतर	मार्च, 2021	30 अप्रैल, 2021	<p>बोर्ड ने निम्नानुसार प्रति माह टीडीएस की कटौती की और जमा कराया :</p> <table border="1" data-bbox="927 919 1365 1438"> <thead> <tr> <th>माह के लिए</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>अप्रैल, 2020</td><td>06 मई, 2020</td></tr> <tr><td>मई, 2020</td><td>05 जून, 2020</td></tr> <tr><td>जून, 2020</td><td>06 जलाई, 2020</td></tr> <tr><td>जुलाई, 2020</td><td>05 अगस्त, 2020</td></tr> <tr><td>अगस्त, 2020</td><td>04 सितंबर, 2020</td></tr> <tr><td>सितंबर, 2020</td><td>06 अक्तुबर, 2020</td></tr> <tr><td>अक्तुबर, 2020</td><td>03 नवंबर, 2020</td></tr> <tr><td>नवंबर, 2020</td><td>04 दिसंबर, 2020</td></tr> <tr><td>दिसंबर, 2020</td><td>05 जनवरी, 2021</td></tr> <tr><td>जनवरी, 2021</td><td>02 फरवरी, 2021</td></tr> <tr><td>फरवरी, 2021</td><td>02 मार्च, 2021</td></tr> <tr><td>मार्च, 2021</td><td>29 अप्रैल, 2021</td></tr> </tbody> </table>	माह के लिए	अंतिम तारीख	अप्रैल, 2020	06 मई, 2020	मई, 2020	05 जून, 2020	जून, 2020	06 जलाई, 2020	जुलाई, 2020	05 अगस्त, 2020	अगस्त, 2020	04 सितंबर, 2020	सितंबर, 2020	06 अक्तुबर, 2020	अक्तुबर, 2020	03 नवंबर, 2020	नवंबर, 2020	04 दिसंबर, 2020	दिसंबर, 2020	05 जनवरी, 2021	जनवरी, 2021	02 फरवरी, 2021	फरवरी, 2021	02 मार्च, 2021	मार्च, 2021	29 अप्रैल, 2021
माह के लिए	अंतिम तारीख																																	
अप्रैल, 2020 – फरवरी, 2021	माह के अंत से सात दिनों के भीतर																																	
मार्च, 2021	30 अप्रैल, 2021																																	
माह के लिए	अंतिम तारीख																																	
अप्रैल, 2020	06 मई, 2020																																	
मई, 2020	05 जून, 2020																																	
जून, 2020	06 जलाई, 2020																																	
जुलाई, 2020	05 अगस्त, 2020																																	
अगस्त, 2020	04 सितंबर, 2020																																	
सितंबर, 2020	06 अक्तुबर, 2020																																	
अक्तुबर, 2020	03 नवंबर, 2020																																	
नवंबर, 2020	04 दिसंबर, 2020																																	
दिसंबर, 2020	05 जनवरी, 2021																																	
जनवरी, 2021	02 फरवरी, 2021																																	
फरवरी, 2021	02 मार्च, 2021																																	
मार्च, 2021	29 अप्रैल, 2021																																	
	<p>आयकर नियम, 1962 का नियम 31क : बोर्ड कर कटौती का एक त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :</p> <table border="1" data-bbox="358 1549 803 1751"> <thead> <tr> <th>को समाप्त तिमाही</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30 जून, 2020</td><td>31 जुलाई, 2020</td></tr> <tr><td>30 सितंबर, 2020</td><td>31 अक्तुबर, 2020</td></tr> <tr><td>31 दिसंबर, 2020</td><td>31 जनवरी, 2021</td></tr> <tr><td>31 मार्च, 2021</td><td>30 जून, 2021</td></tr> </tbody> </table>	को समाप्त तिमाही	अंतिम तारीख	30 जून, 2020	31 जुलाई, 2020	30 सितंबर, 2020	31 अक्तुबर, 2020	31 दिसंबर, 2020	31 जनवरी, 2021	31 मार्च, 2021	30 जून, 2021	<p>बोर्ड ने स्रोत पर कटौती किए गये कर का विवरण निम्नानुसार फाइल किया।</p> <table border="1" data-bbox="927 1549 1365 1751"> <thead> <tr> <th>को समाप्त तिमाही</th> <th>अंतिम तारीख</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30 जून, 2020</td><td>30 जुलाई, 2020</td></tr> <tr><td>30 सितंबर, 2020</td><td>19 अक्तुबर, 2020</td></tr> <tr><td>31 दिसंबर, 2020</td><td>25 जनवरी, 2021</td></tr> <tr><td>31 मार्च, 2021</td><td>22 जून, 2021</td></tr> </tbody> </table>	को समाप्त तिमाही	अंतिम तारीख	30 जून, 2020	30 जुलाई, 2020	30 सितंबर, 2020	19 अक्तुबर, 2020	31 दिसंबर, 2020	25 जनवरी, 2021	31 मार्च, 2021	22 जून, 2021												
को समाप्त तिमाही	अंतिम तारीख																																	
30 जून, 2020	31 जुलाई, 2020																																	
30 सितंबर, 2020	31 अक्तुबर, 2020																																	
31 दिसंबर, 2020	31 जनवरी, 2021																																	
31 मार्च, 2021	30 जून, 2021																																	
को समाप्त तिमाही	अंतिम तारीख																																	
30 जून, 2020	30 जुलाई, 2020																																	
30 सितंबर, 2020	19 अक्तुबर, 2020																																	
31 दिसंबर, 2020	25 जनवरी, 2021																																	
31 मार्च, 2021	22 जून, 2021																																	
<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</p>	<p>धारा 4(1)(ख) : बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर स्वतः प्रकटीकरण करेगा।</p> <p>धारा 7(1) : सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को सूचना प्रदान करेगा।</p> <p>धारा 19(6) : एफएए 45 दिनों के भीतर अपीलों का निपटारा करेगा।</p>	<p>बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार किए गए खुलासे को अद्यतन किया।</p> <p>सीपीआईओ ने 305 आवेदकों को जानकारी दी। इसने सभी मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान की।</p> <p>एफएए ने वर्ष के दौरान प्राप्त 39 अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया।</p>																																

कार्यस्थल पर महिलाओं का रौन उल्पीड़न, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013	बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।	बोर्ड ने 11 नवंबर, 2020 को समिति का पुनर्गठन किया।
केंद्रीय वित्तीय नियम, 2017	<p>नियम 229 (xi) : बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करेगा।</p> <p>नियम 230(8) : इसके लिए बोर्ड के लिए खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, सहायता अनुदान पर समस्त ब्याज या अन्य आय भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को भेजना आवश्यक है।</p> <p>नियम 234 : अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था के रूप में, बोर्ड को अनुदान रजिस्टर का रखरखाव करना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।</p> <p>नियम 238 : वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के संबंध में बोर्ड के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p>	<p>बोर्ड ने 21 मई, 2020 को एमसीए के साथ 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन संपन्न किया।</p> <p>वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज 2020-21 को 12 अगस्त, 2021 को सीएफआई को प्रेषित कर दिया गया है।</p> <p>बोर्ड अनुदान रजिस्टर का रखरखाव करता है और उसने 24 अगस्त, 2021 को एमसीए को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है।</p>
रोजगार संबंधी नियम	<p>भर्ती में आरक्षण</p> <p>कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि/पेंशन : बोर्ड कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की कटौती करके जमा करेगा।</p>	<p>वर्ष के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी।</p> <p>बोर्ड ने :</p> <p>(क) कर्मचारियों की भविष्य निधि के अंशदान की कटौती की और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के योगदान के साथ अपने संबंधित नियोक्ताओं को प्रेषित किया।</p> <p>(ख) नियमित कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए अंशदान की कटौती की और इसे अपने संबंधित एनपीएस खातों में जमा किया।</p> <p>(ग) अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम से संबंधित अंशदायी भविष्य निधि की कटौती की और उसे आवर्ती और सावधि जमा में नियोक्ता के योगदान के साथ जमा किया।</p>
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अनुबंध आधार पर तैनात जनशक्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करे।	बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि जनशक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किया जाए।
अनुबंध श्रम (विनियम और उल्लंघन) अधिनियम 1970	धारा 7 : प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए अनुबंध आधार पर तैनात जनशक्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।	बोर्ड ने दिनांक 3 सितंबर, 2020 के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, इस अधिनियम को अब विलोप कर दिया गया है।

2017 उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने का अधिकार दिया है। हालाँकि, अधिकारी द्वारा अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग रिपोर्टिंग पदानुक्रम में उससे उच्च ग्रेड या स्थिति में किया जा सकता है।

रणनीतिक बैठक

किसी भी संगठन के लिए कार्यनीतिक योजना बनाना महत्वपूर्ण है जो संगठन के उद्देश्य और मापने योग्य लक्ष्यों को चित्रित करने में मदद करती है। यह संगठन को दिशा और साझा दृष्टि की भावना प्रदान करती है। आईबीबीआई जैसे नियामक के लिए, जिसके विभिन्न कार्य और कर्तव्य हैं, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर कार्यनीतिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इस भावना में, आईबीबीआई अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप-कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए वार्षिक कार्यनीतिक बैठकों का आयोजन कर रहा है। 2020-21 के लिए कार्यनीति बैठक कोविड-19 के प्रकोप के कारण नहीं हो सकी। हालांकि, विशिष्ट कार्रवाई योग्य कार्यों के साथ, आईबीबीआई के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए, लघु से मध्यम अवधि के लिए कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की गई थी।

क्षमता निर्माण

आईबीबीआई देश और दुनिया भर में दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता के लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र में अपने अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास करता है। यह इस विकसित क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए शिक्षाविदों, अन्य नियामकों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के महत्व को पहचानता है। तदनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईबीबीआई ने क्षमता निर्माण की दिशा में विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श किया है।

सारणी 82 : 2020-21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले आईबीबीआई के अधिकारी

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम	प्रशिक्षण प्रदाता	प्रशिक्षण का क्षेत्राधिकार/शीर्षक	अधिकारियों की संख्या
1	06.07.20, 15.07.20, 08.07.20, 10.07.20, 13.07.20, 15.07.20	नेतृत्व, टीम निर्माण और संचार कौशल	आईआईसीए	स्वयं के बारे में जागरूकता, व्यक्तित्व के प्रकार, आम सहमति बनाना, संगठन का सहयोग और नेतृत्व। लोक सेवा में नैतिकता।	2
2	04.08.20 -05.08.20	प्रस्तावना कार्यक्रम	आईसीएलएस अकादमी	आईबीसी	7
3	01.09.20 से 04.09.20 और 08.09.20 से 11.09.20	डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी	आईआईसीए	बड़ा डेटा, डेटा पुनर्प्राप्ति, डेटा प्रतिनिधित्व और संगठन।	5
4	16.11.20 से 22.12.20	वाणिज्यिक मध्यस्थता और विचार-विमर्श	आईआईसीए	मध्यस्थता और बातचीत को कवर करने वाले वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।	1

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

आईबीबीआई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार साझा करने और आईबीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है। महामारी के कारण प्रतिबंधों को देखते हुए, इस तरह की बातचीत ज्यादातर ऑनलाइन मोड में हुई। सारणी 81 2020-21 के दौरान उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 81 : 2020-21 में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान

क्र. सं.	तारीख	अध्यक्ष का नाम	पद/संगठन	विषय
1	08.02.21	डॉ. (सुश्री) उदधिबरना बोस	वित्त में सहायक प्रोफेसर, एसेक्स बिजनेस स्कूल, एसेक्स विश्वविद्यालय	क्या शोधन अक्षमता कानून संकटग्रस्त फर्मों के भाग्य में सुधार करता है? क्रेडिट चैनलों की भूमिका
2	09.02.21	डॉ. (सुश्री) अपर्णा रवि	पार्टनर, संवाद पार्टनर्स	दिवाला कानून और समाज पर इसका प्रभाव।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सारणी 82 उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करती है जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के विकसित क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए, कुछ अधिकारियों को विदेश में अध्ययन दौरों पर भेजा गया। इसके अलावा, हितधारकों द्वारा आयोजित कई संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया गया।

5	08.12.20, 10.12.20, 11.12.20, 15.12.20, 17.12.20	वैश्विक अर्थशास्त्र, डिजिटल धन और कारपोरेट प्रशासन परिवर्तन	आईआईसीए	विश्व आर्थिक परिदृश्य, डिजिटल बाजार, फिनटेक दुनिया में नवीनतम विकास, डिजिटल भारत में कारपोरेट प्रशासन।	1
6	07.12.20 से 18.12.20	नियामक प्रदर्शन मूल्यांकन	एफओआईआर	नियामकों का प्रदर्शन मूल्यांकन।	2
7	16.12.20	माल और सेवाओं की ई-खरीद, और संबंधित भारत सरकार वित्तीय नियम	राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली	खरीद में मौलिक सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत, सार्वजनिक खरीद के प्रमुख उद्देश्य, खरीद प्रक्रिया में कदम, खरीद की भूमिका, माल और सेवाओं की खरीद के लिए टीम, भारत सरकार के वित्तीय नियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम।	1
8	29.12.20	निवारक सतर्कता, ई-खरीद और सुशासन की कुंजी	राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली	निवारक सतर्कता, निवारक सतर्कता के उपकरण, सतर्कता में विचार किए गए मामले, मुख्य सतर्कता की भूमिका और कार्य।	1
9	06.01.21 से 10.02.21	वाणिज्यिक मध्यस्थता और विचार-विमर्श	आईआईसीए	मध्यस्थता और बातचीत को कवर करने वाले वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।	1
10	04.01.21 से 22.01.20	समूह 3 नियामक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, "डिजिटल युग में उभरते नियामक मुद्दे"	एफओआईआर	डिजिटल युग में नियामक चुनौतियां और इससे निपटने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीक।	2
11	11.01.21	आरटीआई के माध्यम से सुशासन और पारदर्शिता	राष्ट्रीय उत्पादक परिषद, नई दिल्ली	सूचना का अधिकार अधिनियम और सुशासन और पारदर्शिता में इसकी भूमिका।	1
12	06.02.21 से तीन महीने	नियामक शासन पर सर्टिफिकेट कोर्स	एफओआईआर	विनियमनों को डिजाइन करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए कुशल और प्रभावी साधन।	2
13	08.02.1 से 10.02.21	सेवारत अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	एफओआईआर	नियामक निर्णय लेने में हितधारकों की भागीदारी।	2

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान अपने सभी अधिकारियों के लिए कुछ प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए, जैसा कि सारणी 83 में वर्णित है।

सारणी 83 : आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम/विषय का नाम	संकाय
1	14.07.20, 16.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 28.07.20	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 के समय में दिवाला कानून एमएसएमई का दिवाला व्यष्टिकों का दिवाला आईबीसी और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं दिवाला कानूनों के परिणामों को मापना 	श्री जोस गैरिडो, और सुश्री अंजुम रोशा, सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड
2	04.09.20, 09.09.20, 10.09.20, 11.09.20, 14.09.20	नियामक प्रभाव आकलन	डॉ. क्रिस्टिन वैन ज़िवटेन, एसोसिएट प्रोफेसर, लॉ एंड जस्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और सुश्री एंटोनिया प्रीसीओसा मेनेजेस, सीनियर फाइनेंसियल सेक्टर स्पेसिअलिस्ट, वर्ड बैंक ग्रुप
3	13.10.20	अर्थव्यवस्था, कारपोरेट्स और क्रेडिट आउटलुक पर कोविड-19 की अनलॉकिंग का प्रभाव	क्रिसिल लिमिटेड के रिसोर्स पर्सन
4	22.10.20	प्रीपैक इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क	फोरेन कॉमनवेल्थ एंड डवलपमेंट ऑफिस, यूके टीम
5	23.01.21	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	श्री वडाली रामबाबू, उप सचिव, आईएसटीएम

इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता-ज्ञापन

आईबीबीआई ने भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए 25 जून, 2020 को इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उसी के अधीन, आईबीबीआई इन्वेस्ट इंडिया के स्ट्रेस्ट एसेट्स पोर्टल (एसएपी) के माध्यम से प्रसार के लिए संहिता के अधीन सीआईआरपी के अधीन सीडी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। निवेश भारत समझौता ज्ञापन के अधीन, भारत निवेश ग्रिड पर एसएपी और अन्य निवेशक आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से तनावग्रस्त संपत्तियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा।

आईआईबीएफ के साथ समझौता-ज्ञापन

आईबीबीआई ने 12 अगस्त, 2020 को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के साथ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, बैंकों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर विशेष जोर देने के साथ तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान 'आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स का उद्देश्य बैंकिंग व्यावसायिकों और कर्मचारियों के बीच संहिता के अधीन सीआईआरपी में एफसी और सीओसी की भूमिका और अपेक्षाओं की समझ विकसित करना है। यह उन्हें सीडी और इसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में अत्यंत सावधानी और परिश्रम के साथ वाणिज्यिक निर्णयों सहित अपने वैधानिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा।

आईसीएफआई लॉ स्कूल के साथ समझौता ज्ञापन

आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2020 को आईसीएफआई लॉ स्कूल, हैदराबाद के साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर छह महीने के लंबे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 'भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता कानून' के प्रसार के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं, और दिवाला व्यावसायिक और समाधान, लॉ स्कूल द्वारा पेश किया गया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य उद्यमियों और योग्य व्यावसायिकों, जो इस विकसित क्षेत्र में रुचि रखते हैं, के बीच दिवाला समाधान से संबंधित कौशल सेट और ज्ञान को बढ़ाना है।

संसदीय समितियां

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने 25 अगस्त, 2020 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन' विषय पर एमसीए के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। एमसीए के सचिव और अन्य अधिकारी और अध्यक्ष, आईबीबीआई समिति के सामने पेश हुए और सबूत दिए।

समिति ने 12 जनवरी, 2021 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता-नुकसान और समाधान का कार्यान्वयन' विषय पर एमसीए के प्रतिनिधियों का एक और मौखिक साक्ष्य लिया। एमसीए के सचिव और अन्य अधिकारी और अध्यक्ष, आईबीबीआई समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

ईएसी-पीएम को प्रस्तुति

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने आईबीबीआई, इससे संबंधित मुद्दों और सुझावों आदि पर प्रस्तुतिकरण की मांग की। तदनुसार, डॉ एमएस साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई और श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम,

आईबीबीआई ने 24 नवंबर, 2020 को ईएसी-पीएम को प्रस्तुतिकरण दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईबीबीआई अपनी प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अत्यधिक महत्व को पहचानता है और इसलिए इसकी स्थापना के बाद से अपनी सेवाओं के वितरण के लिए आईटी का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

ई-ऑफिस : पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता सुनिश्चित करना; बेहतर ज्ञान प्रबंधन; आधिकारिक फाइलों और प्राप्तियों के प्रसंस्करण में कर्मचारियों के समय और ऊर्जा की बचत करने की कागज रहित शैली में अंतरण, आईबीबीआई को नवंबर, 2018 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान किए गए ई-ऑफिस एप्लीकेशन में अंतरित कर दिया गया है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन ने ई-फाइल प्रबंधन प्रणाली को तेज और कुशल सक्षम बनाया है। रसीदों को कागज रहित तरीके से जल्दी से संसाधित किया जाता है जिससे कर्मचारियों के समय और श्रम की बचत होती है। ई-ऑफिस ने बोर्ड के अधिकारियों को वास्तविक समय के आधार पर फाइलों की स्थिति और स्थान को ट्रैक करने में सक्षम बनाया है जिससे मामलों का समय पर कार्रवाई और तेजी से निपटारा हुआ है। इसने दस्तावेजों की सुरक्षा, अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार किया है और कुशल पुनर्प्राप्ति प्रणाली स्थापित की है। डिजिटल फाइलों में इस परिवर्तन ने लॉकडाउन के दौरान बोर्ड को भरपूर लाभ दिया है। कोविड-19 के समय में इसने बोर्ड के अधिकारियों को अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए कार्यालय का काम निपटाने में मदद की। ई-ऑफिस का उपयोग पेपरलेस टूर अनुमोदन के लिए भी किया जा रहा है। पैकेज में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है, जो नीतियों और दिशानिर्देशों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करती है। बोर्ड आंतरिक और बाह्य शिक्षण दस्तावेजों को आंतरिक उपयोग के लिए पोर्टल पर अपलोड करता है।

ई-मीटिंग्स : कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले ही, आईबीबीआई ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नामक ई-मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया, ताकि इससे जुड़ी दक्षताओं का दोहन करने के लिए मीटिंग आयोजित की जा सके। इस परिवर्तन ने बोर्ड को अच्छी तरह से भुगतान किया, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी, बोर्ड जीबी बैठकें, आईबीबीआई के भीतर आंतरिक बैठकें और बाहरी संगठनों, विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें कर सका। ई-मीटिंग प्लेटफॉर्म देश और दुनिया भर में फैले हितधारकों के लिए लागत प्रभावी, समय बचाने और सक्षम भागीदारी वाला सिद्ध हुआ है। बोर्ड लॉकडाउन के दौरान बैठकें आयोजित करने में सक्षम रहा और कर्मचारी उत्पादकता में बिना किसी नुकसान के योगदान देने में सक्षम रहे।

वेबसाइट : आईबीबीआई ने डोमेन नाम www.ibbi.gov.in रजिस्ट्रीकृत किया और नवंबर, 2016 में अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए एक वेबसाइट शुरू की। वेबसाइट को संहिता के अधीन अदालतों और न्यायाधिकरणों, बोर्ड और डीसी द्वारा पारित आदेश, सेवा प्रदाताओं, नियामक ढांचे, परीक्षाओं, आदेशों के बारे में विवरण प्रसारित करने के लिए बढ़ाया गया। यह समय पर निर्णय लेने के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए संहिता के अधीन उनसे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और रूपों का विवरण भी होस्ट करता है।

ऑनलाइन परीक्षा : अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र है यदि उसने परीक्षा

उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 से एक आईटी सक्षम परीक्षा उपलब्ध कराई है। परीक्षा कई स्थानों से प्रतिदिन ऑनलाइन दी जाती है। इसी तरह, मूल्यांकन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए, किसी को संबंधित आरिस्त वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 से मूल्यांकन नियमों के अधीन तीन परिस्पति वर्गों, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के लिए आईटी सक्षम मूल्यांकन परीक्षा उपलब्ध कराई। रजिस्ट्रीकरण, भुगतान, नामांकन, उत्पादन सहित पूरी प्रक्रिया प्रश्न पत्र और मूल्यांकन स्वचालित है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण : आवेदन जमा करने और आईपी के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान सहित रजिस्ट्रीकरण की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। आईबीबीआई संबंधित आईपीए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क स्वीकार करता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है। रजिस्ट्रीकृत आईपी का विवरण उसके रजिस्ट्रीकृत होते ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है।

सार्वजनिक परामर्श : आईबीबीआई का यह प्रयास रहा है कि विनियमन बनाने के लिए पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़े। यह अपनी वेबसाइट पर मसौदा विनियमन डालता है, जो टिप्पणियों और सुझावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करता है। यह मौजूदा नियामक ढांचे पर टिप्पणियों और सुझावों की क्राउडसोर्सिंग के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच भी प्रदान करता है।

डेटाबेस तक पहुंच : आईपी को आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो, चाहे वह सीआईआरपी के संबंध में आवेदक या सीओसी द्वारा प्रस्तावित हो। यदि एए आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं, और एए तक पहुंचने के लिए आईबीबीआई की प्रतिक्रिया के लिए पूछताछ करने के लिए एए आईबीबीआई को संदर्भ भेजता है तो इसमें काफी समय लगेगा। यह देखते हुए कि समय संहिता का सार है, आईबीबीआई ने एए को आईपी के लाइव डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की है जो एए को तत्काल एक आईपी नियुक्त करने में सक्षम बनाता है और परिणामस्वरूप तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है। एएएए वाले आईपी का डेटा भी वेबसाइट पर डाला गया है।

नागरिक सेवाएं : आईबीबीआई आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों और अपीलों को ऑनलाइन देखता है। यह ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस में प्राप्त शिकायतों को भी निपटाता है। यह पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस का उपयोग करता है

भर्ती : सभी भर्ती अधिसूचनाएं और उनके परिणाम आईबीबीआई की वेबसाइट पर 'करियर' अनुभाग के अधीन होस्ट किए जाते हैं।

निविदाएं : आईबीबीआई द्वारा जारी सभी निविदाएं (किसी भी संशोधन सहित) आईबीबीआई की वेबसाइट पर 'निविदाएं' खंड के अधीन आमंत्रित की जाती हैं।

पक्ष-समर्थन : आईबीबीआई द्वारा अपने हितधारकों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिसर

आईबीबीआई दो कार्यालय परिसरों नामतः सातवां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली और द्वितीय तल, जीवन विहार, संसद मार्ग, नई दिल्ली से कार्य करता है।

वार्षिक दिवस समारोह

आईबीबीआई ने 01 अक्टूबर, 2020 को अपना चौथा वार्षिक दिवस मनाया। इस उत्सव में कोविड-19 के महिनजर सीमित संख्या में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई। हालांकि, हजारों हितधारकों ने इस कार्यक्रम को युट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव देखा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। अपने संबोधन में, उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 व्यतिक्रमों के संबंध में कारपोरेट दिवाला की फाइलिंग को निलम्बित करने के लिए संहिता में संशोधन एक ऐसा कदम था जो व्यवसायों को समय से पहले बंद होने से बचाने के लिए आवश्यक था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मांग बढ़ने और घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जल्द ही सुधार आएगा।



01 अक्टूबर, 2020 को माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर

अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में, आईबीबीआई ने वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला की स्थापना की है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 'आईबीसी: अनुकूलनशीलता एक महामारी के समय में सुधार की कुंजी है' पर चौथा वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। उन्होंने देखा कि दिवाला कानून ने उधारकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन का नेतृत्व किया है क्योंकि ऋण का भुगतान न करना अब कोई विकल्प नहीं है और फर्म का स्वामित्व अब एक दैवीय अधिकार नहीं है और इक्विटी अब फर्म के मालिक होने का एकमात्र मार्ग नहीं है। उन्होंने देखा कि इस व्यवहारिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप आईबीसी के बाहर लेनदारों के लिए पर्याप्त वसूली हुई और फर्मों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि समय के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए आईबीसी जैसे कानून के लिए अनुकूलनशीलता सबसे जरूरी है।



01 अक्टूबर, 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, श्री गिरीश चंद्र मुर्मु

राष्ट्रीय विजय

आईबीबीआई ने डलडवअ.पद के सहयोग से, देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 01-31 जुलाई, 2020 से 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन विजय' आयोजित की थी। विजय को 1.26 लाख प्रतिभागियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। भारत के हर राज्य और हर संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिभागी शामिल हुए। सी&एजी ने विजय के शीर्ष तीन विजेताओं को पदक और नकद पुरस्कार प्रदान किए।



आईबीबीआई राष्ट्रीय विजय विजेताओं को 01 अक्टूबर, 2020 को पुरस्कार

तनावग्रस्त आस्ति मंच

दिवाला समाधान ने समाधान योजनाओं, अंतरिम वित्त और परिसमापन आस्तियों के मामले में संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार खोल दिया है। किसी भी बाजार में मूल्य की खोज कुशल होती है यदि इसमें कई प्रतिभागी हों और पूर्ण पारदर्शिता हो। कुशल मूल्य खोज के हित में, आईबीबीआई ने संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को सूचीबद्ध किया है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने मंच का उद्घाटन किया।



01 अक्टूबर, 2020 को तनावग्रस्त आस्ति मंच का उद्घाटन



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र की इस वर्ष की थीम 'वीमेन इन लीडरशिप: अचीविंग एन इक्वल एन प्युअर इन कोविड-19 वर्ल्ड' की तर्ज पर आईबीबीआई ने 8 मार्च, 2021 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपी के उभरते व्यवसाय सहित महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। महामारी के दौरान उनकी भूमिका असाधारण रही है।

इस अवसर पर संबोधित करने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सुश्री सुधा आर. रेलंगी, निदेशक (अभियोजन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सुश्री माधवी दीवान, अपर महाधिवक्ता; और सुश्री तृप्ति सिंघल सोमानी, संस्थापक, वुमेनोवेटर और सह-अध्यक्ष, एमएसएमई समिति, पीएचडीसीसीआई शामिल थे। 'इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड वीमेन: मल्टी टास्कर्स' संबंधी तकनीकी सत्र का संचालन सुश्री ज्योति विज, उप महासचिव, फिक्की ने किया। संगोष्ठी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सलाहकार सुश्री ज्योति जिंदगर द्वारा संचालित 'संहिता के अधीन सफल समाधान' विषय पर अनुभव साझा करने के लिए भी एक सत्र था। सेमिनार का सीधा प्रसारण किया गया।

आईआईआर कार्यकारी समिति

डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई को एक वर्ष की अवधि के लिए 4 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर्स (आईआईआर) की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। कार्यकारी समिति आईआईआर का निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, जो आईआईआर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी निर्णय और कार्य करता है।

सूचना का अधिकार और पारदर्शिता

आईबीबीआई, पारदर्शिता के हित में, अपनी वेबसाइट पर नियमों, परिपत्रों और निर्णयों और सेवा प्रदाताओं के विवरण और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न खुलासे करता है। इसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 4 के अधीन निर्धारित खुलासे को अद्यतन किया, इसके अलावा इसे संबोधित किसी भी नागरिक के आवेदन पर जानकारी प्रदान की जा रही है।

आईबीबीआई ने श्री उमेश कुमार शर्मा, सीजीएम को अधिनियम के अधीन किए गए आवेदन पर किसी भी नागरिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 19 अगस्त, 2019 को आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ज) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया। आईबीबीआई में अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के पूरा होने पर, डॉ. सुनील कुमार, डीजीएम को 01 जुलाई, 2020 से सीपीआईओ के रूप में नामित

किया गया था।

आईबीबीआई ने श्री के.आर. साजी कुमार, ईडी को 19 अगस्त, 2019 को आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया। अपने मूल कैडर में उनके प्रत्यावर्तन पर, डॉ अनुराधा गुरु, ईडी को 11 जनवरी, 2021 से एफएए के रूप में नामित किया गया।

सारणी 84 आरटीआई अधिनियम के अधीन 2020-21 के दौरान आवेदनों की प्राप्ति और निपटान और प्रथम अपील का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 84 : आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील की प्राप्ति और निपटान

क्र. सं.	विवरण	संख्या		
		2018-19	2019-20	2020-21
1	पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन	9	9	7
2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने वाले सीपीआईओ को प्राप्त आवेदन	236	230	310
3	आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की गई है	236	232	305
4	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	9	7	12
5	पिछला साल से लाई गई अपीलें	-	0	3
6	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष दायर अपील	29	22	39
7	एफएए द्वारा जिन अपीलों का निपटारा किया गया है	29	19	39
8	एफएए के पास लंबित अपील	0	3	3
9	आवेदन/अपील जिनका निर्धारित समय सीमा में निपटारा नहीं किया गया	0	0	0